## राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस संख्या: 11

गुरुवार,
27 फरवरी 2025

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

### तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम राम। प्रश्न काल।

**प्रश्न संख्या 186**

श्री रामनिवास गावड़िया। श्री रामनिवास गावड़िया।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

**प्रश्न संख्या 187**

श्री रोहित बौहरा। श्री रोहित बौहरा।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

**प्रश्न संख्या 188**

श्री घनश्याम। श्री घनश्याम।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

**बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना**

189. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): जी नहीं। बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंषा नहीं की गई है तथा न ही उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष

विचारार्थ लंबित है तथापि जिला कोटपूतली-बहरोड हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करने की अनुशंषा दिनांक 20.10.2023 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई। नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ में नवीन जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हेतु वर्ष 2025 में बजट घोषणा कर दी गई है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर यथा शीघ्र जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पहले तो मुझे आपका संरक्षण भी चाहिए।

श्री अध्यक्षः पूछिये, पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पिछली सरकार ने ऐसे कर्म किये हैं, जिले खोल दिये, कहीं जिले के 2 नाम होते हैं क्या? फिर कौनसे को आप हैडक्वार्टर मानते हो? यह तो मनचाहे फैसले कर दिये जो उनके अनुसार हुए। जरूरत ही नहीं थी, एक जिला बनाते दूसरी तहसील को उसमें जोड़ देते। यह हमेशा के लिए लोगों के बीच में आपसी तनाव करने के लिए किया।

अब बहरोड में 2 तो एडीजे कोर्ट हैं, 1 एमजेएम कोर्ट है, 4 एसीजेएम कोर्ट हैं व नीमराणा में 1 एमजेएम कोर्ट है, जो बहरोड एडीजे कोर्ट के अधीन ही है। 3 तहसील व 1 उप तहसील कार्यालय स्थापित है व 2 उप खंड कार्यालय बहरोड़ व नीमराणा में स्थापित हैं, इसलिए बहरोड अपने आपमें हर तरीके से न्यायालय के लिए परिपूर्ण था। इसी के साथ में ही, क्योंकि यह एक ही जवाब देंगे, इसके साथ ही यहां मिनी सचिवालय पूर्णतः विकसित है। इसी के साथ उप खंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के लिए भी जमीन आवंटित हो चुकी है। बहरोड़ जिला एवं सैशन न्यायालय खोलने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। यहां पर जमीन व भवन की उपलब्धता है। जिस कोटपूतली-बहरोड़ को 2 तहसीलों के नाम से बनाया गया है, तो बहरोड भी अपने आप में जिला मुख्यालय हुआ। क्या सरकार बहरोड़ में जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? पिछली सरकार और उसके एमएलएज ने जो कुकर्म किये हैं उनको जनता क्यों भुगते।

श्री अध्यक्षः जवाब आ जाने दो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार पुनर्विचार करें, गंभीरता से इस चीज को देखें और जनता के साथ न्याय करें।

श्री अध्यक्षः जवाब आने दो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्षः जवाब आने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात काफी हद तक सही है। किसी भी माननीय सदस्य के लिए उसका विधान सभा क्षेत्र,

सभी के लिए समान होता है। उसके लिए कोई बहरोड़ हो या और कोई हो, फर्क नहीं होता है। उनके लिए पूरा विधान सभा क्षेत्र और फिर विधायक के नाते सभी क्षेत्र उनके लिए एक समान होता है।

जैसा माननीय विधायक ने बताया कि बहरोड़ और नीमराणा में मुकदमेबाजी भी ठीक है। कॉमर्शियल है, औद्योगिक क्षेत्र है। मेरा यह भी मानना है कि यह जयपुर-दिल्ली मैन रोड पर भी है। माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि इसमें मिनी सचिवालय की आवश्यकता भी है। तहसील है, मापदंड भी पूरे करते हैं। जमीन है, भवन है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए है।

ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर, उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। मैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार गंभीरता से इस विषय पर पूरा प्रयास करेगी और आपकी जनता को राहत देगी।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान। आपका आ गया, इससे ज्यादा आपको उत्तर नहीं चाहिए था। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, आपने संरक्षण दिया। आपका धन्यवाद कि इसके लिए आप प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान।

**डीडवाना में संचालित उचित मूल्य की दुकानें**

190. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं? क्या उक्त दुकानें जनसंख्या के अनुपात में सही हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर एक दुकान संचालित है? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर नवीन दुकानें आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला डीडवाना-कुचामन में कुल कितने राशन कार्डधारक हैं? उक्त में से कितनों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 124 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 500 राशन कार्ड अथवा 2,000 यूनिट पर उचित मूल्य दुकान आवंटन के निर्धारित मापदण्डानुसार है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानवार, पात्र परिवारवार विवरण परिशिष्ट-1 पर

संलग्न है।

(2) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) जिला डीडवाना-कुचामन में कुल 4,99,382 राशन कार्ड धारक है। खाद्य सुरक्षा योजना में 2,86,644 परिवारों के 12,14,998 यूनिट को उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है। विधानसभावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चूंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे उत्तर में जो बातें लिखी हैं, उसका अध्ययन भी मैंने कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2023 के अनुसार समावेशन सूची में सम्मिलित अनुसूची-1 के अनुसार खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित पात्र परिवार एवं लाभार्थी को शामिल किया गया है। डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनगणना, अंतिम जनगणना 2011 में हुई और आज 14 साल बाद में 2025 में हम यहां खड़े हैं। यह जो गैप आया जनगणना का, जनगणना 2011 के अनुसार डीडवाना की जनसंख्या जो थी वह लगभग 4 करोड़ थी। अभी जो माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया है, उसमें 4 करोड़ 7 लाख के करीब बताया है। नहीं, 4 लाख 7 हजार, सॉरी, मैं 4 करोड़ को वापिस लेता हूं। इन्होंने लाभान्वित बताये हैं। लगभग 4 लाख 7 हजार बताई है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मेरा यह कहना है, मेरा जो मूल सवाल है वह यह है कि इन्होंने राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में जो इस अधिसूचना के जरिये लोग अधिसूचित किये गये थे, उनमें कितने परिवारों को और कितने लोगों को लाभ दिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं, डीडवाना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा कि डीडवाना क्षेत्र में कुल राशन कार्डों का जो मैंने जवाब दिया कि 1,01,291 हैं और कुल यूनिट 4,07,367 हैं। अब आपका यह है लाभार्थी जोड़ने के लिए, कि हमने इसमें पिछले साल विधान सभा क्षेत्र डीडवाना से 3,580 व्यक्तियों को जोड़ा है। 26 जनवरी, 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोल दिया गया है। इसमें नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें आपके विधान सभा क्षेत्र डीडवाना से 4,276 आवेदन प्राप्त

हुए है। जो आपका प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और दूसरे लाभार्थियों, सबको लाभ मिलना चाहिए। वह इसमें जुडने की प्रक्रिया चालू है और उनको इसमें लाभ मिलेगा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 के अन्दर कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन हुआ यह 2023 में हुआ है। उसके बाद में इसमें जो कैटेगरी डिसाइड की गई हैं, वह 35 कैटेगरी डिसाइड की गई हैं। इनके प्रतिवेदन में ही है। मैंने तो वह पूछा है। यह तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए की बात कर रहे हैं। मैंने तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए के अलावा भी एक अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की है, जो इन्हीं के प्रतिवेदन का हिस्सा है। जिसमें टोटल 32 कैटेगरीजज हैं, उस 32 कैटेगरीज में कितने लोगों को सम्मिलित किया है, यह पूछा है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जितना आपने सूचीवार पूछा है, वह बाइफरकेशन करके, आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): कोई बात नहीं। पहला जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपने दिया कि मैं पूछकर के दे दूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मान लो संज्ञान में नहीं है तो पूछकर के दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अब इन्होंने कहा कि 96 परसेंट हमने जन आधार से जोड़ दिया। जो इनके राशन कार्ड हैं उनको जोड़ दिया है।

**spp/rtm/27.02.2025/11.10/1b**

जब इनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया तो उन लोगों को क्यों वंचित किया गया है, जो 2011 के बाद जन्मे हैं? उन लोगों को इस चीज से क्यों वंचित किया जा रहा है? एक साल हो गया, क्या सरकार जनाधार के माध्यम से जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार खोलने का विचार रखती है, उसके अनुसार ही राशन देने का विचार रखती है? इसके अनुसार ही प्रधान मंत्री जन कल्याण योजना के तहत या जो 5 किलो दिया जाता है, अंत्योदय को 35 किलो और बाकी लोगों को 5 किलो, क्या सरकार देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपने पूछा है 2011 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है, उनको जोड़ने के लिये, तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि पिछले वर्ष हमने 12 लाख 95 हजार लोगों को जोड़ा, उसमें ज्यादातर जो बच्चे थे, उनको जोड़ा और साथ में शादी-शुदा महिलाएं थीं, उनको जोड़ा है। अभी जो 26 जनवरी से पोर्टल शुरू किया गया है, उसमें भी 6 लाख 87 हजार 721 जोड़ दिये गये, उसमें भी ज्यादातर बच्चे हैं और शादी-शुदा महिलाएं हैं, उनको जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। हो गया।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की आंखों का आई कांटेक्ट लेते हैं, पांच साल तक के बच्चों का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्षः यह आप बात कर लेना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे देता हूं। यह जो प्रश्न आपने कहा, इसमें हम EKYC करा रहे हैं, उसमें 10 साल से कम जो बच्चे हैं, उनको छूट दी गयी है। न तो उनको आई कांटेक्ट कराने की जरूरत है, न उनको EKYC कराने की जरूरत है। उनको इस बात की छूट दी गयी है और 70 साल से ऊपर भी हैं, उनको भी छूट दी गयी है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): वह संख्या बता दो आप।

**प्रश्न संख्या 191**

श्री अध्यक्षः श्री डूंगरराम गेदर।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

**प्रश्न संख्या 192**

श्री सुरेश गुर्जर।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

श्री भागचन्द टांकड़ा।

**बांदीकुई में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास एवं संरक्षण**

193. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों का विकास एवं संरक्षण किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आभानेरी चांद बावडी, हर्षद माता का मन्दिर, प्राचीन नन्देरा डूंगरी, सांवलिया धाम करनावर, गुढाकटला की बावडी, मांगा सिद्ध डूंगरी बिवाई, राणा सांगा की छतरी, झाझीरामपुरा स्थित गौमुख ब्रिटिशकालीन प्रोटेस्टेट और कैथोलिक चर्च का संरक्षण एवं विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। दौसा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत सरकार) के अधीन संरक्षित स्मारक हैं। आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराये जा रहे संरक्षण एवं मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

राज्य बजट 2025-26 में ग्रामीण पर्यटन एवं हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

आभानेरी-दौसा को Iconic Tourist Destination के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।

शेष पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विभाग द्वारा पर्यटन विकास कार्यों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): पर्यटन स्थलों के विकास एवं सरंक्षण की क्या नीति है और बांदीकुई में आने वाले पर्यटन स्थलों के विकास के बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि कोई मापदण्ड अभी तक तो निर्धारित नहीं हैं और पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये बजट की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य जैसेकि जन सुविधाओं का विकास, पर्यटन स्थलों का रिनोवेशन, कंजर्वेशन, अपग्रेडेशन, रिपेयर आदि कार्य करवाये जाते हैं और इन्होंने साथ में एक और प्रश्न भी पूछा है तो उसका जवाब भी मैं देती हूं। इन्होंने पूछा कि बांदीकुई विधान सभा में पर्यटक स्थलों के विकास के बारे में, तो बजट 2025-2026 में रूरल टूरिज्म एवं हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आभानेरी दौसा को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी चाँद बावड़ी, आभानेरी एवं हर्षद माता मन्दिर के संरक्षण एवं मरम्मत के कार्य किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः श्री बहादुर सिंह।

**भरतपुर में पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सालय**

**194.** श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर में कितने राजकीय चिकित्सा संस्थानों को, किन-किन संस्थाओं/व्यक्ति/समूह को पीपीपी मोड पर कब से दिया गया है? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं को सरकार द्वारा किस-किस प्रकार की आर्थिक व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने संस्थानों के संचालकों को अयोग्य करार देते हुए संस्थान के संचालन हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह):** (1) जी नहीं। वर्तमान में भरतपुर जिले

में किसी भी चिकित्सा संस्था को पीपीपी मोड पर नहीं दिया गया है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हमने कोई भी हॉस्पिटल पीपीपी मोड नहीं दे रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, डॉक्टरों ने पीपीपी मोड पर हॉस्पिटल बना दिये, वह किस प्रकार बना दिये गये? जो मरीज गरीब होता है, मजदूर होता है, जिस तरह से वह डॉक्टर घर पर बुलाते हैं मरीज को और वह वहां कहते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होगा, सही तरीके से आपको सुविधा नहीं मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा। वह डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री बहादुर सिंह (वैर): डॉक्टर वहां भेज देते हैं और वहां पर उनकी जेबकटी होती है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, यह भरतपुर जिले का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अन्दर जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कठोर कार्यवाही करने का सरकार विचार करती है क्या?

श्री अध्यक्षः बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने पूछा था कि पीपीपी मोड पर पीएचसी दी जाती थी, वह 2021 में कांग्रेस के शासन के समय उनको खत्म कर दिया गया था। लगभग एक एम.ओ. और 11 का स्टॉफ लगता था और महीने के लगभग 1 लाख 80 हजार से 2.50 लाख रुपये तक सरकार उनको पैसे देती थी। वह 2021 में व्यवस्था खत्म हो गयी और आगे विचाराधीन भी नहीं हैं। माननीय सदस्य को प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब यह पूछ रहे हैं कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं, वह इधर रेफर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है तो हमें बताया जाये, हम उस पर सख्त कार्यवाही करेंगे।

**प्रश्न संख्या 195**

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गणेश घोगरा।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

श्री कालीचरण सराफ।

**प्रदेश में गौ अभ्यारण्य की स्थापना**

**196.** श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में मध्य प्रदेश व उड़ीसा की तर्ज पर गौ अभ्यारण्य स्थापित करने का

विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती वसुन्धरा सरकार के समय बीकानेर जिले के नापासर में गायों के संरक्षण के लिये गौ अभयारण्य बनाये जाने का निर्णय लिया गया था और इसके लिये दो समितियों के साथ MOU भी साइन किये गये थे? यदि हां, तो उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2018-19 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बीकानेर जिले के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपये की लागत से गौ अभयारण्य स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। इस गौ अभयारण्य में 5 करोड़ रुपये सरकार द्वारा लगाने का प्रावधान था और जिस संस्था के साथ में MOU हुआ तो उसने भी 5 करोड़ रुपये लगाने का MOU किया था। निदेशालय गोपालन द्वारा गौ अभयारण्य स्थापना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसकी पालना में जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में जिला गोपालन समिति द्वारा अभयारण्य के प्रबन्धन हेतु श्री सोहनलाल भुलादेवी ओझा गौशाला समिति नापासर जिला बीकानेर का चयन किया गया। जिला कलेक्टर एवं उक्त समिति के बीच में MOU हुआ। राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा गौ अभयारण्य हेतु 221.31 हैक्टेयर चरागाह भूमि बिना किस्म परिवर्तन के राजकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पालना नहीं करने के कारण वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोपालन सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को परियोजना के MOU को निरस्त किये जाने हेतु निर्देशित किया।

**jyg/rtm/27.02.25/11.201c**

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तर्ज पर गो अभ्यारण्य बनाये जाने के लिए माननीय मंत्रीजी ने नवम्बर 2024 में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि गो अभ्यारण्य बनाये जाने से गोवंश की देखभाल में सुधार होगा, गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रसंस्करण और उससे उत्पाद निर्माण की योजना बनायी जा सकेगी और इस योजना से खुले में घूमने वाली गायों को आश्रय भी मिलेगा? यदि हां, तो क्या भविष्य में सरकार का गौ अभयारण्य बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में गौ अभयारण्य चल रहे हैं। इसी तर्ज पर पूरे राजस्थान में 1 करोड़ 39 लाख गोवंश है। हमारे यहां राजस्थान में निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोशालाएं संचालित हैं। 4140 के आसपास गोशालाएं संचालित हैं। पात्र गोशालाओं को गोवंश के संवर्धन, चारे-पानी के लिए बड़े गोवंश के 44 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसे अभी बजट वर्ष 2025-26 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में माननीय दिया कुमारीजी ने 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपये बड़े गोवंश को और 25 रुपये छोटे गोवंश को प्रतिदिन करने का निर्णय किया है, इसकी बजट में घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो अनुदान दिया जा रहा है इस वर्ष 2024-25 में 21.02.25 तक 1147 करोड़ का अनुदान गोवंश के भरण-पोषण के लिए हमने जारी किया है। इसके साथ में अभी राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनमें निराश्रित व बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। जिला स्तरीय गोशालाएं चल रही हैं, जिनमें 15 गोशालाओं में हमने 6 करोड़ 75 लाख रुपये के काम कराये हैं। पंचायत समिति स्तरीय गोशालाएं चल रही हैं, जिनमें 95 गोशालाओं में, नन्दीशालाओं में 49.47 करोड़ रुपये के काम कराये हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय पशु आश्रय स्थल योजना चल रही है जिसमें हमने 10 गोशालाओं में 4 करोड़ के काम कराये हैं। गोशाला विकास योजना चल रही है जिसमें 455 गोशालाओं में हमने 26.16 करोड़ रुपये के काम कराये हैं। साथ ही साथ गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 गोशालाओं में गोकाष्ठ मशीनें देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उड़ीसा व मध्य प्रदेश में चल रही गौ अभयारण्य की योजनाओं की जानकारी विभागीय स्तर पर मंगवा रहे हैं, उन दोनों सरकारों को हमने पत्र भी लिखा है। उन योजनाओं को मंगवायेंगे और मंगवाकर उनका परीक्षण करवायेंगे और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे निर्णय भी लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ...(व्यवधान)... आपके दो पूरक प्रश्न हो गये। हो गया आपका, इसका उत्तर इतने डिटेल में आ गया।

श्री अरूण चौधरी।

**बालोतरा में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों**
**से आ रहे प्रदूषित पानी की रोकथाम**

197. श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बालोतरा के डोली, अराबा, कल्याणपुर ग्राम में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी से वहां की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित हो रहा है? यदि

हां, तो सरकार द्वारा लिये गये सैम्पल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रदूषित पानी को रोकने हेतु सरकार की कोई कार्ययोजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिला बालोतरा में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से आ रहे प्रदूषित पानी के लिये किन-किन दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जोधपुर क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल एवं स्टील उद्योग से जनित होने वाले औधोगिक उच्छिष्ट (Industrial Effluent) को उपचारित करने हेतु दो सी.ई.टी.पी. क्रमशः 18.50 MLD (Textile) एवं 1.50 MLD (Steel) संचालित है।

Steel उद्योगो से संबंधित सी.ई.टी.पी. द्वारा उपचारित जल को पूर्णतया recycle कर reuse किया जाता है एवं Textile उद्योगो से संबंधित सी.ई.टी.पी. द्वारा औद्योगिक उच्छिष्ट (Industrial Effluent) को तृतीयक स्तर (Tertiary Treatment) तक उपचारित कर निस्रावित (Discharge) किया जाता है।

जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी से जिला बालोतरा के ग्राम डोली, अराबा, कल्याणपुर की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध नहीं है। डोली, अराबा, कल्याणपुर क्षेत्र से माह दिसम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 में लिए गये छह (Six) सैम्पलो की रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदूषित पानी को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) डोली अराबा में जल प्रदूषण की समस्या के बाबत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी लंबित हैं एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में किया जा चुका है एवं एक जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में किया जा चुका है।

इस समिति का उद्देश्य प्रदूषण की समस्या की नियमित निगरानी करना और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक तो सवाल यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार इसमें यह जवाब दिया गया है, मैंने प्रश्न पूछा था कि किन-किन दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गयी है? एक यह लिखा है कि जमीन पर वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध नहीं है। जब मेरे द्वारा 2024 के अन्दर और जनवरी 2025 में सैम्पल लेने के लिए और मैंने आवश्यक निर्देश दिये और उस निर्देश की पालना में जो रिपोर्ट आयी उसके आधार पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं माननीय मंत्रीजी से एक तो यह निवेदन करूंगा कि

जो दोषी अधिकारी हैं, जोधपुर का गंदा पानी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र और हमारे संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, जोगारामजी पटेल, इनके विधान सभा क्षेत्र से भी आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी दुर्गति है...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): मैं चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है इसमें जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा 21.02.2025 को एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है। एक तो इस समिति की रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आ जाये और मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक समिति वहां पर, पर्टिकुलर वहां पर जाकर वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन करे कि वहां की स्थिति कैसी है। एक नाला या कोई और योजना की डीपीआर बनाने की घोषणा करावें मंत्री महोदय जिससे उस क्षेत्र के अन्दर यह दुर्गति दूर हो सके।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहना है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जोधपुर शहर में सीवरेज के कुल लगभग 230 एमएलडी जनित हो रहा है। जिसमें लगभग 120 एमएलडी का ट्रीटमेंट सीईटीपी के माध्यम से किया जा रहा है। शेष 110 एमएलडी सीवरेज अनट्रीटेड नदी में जा रहा है। इस हेतु यूडीएच, एलएसजी के द्वारा 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि औद्योगिक उचिष्ट के ट्रीटमेंट हेतु कुल 120 एमएलडी, 18 एमएलडी टेक्सटाइल्स सीईटीपी एवं 1.5 एमएलडी स्टील सीईटीपी क्षमता के सीईटीपी प्लांट स्थापित हैं। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले औद्योगिक उचिष्ट के ट्रीटमेंट उपरांत स्टील सीईटीपी से पुन: चक्रण एवं टेक्सटाइल्स सीटीपी से नदी में स्राव किया जाता है। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने जो डिमांड रखी कि वहां पर समिति जाकर समय-समय पर जांच करे तो जिला कलेक्टर महोदय ने जो जांच कमेटी बनायी है, उक्त कमेटी जोजरी नदी में आने वाले समस्त जल उच्छिष्ट स्रोतों के साथ-साथ उक्त नदी में उच्छिष्ट डिस्चार्ज करने वाले स्रोत इकाइयों को चिंहित कर, उनकी फोटोग्राफी कर एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करवायेगी। नियम विरुद्ध अनुपचारित जल उच्छिष्ट स्रावित करते हुए पायी जाने वाली अवैध इकाइयों की फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

**जावर माइंस में वेदान्ता ग्रुप के कार्यरत श्रमिक**

198. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर में जावर माइंस में वर्ष 2020 से अब तक वेदान्ता ग्रुप की कौन-कौनसी कम्पनी में कितने श्रमिक कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त माइंस में कार्यरत कितने श्रमिक प्रभावित पंचायतों के कार्यरत है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (श्रम मंत्री के स्थान पर): (1) उदयपुर में जावर माइंस में वर्ष 2020 से अब तक वेदान्ता ग्रुप (मुख्य नियोजक) के रुप में पंजीकृत है। वर्तमान में 50 कम्पनियों के कुल 6280 ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) उक्त माइंस में प्रभावित पंचायतों के 2533 श्रमिक कार्यरत हैं। (संलग्न परिशिष्ट-2)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं कि वहां जावर माइंस के अन्दर 6280 मजदूर काम कर रहे हैं मगर जो प्रभावित पंचायतें हैं, 9 पंचायतें हैं। उस माइंस के अन्दर कांग्रेस की एक यूनियन है इन्टक के नाम से, वो हमारे मजदूरों के लिए और गांव वालों ने माइंस को धरना-प्रदर्शन करके रोजगार के लिए बंद की थी।

**MLS/RTM/27.02.2025/11:30/1d**

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 17 दिनों तक धरने पर बैठे, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि 85 परसेंट लोकल मजदूरों को हमने लगा रखा है, मगर आज मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2533 मजूदर काम कर रहे हैं, 40 परसेंट लोकल मजदूर काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बाहर के मजदूर, यानी 60 परसेंट वहां काम कर रहे हैं, जबकि वहां पर 90 परसेंट से ऊपर की ट्राइबल आबादी है। उन लोकल आदमियों को 17 दिनों तक धरने पर बन्द रखा माइंस को, उसके बावजूद भी रोजगार में नहीं लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 आदमियों को रोजगार के लिये लेने का आश्वासन देकर माइंस चलाईं, मगर आज भी उन 20 आदमियों को रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। हमारे 30 आदमियों को भारतीय जनता पार्टी का बहाना करके घर पर बैठाया है, क्या उन्हें रोजगार देने का विचार है? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहूंगा,

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश भारत सरकार द्वारा 2022 में किया गया, जिसके बाद इसे वेदान्ता लिमिटेड ने अधिग्रहित कर लिया। वेदान्ता ग्रुप में 514 कर्मचारी भी कार्यरत हैं। उनमें भी स्थानीय कर्मचारी काफी हैं। यह जो मैंने आपको सूची दी, उसमें 6280 श्रमिक हैं, जिसमें से आपके 2500-3300 ठेका कम्पनियों द्वारा लगाये गये। आपका प्रश्न जो है, आपका क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं और यह होना भी चाहिये, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिये तो बिलकुल यदि वे सक्षम लोग हैं, उनके पास टेक्निकल डिग्री है तो उन स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास सरकार द्वारा बिलकुल किया जायेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन माइंस ने हमारी पंचायतों से एनओसी ली थी, तब उन्होंने यह वादा किया था...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नहीं, यह अलग है, मैं सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछ रहा हूं। उन्होंने यह वादा किया था कि हम वहां पर ट्रेनिंग सैंटर्स खोलकर इनको माइनिंग की इंजीनियरिंग करवाएंगे। आज दिन तक माइनिंग की इंजीनियरिंग नहीं करवायी है और वहां पर जो फिल्टर्ड पानी देने का वादा किया था, आज भी हमारे वहां फ्लोराइड का पानी दे रहे हैं। मैंने मंत्री के मैनेजर को और इनको बताया, मगर आज भी वे वहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं। एक तो माइनिंग कॉलेज खोलने का उनका जो वादा था, वह आज दिन तक पूरा नहीं किया। मेरा निवेदन है, वहां लोकल लोगों को इंजीनियरिंग करवाकर वहां रोजगार दें और शुद्ध पानी कब तक दिला देंगे?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर यह है कि वास्तव में यदि इस तरह का एग्रीमेंट वहां पर किया गया है, जब जिस समय यह विनिवेश किया गया था और जब यह वेदान्ता ग्रुप ने लिया, यदि वहां पर छात्र-छात्राओं को आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दिये जाने का इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया गया है तो बिलकुल मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि इस तरह का एग्रीमेंट है तो सरकार उसे लागू करायेगी।

दूसरा, फिल्टर्ड पानी की बात है, यह तो आपका हक बनता है, फिल्टर्ड पानी के लिये हमने विभाग के द्वारा, वैसे तो यह विषय श्रम समवर्ती सूची के कारण भारत सरकार के श्रम विभाग के अधीन भी आता है, पर बिलकुल हम राज्य सरकार के द्वारा, कि आदिवासी क्षेत्र है, उनको फिल्टर्ड पानी मिले, ताकि उन्हें बीमारियों से भी मुक्ति मिले, उसको लागू कराएंगे बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

## आर जी एच एस में बायोमैट्रिक अनिवार्यता में शिथिलता

199. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को आरजीएचएस (RGHS) योजना में

बायोमैट्रिक एंट्री के साथ लाइव फोटो अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त निर्णय से असक्षम कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को हो रही समस्या के कारण शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वित्त मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) आरजीएचएस योजनान्तर्गत राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिये चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों का लाइव फोटो अनिवार्य किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-1 दिशा-निर्देश दिनांक 28.11.2024)

उक्त दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में निर्देश दिनांक 16.01.2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22.01.2025 के द्वारा गम्भीर बीमारियों से ग्रसित Bed-ridden पेंशेंट एवं 75 या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो से छूट प्रदान की गयी है। (संलग्न परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3)

कारणः- आरजीएचएस योजनान्तर्गत सतर्कता शाखा द्वारा विश्लेषण उपरान्त कतिपय प्रकरणों में दुरुपयोग पाये जाने के कारण दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत उक्त परिवर्तन किये गये हैं।

(2) आरजीएचएस योजनान्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 16.01.2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22.01.2025 के द्वारा सभी सरकारी एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में गम्भीर बीमारियों से ग्रसित Bed-ridden पेशेंट एवं 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के आरजीएचएस लाभार्थियों को सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुविधा के सम्बन्ध में लाइव फोटो में शिथिलता प्रदान की गयी है। (संलग्न- परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि अनेक प्राइवेट मेडिकल अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल दुकान वालों द्वारा आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होते हुए भी रिटायर्ड राजकीय कर्मचारियों को मना कर दिया जाता है कि हम आरजीएचएस नहीं मानते हैं। क्या यह स्कीम बन्द होने वाली है या भविष्य में बन्द हो जायेगी? ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को न एडमिट किया जाता है, न समय पर दवाइयां मिलती हैं। माननीय मंत्री महोदया, इस भ्रम को दूर करने हेतु बताएं कि आरजीएचएस स्कीम का भविष्य क्या है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि आज की स्थिति में इस स्कीम को बन्द करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक रजिस्टर्ड अस्पतालों द्वारा इलाज करने से मना करने एवं दवाई वालों द्वारा दवाई देने से मना करने की जो बात माननीय सदस्य ने बतायी कि वे मना करते हैं तो यह गलत है। ऐसे प्रकरणों में सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उनके खिलाफ

कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदया, सरकारी कर्मचारी 30-40 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है, उसके बाद भी उसे सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसमें गम्भीर बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स तथा 75 से अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो और बायोमैट्रिक में छूट प्रदान की गयी है, परन्तु आज की जीवनशैली में 50 की आयु के बाद ही व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यह छूट 75 वर्ष से कम करके 60 वर्ष की जाये। 60 वर्ष की आयु वालों को लाइव फोटो और बायोमैट्रिक में छूट प्रदान किये जाने की सरकार की मंशा है अथवा नहीं, यह एक बार बताएं और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि लाइव फोटो की अनिवार्यता दुरुपयोग को रोकने के लिये की गयी है एवं सरकार द्वारा गम्भीर बीमारियों से ग्रसित कार्मिकों के लिये आयु की सीमा नहीं रखी गयी है। अतः पेंशनर्स एवं सरकारी कर्मचारियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और यदि कोई गम्भीर बीमारी से ग्रसित है, चाहे वह 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, उसका इलाज किया जायेगा।

**प्रश्न संख्या 200**

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनीष यादव।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

**भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम**

201. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा ई-वाणिज्यिक क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों और दोषपूर्ण उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये?

(2) सरकार ने ई-वाणिज्यिक कम्पनियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिये क्या नियामक कदम उठाये हैं?

(3) अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये नीतिगत और कानूनी प्रावधान क्या हैं?

(4) क्या अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त कम्पनियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है? यदि हां तो आरोपित कम्पनियों पर किसी प्रकार की शास्ति लगायी गयी है?

उपभोक्ता मामलात मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) ई-कॉमर्स क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन एवं दोषपूर्ण उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिये विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारों का एवं इसके अन्तर्गत मिलने वाले प्रतितोष का

समय-समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं उनके निराकरण के लिये वैकल्पिक शिकायत निवारण व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन सोमवार से शनिवार (राजकीय अवकाश को छोड़कर) प्रातः 10.00 से सायंकाल 05.00 बजे तक नियमित किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन पर इससे सम्बन्धित शिकायतें टोल फ्री नम्बर 18001806030 एवं 14435 पर, व्हाटसएप नम्बर 7230086030 पर की जा सकती हैं तथा मेल/डाक अथवा व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

हैल्पलाइन द्वारा इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को प्रतितोष हेतु सम्बन्धित आयोग में परिवाद दायर करने हेतु निःशुल्क सलाह/परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

(2) ई-वाणिज्यिक कम्पनियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिये नियामक कदम उठाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-94 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार सक्षम है।

इस क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 जारी किये गये हैं।

(3) अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिये केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये/अपनाये जा रहे नीतिगत एवं कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009
- राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011
- विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011

(4) अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त कम्पनियों पर कार्यवाही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-35 के अन्तर्गत स्वयं उपभोक्ता द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में की जा सकती है।

आरोपी कम्पनियों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विधिक आलोक में आयोग की न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से शास्ति लगाये जाने का प्रावधान है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार सिद्ध हो जाने पर जिला आयोग त्रुटि दूर करने, अनुचित व्यापार व्यवहार बन्द करने, परिसंकटमय वस्तु के निर्माण को बन्द करने, राशि ब्याज सहित वापस लौटाने तथा ऐसी राशि देने, जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन-वहन की गयी है, को जिला आयोग दण्ड/शास्ति, जिसे वह ठीक समझे, लगाये जाने में सक्षम है।

**MKD/RTM/27.02.2025/11:40/1e**

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि इन्होंने हैल्प लाइन नम्बर के बारे में तो बताया है, पर मैं यह जानना चाहूंगी कि ई-वाणिज्य क्षेत्र में जो नकली छूट, फर्जी रिव्यू और ग्राहकों को गुमराह करने वाले जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर रोक लगानी चाहिए, उसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाये हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी इसके लिए बड़ी जागरूक है। सभी जगह कैम्पेन, चाहे राष्ट्रीय मीडिया पर हो, चाहे स्थानीय अखबारों में जागो ग्राहक कैम्पेन के नाम से लगातार चलाये जा रहे हैं। जिससे लोगों में जागरूकता आये और उसका असर भी आम लोगों में देखने को मिला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगी कि जो राज्य में उपभोक्ता हैल्पलाइन है, उसमें वर्तमान में एवं विगत वर्ष में प्रति वर्ष कितनी उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और इनका समाधान करने की प्रगति क्या है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विगत वर्ष में 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रहीं और जो लम्बित हैं, वे 180 हैं।

हमारा विभाग, आयोग लगातार उपभोक्ता हैल्प लाइन के माध्यम से, उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरुकता भी आये और उपभोक्ताओं को भी लगे। जिस तरह केन्द्र सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं कि भारत, विकसित भारत बने तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीजें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है।

**जैसलमेर में स्थित प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत**

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छोटू सिंह।

202. श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जैसलमेर में पुरातात्विक महत्व के देवालय व प्राचीन मंदिर कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पुरातात्विक महत्व के कई देवालय व प्राचीन मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उक्त मंदिरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जैसलमेर जिले में पुरातात्विक महत्व के देवालय और प्राचीन मंदिरों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त देवालयों और प्राचीन मंदिरों में नभडूंगरी-शिव मंदिर वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

उक्त मंदिर विभाग द्वारा संरक्षित मंदिरों/देवालयों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं तथा वर्तमान में इसके जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन/प्रक्रियाधीन नहीं है।

विभाग द्वारा बजट उपलब्धता एवं युक्तियुक्त प्राथमिकता के आधार पुरातात्विक महत्व के स्थलों/स्मारकों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, आपका जवाब परिशिष्ट-1 पर आया। जैसलमेर एक विशाल क्षेत्र है और आजादी से पहले के इस क्षेत्र के अन्दर कई गढ़ बने हुए हैं, वे भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उन गढ़ों के अन्दर मन्दिर भी हैं। वहां के लोग वहां पूजा करते हैं, लेकिन वे भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। विशेषकर जो नभ-डूंगर मन्दिर है, उसके पास में भी, जिसको मुहार के नाम से जाना जाता है, वहां शिव मन्दिर है, वह उस समय का बना हुआ है, जब आजादी से पहले वहां चौरासी खेड़े पालेवाला के रहते थे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): वह आज शीर्ण अवस्था में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कई मन्दिर हैं, जिनको इस रिकॉर्ड में इन्होंने परिशिष्ट-अ पर नहीं दिया है। हमें याद है, उन मन्दिरों को इस रिकॉर्ड में लेकर उनकी मरम्मत करवाना, उनको नई अवस्था में लाने का विचार रखते हैं? या नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी कि जीर्ण-शीर्ण मन्दिरों एवं स्मारकों का जीर्णाद्धार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जो बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाता है। मैं नभ-डूंगरी मन्दिर को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करवा लेती हूं और आवश्यकता होने पर हम लोग बिलकुल इसका कार्य भी करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष उन मन्दिरों के बारे में, मैं सीमान्त का रहने वाला हूं। वहां एक घोटेरू सीमान्त जगह पर एक गढ़ बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): वह गढ़ आज भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। वहां मैय्या का मन्दिर है, जोमाया का। साहब सुनिये, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): सुनिये, उस मन्दिर को या मेघा गांव के पास जो चाचक देव का मन्दिर है और उसमें परमानेंट पानी रहता है, ठीक उसी प्रकार से एक भीम गोडा के नाम से जाना जाता है। दंतकथाओं और पुरानी कथाओं में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में भीम ने यहां गोडा लगाया था, जिससे वहां परमानेंट पानी चलता रहता है। क्या उस जगह पर आप मन्दिर बनाने का विचार रखते हैं? साथ ही निवेदन है कि उन मन्दिरों के पास अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, खेजड़ी हैं, केर हैं, जाल हैं, बोरड़ी हैं, बूंदी हैं तो क्या उन पूरी मुंह बोली ओरण का भी संरक्षण करना चाहते हो? विकसित करना चाहते हो? मैं आपके मार्फत आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः विरोजो। माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर पूरा आश्वासन देती हूं माननीय सदस्य को कि आप जो बता रहे हैं कि मन्दिर भी हैं, स्मारक भी हैं तो आप मुझे अगर पूरी सूची दे दें और जो-जो कार्य करवाने हैं, उनका विवरण दे दें तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ये सारे काम करवायेगी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। प्रताप सिंह सिंघवी।

**छबड़ा में वन भूमि पर अतिक्रमण**

203. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के गांव जांचरोड़ा, अल्लापुरा, कडैयाचोर तथा कादरपुरा की वन भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो किन-किन लोगों का कहां-कहां? अतिक्रमियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अतिक्रमण के लिये दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। छबडा क्षेत्र के गांव जांचरोडा, अल्लापुर, कडैयाचोर तथा कादरपुरा में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। अनधिकृत कब्जेधारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) जी हां। उक्त गांवों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु LRA-91 के प्रकरण बनाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक छीपाबडौद में प्रस्तुत कर दिये गये हैं, न्यायालय के निर्णय उपरान्त नियमानुसार अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 11 (10)

जांच/प्रमुवसं./2025/ राज काज नं. 13814903 दिनांक 25.02.2025 संलग्न परिशिष्ट-2 के द्वारा रेंज छबडा में वनभूमि के अतिक्रमण के क्रम में वन संरक्षक (मूल्यांकन एवं प्रबोधन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह जो जवाब दिया गया है, सरकार के द्वारा, यह अधूरा है, पूर्ण जवाब नहीं है।

परिशिष्ट-अ में, जो जवाब दिया है, उसमें अल्लापुरा में किन-किन लोगों की कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा है, वन भूमि पर, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है, नम्बर वन।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैंने यह प्रश्न लगाया और लिस्टेड हुआ, उसके बाद प्रधान वन संरक्षक ने 25 फरवरी को 91 की कार्यवाही के आदेश सीसीएफ, कोटा को दिये।

मैं यह जानना चाहूंगा कि जब मैं 2005 से, 2022 से लगातार चिट्ठी लिख रहा हूं कि इस वन भूमि पर करोड़ों की टीक वुड, सागवान के पेड़ काटकर कब्जा करके लोग-बाग़ ट्यबवैल लगाकर खेती कर रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है फॉरेस्ट विभाग की या वहां के स्थानीय प्रशासन की कि इस कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है? जबकि मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत भी मिल चुका। मंत्री महोदय ने भी मुझे आश्वस्त किया कि मैं निश्चित रूप से इस कब्जे को हटवा दूंगा, पर यह 91 की कार्यवाही करना, वह भी जैसे मेरा 50 बीघा पर कब्जा है..।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक मिनट साहब। 50 बीघा पर कब्जा है और उसको स्प्लिट करके किसी के नाम से दो बीघा, किसी के नाम पर तीन बीघा, किसी के नाम पर पांच बीघा, ताकि वह 50 बीघा का चंक फॉरेस्ट के अधिकारियों के या मंत्री जी की निगाह में नहीं आये।

**Bhs/Rtm/27.02.25/11.50/1f**

और 91 की कार्यवाही जहां तक मैं समझता हूं मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, चालीस साल से इस विधान सभा में आ रहा हूं पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि लगातार पत्र लिखने के बाद चाहे सरकार पक्ष की रही हो या विपक्ष की रही हो, निश्चित रूप से कार्यवाही हुई है और इस भूमि पर तो फॉरेस्ट विभाग ने चौकी लगा कर अतिक्रमण नहीं हो इस प्रकार की कार्यवाही की थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चौकी हटा कर उन्हीं लोगों को वापस कब्जा करवा दिया? और वो ट्यूबवैल लगवा कर वहां पर खेती कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इससे शर्मनाक बात इस पूरे फॉरेस्ट विभाग के लिए कोई कुछ नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न पूछो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मैंने सरकार को जो पांच पत्र लिखे हैं वो तो मैं टेबल कर ही रहा हूं साथ ही, मैं माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप यह अतिक्रमण हटवा नहीं पा रहे हो? या तो मजबूरी बताओ, जैसे हमारे हाड़ौती में कहावत है या तो पाप बताओ या श्राद्ध करो। पाप बताना पड़ेगा या श्राद्ध करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। उत्तर सुनिये। माननीय सदस्य, उत्तर सुनिये। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): ...(व्यवधान)... आपको इस जमीन पर से, हमारे प्रधान मंत्री चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। हमारे प्रधान मंत्री, हमारे मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)... आप पूरी बात तो सुन लो, साहब।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आने दो। भाषण नहीं। प्रश्न का उत्तर आने दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): भाषण नहीं दे रहा हूं मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जवाब ही पूरा नहीं आया। जवाब पूरा दो।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आने दो। विराजो। आपको उत्तर दिलवा रहा हूं न।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): यह मैं टेबल कर रहा हूं जो मैंने पत्र लिखे हैं न। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ठीक है। यह सदन है। प्रश्न काल है। आप उत्तर दीजिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है विशेष रूप से अल्लापुरा गांव का जो उल्लेख किया है। ग्राम अल्लापुरा के सभी नौ प्रकरणों में कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर दिये गये और सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन प्रकरणों में कुल पेनल्टी 1 लाख 13 हजार 200 रुपये अधिरोपित की गई है तथा ग्राम अल्लापुरा के सभी अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही साथ, आपने जिस प्रकरण की अभी चर्चा की और थोड़ा बोलते-बोलते बड़े हाईपर हो गये थे, 2022 से आपने आरोप लगाया है। 2022 में कांग्रेस की सरकार थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार संवेदनशील भी है और पारदर्शी भी है। आपने जो भी पत्र लिखे उस सन्दर्भ में जांच भी की जा रही है और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पत्र जा चुका है और आने वाले समय में जो भी अतिक्रमी वन भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, अतिक्रमण हटा कर वन भूमि को सुरक्षित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्र भान सिंह।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आपके बहुत आ गये, चार प्रश्न आ गये। आपने टेबल कर दिया और क्या चाहिये?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): आप पूछने तो दें।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं। श्री चन्द्र भान सिंह।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। सारे उत्तर दे दिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अल्लापुरा में खसरा नम्बर 88, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह आप मिल कर दे देना। माननीय मंत्री जी, श्री चन्द्र भान सिंह का।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): आप जवाब दिलवा दें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। इससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता। पूरा दे दिया मंत्री जी ने। आप विराजें। 10 मिनट एक प्रश्न पर पूरक प्रश्न थोड़े पूछा जाता है।

**गडरा रोड शाखा का निर्माण**

204. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़) (श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव) के स्थान पर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की संशोधित परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में गडरा रोड शाखा की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शाखा कहां से कहां तक तथा कितनी राशि की स्वीकृत की गई? उक्त का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया तथा अब तक कितना निर्माण पूर्ण किया जाकर स्वीकृत राशि में से कितना व्यय हो चुका है व उक्त से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में गडरा रोड शाखा का कार्य बंद है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में बाड़मेर जिले में गडरा रोड उप शाखा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे प्रथमतः वर्ष 1987 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट में सम्मिलित किया गया था जिसे वर्ष 1993 में संशोधित किया गया। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1998 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल लागत रुपये 3398.91 करोड़) में गडरा रोड़ उपशाखा प्रणाली के लिये रू 487.59 करोड का प्रावधान निर्धारित था। (परिशिष्ट-1)

(2) गडरा रोड़ उपशाखा, सागरमल गोपा शाखा की आर.डी. 314 (टेल) (रामगढ़, जैसलमेर) से शुरू होकर 114 किमी लम्बाई में तथा इसकी टेल से 80.77 किमी लम्बाई में गडरा रोड़ वितरिका गडरा रोड तक निर्मित की जानी प्रस्तावित थी। जिसमें से 92.05 किमी तक उपशाखा तथा इससे निकलने वाले वितरण प्रणाली का निर्माण 437.93 किमी में किया गया है। गडरा रोड उपशाखा प्रणाली हेतु वर्ष 1998 में स्वीकृत इ.गा.न.प. द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल स्वीकृत राशि 3398.91 करोड़) में गडरा रोड उपशाखा प्रणाली हेतु

रुपये 487.59 करोड़ का प्रावधान निर्धारित था। उक्त नहर प्रणाली के प्लानिंग व सर्वे का कार्य वर्ष 1987 से ही आरम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2013 तक नहर निर्माण कार्य किया गया। तब तक उक्त कार्य पर रुपये 374.26 करोड़ व्यय किये गये। उक्त नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में औसत 13116 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है।

(3) जी हां, वर्तमान में गडरा रोड उप शाखा का नहर निर्माण कार्य बन्द है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण नहर निर्माण के मात्र प्रगतिधीन कार्यों को ही पूर्ण करने की अनुमति दिये जाने के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिंचित क्षेत्र सीमित कर दिया गया। जिसके कारण गडरा रोड उप शाखा  के 92.05 किलोमीटर तक का ही कार्य पूर्ण हो सका। परियोजना के सिंचित क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण उक्त नहर का आगे निर्माण कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है यह इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी गडरा रोड तक क्यों नहीं पहुंचा है इसके बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना दूंगा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): कौन सी नहर का है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न उनका है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो इन्दिरा गांधी कैनाल है वो मैन कैनाल है वह मोहनगढ़ तक चलती है और उसके बाद एक जो उसकी ब्रांच है सागरमल गोपा वह 95.07 किलोमीटर बना दी गई है। सागरमल गोपा ब्रांच के बाद में एक सब ब्रांच है बाबा रामदेव जो गडरा रोड के लिए बनी है उसका भी 92 किलोमीटर निर्माण हो चुका है और बेलेंस 22 किलोमीटर अभी जो डिस्ट्रिब्यूटरी है अभी उसका कार्य नहीं हुआ है उसमें 22 किलोमीटर अगर हो जाता तो 80 किलोमीटर और बनने पर गडरा रोड पानी पहुंच जाता। अभी तक इसका जो सैंक्शंड अमाउंट 487.59 करोड़ था, खर्चा 474 करोड़ हो चुका है और 13,116 हैक्टेयर इर्रिगेटेड जो जमीन है पिछले पांच साल में इसका इर्रिगेशन हुआ है। यह प्रश्न प्रश्नकर्ता ने पूछा था। इसका कारण यह है कि 1981 में राजस्थान और पंजाब के बीच में एक ट्रीटी हुई थी 0.6 मिलियन एकड़ फुट एम.ए.एफ. पानी पंजाब राजस्थान को देगा। उसके पश्चात हुआ क्या कि हमारा कैनाल का सिविल वर्क्स तैयार नहीं था। काफी हद तक हमने पानी यूज करने दिया उसके बाद पंजाब ने पानी देना रिफ्यूज कर दिया। जो मुख्य कारण गडरा रोड के पानी का वो मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, बता रहा हूं। इसके पश्चात 28.10.2005 को हमारे मुख्य मंत्री जी की मीटिंग थी, उनकी चैयरमेनशिप में और उसमें यह डिस्कसन किया गया था कि हमें क्या करना चाहिये तो जब पानी है ही नहीं, पंजाब अपनी ट्रीट को ऑनर नहीं कर रहा है तो आगे कैनाल का सिविल वर्क्स करना अनुचित है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न प्रतिवेदन के साथ

संलग्न है। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्तमान में उसका नाम चैंज होकर वर्तमान में नीति आयोग बन गया। पत्र दिनांक 11 मार्च, 1998 के अनुसार गडरा रोड नहर व उसके जुड़े कार्यों को वर्ष 2005-06 तक पूरा करना था तथा उसके लिए पूरी राशि 486.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी। सरकार ने इस कार्य को समय रहते पूरा क्यों नहीं किया और 497 में पास हुआ, 374 करोड़ रुपये खर्च हुए। 63.34 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। राशि शेष है जिसको खर्च करने का विचार रखती है तथा कोई नयी राशि का प्रावधान करने का भी विचार रखती है कि नहीं रखती सरकार?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मैंने इश्यु रेज किया है कि इतना सैंक्शंड है उस कमीशन ने सैंक्शन किया था जब वो ट्रीटी ही रद्द कर दी पंजाब ने पानी है ही नहीं तो फिर निर्माण करके क्या करेंगे? यह मैंने आपको जवाब दे दिया था तो पानी है ही नहीं, दूसरे स्टेट ने उल्लंघन किया उस ट्रीटी का, हम सुप्रीम कोर्ट में गये हैं तो आगे बनाना, निर्माण करना, बजट जो अलोकेटेड उसका कोई औचित्य नहीं है। पानी ही नहीं है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): पानी भी है, रिनोवेशन हुआ नहीं है। वर्तमान में 2005 परियोजना सिंचित को सीमित करने के क्या कारण थे? किस नहर का कितना सिंचित क्षेत्र घटाया गया? किस नहर का सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया? सिंचित क्षेत्र के घटने से जो कार्य नहीं करवाये गये हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि का उपयोग कहां किया जाना उचित है और इन्दिरा गांधी जी, दादी जी, यह सब नहीं, मेरे को डाइरेक्ट इसका जवाब चाहिये, साहब। दादी जी की बात नहीं करनी, इन्दिरा गांधी जी की बात नहीं करनी, इसका थोड़ा जवाब दे दें, साहब।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो पूछा था प्रश्नकर्ता ने उन्होंने इर्रिगेशन के बारे में बात की और मैंने जवाब भी दे दिया कि 13,116 हैक्टेयर पिछले पांच साल में इर्रिगेट किया गया तो जवाब तो मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

**माण्डलगढ़ में भवनविहीन आगंनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण**

205. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में तथा कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? क्या सरकार भवनविहिन आंगनबाडियों के भवन बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अन्तर्गत दो परियोजनाओं माण्डलगढ़ एवं कोटडी के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | कुल स्वीकृत आँगन-बाड़ी केन्द्र | कुल संचालित आँगन-बाड़ी केन्द्र | विभागीय भवनों में संचालित आँगन-बाड़ी केन्द्र | किराये के भवनों में संचालित आँगन-बाड़ी केन्द्र | विद्यालय में संचालित आँगन-बाड़ी केन्द्र | अन्य भवनों में संचालित आँगन-बाड़ी केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | माण्डलगढ़ | 293 | 292 | 201 | 23 | 68 | 00 |
| 2. | कोटडी | 80 | 80 | 53 | 01 | 24 | 02 |
| | कुल योग | 373 | 372 | 254 | 24 | 92 | 02 |

विभागीय भवन के अलावा अन्यत्र संचालित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आंवटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये करवाया जाता है।

किराये में संचालित 24 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4 आंगनबाड़ी केन्द्रों क्रमशः पीपली का डेरा (जलीन्द्री), धाबाई की झोंपडिया (बरून्दनी), सारण का खेडा (महुआ), फूलजी की खेडी (श्यामगढ) के लिये भूमि आंवटन हो चुका है। इन केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): मंत्री जी, जवाब आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनके भवन निर्माण की क्या नीति है? दूसरा प्रश्न है, माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु आप बनाने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक साथ दो प्रश्न पूछ लिये हैं तो मैं उनका एक साथ ही उत्तर दे देती हूं, समय भी कम है।

श्री अध्यक्ष: एक साथ दे दें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य ने पूछा भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्या विचार है? माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 24 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं जिनमें चार आंगनबाड़ी केन्द्र जिनमें भूमि आवंटन हो चुका है के भवननिर्माण हेतु प्रस्ताव जिला परिषद, भीलवाड़ा के अनटाइड फंड से राशि स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। जिला परिषद से राशि की स्वीकृति के पश्चात भवन निर्माण करवाया जायेगा। शेष बीस आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन करवाने हेतु

प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि आवंटन किये जाने के उपरान्त बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): दूसरा प्रश्न था न, भवन निर्माण हेतु क्या विचार है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवनों का निर्माण नरेगा योजना के अन्तर्गत कन्वर्जस के माध्यम से करवाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये की राशि निर्धारित है जिसमें से 2 लाख रुपये विभाग द्वारा, 8 लाख रुपये नरेगा कन्वर्जन से तथा 2 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग या जिला परिषद द्वारा अन्य किसी अनटाइड फंड से लिये जाते हैं। प्राथमिकता से क्रमशः किराये के भवन, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अन्त में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाया जाता है।

**Kas/rtm/27.02.2025/12.00/1g**

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर एवं डीग जिले को यमुना जल समझौता अनुसार पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से श्रमिकों की मृत्यु उपरान्त आश्रितों को एफ.डी. की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. डॉ ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा में दादी शब्द को असंसदीय होने का आरोप लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा में दादी शब्द से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड-पे नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

6. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से डूँगरपुर जिले में संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री यूनुस खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विद्युत कार्यों में संवेदकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री उमेश मीणा (23), श्री यूनुस खान(121) एवं श्री रविन्द्र सिंह भाटी (126) को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

**नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं**

1. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा में बाघों की शिफ्टिंग के संबंध में।

2. श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत के संबंध में।

3. श्री लालाराम बैरवा, सदस्य की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय शाहपुरा के नवीन भवन निर्माण के संबंध में।

4. श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अंता में किसानों की पत्रावलियां गायब होने के संबंध में।

5. श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुँचने के संबंध में।

6. श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन में इन्द्रगढ़ को पंचायत समिति बनाये जाने के संबंध में।

7. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन खोले जाने के संबंध में।

8. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर में अतिक्रमण बताकर नियमानुसार निर्मित भवनों को तोड़े जाने के संबंध में।

9. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की पेयजल समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

10.श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में बाईपास के निर्माण के संबंध में।

11.श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर में स्वीकृत उप जिला चिकित्सालय के भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के संबंध में।

12. श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में।

13. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर में सुपर

स्पेशियलिटीज की सेवाएं प्रारम्भ करने के संबंध में।

14. श्री नाना लाल निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट में 132 केवी जी.एस.एस. निर्माण के संबंध में।

15. श्री श्रीचंद कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पॉच सड़कों को मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

**पर्ची**

आज दिनांक 27/02/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | माननीय सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 1. | श्री डूंगरराम गेदर | सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में। |
| 2. | श्री गुरवीर सिंह | विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तरके कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति पर निगरानी बाबत। |
| 3. | डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | राजस्थान में सोलर प्लांट लगने वाले स्थानों पर खेजडी कटाई को रोकने बाबत। |
| 4. | श्री अर्जुन लाल | सदन में दादी शब्द पर चल रहे गतिरोध से जनहित के मुद्दो पर चर्चा हेतु सदन को पुनः समाधान निकालने की आवश्यकता पर चर्चा। |

श्री उमेश मीणा (अनुपस्थित)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): साहब, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देते समय आप 295 के बारे में बोलना भूल गये। व्यवस्था देते समय 295 पढ़ने की अनुमति होगी, यह बोलना शायद आप भूल गये, वापस बोल दें।

श्री अध्यक्ष: 295 सबको पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): एक व्यवस्था का प्रश्न है। अर्जेंट है।

श्री अध्यक्ष: सब अर्जेंट है। मेरे को लिख कर भेजो, बैठिए।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

श्री उमेश मीणा (अनुपस्थित)।

श्री यूनुस खान।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। आप स्लिप भेज दो, क्या बोलना चाह रहे हो। आप लिख कर भेजा व्यवस्था का प्रश्न क्या है। आप विराजो, बिना अनुमति नहीं। आप लिख कर भेज दो, क्या बोलना चाह रहे हो।

**डीडवाना में पेयजल संकट**

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया माननीय वसुन्धरा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारा अखंडित नागौर, जिसमें 10 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें उन्होंने लगभग 4000 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर के पीने के पानी के लिये दिये, उसके लिये तो मैं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को और माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन बीच-बीच में जो पांच साल का कालखण्ड आता है, उसमें यह प्रोजेक्ट रुक जाता है। 761 करोड़ रुपये का फर्स्ट फेज, जो वसुन्धरा जी ने 2003-08 में शुरू किया और सेकण्ड टर्म में 2013-18 में लगभग 2938 करोड़ रुपये का सेकण्ड फेज शुरू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हमारे साथ भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण डीडवाना और हमारा बाकी शेष जिला भी पानी नहीं पी पा रहा है। हमको फर्स्ट फेज में 100 एमएलडी पानी दिया गया और सेकण्ड फेज में 200 एमएलडी, टोटल 300 एमएलडी पानी मिलना चाहिये था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो अखण्ड नागौर जिला है, उसका लगभग 125 एमएलडी पानी हमें कम मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिये कि पीने का पानी पहले मिले और सिंचाई का बाद में मिले। हमारा आपसे आग्रह है कि गर्मियां आ रही हैं और पानी नहीं मिल रहा है। जहां तक डीडवाना का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमे डीडवाना में 40 एमएलडी पानी मिलना चाहिये, जिसमें 32 एमएलडी हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है और 8 एमएलडी शहरी क्षेत्र का है। उसमें से लगभग हमें 27 एमएलडी पानी मिल रहा है और 13 एमएलडी पानी नहीं मिलने के कारण लगभग 108-120 घंटे के अंतराल से पानी आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक बहुत गंभीर मामला है, हमारे डीडवाना और मोलासर के लिये जेजेएम प्रोजेक्ट में लगभग 98 करोड़ की राशि की एक निविदा पड़ी है, जिसमें लगभग 34 गांव और 240 ढाणियां कवर होनी थीं। पिछले डेढ़ साल से वह टेंडर पूरा नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है, माननीय भजन लाल जी का सपना है कि हर घर में नल जाये। मैं आपके माध्यम से पीएचईडी मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उस टेंडर में जो बाधाएं हैं, उनको दूरा करा कर हमारी 240 ढाणियां और 34 गांवों में पीने का पानी दें और जो हमारा हिस्सा है 40 एमएलडी, वह पूरा दिलवाएं, यही आपके माध्यम से आग्रह है, जिससे जनता को आने वाली गर्मी में राहत मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी (अनुपस्थित)।

प्रक्रिया के नियम 295, श्री संदीप शर्मा।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में बाघों की शिफ्टिंग

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व में बाघों की शिफ्टिंग हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा का मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र 80 के दशक में बाघों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन विभिन्न कारणों से यहां पर बाघ समाप्त हो गये। चम्बल नदी के साथ ही जैव विविधता से जलवायु और वानिकी परिस्थिति बाघों के अनुकूल होने के चलते यहां पर बाघ नहीं होने के बावजूद भी बाघ रिजर्व बनाया गया।

इस रिजर्व में 2020 में बाघों की जोड़ियां बनाकर लायी गईं, किंतु कांग्रेस सरकार ने न तो इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और न ही इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा, नतीजा यह हुआ कि 3 वर्षों में ही 3 बाघों की मृत्यु हो गई। 760 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में वर्तमान में मात्र 3 बाघ ही बचे हैं।

गत वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मुकुंदरा में 1 बाघ और 2 बाघिन को लाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इन बाघों की शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। इसी प्रकार इंटरस्टेट बाघ कॉरीडोर के लिए भी बाघों के. आदान प्रदान योजना में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के टाईगर रिजर्व से मुकुंदरा में बाघ लाने की योजना को भी बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। वहीं दोनों राज्य सरकारों ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुकुंदरा में बाघ आने से न केवल यहां के प्राकृतिक अनुकूल वातावरण का लाभबाघों को मिलेगा अपितु कोटा के वन्य पर्यटन में भी इजाफा होगा।

इसलिए सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व में प्रस्तावित बाघों की शिफ्टिंग का कार्य अविलम्ब पूरा करवाया जाये। धन्यवाद।

**msk/rtm/27.02.25/1210/1h**

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

## माण्डलगढ़ की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मांडलगढ विधान सभा क्षेत्र के भांड का खेड़ा में मेनाली नदी की पुलिया व अन्य नदियों की निम्न स्तरीय पुलियाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही क्षतिग्रस्त हैं। व्यस्त मार्ग होने से आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र अत्यधिक बारिश व नदीय क्षेत्र होने से बारिश के दिनों में पुलिया नीचे होने से मार्ग अवरूद्ध हो जाता है व पुलिया पार करते समय काफ़ी

दुर्घटनाएं व जनहानि हुई हैं। क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की दशा को देखते हुए इनका निर्माण किया जाना था, जो नहीं किया। क्षेत्र के आमजन की मांग को देखते हुए निम्न उच्च स्तरीय पुलों व सड़कों का निर्माण करवाया जाकर राहत प्रदान करावें।

1. त्रिवेणी-जोजवा सड़क ग्राम भांड़ का खेडा मेनाली नदी पर उच्च स्तरीय पुल।
2. बिगोद-खटवाड़ा सड़क बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल।
3. सांडलगढ-गुरला सड़क बडलियास बेड़च नदी पर उच्च स्तरीय पुल।
4. बिजौलियां-मांगटला सड़क का चौडाईकरण व सुदृढ़ीकरण 25 किमी.।
5. बड़लियास से आकोला सड़क का चौडाईकरण व सुदृढीकरण 6 किमी.।
6. गुल्ला का खेड़ा मोड़ से गोरलियां बाईपास सड़क 3 किमी.।
8. हरिसिंहजी का खेड़ा से थलकलां सड़क 5 किमी.।
9. जोजवा से लोडियाणा सड़क 2 किमी.।
10. अमरतिया से पदमपुरा सड़क 3 किमी.।

अतः सरकार से निवेदन है कि लोकहित को देखते हुए निम्न उच्च स्तरीय पुलों व सडकों का निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवायी जाये।

**(समय: बजे)**

**(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)**

श्री सभापतिः श्री लालाराम बैरवा। (अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल।

**अंता में किसानों की गायब पत्रावलियां**

श्री कंवरलाल (अंता): राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत अंता विधान सभा के किसानों की जमीन गैर खातेदारी में दर्ज होने से, खातेदारी में दर्ज करने की पत्रावलियां गायब होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र अंता कृषक प्रधान है, जिसकी 75 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 965 किसानों की भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है, जिनकी जमीनों को खातेदारी में किया जाना था, जिनकी पत्रावलियां निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय बारां में थीं। गत सरकार के समय उन पत्रावलियों को ही गायब कर दिया गया, जिसके कारण उक्त किसानों की भूमि का खातेदारी भूमि में इन्द्राज नहीं हो सका है।

अतः मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से अनुरोध व विनम्र आग्रह है कि उक्त किसानों की गायब हुई पत्रावलियों का निस्तारण कर किसानों को राहत प्रदान करें। साथ ही, पत्रावलियां गायब होने में किस-किस अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही रही, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री सभापतिः श्री लालाराम बैरवा।

**शाहपुरा के राजकीय जिला चिकित्सालय का नवीन भवन निर्माण**

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा के नवीन भवन

निर्माण का कार्य आज तक पूर्ण नहीं होकर, लम्बे समय से कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा-181 अंतर्गत राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा के नवीन भवन निर्माण हेतु 3.1 करोड़ की राशि की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु 26.33 करोड़ ही प्राप्त होकर शाहपुरा में नजुल सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त राशि 458 लाख आज तक चिकित्सालय के निर्माण हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इस कार्य हेतु सिविल कार्य के कार्यादेश 09/04/2022 को होकर निर्माण कार्य 08/04/2024 को पूर्ण होना था, जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं होकर कार्य लंबित है, जिसके कारण शाहपुरा क्षेत्र की जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी थीं, वे नहीं हो रही हैं और जनता को अपने इलाज के लिए आज भी परेशान होकर बाहर दूर दराज जाना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र शेष राशि जिला अस्पताल के लिए उपलब्ध करायें, जिससे निर्माण कार्य पूर्ण होकर मेरे शाहपुरा की देवतुल्य जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

श्री सभापतिः श्री छोटूसिंह।

**जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचना**

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): नियम 295 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के अंतिम छोर जैसलमेर जिले को इस बार बारी-बंदी का पर्याप्त पानी नहीं मिलने के संबंध में निवेदन है कि जैसलमेर का नहरी क्षेत्र इस बार खेती के लिए पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस बार पानी की कमी के कारण इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंतिम छोर के किसानों को खेती के लिए आधी बारी का भी पानी नहीं मिला। वह भी, एक भी बारी समय पर नहीं मिली। वैसे भी हमें हर बार कम पानी ही मिलता है। थोड़ा बहुत भगवान मेहरबान हो जाता है तो काम चल जाता है। इस बार न तो मावठ पड़ी और न ही एक बार भी बारिश हुई। रेगुलेशन सिस्टम बहुत कमजोर होने और अन्य प्रान्तों से तालमेल के अभाव में कम पानी का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। हमें हर बार गोल बारी मिलती है, गोल बारी यानि पानी आया तो देंगे। इस बार जैसलमेर जिले को तीन बारियां पानी ही मिला। वह भी जब जरूरत हुई तब नहीं मिला। बारी बंदी पीटने और भगवान के नाराज हो जाने के कारण फसलों की स्थिति अत्यंत ही कमजोर है। पिछली 2 अक्तूबर को हुई जल परामर्श समिति की बैठक में चार बारियों का तय होने के बावजूद वे भी नहीं दी गयीं, जबकि प्रथम चरण में ही बीकानेर जिले में पांच-पांच बारियां दी गयीं। हमारे यहां कई नहरें, जैसे एटीडी, टीएनडी, सादा सहित अधिकांश नहरों में तीन-तीन बारियां ही मिलीं। मैनेजमेंट की कमी के कारण कहीं बीच की नहरों में सेविंग पानी, जो कि असमय देकर चार बारियां गिना दी गयीं। जिले के साथ ऐसा अन्याय क्यों? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी नहीं मिलने से किसान कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अब फसलें पकने की ओर हैं और एक बार यदि सभी किसानों को बारीबंदी का पानी मिल जाए तो किसान थोड़ी बहुत फसल प्राप्त कर अपनी

लगायी हुई पूंजी प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरंत ही जिले में अंतिम छोर में बैठे किसानों को बारीबंदी का पानी उपलब्ध करवाया जाये और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाये।

**mdp/rtm/27.02.2025/12:20/1j**

श्री सभापतिः श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (अनुपस्थित), श्री हमीर सिंह भायल।

**सिणधरी (सिवाना) में 33 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन**

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, सिणधरी उप खंड मुख्यालय आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व विद्युत से जुड़ गया था तभी से आगे गाँवों में विद्युत तंत्र में विस्तार के तहत लाइनों को लंबा करते रहे, लेकिन तंत्र को सुधार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हो सका। सिणधरी उप खंड में कृषि क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र दोनों ही में विद्युत कनेक्शन लगातार बढे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 20 हजार से अधिक और कृषि उपभोक्ताओं की संख्या भी 2000 से अधिक है। केंद्र की दीन- दयाल घरेलू विद्युत योजना से इस क्षेत्र में अकेले ही 19 हजार से अधिक घरों को रोशन किया है, लेकिन कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत तंत्र व्यवस्था एक ही है, जिससे सिणधरी मुख्यालय की विद्युत व्यवस्था भी प्रभवित होती है। ग्रामीण क्षेत्र की लाइन फाल्ट होने पर सिणधरी कस्बा भी बंद रहता है। 40 साल पहले की लाइनों को अब बदला जाना आवश्यक है। कस्बे की विद्युत लाइनों के तार रोज टूटते हैं। आबादी क्षेत्र में कोई अनहोनी घटना नहीं हो जावे, उससे पूर्व ही लाइनों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र और कस्बा के क्षेत्र को अलग करने के लिए सिणधरी मुख्यालय पर एक नया 33 के.वी. का सब- स्टेशन बनाकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। सिणधरी कस्बा पूर्व में एक ही ग्राम पंचायत का क्षेत्र था, जो आज तीन ग्राम पंचायतों में विभक्त है। जनसंख्या और आबादी के घनत्व को देखते हुए बिजली तंत्र में सुधार किया जाना जनहित में होगा।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उप खंड मुख्यालय सिणधरी पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक नया 33 के.वी. सब-स्टेशन विद्युत विभाग के निर्माण की स्वीकृति जारी करवाकर आम जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अनिल कुमार शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार। (अनुपस्थित)

श्री समरजीत सिंह। (अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्र बुडानियां। (अनुपस्थित)

श्री कैलाश चन्द्र मीणा।

**गढ़ी के चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्थाएं**

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में ब्लॉक गढी की CHC/PHC में पनप रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के संबंध में बोलने का मौका देने पर बहुत-बहुत धन्यवाद।

विषयान्तर्गत चिकित्सा विभाग के अंतर्गत ब्लॉक गढ़ी के अंतर्गत उप जिला चिकित्सालय परतापुर, CHC पालादो, तलवाडा, गढी, अरधुना, जोलान सरेडी बडी संचालित हैं एवं PHC लाहोरीया, भीमपुर, खोड़न मोर, बोरी आंजना, पांचवडा, कोटडा, आडेवाडा, पनासी छोटी, गोपीनाथ का गडा, वजवाना, कोहाला, चिडियावासा, धलकीया आदि क्षेत्र में संचालित हैं, जिनमें ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी CHC, PHC प्रभारियों द्वारा साफ-सफाई मेंटेनेंस रख-रखाव की राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ रहा है। विगत वर्ष 2022, 2023, 2024 के तहत उक्त राशि का टेंडर चहेतों को दिया गया था। मजदूर नहीं लगाकर फर्जी राशि उठाई गई। वर्ष 2024-25 में बिना टेंडर के सभी स्थानों पर फर्जी सफाई कर्मियों के नाम लिख कर राशि उठाई जा रही है एवं उप-जिला चिकित्सालय की दुर्दशा है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। समस्त CHC, PHC में से लेट-बाथ एवं वार्डों से गंदगी से मरीज परेशान हो रहे हैं। चिकित्सा ब्लॉक अधिकारी एवं अन्य इंचार्ज द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार एवं विभाग से इस ओर ध्यान आकर्षित करने का निवेदन है।

श्री सभापति: डा.सुभाष गर्ग।

**आर.बी.एम. अस्पताल, भरतपुर में सुपर-स्पेशियलिटीज सेवाएं**

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन आर.बी.एम. अस्पताल में विगत कई बजट घोषणाओं में सुपर स्पेशियलिटीज की 10 सेवायें शुरू करने की घोषणा की गई थी, किन्तु उक्त समस्त सेवाओं को आज दिनांक तक शुरू कर धरातल पर नहीं उतारा गया है, केवल पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। अधिकांश पद रिक्त हैं। आर.बी.एम. अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या प्रतिदिन 4000 के लगभग है। उक्त अस्पताल में डीग, कामां, नदबई, बयाना एवं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण-जन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने प्रतिदिन आते हैं।

उक्त अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिये अभी तक जिस स्तर के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है। आई.सी.यू. में भी आई.सी.यू. जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तथा इमरजेन्सी में भी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। कम गंभीर रोगियों को भी भरतपुर से जयपुर या अन्यत्र स्थानों पर रैफर कर दिया जाता है।

उल्लेखनीय यह है कि भरतपुर संभाग का यह सबसे बड़ा अस्पताल है, विस्तार प्रक्रिया के तहत भवन निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भवन निर्माण कार्य में टेंडर की शर्तों में दी गई समयावधि में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किया जाने पर भी सरकार द्वारा कोई

विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में की गई सुपर स्पेशियलिटीज सेवाओं को शीघ्रातिशीध्र शुरू कर मरीजों के साथ-साथ आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री नाना लाल निनामा। (अनुपस्थित)

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

**निम्बाहेड़ा की पांच सड़कों की मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नति**

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा-छोटी सादडी जो कि सीमेन्ट हब होने के कारण यहां पर वाहनों का परिवहन अत्यधिक मात्रा में होता है, ऐसे में यहां की पांच प्रमुख सड़कें जिन्हें मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नत करने की अति-आवश्यकता है।

1. यह सड़क मार्ग अम्बामाता से होकर वाया मरजीवी-केलूखेडा-बरखेड़ा-रम्भावली से एनएच-113 रम्भावली चौराहे तक कुल 49 किमी. लम्बाई की अंतर जिला सड़क है। जो चितौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिला एवं निम्बाहेडा एवं छोटीसादड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है।

2. यह सड़क मार्ग करजूमोड़ (एसएच 15) उदपुरा से वाया साठोला- देवकमाता चौराहा-धोलापानी से एनएच 113 तक कुल 35.8 किमी. लम्बाई की अन्तर जिला सड़क है। जो चितौड़गढ़ एवं, प्रतापगढ़ जिला एवं बड़ीसादड़ी एवं छोटीसादड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है।

3. यह सड़क मार्ग मांगरोल (एनएच 79) अरनिया जोशी-अरनोदा-मेवासा-उदपुरा-पालछा (एमडीआर 20) तक कुल 30.00 किमी. लम्बाई की सड़क है। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वूपर्ण वैकल्पिक मार्ग है।

4. यह सड़क मार्ग निम्बाहेड़ा से वाया करथाना-फाचर सोलकीं मायरा (एमडीआर 209) तक कुल 20.00 किमी. लम्बाई की सड़क है। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा तहसीलों को जोडने वाला कम दूरी का महत्वूपर्ण वैकल्पिक मार्ग है।

5. यह सड़क मार्ग एनएच 113 बाडी से बम्बोरी (एमडीआर 210) तक कुल 15.00 किमी. लम्बाई की सड़क है। निम्बाहेड़ा एवं छोटीसादड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वूपर्ण वैकल्पिक मार्ग है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त अति आवश्यक सडक मार्गों को मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर) में क्रमोन्नत करने का श्रम कर आमजन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद ।

**Ans/rtm 12.30 1k 27.02.2025**

श्री सभापतिः पर्ची।

**पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे**

श्री डूंगरराम गेदर। (अनुपस्थित)

श्री गुरवीर सिंह।

**ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी**

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की एक समस्या मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे ग्राम स्तर के जितने भी अधिकारी है विभिन्न विभागों में, चाहे वह पंचायती राज का सेक्रेटरी है, चाहे वह कृषि विभाग का ग्राम सेवक है, पटवारी गिरदावर है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ है, लाइन मैन हैं, ऐसे बहुत से अधिकारी-कर्मचारी हैं जिनकी उपस्थिति पंचायत हैडक्वाटर पर पूरे राजस्थान में लगती है। उनके कार्यालय निर्धारित है, सबको वहां उपस्थिति दर्ज कराना लाजमी है, परन्तु 90 परसेंट वहां उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं और उनकी निगरानी की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है।

आज टेक्नोलोजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का जमाना है, हमारी मोबाइल लोकेशन से दुनिया भर की एप्स यूज करके तरह-तरह के काम किये जा सकते हैं। मेरी सरकार से मांग है, सुझाव है कि राजस्थान की सरकार को भी कोई सॉफ्टवेयर डवलप करके कोई ना कोई ऐसा डेशबोर्ड बनाया जाए कि जब वह अधिकारी या कर्मचारी पंचायत स्तर पर हैडक्वाटर छोड़े तो नोटिफिकेशन आये और उससे जवाब मांगा जाए। उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई तरीका नहीं है, इसके ऊपर स्तर पर जाए तो किसी से भी जाकर पूछा जाए तो उनके पास एक ही बहाना है वी.सी. चल रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वी.सी. के लिए भी कोई डेट निर्धारित की जाए। आज मजदूर आदमी, किसान अपना काम-काज छोड़कर जब अधिकारियों-कर्मचारियों के चक्कर काटता है और वे वहां नहीं मिलते, वह पीछे तहसील हैडक्वाटर पर भागता है। दिन में 300-400 रूपये कमाना वाला आदमी उनके पीछे-पीछे भागता है, नरेगा का कर्मचारी उनके पीछे-पीछे भागता है। एक सिम्पल सी बात है मोबाइल डिवाइस की लोकेशन को देखकर उनकी उपस्थिति, उनके सम्बन्धित पंचायत हैडक्वाटर पर सुनिश्चित करे, मेरी सरकार से मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः यदि मंत्री महोदय बोलना चाहे तो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि वी.सी. वाले विषय को रिव्यू कर ले। किसी से भी जब भी बात करो, चाहे उसकी वी.सी. चल रही हो या नहीं चल रही हो, वह अधिकारी कहता है कि वीसी में हूं। सचिवालय से आज पीएचईडी सेक्रेटरी लेगा, कल पीडब्ल्यूडी लेगा, परसों होम लेगा, तो वे सारे अधिकारी इन्वाल्व हो जाते हैं। इसकी कोई ना कोई विधि तय करे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार से आग्रह है कि इसका रिव्यू करके शिड्यूल तय करवा दें।

श्री सभापतिः डॉ. श्री विश्वनाथ मेघवाल।

## सोलर प्लांट हेतु चिह्नित स्थानों पर खेजडी कटाई पर रोक

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के बहुत सारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, जिसके तहत मेरी विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला, बीकानेर में भी सोलर प्लांट लगाये जा रहे हैं। यह बात सही है कि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसकी और बढ़ोतरी होगी। प्लांट स्थापित करने के लिए हज़ारों बीघा ज़मीनों की आवश्यकता रहती है। इन ज़मीनों में हमारे पुराने खेजड़ी के वृक्ष लगे हुए हैं जो हमारे पूर्वजों ने बचाकर रखे हैं। खेजड़ी वृक्ष पवित्र वृक्ष है जो एक समाज विशेष, विश्नोई  समाज या धर्म से जुड़ा हुआ भी है। एक राज्य वृक्ष की श्रेणी में भी आता है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय बिना अनुमति के लगभग 50-60 हजार खेजड़ी के पेड़ों का काटा जाना, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पर्यावरण प्रेमियों द्वारा बताया गया, जिसके लिए पिछले वर्ष खेजड़ी बचाओ संघर्ष समिति एवं पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति संगठनों द्वारा करीब 60-70 दिन तक बीकानेर में धरना प्रदर्शन भी किया गया, प्रशासन से कई बार वार्ता भी हुई। उक्त समस्या को माननीय मुख्य मंत्री  भजनलाल जी के समक्ष भी रखा गया।

सभापति महोदय, जोधपुर में खेजड़ली ग्राम में सन् 1730 में खेजड़ी बचाने के लिए अमृता देवी एवं 363 स्त्री-पुरुषों द्वारा बलिदान भी दिया गया था। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार सोलर प्लांट के लिए भूमि का चयन ऐसे स्थान पर करे जहां बंजर जमीन हो, वृक्ष बहुत कम हो, खेजड़ी के वृक्ष भी बहुत कम हो। 70 साल से खेजडी कटने पर पुराने नियम है उसमें 100 रुपये का जुर्माना है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जुर्माना बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जाए और जो ऐसी घटना करता है उसके कठोर कारावास का प्रावधान भी किया जाए। एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार बनाये जिसमें कड़े नियम बनाकर खेजड़ी कटने से रोका जाए। वर्तमान में सोलर प्लांट स्थापित करने में, खेजड़ी वृक्षों की ट्रिमिंग या छंगाई कर, खेजड़ी को काटने से रोककर उसको बचाया जाए।

सभापति महोदय, पर्यावरण को बचाने के लिए सोलर कम्पनियों को पाबंद कर उसकी एवज में पेड़ लगाने व खेजड़ी लगाने का नियम भी बनाया जाए। मैं इस मौक़े पर यह बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत ही अच्छा विचार व सोच है। मैंने पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया था, जिसमें सोलर कम्पनियों द्वारा एससी, एसटी की जमीन लीज पर दिये जाने का, कन्वर्जन करने का नियम था, उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिथिलता प्रदान कर हमारे क्षेत्र व पूरे राजस्थान के एससी, एसटी के भाईयों को बड़ी सौगात दी। अपनी जमीन को लीज पर देकर, जो नियम है उसको सरल बनाया। इस मौक़े पर मैं यह कहना चाहूंगा कि खेजड़ी बचाने के लिए एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर पर्यावरण प्रेमियों की भावना का सम्मान किया जाए, यही मेरा कहना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल। पर्ची, श्री अर्जुन लाल जी। ...(व्यवधान)... जब आपको मालूम है कि आपकी पर्ची है, तो आपको सदन के अन्दर बैठना चाहिए।

**सदन में जारी गतिरोध का समाधान**

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): साहब, माफी चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माफी भी चाहता हूं। दिनांक 21.02.2025 को सदन में प्रश्न काल के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रश्न के उत्तर में एक योजना का नाम गिना रहे थे। योजना के नाम में इंदिरा गांधी महिला कामकाजी हॉस्टल जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी लेकिन गत सरकार ने इस योजना पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया, ना बजट में कोई प्रावधान रखा। योजना के नाम के आगे, जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो फ्लो में 'दादी' शब्द बोल दिया गया। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, देश के पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम के आगे 'चाचा' लगता है, मोहन चंद कर्मचंद गांधी के आगे 'बापू', 'महात्मा' लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे 'सरदार' लगता है, पूर्व उप प्रधान मंत्री थे देवीलाल उनके नाम के आगे 'ताऊ' लगता है, राष्ट्रपति रही प्रतिभा जी पाटिल के नाम के आगे 'ताई' लगता है, लोकसभा पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थीं उनके नाम के आगे भी 'ताई' लगता है, तो उनके 'उर्फ' नाम से संबोधित करने पर, 'बापू', 'चाचा', 'सरदार', 'ताऊ', 'ताई', 'दादी' ये सम्मानजनक शब्द हैं, असंसदीय नहीं है।

मैं 'दादी' पर कहना चाहूंगा।

प्रेम, वात्सल्य, संस्कार, अनुभव, भाषा की खान है दादी।

सारी मुश्किलों के फलों का आधार है दादी।

फलते-फूलते परिवार की जुबान है दादी।

फिर कैसे किसी का अपमान है दादी।

इंदिरा गांधी जी का नाम बोलते वक्त फ्लो में 'दादी' शब्द आ गया जिससे विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने एतराज किया।

**VPS-RTM-27.02.2024-12.40-1I**

उन्होंने कहा कि यदि 'दादी' शब्द विधान सभा में असंसदीय शब्द हो तो इसको एक्सपंज करने का भी हमारे माननीय मंत्रीजी ने उस समय निवेदन कर दिया था, लेकिन विपक्ष के पास हमारे जो मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा ने यह इस बार जो बजट रखा था, यह बजट समावेशी, सर्व कल्याणकारी बजट था और विपक्ष के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था, इसमें कोई खोट-कमी नहीं निकाल सकता था, इसलिए उन्होंने इसको स्थगन करने के लिए, जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आसन के ऊपर जाकर अपने हाथों से इशारा

करते हुए, लहराते हुए, जाकर ये डायस पर चढ़ गये और बाद में माननीय अध्यक्षजी ने इस सदन को तीन-चार बार स्थगित किया। पहली बार स्थगन करने के बाद यहां पर सदन के अन्दर फ्लोर में सभी माननीय सदस्य यह देख रहे थे कि हमारे ...(व्यवधान)...

श्री यूनुस खान (डीडवाना): आप हाउस इन नियमों से चलाओगे या कैसे चलाओगे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आप बैठिये। आप बैठिये। आपका नम्बर आये तब बोलना। लेकिन, विपक्ष द्वारा मंत्री महोदय के माफी मांगने पर, वे एक बहाना बनाकर अड़ गये और इस सदन में आज पांच दिन से निरंतर एक गतिरोध बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जो अपनी एक महती भूमिका रखता है, वह भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ आह्वान करके, आसन के प्रति अपशब्द बोले, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, क्षमा करने योग्य नहीं है, यह पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है। बाद में मीडिया में जाकर बाहर यह कहते हैं कि अध्यक्षजी ने एक प्लान के तहत हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाकर इन्होंने ऐसा छपवा दिया है, लेकिन यह हकीकत बात है कि वे सबके सामने यहां पर बोल रहे थे। अध्यक्षजी और जो राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय जो प्रिंट मीडिया है, अख़बार हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने आक्षेप लगाया तो वह भी एक ऐसा कुकृत्य है, उनके लिए क्षमा योग्य नहीं है। यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की ओछी मानसिकता दर्शाती है। यह कृत्य भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। हमारा दल इसकी निंदा करता है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन को चलाने में जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी की उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है और यह सदन मर्यादाओं, नियमों एवं परंपराओं से चलता है। मैं सदन के माध्यम से आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई न कोई योजना बनाकर जल्दी से इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। आज जो सत्ता पक्ष है, वह बड़ा भाई है और जो इन्होंने कुकृत्य किया है उसके ऊपर भी कहते हैं कि-

क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात।
कह रहीम का घट्यौ, विष्णु के भृगु मारी जब लात।।
भली-भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराय।
कहे कबीर शीतल भया, क्षमा जो आग बुझाये।।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सदन के सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस गतिरोध को खतम करें और विधान सभा जो पहले चल रही थी, वैसे ही शुरू करें। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापतिः नियम समिति, 2024-25, समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः हां। मंत्री महोदय पर्ची के जवाब में अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, वह निश्चित रूप से एक गम्भीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गये और वेल में विरोध प्रदर्शन करना सदन की एक परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है लेकिन आसन पर चढ़कर, आसन के प्रति जिस तरह का यह व्यवहार देखने को मिला और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्षजी द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये और जब वे सीटों पर नहीं गये, आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया और अध्यक्षजी को कुर्सी छोड़कर साइड में आना पडा और हाउस को एडजोर्न करना पडा। हाउस एडजोर्न करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनीं और छह सदस्यों को निलंबित करना पड़ा।

सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे सम्पर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है, आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की ये घोषणाएं की हैं, आपको कुछ एड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है तो सदन में सुचारु रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करे। एक आगे बढ़ी बात माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में, दोनों दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और उसमें यह तय किया गया कि आसन का अपमान करने वाले माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, अब वे निलंबित हैं, उनको सदन के आसन के प्रति किये गये अपमान की सदन में खड़े होकर खेद व्यक्त करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी। हामी भरने के बाद सदन की कार्यवाही चूंकि, समय निश्चित था, माननीय अध्यक्षजी आसन पर आ गये, सुचारु रूप से चलने लगी। व्यवस्थाएं तय होती, इस बीच में ही माननीय सदस्य और उनके साथी सदन में आकर हल्ला करने लगे और उस हो-हल्ला के कारण पुनः सदन को स्थगित करना पडा, लेकिन उस बीच में जो हुआ, इस सदन को फिर शर्मसार करने की बात हुई। जिस तरह के स्तर-हीन शब्दों का उपयोग आसन के प्रति और माननीय अध्यक्षजी के प्रति किया गया, इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में निश्चित रूप से इस इतिहास को कलंकित करने वाला है। हो सकता है कि हम से वरिष्ठ लोग यहां आये हों, उन्होंने सदन की परंपराओं के हवाले दिये हों, लेकिन इस तरह का व्यवहार और जो अखबारों में भी छपा और कल वे ही निलंबित सदस्य बाहर जब प्रेस कांफ्रेंस करते हैं तो अध्यक्षजी पर और एक अख़बार पर आपस में बातचीत करने का जो आरोप लगाते हैं, इससे अख़बार की साख पर भी एक तरह से प्रश्न-चिन्ह उठा है। अख़बार को भी यह स्पष्ट करना चाहिए और जो भाषा यहां पर बोली गयी, इस सदन के कई सम्मानित सदस्य उसके साक्षी हैं। उन्होंने प्रतिरोध भी किया कि इस

तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सदन का अध्यक्ष सबका सम्माननीय होता है और सदन के अध्यक्ष की गरिमा और सदन की परंपराओं की गरिमा रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन विपक्ष के साथियों को पता नहीं क्या हो गया? जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहते हैं और उसी बात को लेकर जब पुनः गतिरोध तोड़ने की बात हुई तो कक्ष के अन्दर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हां, मेरे से गलती हो गयी, दुबारा अभी मैंने स्तर-हीन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, उसकी मैं माफी मांग लूंगा और पुनः तय हुआ माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेन्द्रजी पारीक साहब जो सीकर से आते हैं उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सदन की गरिमा बनाने के लिए आप चूंकि, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी हैसियत के मुताबिक आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए।

यह सारा तय होने के बाद वे यहां आये और यहां आने के बाद फिर मुकर गये और मुकर कर उसको घुमाकर बात को कहना चाहा और उनकी घुमाकर बात कहने के बाद कांग्रेस के वे साथी जो कई-कई बार से इस सदन में आ रहे हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष से, जो उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आकर वे बहिर्गमन इसलिए कर गये कि राजस्थान की सरकार जो अच्छे काम कर रही है, वह उनके कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जिस अख़बार में वह अमर्यादित शब्द छपे हैं और आसन की ओर इंगित करने के लिए इन्होंने प्रेस में कहा है, वह स्पष्टीकरण भी होना चाहिए और जो माननीय सदस्यों ने अपने कानों से सुना है कि यहां वेल में आकर भले ही सदन की कार्यवाही में वे शब्द नहीं हों, क्योंकि सदन स्थगित हुआ पड़ा था।

**ssy/rtm/**27.02.2025**/**1**2.5**0**/1m**

तो उन माननीय सदस्यों से भी मेरा आग्रह है कि इस सदन में निश्चित रूप से मैं उन शब्दों की निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे कृत्य के लिए जिन माननीय सदस्यों ने वह कृत्य किया है, उसके लिए माफी सदन में ही मंगवानी चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, जब बजट यहां पर पढ़ा गया और उस बजट की सराहना पूरा राजस्थान कर रहा था, डोटासरा जी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य 2 दिन तक हाउस में नहीं थे और जिस दिन हाउस में वे आये, सबको महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ आज होगी और वह हुई भी है।

मैं अविनाश जी की भी थोड़ी गलती मानता हूं। गलती यह मानता हूं कि इनको दादी मां की जगह ग्रांड मदर कहते तो यह दिक्कत नहीं आती। आपने दादी मां बोल दिया। ये इटली की परंपरा के लोग हैं। अगर आप कहते ना कि आपकी ग्रांड मदर के नाम पर आपने योजना बनाई तो कोई दिक्कत ही नहीं होती।

सभापति महोदय, लेकिन जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी की अवमानना की गई, जिस तरह वेल में आकर और डायस पर चढ़कर अध्यक्ष जी के लिए गलत शब्द यूज किये गये,

जिस तरह हाउस एडजोर्न होने के बाद, क्योंकि मैं तो यहां मौजूद था, कई सदस्य और मौजूद थे, जिस तरह यहां पर गंदी-गंदी भाषा का उपयोग किया गया, मैं गवाह हूं ना इस बात का। सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि मेरा जूता भी माफी नहीं मांगेगा। कौन होता है यह अध्यक्ष? यह तो मुख्य मंत्री का फोन नहीं, अंट-शंट, जो भी बातें करनी थी उन्होंने कहीं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सदन में, चाहे सदन चल रहा हो, चाहे सदन नहीं चल रहा हो, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी को, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम जी को, हमारे सचेतक महोदय जोगेश्वर जी गर्ग साहब को, हम सबने इस बात का प्रयास किया कि किसी भी तरह से इसका रास्ता निकल जाये। सभापति महोदय, लेकिन ये रास्ता निकालना ही नहीं चाहते थे।

आज मुझे पता है कि जितने एमएलए यहां बैठे हैं, विधायक गण बैठे हैं, आप पूछो इनसे, इनके रिश्तेदार हिन्दुस्तान में जहां भी रहते होंगे, फोन कर-करके पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया राजस्थान में कि दादी मां के नाम पर यह भड़क गये। ताऊ के नाम पर भड़क जाते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से भड़क जाते हैं। मामा के नाम पर भड़क जाते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इटली से संचालित पार्टी है और इनको ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का निर्णय लें कि आने वाले समय में सदन में, अध्यक्ष जी जितनी छूट दे सकते थे, अध्यक्ष जी ने जितनी दया दिखाई, अध्यक्ष जी ने जितना प्रयास किया, अध्यक्ष जी ने, यह सही कह रहे थे बेढ़म साहब अभी कि एक निष्कासित सदस्य को सदन में बुलाकर उससे वक्तव्य दिलाना यह भी हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक किसी ने नहीं दिलाया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वह हमारी गलती थी। अगर वह अन्दर आकर माफी मांगते, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट यहां आकर बदल दिया।

सभापति महोदय, सदन में बैठकर हम सबको इनकी भर्त्सना करनी चाहिए। यह ठीक है कि डैडलॉक तोड़ना चाहिए। प्रजातंत्र इसी को कहता है कि कितनी भी बात हो जाये लेकिन डैडलॉक टूटना चाहिए। सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को चलाते हैं, लेकिन विपक्ष की जिस तरह की भूमिका है और यह सारी भूमिका बनी है राजस्थान में पिछले 2 बजट जो भजन लाल जी की सरकार ने दिये हैं, उस बजट को लेकर इनके दिमाग में, इनका दिमाग गड़बड़ हो गया।

आपको तो ध्यान होगा कालीचरण जी, मैं तो नहीं था उस सदन में, गहलोत साहब जब बजट पढ़ रहे थे, एक साल पुराना बजट पढ़ लिया उन्होंने। पढ़ लिया था नहीं पढ़ लिया था? उन्होंने एक साल पुराना बजट पढ़ लिया था और सबसे बड़ी चीज है कि उनको बजट की कोई जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने तो अपने सारे कांग्रेस के एमएलएज को एक-एक अटैची दे रखी थी। नकद बजट दिया था। जाओ और लूटो और निपटाओ सबको।

सभापति महोदय, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि गंभीरता से इस बात

पर विचार करें कि जिन लोगों का इसमें दोष है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भी सदन तय करेगा और इस तरह के नियम बनाये जायें कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। सदन एडजोर्न होने के बाद भी सदन के अन्दर कोई इस तरह का गाली-गलौच, दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो। ऐसा नियम बनना चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, एक सैकण्ड।

श्री सभापति: विराजिये। अब विराजिये। विराजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): पहली बार सदन में देखने को मिल रहा है कि पर्ची से कोई इश्यु उठाया गया जिस पर आप परिचर्चा करा रहे हैं। लेकिन मेरे को भी मौका दिया जाये जो मैं एक बीच की बात कह सकूं। क्योंकि जब आपने उनको भी मौका दिया है तो एक मिनट में बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पहले तो मैं आपको अवगत कराऊं...।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय,...।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सुभाष जी, यह राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है ...(व्यवधान)... अगर वे बुलवा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको?

श्री सभापति: मैं आपको अवगत करा दूं कि यह पहली बार अवसर नहीं है। पर्ची पर बोलने का पूर्व में भी, मैंने बैठते ही यहां कहा था, पर्ची प्रारंभ होने से पहले ही यदि कोई मंत्री जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मंत्री जी ने बोल दिया। उसके बाद आपने सदस्य को बुलवाया है।

श्री सभापति: ठीक है आप विराजिये। ...(व्यवधान)...देखिये, अब आप विराजिये। कोई वरिष्ठ सदस्य, आप विराजिये, वरिष्ठ हैं, आप विराजिये। देखिये, जो विषय आया, आसन की व्यवस्था है, आप विराजिये। वरिष्ठ हैं आप, मंत्री रहे हैं। विराजिये। प्लीज, आप विराजिये ...(व्यवधान)... आप भी बैठिये। मंत्री महोदय, प्लीज। आप बैठिये। देखिये, आप विराजिये। प्लीज।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): किस नियम के तहत ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये। गोपाल जी आप समझदार हैं। विराजिये, आप विराजिये। मंत्री महोदय आप विराजिये। जो पर्ची में विषय आया उस विषय में माननीय मंत्री महोदय ने अपने विचार रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय की कार्य प्रणाली है, वह कार्य प्रणाली, सदन में उनकी सहजता, सरलता, शुचिता और निष्पक्षता के लिए चहुं ओर उसकी प्रशंसा होती है।

हमने देखा कि माननीय अध्यक्ष जी लगातार उदार मन से, उदार दिल से इस घटना क्रम में भी पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयत्न किया। उनका भाव कभी यह नहीं रहा कि कोई माननीय सदस्य आकर उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगे। वह जो ऐतिहासिक परंपराएं इस आसन की रही हैं वे सिर्फ उस आसन की परंपरा के प्रति खेद प्रकट करवाना चाहते थे। क्षमा से भी उन्होंने यह शब्द कह दिये थे, बहुत इजी गोइंग, बहुत सरल, आसन के प्रति खेद प्रकट कर दिया जाये और वह खेद भी इसलिए क्योंकि इस आसन का अपना महत्व है, आसन की अपनी गरिमा है। इस सदन की गरिमा बनी रहे यह प्रयास माननीय अध्यक्ष जी का था। खैर, ये सारे विषय अब सामने आये हैं। अपन आगे की व्यवस्था के लिए, नियम समिति 2024-25 का।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापतिः अब यह विषय हो गया। माननीय अब यह विषय हो गया।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट, एक मिनट। मैं एक मिनट बात रखूंगा।

श्री सभापतिः अब यह विषय हो गया।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय, एक मिनट। सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि हम पिछली बार 15वीं विधान सभा में भी सदस्य थे। हमने देखा किस तरह आसन का हमारे नेता, प्रतिपक्ष, उप नेता, प्रतिपक्ष बात करते थे। कोई गलती माननीय सदस्य से हो जाती थी तो क्षमा मांगने में 2 मिनट भी नहीं लगाते थे। पर इस बार हमने पहली बार देखा है कि नेता, प्रतिपक्ष, उप नेता, प्रतिपक्ष, उनको उनके स्वयं के नेता ही नहीं मान रहे। जो उस दिन की घटना लक्ष्मणगढ़ के विधायक द्वारा की गई, माननीय सदस्य द्वारा, जिस तरह उनके शब्द थे, जिस तरह बोलना, ऐसे शब्द हमने 6 साल विधान सभा में कहीं नहीं सुने।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ना सिर्फ ऐसे शब्द सुने बल्कि एक निवेदन और करते हुए कि ऐसे सदस्य जिन्होंने ऐसी अशोभनीय भाषा का यहां इस्तेमाल किया और उसके बाद भी विधान सभा अध्यक्ष जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उनको फिर सदन में बुलाकर माफी का निवेदन किया। फिर भी उन्होंने नहीं किया।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो ऐसे सदस्य की तो भर्त्सना की जानी चाहिए ताकि जितने भी नये विधायक हैं वे सोचें कि ऐसे जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और 4 बार के विधायक, इतने वरिष्ठ आदमी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो नये व्यक्ति कहां से सीखकर जायेंगे।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, सभी सदस्य चाहे वह पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के

हों, राजस्थान की 8 करोड़ जनता यही चाहती है कि यहां आपस में दोनों स्वस्थ तरीके से बैठें और यह गतिरोध खत्म हो। मैं समझता हूं कि इसके लिए जरूर प्रतिपक्ष भी और पक्ष भी इस विषय में पूरी गंभीरता के साथ सोच रहे होंगे। इसमें अपन आगे की कार्यवाही कर सकें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आज चूंकि बजट प्रस्तावों पर चर्चा का अंतिम दिन है और उप मुख्य मंत्री जी का जवाब भी आना है। वक्ताओं की संख्या भी लंबी है, इसलिए आज भोजन अवकाश को निलंबित रखा जाये।

श्री सभापति: भोजन अवकाश नहीं होगा।

नियम समिति, 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

**समिति प्रतिवेदन**

**नियम समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 2)**

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

**spp/rtm/27.02.2025/13.00/1n**

**समिति का गठन**

**वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव**

श्री सभापति: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं, आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2025-26 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क", 2025-26 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 2025-26 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में

से राजकीय उपक्रम समिति, 2025-26 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग, वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**(समयः बजे)**

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

**वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव**

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, 2025-26, प्राक्कलन समिति "क", 2025-26, प्राक्कलन समिति "ख", 2025-26 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2025-26, प्रत्येक के लिये अधिकतम 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़।

**आय-व्ययक**

**आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद**

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय

अध्यक्ष महोदय, यह बजट प्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं सदन के नेता, आदरणीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस सदन में जो घटनाक्रम घटा है, मैं भी जनता के आशीर्वाद से सन् 1993 से इस सदन में आ रहा हूं, लेकिन मैंने पहली बार मेरी आंखों से ऐसी घटना देखी है। यह बड़े दु:ख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि सदन में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया है, यह अनुमान पहले से ही लग रहा था। जब से यह दूसरा बजट भजन लाल जी सरकार का यहां आया और महामहिम राज्यपाल महोदय यहां अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस समय भी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बीच-बीच में बाधा पैदा करने का कार्य किया था। जब दूसरा बजट पेश हो गया तो प्रतिपक्ष के पास में अब सरकार के खिलाफ बोलने के लिये ऐसा कोई मामला ही नहीं था इसलिए उन्होंने इस तरह का विवाद उत्पन्न किया। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार आर एस एस के हैं। हम तो स्वीकार करते हैं कि हम सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के लेकिन आर एस एस के परिवार के कोई कार्यक्रम होते हैं, यदि हम उसमें जाते हैं तो वहां से कुछ सीखकर आते हैं। यदि कांग्रेस में भी ऐसा कोई संगठन सिखाने वाला होता तो इस तरह का कृत्य आपके सामने नहीं करते।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया सन् 1993 में, मात्र 30 वर्ष की उम्र में विधायक बना था। आदरणीय भैरोंसिंहजी उस समय मुख्य मंत्री थे और आदरणीय कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे। मैं चुनाव जीतने के दो महीने बाद जब मुख्य मंत्रीजी के निवास पर मिलने गया था तो मैं जिनसे चुनाव जीता था आदरणीय हीरालाल जी देवपुरा से, वह इस सदन के नेता भी रहे हैं, वह बहुत वरिष्ठ नेता थे। भैरोंसिंह जी ने सबसे पहले मुझसे यह पहला प्रश्न पूछा कि, सुरेन्द्र सिंह, देवपुरा साहब के क्या हालचाल हैं? मैंने कहा कि मैं तो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर आया हूं। दो महीने हो गये, उन्होंने मुझे चुनाव में बहुत परेशान किया, सरकार ने पूरी पुलिस लगा दी थी, मेरे को हीरालाल जी देवपुरा से क्या लेना-देना? उन्होंने कहा नहीं, तू तेरा कागज यहां रख दे और एस.एम.एस. हॉस्पिटल में जा और रात को 12.00 बजे बीमार थे, अब वह कॉटेज नंबर 7 में शिफ्ट हो गये। मैंने कहा कि मैं तो एस.एम.एस. में जानता ही नहीं कि 7 नंबर कॉटेज कहां है? उन्होंने कहा कि यहां से मैं एक कर्मचारी तेरे साथ भेजता हूं। 22 गोदाम पर जाना, वहां से थोड़े फ्रूट लेना और एक अच्छा-सा गुलाब का गुलदस्ता लेना, वहां पर हॉस्पिटल में जाकर देवपुरा साहब के पांव छूना और कहना चारभुजा नाथ जी की कृपा से आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर पधारें। उस दिन मेरे मन में आया कि जिनसे मैंने इतना संघर्ष करके पहली बार चुनाव लड़ा, मैं उस समय 30 वर्ष का था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेरी जितनी उम्र है उससे डबल उनकी

उम्र है, उनका मान-सम्मान करना। पांच साल एक एरिये में कभी देवपुरा साहब के ऊपर आरोप मत लगाना। कभी मत कहना कि विकास नहीं किया, यह काम नहीं किया और पब्लिक में तेरे को कहीं नजर आये तो पांच हजार लोगों के सामने भी उनको पांव छूकर नमस्कार करना। यह भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। यह हमें इसलिए सिखाया, इतने सालों से यहां आ रहा हूं लेकिन कभी भी न आसन की तरफ ऊंची आवाज उठाकर बोलता हूं। जैसे ही आप वहां से बेल बजाते हैं, मैं नीचे बैठता हूं। यह प्रशिक्षण हमको भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। यदि इस तरह का संस्कार उनको भी मिलता तो शायद यह कृत्य नहीं होता। आप उस दिन जिस तरह से भावुक हुए, हमें भी सबको इस बात का बहुत दुःख हुआ।

**jyg/rtm/27.02.25/13.10/1o**

लेकिन निश्चित तौर से मैं उसकी पूरे शब्दों में निन्दा करता हूं, फिर भी सदन में जो निर्णय होगा, वो तो जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो ही सदन में बैठकर निर्णय करेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में भजन लाल जी की सरकार ने बच्चों से लगाकर बुजुर्गों तक किसी न किसी मद में कुछ न कुछ व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा, पूर्व में सब आंकड़े यहां पर आये। 3 से 6 साल के बच्चे यदि आंगनबाड़ी में आते हैं, पहले ही बजट में भजन लाल जी ने सप्ताह में 3 दिन उनको दूध देने की व्यवस्था की है और जब यह दूसरा बजट आया तो अभी उन्होंने घोषणा की है कि सप्ताह में पांच दिन तक उन बच्चों को दूध पिलाया जायेगा, बच्चे कोई वोटिंग नहीं करते हैं, वोट देखकर भजन लाल जी सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार चाहती है कि यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो वे आगे जाकर इस देश का नाम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए 1 लाख 25 हजार नई भर्ती की घोषणा हुई है। प्राइवेट जॉब में भी 1 लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की गयी है। यही नहीं बुजुर्गों को घर बैठे 70 साल के बुजुर्ग होने पर, घर बैठे नि:शुल्क चिकित्सा सेवा पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। किसान निधि में जिस तरह से इस देश में हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने सीधे किसान के खाते में सीधे 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में जमा करवा रहे हैं। राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री अब भजन लाल जी हो गये हैं जिनकी सरकार आने के बाद किसान सम्मान निधि में पहले बजट में 2000 और इस बजट में 1000, दोनों मिलाकर 3000 रुपये इन्होंने किसान सम्मान निधि में देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। इस योजना के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ही बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आमेट में सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय, सरदारगढ़ पीएचसी को सीएचसी में, माही जाखम परियोजना से 300 गांव और ढाणियों को पेयजल की व्यवस्था के लिए, बेड़च नाका, झोग नाका, आगरा नाका, सैकड़ों सड़कों का इस बजट में

प्रावधान मिला। कुछ समस्याएं बीस साल से पेंडिंग थी, लेकिन आदरणीय भजन लाल जी ने पहले ही बजट में यह दिया। अभी जो बजट रखा है उस बजट में आमेट की रोडों पर 30 करोड़, आमेट सरदारगढ़ रोड पर 40 करोड़ रुपये, चार भुजा से सेवंदरी 6 करोड़, वायाटूगड़ा में एनिकट और अभी 10 करोड़ की सड़कें हमें मिली हैं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय भजन लाल जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि जेजेएम में राजस्थान में समय पूरा हो गया लेकिन इन्होंने भारत सरकार से बात कर, मोदीजी से बात कर, जल संसाधन मंत्रीजी से बात कर 2028 तक का इसका कार्यकाल बढ़ाया जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 61 गांवों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुझे फण्ड मिलेगा। यही नहीं मगरा विकास में 50 करोड़ के बजट को 100 करोड़ किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समिति में मगरा विकास में भी पैसा होगा और हर दृष्टि से क्षेत्र में विकास का काम होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निवेश के बारे में 35 लाख करोड़ निवेश आ रहा है। खनन नीति भी आयी है, मैं खनन नीति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः समअप करिये।

आज आपका जवाब भी है और बोलने वाले 18-20 माननीय सदस्य हैं। 10-10 मिनट बोल लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

नई खनिज नीति के अन्दर यह प्रावधान कर दिया है कि हर वर्ष अब ड्रोन से सर्वे करके लीज धारको को रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजसमन्द जिले में पहले मास्टर प्लान में जो लीजें दी हुई हैं वो 60 गुणा 60 मीटर की हैं, लेकिन सेकण्ड बार दस साल में प्लान बना तो वो 100 गुणा 100 मीटर की हैं, उसके बाद बड़ी खदानें मिली हैं। यदि उन छोटी खदानों का ड्रोन के जरिये सर्वे कराया जायेगा तो 100 से 150 फीट गहरी खानें चली गयी हैं, आपस में विवाद खड़े होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी सरलता के लिए फिर से विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी चार-पांच मांगें रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चारभुजा देसूरी एक दुर्घटना स्थल है, पहले भी जब आप भी मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, वहां देश की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी। मुझे विश्वास है कि इस बार पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी दिया कुमारीजी स्वयं जब आयीं, हमारी सांसद ने भी दिल्ली में यह बात उठायी है, मुझे विश्वास है कि इसको नेशनल हाईवे में देकर उसके बजट से एलिवेटेड रोड के लिए 1250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने यहां डबल इंजन की सरकार है, आने वाले समय में यह पैसा मिलेगा और यह देसूरी की नाल जहां पर आये दिन दुर्घटनाओं की समस्या आती है, वो समाप्त होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कुम्भलगढ़ एक ऐतिहासिक दुर्ग है, यह पर्यटन

स्थल भी है, यह तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कुम्भलगढ़ का अभी राज्य सरकार के पास है, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, हमें विश्वास है कि अति शीघ्र कुम्भलगढ़ अभयारण्य में टाइगर जोन की घोषणा करके टाइगर लाने की व्यवस्था की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केलवाड़ा सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में, आगरिया पीएचसी को सीएचसी में, जीलवाड़ा, आइवाड़ा, नाभरिया में नई पीएचसी, चारभुजा में कॉलेज, बड़गुला और गारेदरा में एनिकट, सरदारगढ़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्षः श्री श्रीचन्द कृपलानी।

**(समयः बजे)**

**(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)**

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बजट वर्ष 2025-26 के भाषण पर हो रही चर्चा पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बीच में नहीं कहेंगे।

श्री सभापतिः मैं पहले ही कह दूं, अध्यक्ष महोदय ने 9 मिनट दिये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। आपको पूरे राजस्थान में मेरे जैसा आज्ञा का पालन करने वाला कोई नहीं मिलेगा लेकिन मुझे बोलने देना आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं शुरूआत कर रहा हूं।

**'अपने सपने को चूर-चूर होते हुए देख रही है कांग्रेस,**
**अब विकास का जादू छा रहा है,**
**आपस में लड़-झगड़कर मजबूर हो रही है यह कांग्रेस,**
**भाजपा का भजन लाल दुनिया में छा रहा है।'**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि 2023-24 में जब अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया था तो वो इतने क्या कहते हैं कि हाफळे-गाफळे हो रहे थे, क्या कहते हैं वो? वो क्या था कि एक साल पुराना बजट पढ़ गये वो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पुराना बजट पढ़ने लग गये थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, वो एक साल पुराना बजट पढ़ने लग गये थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारीजी ने जो बजट पढ़ा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाला वर्ष इस राजस्थान के विकास के इतिहास का एक नया वर्ष होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास बहुत चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूं उनको, लेकिन थोड़ी तुलना करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप मुझे 15 मिनट से

ज्यादा बोलने नहीं देंगे।

माननीय सभापति महोदय, बजट में राजस्थान को 350 अरब अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का कहा गया है। राइजिंग राजस्थान, ग्रीन थीम बजट, यह पहला बजट है, रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट केन्द्रित था, इस बजट में महिला, किसान, बुजुर्ग और युवाओं के लिए बड़े-बड़े ऐलान किये गये। माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के पांच साल के राज की और हमारे एक साल क्योंकि हमारे को अभी 13-14 महीने ही हुए हैं, उसकी जरूर तुलना करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि इस बजट में राजस्थान में 9 ग्रीन फ्रील्ड एक्सप्रेस-वे बनाये जाने का कहा गया और 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे वो, जबकि कांग्रेस के राज में सड़कों की हालत इस राजस्थान की जनता ने देखी है। ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में हमने रिंग रोड बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। कांग्रेस के समय में जनता ट्रैफिक की समस्या से कितनी त्राहि-त्राहि मचा रही थी, वो हमने देखा है। माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है कि विधायक फण्ड के अलावा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 10-10 करोड़ रुपये नोन पेचेबल सड़क और मिसिंग लिंक के लिए देने की घोषणा की है, उसके लिए आप भी ताली बजाकर धन्यवाद दो। 15 करोड़ रुपये मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए दिये हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा, 500 करोड़ की लागत से 500 गांवों को लाभ दिया जायेगा।

**MLS/RTM/27.02.2025/13:20/1p**

जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जायेगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज अगर कांग्रेस की तुलना में हम करें तो इस बार हमने 400 करोड़ खर्च करके 2 लाख घरों को कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के 5 साल के राज में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना करप्शन हुआ, ईडी की रेड पड़ी, छापे पड़े और कितने लोग जेल में, अभी तक तो पूरे गये नहीं, लेकिन वे भी जाएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ अशोक गहलोत की सरकार ने जितना कुठाराघात किया, मन में बड़ा दर्द होता है। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम 2 लाख मकानों को पेयजल कनेक्शंस आने वाले वर्ष में उपलब्ध कराएंगे। यह हमारे लिये बहुत बड़ी खुशी की बात है।

सभापति महोदय, एक साल में 2.75 लाख सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालना, अब ये कांग्रेस वाले बार-बार हंसते हैं कि आप खाली घोषणा करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, जबकि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया, 65 हजार लोगों की भर्तियां भी हो गईं और निजी उद्योगों में, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं, वे धीरे-धीरे अब मूर्त रूप लेने लग गये हैं, राजस्थान में आने लग गये हैं। मैं उम्मीद करता

हूं कि आने वाले समय में ये 5 लाख की जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हों या प्राइवेट क्षेत्र में हों।

150 यूनिट बिजली मुफ्त देना, पिछली सरकार ने क्या किया, बिजली बैंकिंग करने के नाम पर बिना सोचे-समझे जो उन्होंने समझौते किये, उनकी तकलीफ आज हम झेल रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती करके राजस्थान की जनता को कांग्रेस ने बेहाल छोड़ दिया था, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले 14 महीनों में, ये कांग्रेस के, विपक्ष के लोग यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन ये भी जब बिजली की बात आती है तो ऑफ द रिकॉर्ड हो, चाहे सामने बात हो, एक बात जरूर करते हैं कि अशोक गहलोत जी के राज से अच्छी बिजली भजन लाल जी के राज में मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अच्छी बिजली मिल रही है। यह हमारे मुख्य मंत्री जी का चमत्कार है।

सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय मैं भी मंत्री था। उस समय मैंने द्रव्यवती नदी की योजना बनायी थी। द्रव्यवती योजना बनाकर इस जयपुर को खूबसूरत करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस का राज आने के बाद उस द्रव्यवती नदी, जो अमानीशाह नाला कहलाता था, एक गन्दा नाला था, कीचड़ से युक्त नाला था, उसे इतनी खूबसूरत द्रव्यवती नदी के रूप में हमने बनाया, उसका सत्यानाश 5 साल में कांग्रेस ने किया। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को, दिया जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस द्रव्यवती नदी को वापस अपग्रेड करके, इसको सुन्दर बनाने की इस बजट में घोषणा की है।

सभापति महोदय, आपको पता है, पिछली बार जब यह रिंग रोड नहीं थी, यह रिंग रोड भी भाजपा की देन है, अब रिंग रोड हमने बना दिया, कुछ टुकड़ा उसका बाकी है, लेकिन कांग्रेस के 5 साल के राज में क्लोवर लीफ के अधूरे काम को वे आगे नहीं बढ़ा पाये। प्रेमचन्द जी, बढ़ा पाये क्या? ...(व्यवधान)... कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ नहीं कर पाये, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वह काम कम्प्लीट होगा और रिंग रोड का लाभ जयपुर ही नहीं इस पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के लाखों लोग रोजाना जयपुर आते हैं, अलग-अलग रास्तों पर जाते हैं।

सभापति महोदय, यूडीएच वगैरह आप देखें तो धारीवाल जी उस समय मंत्री थे। कोटा, जोधपुर, मुख्य मंत्री जी जोधपुर के थे। और शहरों की ओर ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। अगर ये ध्यान देते तो कोटा और जोधपुर जैसे खूबसूरत शहर राजस्थान में बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ध्यान किस बात पर दिया, कि कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीते। सबके 2 टुकड़े कर दिये। जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिये, कोटा के 2 टुकड़े कर दिये, जयपुर के 2 टुकड़े कर दिये। सिर्फ राजनीतिक आधार पर 2 टुकड़े करके जीतने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि इनको वापस जोड़ा जायेगा, ताकि समुचित विकास, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे राजस्थान का छोटा-सा शहर हो, चाहे

राजस्थान का बड़ा शहर हो, उसका विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि हमने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से उसका विकास होगा।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत बातें हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब, बैरवा साहब बैठे हैं, इन्होंने 500 बसों की घोषणा की थी। 500 बसें तो आ गईं। अब 500 बसें और आ रही हैं। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। जयपुर शहर में लोगों को जो समस्याएं थीं, उनका समाधान करने के लिये...। उसके अलावा ट्रक, बस ड्राइवर, बढ़ई, कारीगर, दर्जी, नाई, जिनको फ्री चश्मा देने के लिए ''मां नेत्र वाउचर योजना'' का ऐलान इस बजट में किया गया है, जिसमें 75 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

सभापति महोदय, 50 हजार बुजुर्गों को ट्रेन से और 60 हजार बुजुर्गों को प्लेन से धार्मिक यात्रा कराना, और सबसे बड़ी चीज, मुख्य मंत्री जी को आप तो ताली बजाकर धन्यवाद दो, महाकुम्भ की यात्रा करा लाये। बहुत बड़ा कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाया। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आये। उसके बाद ही इन विपक्षियों का दिमाग खराब हुआ। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, ईमानदारी की बहुत चीजें हैं इस बजट में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें, समय समाप्त है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, समय ऐसे समाप्त नहीं होता है। मेरा आपसे निवेदन है, महिला एवं बाल विकास हो, चाहे उसमें 35 हजार स्कूटीज देने की घोषणा की हो, 20 लाख लखपति दीदी बनानी हों, महिलाओं के लिए 175 करोड़ की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनाने हों, और सबसे बड़ी बात है, पूरे राजस्थान के लोगों को एक सुविधा जो इन्होंने दी है, अपनी पत्नी के साथ खरीदी गयी जो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी है। यह बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लोग बार-बार, चाहे हरियाणा हो, चाहे लोक सभा हो, अग्निवीर-अग्निवीर करते रहे, अग्निवीर का फायदा उन्हें हरियाणा में नहीं मिला, अग्निवीर का फायदा उन्हें लोक सभा में नहीं मिला, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने उन अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिये पुलिस, जेल, वन, अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ी बात है।

चाहे पंचायतों के हमारे जन प्रतिनिधि हों, चाहे स्थानीय निकाय में जन प्रतिनिधि हों, 10 परसेंट उनके वेतन में भी वृद्धि की है, उनके मानदेय में वृद्धि की है। सभापति महोदय, अभी जब हम महाकुम्भ में गये थे, आप भी थे, हमारे मुख्य मंत्री जी ने वहां कैबिनेट की मीटिंग बुलायी और एक बहुत बड़ा धर्म का काम किया, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता थी। किसान सम्मान निधि की बात हम बार-बार करते हैं। सभापति महोदय, किसान सम्मान निधि में पूरे हिन्दुस्तान के किसानों को 6 हजार रुपये हमारे प्रधान मंत्री जी ने देने की घोषणा की। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि हम 6 के 12 करेंगे। 2 हजार उन्होंने पिछली बार बढ़ाये, इस बार 1 हजार उन्होंने और बढ़ाये, 9 हजार रुपये कर दिये। मैं समझता हूं, आने वाले 3 बजट और हैं, उनमें आराम से 12 हजार रुपये साल के उनके हो जाएंगे और किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, 50 हजार कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शंस, 900 करोड़ रुपये से क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का ऐलान। सभापति महोदय, इतनी चीजें हैं इसमें कि मैं 4 घंटे तक बोलता रहूं तो भी कम है।

श्री सभापति: आप अनुभवी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। समय का अभाव होते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं आपका आदेश मानूंगा, लेकिन एक चीज हमारे मुख्य मंत्री जी ने अच्छी की कि हमारे एमएलएज को 10-10 लाख रुपये जन सुनवाई केन्द्र बनाने के लिये दिये, मैं उसमें एक रिक्वेस्ट यह करूंगा कि 10 की तुलना में 15-20 कर दें, ताकि और सुविधाएं भी वहां पर हो जाएं। ...(व्यवधान)... 25 लाख रुपये उसमें हो जाएंगे तो...। एमएसपी बढ़ाने की बात हो, कृषि में नयी तकनीक की बात हो, कई चीजें इस बजट में हुई हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, 20 आदमी हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बस, 2 मिनट और बोल रहा हूं। जिन्दगी कहती है कि व्यक्ति एक बार भूल होने पर खुद से क्षमा याचना करे, दो बार भूल होने पर खुद को चेतावनी दे, दो से अधिक बार भूल होने पर सबसे क्षमा मांगे। यही जीने की राह है।

**'डरने वाले लोगों को डराएंगे,**<br>
**झुकने वाले लोगों को झुकाएंगे,**<br>
**हौसले से सफर तय कर नादां,**<br>
**तेरे इरादों से लोग सहम जाएंगे।'**

भजन लाल जी शर्मा के लिए मैं कहना चाहूंगा:-

**'बाधाओं में बल नहीं,**<br>
**जो बादल तूफान को क्या जानें,**<br>
**पहचान नहीं दे जाता वो,**<br>
**जो समर्पण भाव मन में ठाने,**<br>
**मैं चल पड़ा हूं, आंधियां हट जाएंगी,**<br>
**बिजलियां हो मौन वहीं डंट जाएंगी,**<br>
**तूफान की औकात क्या जो मुझ मुसाफिर को रोक ले,**<br>
**मेरे विश्वास की आर से चट्टान तक कट जायेगी।'**

एक बार फिर धन्यवाद। सभापति महोदय, बोलने की तो बहुत चीजें हैं, लेकिन आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री जीतेन्द्र कुमार जी गोठवाल। प्लीज सदस्य, 20 व्यक्ति हैं, अध्यक्ष महोदय ने 9 मिनट दिये हैं। 8 मिनट पर घंटी बजाऊंगा, 9 मिनट तक समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के

बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**MKD/RTM/27.02.2025/13:30/1q**

राजस्थान की आठ करोड़ जनता का सपना है। यह बजट युवाओं को नौकरी देने वाला बजट है। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने वाला बजट है। यह बजट किसानों के हित का बजट है। यह बजट गरीब आदमी को घर देने का बजट है। यह बजट जहां पर गांवों में पानी नहीं पहुंचता, उसको नल से पानी पिलाने का बजट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को और उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में जो इस देश की, इस सृष्टि की बड़ी चिन्ता है, उसको महत्व देते हुए पूरे देश भर में सबसे पहला ग्रीन बजट राजस्थान के अन्दर पेश किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जहां पर पर्यावरण हमारी बड़ी चिन्ता है, वहीं पर ग्रीन बजट का नाम आते ही राजस्थान की ओर पूरे देश के राज्यों की नजर घूम गई और उन्होंने इस बजट का अध्ययन करके उनके प्रदेश में ग्रीन बजट कैसे लागू हो, इस पर भी काम करना प्रारम्भ किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह अहसास दिला दिया कि एक किसान का बेटा जब खेत में पाणत करता है, फसल के बीज बोता है और धूप में कड़ी ठंड में बैठकर अपनी फसल की सुरक्षा करता है, उन्हीं मजबूत हाथों से जब वह राजस्थान के विकास की, राजस्थान की जनता के हित की बात सोच लेता है तो ऐसा बजट लिख देता है, राजस्थान के लोगों को भला कर देता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि ऐसे मुख्य मंत्री जो किसान के सुपुत्र हैं, उन्होंने यह बजट किसानों और युवाओं को समर्पित किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जब बजट की बात चल रही हो, प्रदेश की बात चल रही हो और राजस्थान में सदन के अन्दर विपक्ष के लोग नहीं हों और वो भी किस मुद्दे पर, दादी जैसे शब्द के मुद्दे पर। जबकि, दादी एक प्यार भरा, सम्मान भरा, पोते को संरक्षण देने वाला एक ऐसा शब्द है, जिसके अन्दर मुझे याद है, दादी जब भी पिता की डांट पड़ती तो उससे संरक्षण देती थी। पढ़ाई के लिए जब टीचर डांटता था, तो दादी उससे संरक्षण देती थी और जब धूप से हम लोग लौटकर आते थे तो दादी ठंडा पानी, शीतल जल पिलाने का काम करती थी। सभापति महोदय, उस दादी के नाम पर इतने दिन सदन डिस्टर्ब रहा तो यह दर्शाता है कि दादी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है और दादी शब्द के कारण इन्होंने इस सदन को इतने दिन डिस्टर्ब किया।

माननीय सभापति महोदय, एक दिन मैंने अख़बार में पढ़ा। किसी नेता ने कहा कि दादी को हिन्दी में दादी कहते हैं, उसमें प्यार और ममता है और फारसी में क्या कहते हैं, तो मेरे मन में क्यूरोसिटी थी कि शायद फारसी में इस शब्द का उच्चारण हम लोग सदन में करें तो

विपक्ष के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, फारसी के अन्दर दादी को पेदर बुजुर्ग कहते हैं और छात्री कहते हैं। अगर उनको दादी शब्द से तकलीफ है तो मैं उसमें संशोधन करता हूं और फारसी शब्द का उच्चारण भी मैंने इस सदन के माध्यम से किया। मुझे लगता है, उसके बाद में यह गतिरोध खत्म हो जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इंग्लिश में ग्रांड मदर कहते हैं। इटली में, मैं पूछकर आऊंगा। सभापति महोदय, आप मुझे यहां नेट चलाने की अनुमति नहीं देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बजट के अन्दर, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने रामसेतु जल लिंक योजना का जो काम पिछले बजट में प्रारम्भ कराया था, उसके लिए बहुत-बड़ा प्रावधान बजट के अन्दर रखा। जिसके अन्दर 25 हजार फार्मर, 100 एनिकट और 11 लाख किसानों को इक्यूपमेंट मिलेंगे और किसानों को सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा।

सभापति महोदय, हम बार-बार बजट की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने का माननीय प्रधान मंत्री जी ने वादा किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको भी पूरा करने के साथ-साथ पहले बजट में दो हजार रुपये और दूसरे बजट में एक हजार रुपये बढ़ाकर, अब किसान को सम्मान निधि के रूप में राजस्थान के अन्दर 9 हजार रुपये की किस्त मिलेगी और अभी तीन दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष की किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का भी काम किया।

सभापति महोदय, आपसे इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से पिछले बजट में और इस बजट में युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने घोषणाएं कीं, सभापति महोदय, 59 हजार नौकरियों हमने 6 महीने में देने का काम किया और इस बजट के माध्यम से 1 लाख 25 हजार नौकरियां हम लोग और इस साल देने का काम करने वाले हैं। एक ओर पेपर लीक, एक सरकार लगातार 19 बार पेपर लीक करती है और सिर्फ और सिर्फ पांच सालों के अन्दर किसानों को मात्र 38 हजार नौकरी देने का काम करती है। एक किसान का बेटा जब मुख्य मंत्री बनता है तो अपनी घोषणा के अनुसार इस सदन के माध्यम से जो बोला, उन सब वादों को पूरा करने का काम करता है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 59 हजार नौकरियां पिछले वर्ष में और सवा लाख नौकरियां इस वर्ष में देने की घोषणा करके यह साबित कर दिया कि हम लोग राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए काम करने वाले हैं।

सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान की बात आ रही थी। उसमें भी बार-बार एक बात आ रही थी कि कितने एमओयू साइन हुए। अभी विपक्ष यहां पर नहीं है। मेरा उनसे सवाल है, जब उनकी सरकार जाने लगी थी तो पैसे बंटोरने के लिए जनता के सामने असत्य बोलकर उन्होंने भी राइंजिग राजस्थान का आयोजन किया था, लेकिन साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करने के बाद भी इन्होंने पूरे

राजस्थान के अन्दर मात्र दो एमओयू साइन किये और उन एमओयू में किसी में भी काम प्रारम्भ नहीं हो पाया। हमने 70 प्रतिशत एमओयू साइन कर दिये। हमने 70 प्रतिशत एमओयू साइन करने के साथ-साथ उनमें काम प्रारम्भ करा दिया।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): उनको लैंड उपलब्ध करा दी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वादा किया था, सिंगल विंडो के माध्यम से इन सभी कम्पनियों को लगातार हम मदद करने का काम कर रहे हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि माननीय भजन लाल जी जो इस सदन में अन्दर घोषणा करेंगे, हम शत-प्रतिशत उस घोषणा को पूरा करने का काम करेंगे, यह हमारे भजन लाल जी का वादा है। माननीय भजन लाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे क्षेत्र के अन्दर भी सभापति महोदय, बजट रिप्लाई में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री अतुल भंसाली जी।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मेरी एक उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र की अपेक्षा थी और मुझे लगता है कि उसकी घोषणा निश्चित तौर पर होगी। धन्यवाद, सभापति महोदय।

**Bhs/Rtm/27.02.25/13.40/2a**

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और एक किसान के बेटे जिन्होंने अभावों के अन्दर अपनी जिन्दगी निकाली उन्होंने गांव, गरीब लोगों की आवश्यकता को समझा और उनके दिशा-निर्देश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए और भारत के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक सरकार का शासन का लाभ पहुंचे उसी उद्देश्य के साथ उनके कार्यकाल का यह दूसरा बजट हमारी यशस्वी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है। इस बजट के ऊपर सब लोग अलग-अलग तरह से प्रकाश डाल चुके हैं। अभी जिस तरह का गतिरोध पिछले दिनों से सदन में देखने को मिल रहा है और सभी वक्ताओं ने जो बात कही कि 2024 और 2025 का बजट इतना अकल्पनीय और जनता के हित में है कि कांग्रेस वाले उसकी तारीफ नहीं सुन सकते इसके लिए बहाना बना कर सदन से उन्होंने वाक आउट किया।

मैं उसी कड़ी में और आगे बात करता हूं। जब दो दिन पहले यहां गतिरोध चल रहा था और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जो जोधपुर से आते हैं वो इस सदन के बाहर धरने पर बैठे थे। अगर वो अपने आपको कांग्रेस के सर्वोच्च नेता गिनते हैं, राजस्थान के अन्दर कांग्रेस चलाने की अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं, अगर उनको कुछ बोलना होता बजट के बारे में यहां सदन के गतिरोध को खतम करने के लिए तो वो स्वयं सदन में आकर वो चूंकि इस सदन के सम्माननीय सदस्य भी हैं, यह बात कर सकते थे परन्तु उन्होंने यह

नहीं किया और उसके दो दिन पहले जब बजट आया उसके लगभग एक दिन बाद वो जोधपुर पहुंचे थे और जोधपुर में प्रेस के सामने जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने एक ही बात कही कि बजट हवाहवाई है, पिछली घोषणाएं पूरी नहीं हुई, पिछले काम पूरे नहीं हुए। अन्य गलत बातें करते हुए उन्होंने इस बजट 2025 के स्वर्णिम बजट की बुराई की और विरोधाभास प्रकट किया और बाद में उन्होंने एक लाइन कही कि अब मैं खुद बैठ कर अधिकारियों की मीटिंग बुलाऊंगा जोधपुर में और इस बजट में और पिछले बजट में क्या-क्या कार्य हुआ उसके बारे में मैं सभी अधिकारियों से उसकी रिपोर्ट लूंगा और अधिकारियों को पूछूंगा कि कौनसे काम हुए और कौनसे नहीं हुए और क्या बजट में घोषणा हूई और किस घोषणा की क्रियान्विति हुई।

मैं अशोक जी गहलोत, इस सदन के माध्यम से आपको कहता हूं कि जब आपने पिछले पांच साल, पांच साल नहीं आपने पन्द्रह साल तक बजट पेश किया और एक बजट तो पिछला ऐसा पेश किया कि जो आप बजट का ईयर ही लांघ गये, आपने पिछले साल का बजट पढ़ लिया तो आपकी दूरदर्शिता और आप बजट कैसे बनाते थे यह पब्लिक को समझ में आया हुआ है कि जो बजट आपने बनाया नहीं उसको भी पढ़ दिया। ईयर भी मालूम नहीं आपको और आज जब माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार जब दो बजट बनायें और उससे भी बड़ी बात बजट बनाने के बाद में हर पन्द्रह दिन में विधायकों को फोन करना, प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग करवाना, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिले में मीटिंग करवाना कि आपकी बजट घोषणाओं की पालना कहां तक हुई है? आपका बजट जो पिछला 2024-25 का था वो धरातल पर उतरा कि नहीं उतरा? उस बजट की राशि स्वीकृत हुई कि नहीं हुई? जमीन अलॉट हुई कि नहीं हुई, कहां परेशानी आ रही है? और मैं कहता हूं कि यह जो बजट 2024-25 का और 2025-26 का बजट है उसकी क्रियान्विति के लिए एक दिन बाद ही अधिकारियों को और प्रभारी मंत्रियों को अपने जिला प्रभार में भेजने का यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है क्योंकि जिसके मन में काम करने की इच्छा थी, काम करने की इच्छा है और काम करेंगे उन्होंने अपने विधायकों को भी इसी तरह लगा कर रखा कि आपकी जिम्मेदारी है इस बजट की अगर कोई भी एक चीज बाकी रह गई तो। कोई भी वित्तीय स्वीकृति बाकी रह गई तो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ में सरकार चल रही है आदरणीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और सारे मंत्री गण और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण जिस जिम्मेदारी के साथ में बजट के क्रियान्वयन को लेकर और बजट में की हुई वास्तविक घोषणा क्योंकि घोषणाएं वास्तविक हैं इसलिये क्रियान्वित होंगी, उनकी जैसे हवाहवाई घोषणाएं नहीं थी।

सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारे मुख्य मंत्री ने इस सदन के अभी सत्र के चालू होने के समय अपने वक्तव्य में एक पुलिन्दा साथ में लेकर आये थे वो कि पिछले पांच साल की बजट की घोषणाएं इस सरकार की घोषणाएं जो कांग्रेस की थी, वो कितनी क्रियान्वित हुई,

वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए तैयार नहीं थे। ...(व्यवधान)... अभी भी नहीं हुई हैं और वो लैप्स ही हो गई, भाई साहब। अब तो वो हैं ही नहीं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो इस सदन के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि पहली बार राजस्थान के अन्दर उन युवाओं को रोशनी देने का, उन युवाओं को आशा की किरण दिखाने का, उन युवाओं को नया सवेरा देखने को मिला है जिस युवा नीति के साथ में इस बजट में युवाओं के लिए घोषणा की गई। सवा लाख सरकारी नौकरियां, डेढ़ लाख प्राइवेट सेक्टर में लोकल युवाओं को रोजगार, स्किल डवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, इतनी चीजें उन्होंने इस बजट में युवाओं को दी हैं जिसकी युवा वर्ग को बहुत अपेक्षा थी। अपेक्षा इसलिये थी क्योंकि पिछली सरकार के अन्दर युवाओं के भविष्य के साथ पेपर लीक हो या घोटाले हों, उनकी भेंट पूरा युवा चढ़ गया था और राजस्थान का युवा एक निराशाजनक स्थिति में था।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जिस वित्तीय संतुलन को बना कर इस सरकार ने बजट पेश किया, बजटीय घाटे को नियंत्रण में रखा। हमारे एक सदस्य बोहरा जी जब इस बजट के ऊपर चर्चा चालू हुई तो हर बात पर जीरो-जीरो-जीरो। मैं समझता हूं कि उनको हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी से मिल लेना चाहिये जिनको मालूम है कि उनकी लगभग 4200 में से 1800 घोषणाएं जीरो ही है, जिनके ऊपर पांच साल में काम नहीं हुआ और गनीमत यह है कि हमारी सरकार ने पिछला बजट देने के बाद में 6 महीने निकले और 6 महीने के अन्दर लगभग 95 प्रतिशत जो बजट की घोषणाएं थी उनको जमीन पर उतारने का काम किया।

आदरणीय बोहरा जी, आप यह बोल कर तो यहां से चले गये, आप में वापस सुनने का माद्दा नहीं था। हमारे विधायकों ने जब जवाब दिया तब आप यहां से उठ कर गये, बिलकुल मुंह छिपाते हुए सदन से बाहर निकले थे, आपको सब देख रहे थे। केवल असत्य आंकड़ों पर बोल कर चुपचाप भागना नहीं है और अब तो आपका पूरा विपक्ष यहां से भाग चुका है क्योंकि आपके अन्दर इस बजट के विरोधाभास में कहने के लिए कुछ नहीं था।

सभापति महोदय, दूसरी बात आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता जहां से मैं चुन कर आया हूं, अभी मेरे से पहले हमारे विधायक महोदय ने एक बात कही थी कि अशोक गहलोत जी का पूरा-पूरा ध्यान जयपुर और जोधपुर के ऊपर रहता था, मैं आपको बता दूं कि उनका ध्यान कभी जोधपुर के ऊपर रहा ही नहीं और जोधपुर में पिछले पांच साल के कार्यकाल में और दस साल के कार्यकाल में बताऊं, उनके जितने नामित मुख्य मंत्री के पहरेदार थे वो सबके सब कोई कॉलेज घोटाले में जेल गया, कोई भर्ती घोटाले में जेल गया, कोई जे.डी.ए. घोटाले में जेल गया और सारे के सारे अधिकारियों के साथ मिल कर वसूली काम में लगे हुए थे और पूरा जोधपुर उस दर्द को आज भी महसूस करता है और जोधपुर की जो दुर्दशा आज हुई है वो उनकी वजह से हुई है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं एक मिनट ही बात कहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस बजट के अन्दर हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा हमको इस सरकार के 2025 में भजन लाल जी ने दिया है। एक बात और रिपीट करूंगा कि विधायकों के कार्यालय के लिए जनसुनवाई केन्द्र के लिए पच्चीस लाख की घोषणा में मैं भी सहमति करता हूं कि उसकी लिमिट बढ़ाई जाये और आदरणीय बैरवा जी जो मेरे बजट के भाषण की तारीफ कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे जोधपुर के अन्दर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को बढ़ाया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधान सेवक और हमारे माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करते हुए और जनता द्वारा व्यक्त किये हुए विश्वास को सही प्रमाणित किया है और 9,600 से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया गया है और इस अवसर पर मैं हमारे यशस्वी, हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेश की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने प्रदेश की आठ करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस बजट में खुशहाल राजस्थान के विकास का...

**Kas/rtm/27.02.2025/13.50/2b**

जो खाका तैयार किया, उसके लिये मैं प्रदेश और नसीराबाद की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो घोषणाएं हुईं, उनके लिये भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीसांगन में उच्च जलाशय व पेयजल पाइप लाइन की घोषणा की, उसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीसांगन एवं नसीराबाद में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय के लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से जो नोन पेचेबल सड़कों की आपने घोषणा की है, उसमें मिसिंग लिंक को जोड़ते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया हैं, इसके लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार। लाखोलाव तालाब, हणुवंतिया छोटा तालाब, जैतगढ़ में तालाब की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिये भी आपने जो स्वीकृति की है, उसके लिये भी बहुत-बहुत आभार। पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ के लिये 2 करोड़ रुपये की जो आपने घोषणा की है, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

नसीराबाद में जलापूर्ति के लिये सर्विस लेवल, सप्लाई अंतराल व प्रेशर में सुधार सम्बन्धी कार्य हेतु बजट में जो आपने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में 5 ट्यूबवैल व 10 हैंडपम्प, जो इस वित्तीय वर्ष में खोदे जायेंगे, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी व हमारी वित्त मंत्री का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आगामी कार्ययोजना में जो कुछ और घोषणाएं होनी चाहिये, उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पीसांगन में नगर पालिका की घोषणा करवाना। पीसांगन में पुलिस उपाधिक्षक कार्यालय खोलने की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार ने वित्तीय हालात का रोना नहीं रोया और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की बेहतरी, खुशहाली, समृद्धि के लिये एक शानदार और जानदार बजट देकर प्रदेशवासियों की उम्मीदों को पंख लगाये, इसके लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार। जनहित की घोषणाओं में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी 200 विधान सभा क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपने घोषणाएं कीं, उसके लिये भी बहुत-बहुत आभार। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक हमारे घोषणा पत्र के काम हुए, उनको प्रथम वर्ष में आपने शुरू करवाने का काम किया, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया, इसके लिये भी उनका बहुत-बहुत आभार। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि ईआरसीपी का नाम बदल कर राम जल सेतु लिंक परियोजना करने से कुछ नहीं होगा, अभी तक पैसा तो एक रुपया जारी नहीं किया गया है। इसी बजट में राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिये 9300 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने इस बजट में प्रदेश के युवाओं के लिये 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा एवं निजी क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जो घोषणा की है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे बड़ी घोषणा जो आम जनता से जुड़ी हुई है, 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बिजली फ्री करने की हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, इसके लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार। किसानों के लिये आप कई योजनाएं लेकर आये। 50 हजार नये कृषि कनेक्शन व 5 लाख नये घरेलू कनेक्शन देने की जो घोषणा की है, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 425 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) में आपने घोषणा की है और उसमें नसीराबाद को भी जोड़ा है, उसके लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार। किसानों के लिये किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी सहित कई किसान कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश

की जनता को राहत देने के लिये आपने शुरू की हैं, उसके लिये भी बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार चुनाव का इंतजार करने वाली सरकार नहीं है। यह राजस्थान को विकसित, खुशहाल राजस्थान बनाने के संकल्प को साकार करने वाली सरकार है, इसके लिये भी मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाह रहा हूं-

**'रख तू दो-चार कदम ही मंजिल राहें पर, मगर जरा तबीयत से,**
**हालात पर रोने वालों मत भूल कि तेरी तस्वीर बदलने वाली है।'**

माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए नसीराबाद में और जो काम हैं, मैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। नसीराबाद में एक ट्रोमा सेंटर खोला, क्योंकि हमारे भीलवाड़ा से अजमेर जिले में हाई-वे पर कोई ट्रोमा सेंटर स्थित नहीं है, इससे हमारी आम जनता को एक्सीडेंटल केसेज में काफी लाभ मिलेगा। जेठाणा में बरसात के दिनों में कई बार अंडरपास बंद हो जाते हैं, तो अजमेर जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि ओवर ब्रिज निर्माण में अगर देरी हो तो इसके विकल्प के रूप में फाटक चालू हो जाये तो आम जनता को राहत मिलेगी। अंडरपास में आधे समय पानी भरा रहता है, चाहे बरसात हो या नहीं हो। अंडरपास की हालत बहुत खराब है। पीसांगन में स्टेट हाई-वे पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो, इसके लिये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पीसांगन में अभी बाढ़ के हालात हो गये और कई जनों के डूबने के हादसे भी हो गये। यह हाई लेवल ब्रिज बनने से पीसांगन में आना-जाना सुगम हो सकेगा।

सभापति महोदय, किसानों के लिये मैं मांग करना चाहता हूं कि जो हाई पावर ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गया है, उसको जल्द से जल्द स्थापित किया जाये ताकि ट्रिपिंग व अन्य छोटी-मोटी समस्याओं से निजात मिल सके। नसीराबाद से अजमेर रोडवेज में बहुत कम बसे चल रही हैं, उनको भी बढ़ाया जाये। हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे यह मांग करना चाह रहा हूं। श्रीनगर से अजमेर के लिये जो लो फ्लोर बसें संचालित हैं, वो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं जा रही हैं, उनको आगे रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाये, ताकि जो रोजाना की सवारियां हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, उनको पूरी सुविधा मिले।

सभापति महोदय, और भी कई मांगें हैं, उनको मैं रखना चाह रहा हूं। नसीराबाद शहर जो एक ऐतिहासिक छावनी है, उसको नसीराबाद नगर पालिका में सम्मिलित करने का प्रस्ताव हमारी सरकार के लेवल पर पेंडिंग है, इसलिए जल्दी से जल्दी नसीराबाद शहर को नसीराबाद नगर पालिका में सम्मिलित करें, ताकि वहां की मूलभूत विकास की समस्याएं दूर हो सकें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बजट की प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विकसित राजस्थान का बजट पेश किया है, उसके लिये बहुत-

बहुत धन्यवाद, हमारी वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री भैरा राम जी चौधरी।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, 16वीं राजस्थान विधान सभा के दूसरे पूर्णकालिक बजट 2025-26 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के लोकप्रिय नेता व देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के संकल्पों को साकार करने वाला और ऐतिहासिक बजट प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बेहतरीन व सर्वस्पर्शीय बजट प्रस्तुत कर राज्य की जनता को विशेष सौगात प्रदान कर राहत दी है, जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश ने अद्भुत प्रगति की है और मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपने वर्तमान का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और भविष्य में नई चुनौतियों के लिये समय को तैयार किया है। केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच में डबल इंजन की सरकारों में बेहतर समन्वय से सहकारी संघ वाद की अवधारणा सशक्त हुई है। राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है।

**'जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं,**
**वह हृदय ही नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।'**

**msk/rtm/27.02.25/1400/2c**

भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए विचारधारा व दल से पहले देश है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र हित में निर्णय लेना सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। इसी क्रम में एक राष्ट्र, एक चुनाव की ओर देश आगे बढ़ रहा है, ताकि आर्थिक बोझ के साथ-साथ धन व समय की बचत भी की जा सके। प्रदेश की भाजपा सरकार भी पंचायतों व निकायों के पुनर्गठन के काम को भी सुचारु रूप से कर रही है। प्रदेश के इस बजट में युगपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए एकात्मकता और मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया। हमारे प्रदेश की भाजपा की सरकार ने बजट में माताओं, बहनों, युवाओं, किसानों, मजदूरों सहित तबके के वर्गों का विशेष खयाल रखते हुए जीवन में बेहतर करने का प्रयास किया है। राज्य के इस बजट में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता के उम्मीदों पर हर हालत में खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास कर राज्य के विकास को गति देने के लिए पूरी कोशिश की है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार की जनहित की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चाहे ईआरसीपी हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट 'ए' व 'सी' हो, सहित अनेकों सरकारी स्कीमों को राजनीतिक दुर्भावना के चक्कर में जान-बूझकर रोड़ा, उनको अटकाने, भटकाने का काम किया है। इसी चक्कर में कि कहीं इन

योजनाओं में केन्द्र की मोदी सरकार को क्रेडिट न मिल जाये, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के इस रवैये से दोहरी मानसिकता प्रदर्शित होती है। प्रदेश में भाजपा की भजन लाल जी की सरकार ने पहले ही साल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राइजिंग राजस्थान करवाकर प्रदेश के चहुंमुखी विकास का खाका तैयार कर इस प्रकार की दूरदर्शी सोच का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों ने भाग लिया है, जिसमें 16 देशों ने अपनी पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभायी है। कार्यकाल के पहले साल में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी है। इसी के तहत हमारे विधान सभा क्षेत्र में ओसियां में राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुआ है, वह भी धरातल पर उतरा है। तिंवरी में अपने रीको क्षेत्र में जमीन भी आवंटित हो गयी है और लगभग 45 करोड़ के निवेश से जर्मन कंपनियों की डिफेंस मैन्युफैक्चिरिंग यूनिट भी वहां पर लगायी जा रही हैं, जिससे स्थानीय जनों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

वचनबद्धता पर कटिबद्ध रहते हुए निश्चित समय में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने पहली वर्षगांठ पर चुनाव से पूर्व किये गये वादों पर खरा उतरते हुए पूर्वी राजस्थान के एक दर्जन से अधिक जिलों में पीकेसी और ईआरसीपी के तहत ऐतिहासिक सौगात प्रदान की है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विकास की सर्वांगीण नींव रखी है। इस आधार पर प्रदेश की जीवनदायिनी जो नदियां हैं, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु के कलश में प्रवाहित किया है। इस जल परियोजना के साकार होने से समृद्धि और खुशहाली के नये युग की शुरूआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि की सिंचाई होगी और 3 करोड़ से अधिक की आबादी की पेयजल की जरूरत को पूरी करेगी। 12 हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृत्तियां जारी कर दी गयी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के सीकर, चूरू, झुझुनूं जिलों में यमुना का जल लाने की दिशा में, जबकि राजस्थान और हरियाणा के बीच में केन्द्र की सरकार की मध्यस्थता से पूर्व में हो रखे अपने जल समझौते को लागू करने की राह में भी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, भ्रमित किया है, इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हमेशा अटकाने और लटकाने का काम किया है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेही व प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए वचनबद्धता पर खरा उतरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। अपनी भाजपा सरकार के आते ही जन हितैषी प्रमुख मुद्दों और कार्यों को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। मारवाड़ की जनता भी राज्य सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। पी.के.सी. और ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान के थार मरूस्थलीय जिलों के अन्दर भी डब्ल्यू.आर.सी.पी. (Western Rajasthan Canal Project) योजना लाने की भी मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है।

**म्हारो मरूधर देश,**
**जल उण्डो, थल ऊजलो,**

**नारी नवले वेश, पुरुष पटघर निपजे,**
**म्हारो मरुधर देश।**

जहां पानी हो गहरा, जहां जमीन सोने की तरह चमकदार हो, जहां नारी का वेश हो सतरंगी और वहां का पुरुष हो, बलवान एवं वीर। ऐसी हमारी मरूधरा की धरती है, जहां पर नहरी पानी आ जाये तो यहां के खेत और खलिहान भी प्रदेश के किसानों में सुख-समृद्धि और खुशहाली की राह पर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी हेतु पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के जिलों में डब्ल्यू.आर.सी.पी. लाने हेतु उसकी डीपीआर बनाने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशानुरूप आपके घर-घर नल पहुंचना, लेकिन राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दुर्भावनाओं से जल जीवन मिशन को जान-बूझकर अटका कर रखा है। उनके टेण्डर भी कैंसिल हुए, उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हुए। उनके घोटालों में प्रदेश की साख पर गहरा धब्बा लगाने का काम किया है। इस कलंक से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी भी हुई है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार की दुर्भावना से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दल विशेष की विचारधारा के लोगों की ढाणियों का सर्वे किया है और कुछ ढाणियों को नजरंअदाज किया है। हमारी भाजपा की सरकार आने के बाद में वंचित ढाणियों में पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए पुनः सर्वे करवाकर लगभग आधी से ज्यादा आबादी को ढाणियों में जो डेविएशन, जो विचलन आ रहा है, वह जनता की मांग पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाकर एक बार जो राहत प्रदान की है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

प्रदेश की भाजपा सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में चुनाव से पूर्व किये गये वादों पर खरा उतरने के लिए संकल्प पत्रों और घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ में, राजस्थान की टीम जनता के हर सपने को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत में जुटी हुई है। पहले ही वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत बजट घोषणाओं को पूर्ण कर लिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वधर्म समभाव' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की राह पर आगे बढ़ रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर जाति व वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय जी, दो-चार मिनट और दे दीजिए। पूर्ववर्ती सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को हमेशा अंधेरे में डूबोकर रखा है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है, हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से हमेशा जूझते रहे। हमारी भाजपा की सरकार आते ही, सेवा का दायित्व संभालते ही केन्द्र की सरकार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के साथ समन्वय स्थापित करके कोयले का खनन पुनः प्रारंभ करवाया, जिससे हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानों को 2027 तक खेती के लिए दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे मूर्त रूप देने के लिए

प्रधानमंत्री कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जा दाता भी बन रहा है।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, एक या दो मिनट दे दीजिये। मैं, मेरे क्षेत्र की भी बात करूंगा।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज। समय की पाबन्दी है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): ओसियां विधान सभा क्षेत्र में आपने पिछले बजट में तिंवरी नगरपालिका दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आगे आने वाले में मेरी मांग रहेगी कि मथाणिया और ओसियां, दोनों ही नगरपालिका बन जाये और मांडेखुर्द के अन्दर पीएचसी बन जाये। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के उदयपुर दौरे 2017 के अन्दर 126 किलोमीटर सड़क सोयला से बालेसर की जो घोषणा हुई है, उसकी डीपीआर बन गयी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि उस सड़क के बारे में आवश्यक चिंता करते हुए 126 किलोमीटर नेशनल हाईवे की घोषणा करायें।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये। श्री छोटूसिंह जी।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आपकी शिक्षा की पॉलिसी तो हो गयी, एक कॉलेज का नामांकन होना है, उसको आप थोड़ा जल्दी कराइये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने 2025-26 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आदरणीय सभापति महोदय, यह बजट राजस्थान प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक साहसिक कदम है, यह अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। माननीय सभापति महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों की सोच है कि प्रदेश इस राष्ट्र के अन्दर प्रथम स्थान पर आये। आदरणीय, देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में देश ने अद्भुत प्रगति की है। माननीय, हाल ही में 2025-26 का देश का बजट जन केन्द्रित और विकासोन्मुखी बजट है, समावेशी और विकसित भारत को समर्पित बजट है। आदरणीय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छे लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए इस प्रदेश के औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसको धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के राइजिंग राजस्थान के अन्तर्गत देश और विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से अधिक की राशि के एमओयू हस्ताक्षरित किये हैं।

**mdp/rtm/27.02.2025/14:10/2d**

आदरणीय, हमने आमजन के लिए वादों एवं जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत व बजट

घोषणा की 73 प्रतिशत प्रगति को स्वीकृत किया है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं कि जैसलमेर शहर में विगत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विकास कार्य में हुई देरी एवं बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्ताओं से नागरिकों की दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पडा, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार ने करोड़ों की लागत से शहर के सौन्दर्यीकरण एवं उन्नत विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके लिए मैं ऊजार्वान मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्य मंत्री आदरणीया दिया कुमारी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय, हम सभी का सोच सर्वजन हिताय, प्रदेशवासियों का सर्वांगीण विकास हो। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी व केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने जल जीवन योजना की समयावधि 2028 तक बढ़ाया, इसके लिए सभी प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही, माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी एवं उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में आपने जो मैंने मांगा, वह दिया। क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदरणीय, वैसे देखा जाए तो विद्युत के अन्दर जैसलमेर शहर में चौराहों के विकास एवं डामरीकरण के साथ ही जैसलमेर शहर का विशेष ध्यान रखते हुए, पर्यटन विकास की सोच रखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने इस सोने जैसे शहर के लिए घोषणाएं कीं।

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य आवाज कम करते हुए बात करें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, साथ ही गोल्डन किले के लिए किले का विकास, उसकी पार्किंग की व्यवस्था, शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में हमारे डेजर्ट फेस्टिवल होता है, जिसमें अपरा ट्रेफिक आती है, लेकिन वहां पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण, वहां आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था अंडर ग्राउण्ड की घोषणा की। साथ ही, जैसलमेर का चयन धार्मिक स्थलों की आधारभूत सुविधा के लिए, मां तनोट, जो सीमांत गांव है, उसका चयन किया, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय, विशेष धन्यवाद जैसलमेर के आम जन और आम जननी की ओर से देता हूं कि जैसलमेर शहर एक सीमांत शहर है और राजस्थान के लिए सीमांत एक दीवार के रूप में खड़ा है। हमारे पूर्वजों ने भी इस प्रदेश और इस राष्ट्र के लिए देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसके लिए आपने बहुत बड़ा तोहफा जैसलमेर में बालिका सैनिक स्कूल की घोषणा की है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय, चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय सी.एम.साहब, माननीय उप सी.एम. साहब, आदरणीय मंत्री गजेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जैसलमेर जैसे विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मूलाना ग्राम पंचायत को पी.एच.सी., केजमालता ग्राम पंचायत को पी.एच.सी, जैसलमेर शहर केलिए क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी जैसलमेर को गठित किया, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाले 3 वर्षों के लिए ग्रीन इको सिटी के

रूप में विकसित किए जाने की घोषणा के लिए माननीय सी.एम.साहब, उप सी.एम.साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही, शहर में नवीनीकरण के लिए, हमारे नहरी क्षेत्र की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए, इसके साथ ही और बहुत सारा बजट आपने मेरे जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र को दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत कुछ दिया। विशेषकर मेरे सीमांत क्षेत्र विकास के लिए दूसरे जिलों को 10 करोड़ देते थे और हमारे सीमांत जिले केलिए आपने 15 करोड़ की घोषणा की सड़क निधि के लिए। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सीमांत क्षेत्र है। पूर्ववर्ती सरकार, सबसे ज्यादा समय इस कांग्रेस सरकार का, 2023 व 2024 व 2022-23 जैसलमेर में रहा है। इन्होंने धरातल पर कुछ नहीं देखा। वहां पानी की विकट समस्या थी, वहां बिजली की समस्या थी। बिजली के अन्दर इन्होंने घोषणा कर दी।

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य आवाज कम। बार-बार कहने के बाद भी कर रहे हैं।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): सभापति महोदय जी, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 220 की घोषणा भी की, 132 की भी की, लेकिन जानबूझ कर वहां हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क, डी.एन.पी. जिसके कहा जाता है शॉर्ट नाम में, उसको अंत में किया, जिससे कि उसका काम चालू आज तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं उस 220 को चांदण से होते हुए पास में ही ग्राम पंचायत धायसर के अन्दर बनवाया जाए तो वहां के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, वहां के पेयजल, ट्यूबवेल को भी बढ़ावा मिलेगा।

आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि जलदाय के मंत्री यहां विराजे हैं। जैसलमेर में विकट समस्या जल की है। हमारा शहर जैसलमेर और हमारे गांव आई.जी.एन.पी. केनाल पर निर्भर है। आई.जी.एन.पी. की पूर्ववर्ती जो पाइप लाइन है, वह जगह-जगह डेमेज है। इस कारण जैसलमेर में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं एस्टीमेट आपके सामने सरकार ने भेज दिया। मैं चाहता हूं कि गजरूप सागर, जो पूर्ववर्ती राजशाही समय में तालाब बना हुआ था, वह ऑलरेडी भरा हुआ है, यदि एक महीने का पानी वहां स्टॉक कर दिया जाए तो मेरे जैसलमेर को पर्याप्त पानी मिल सकता है।

आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए, आदरणीय मंत्री जी भी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं यह जो स्कीम आपके विभाग के द्वारा स्वीकृत करवाकर भेजी है, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दें, जिससे मेरे जिले को, मेरे शहर को पानी मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री गोपाल जी शर्मा। प्लीज, बात रखिए।

## सूचना

## ब्यावर के विजय नगर में नाबालिगों से दुष्कर्म व धर्मान्तरण की घटनाएं

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, दो बार के बजट में आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने...

श्री सभापतिः आपने विजय नगर के लिए कोई पर्ची दी थी, उसके बारे में।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बिलकुल, सॉरी साहब।

श्री सभापतिः संक्षिप्त में, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बिलकुल, साहब। आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस घटना ने पूरे देश के अन्दर राजस्थान को कलंकित करने का काम किया। जिस घटनाक्रम के अन्दर घोषित रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल थे। कोर्ट के अन्दर, बयानों के अन्दर नाम आया। इतने बड़े-बड़े नेताओं के नाम आए, जिनके पास महिलाएं गयीं कि उनका नाम लेना हमारे राजस्थान के लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए मैं इतने सीनियर नेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, ब्यावर जिले के विजय नगर में नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए मजबूर और ब्लेकमेल करने की सिलसिलेवार घटनाओं ने प्रदेश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरे राजस्थान में इस जघन्य घटनाक्रम के खिलाफ शेखावाटी से लेकर मेवाड़ तक, हमारे वागड़ से लेकर ढूंढाड़ तक, मतस्य प्रदेश तक सब जगह प्रदर्शन और बंद आयोजित हो रहे हैं और विजय नगर सुलग रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, अजमेर अश्लील कांड की याद दिलाने वाले इस लव जिहादी घटनाक्रम पर आम जनता विधान सभा की ओर टुकर-टुकर देख रही है। वह न्याय चाहती है। राज्य सरकार की सजगता और पुलिस की सक्रियता के कारण कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका कथित सरगना भी पकड़ा गया है, लेकिन वहां से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उस कथित सरगना के कांग्रेस से सम्बन्ध है। कांग्रेस के नेताओं से सम्बन्ध है।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिए।

**Ans/rtm 14.20 2e 27.02.2025**

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): केवल एक वाक्य है। सभापति महोदय, स्थानीय जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, वह अभी न्याय चाहती है। 12 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, 15 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, 27 अपराधियों के चेहरे सामने हैं, इस संगठित लव जिहाद गिरोह को अभियान चलाकर ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह की घटनाओं ने पाकिस्तान बनाया।

श्री सभापतिः श्री पब्बाराम जी।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मिनी पाकिस्तान नहीं बनने दे, नहीं बनने दे। धन्यवाद, आपने यह कहने की अनुमति दी।

## आय-व्ययक

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात राज्य के यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी के लिए चार लाइनों के साथ शुरू करुंगा।

हम इस तरह से हर अंधेरे को मिटा कर सूर्य का पर्याय बनना चाहते हैं,<br>
हम राजस्थान के इतिहास में श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहते हैं,<br>
यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है,<br>
हवा की ओट लेकर भी चिराग जलाया करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प, भारत जब 2047 में अपनी आजादी का 100 वां वर्ष, शताब्दी समारोह मनाएगा तो भारत एक विकसित भारत होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस संकल्प की सिद्धि के लिए राजस्थान भी विकसित बने इस अवधारणा के साथ हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछली 19 तारीख को राज्य की उप मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री राजकुमारी दिया कुमारी जी ने यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट दूरदर्शी सोच के साथ सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। आम लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहला और दूसरा बजट पेश किया गया है ऐसा तो सरकारों के अन्दर चौथा व पाँचवाँ बजट प्रस्तुत किया जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करना चाहती है। शुरूआत के दो बजट ही इस प्रकार के दिये हैं जो राजस्थान के विकास को नये आयाम दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो भी बजट घोषणाएं हुई, चाहे पहले बजट की घोषणाएँ हुईं, चाहे अभी दूसरे बजट की घोषणाएँ हुईं, इन बजट घोषणाओं के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी की इतनी दीवानगी, मैं अचम्भित हूं, मेरे सक्रिय राजनीति के 20 साल हो गए, उससे पहले भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए राजनीतिक गतिविधियों व बजटों पर मैं करीने से निगाह रखता आया हूं, मेरे से सीनियर भी यहां बैठे हैं उनका भी अनुभव है। 19 तारीख को बजट पढ़ा गया और नैक्स्ट सटरडे को ही सभी ज़िलों के प्रभारी मंत्री ज़िलों में गये और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मीटिंग ली और जो भी घोषणाएँ हुई है उनको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है वह सारे फीडबैक लिये। उनके भूमि अलॉटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन की सारी कार्य योजना लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी को रिपोर्ट दी, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी भी सरकार में ऐसा हुआ हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष दूरदर्शिता व संकल्प के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं।

हमारी सरकार सिर्फ वादों की सरकार नहीं है, यह मजबूत इरादों की सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार घोषणाओं की सरकार थी और उनके पहले बजट की अनेक घोषणाएँ आज भी शुरू नहीं हुई हैं, अथवा अधूरी पड़ी हैं।

राजस्थान में जल का महत्व किसी से छिपा नहीं है। हमारे यहां पर कहा जाता है कि यहां घी सस्ता है और पानी महंगा है। ऐसे में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने भागीरथी प्रयास किये और राज्य की कमान संभालते ही, डबल इंजन की सरकार के आते ही, केन्द्र सरकार से ईआरसीपी को स्वीकृति दिलाकर बहु प्रतिष्ठित ईआरसीपी यानी राम जल सेतु योजना को लागू कर बजट अलाटमेंट भी कर दिया, कार्य शुरू भी कर दिया और कार्य प्रगति पर है। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 ज़िले सरसब्ज होंगे और आम लोगों के कंठ की प्यास भी बुझेगी। पिछली सरकार में राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए इस योजना को लटकाना भटकाना कर रखा था। पूरे पांच वर्ष गाते रहे और उन्होंने काम नहीं किया। तीन ज़िले जो मरूस्थलीय कहेंगे झुन्झुनूं, चूरू और सीकर इनमें यमुना जल प्रभावित होगा। यहां की सदियों से प्यासी धरती सरसब्ज होगी। वहां के वाशिंदों को, उनके कंठों को शीतलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

जल जीवन है इसी बात को माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन की शुरूआत की। इन योजनाओं को पिछली सरकार ने बे-पटरी करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया और शुरू भी किया गया तो इस प्रकार से उस योजना को बनाई कि यह प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई योजना में कहीं पर भी पानी नहीं पहुंचे। इस प्रकार का सर्वे किया कि अपनों की ढाणियों को चयनित करना और बीजेपी समर्थक है उनको वंचित रखना ऐसा कार्य किया। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसका पुनः सर्वे कराकर वंचित लोगों को फिर से जोड़ा जाए। मैं प्रधान मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2028 तक इसकी बढ़ोतरी की।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। आपने 60 हजार नौकरियां पिछले सात माह की अवधि में प्रदान की और 01 लाख 25 हजार अगले वर्ष देने की घोषणा की है, युवाओं को आप पर पूरा भरोसा है, आपने कैलेण्डर भी जारी कर दिया।

डिस्कॉम को इन्होंने घाटे में छोड़ दिया। किसानों के लिए जीएसएस नहीं बनाए। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी दीजिए। आपने आते ही मेरे ही क्षेत्र में सात जीएसएस स्वीकृत किए और साथ में एक 32 का जीएसएस स्वीकृत करके मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट में बहुत कुछ मिला है। जांबा से दादरवाला तक की डबल रोड 56 करोड़ की लागत से बनेगी, लोक देवता हडभूजी के लिए पेनोरमा बनेगा, 132 का जीएसएस, न्यायालयों का क्रमोन्नयन, अनेक ऐसी बात है। जयपुर-फलौदी ग्रीन एक्सप्रेस-वे के लिए बजट का आवंटन। हमारा नया जिला है। इन लोगों ने ज़िले घोषित किये परन्तु उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। हमारी सरकार ने... (समय समाप्ति सूचक घंटी) अपन पड़ोसी है, पड़ोसी धर्म निभाएं। दो मिनट।

**VPS-RTM-27.02.2025-14.30-2f**

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): एक हजार करोड़ का जिसमें 125 करोड़ रुपया अपने फलौदी जिले को भी मिलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, समय समाप्त हो गया।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांगें, अपनी बात रखकर अपनी बात को पूरी करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्रीजी को मैंने कुछ लिखित में मांगें भी दी हैं इसके अतिरिक्त फलौदी नगर परिषद की सीवरेज समस्या को हल करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इसको अमृत योजना में सम्मिलित करके इस समस्या से निजात दिलायें और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन भी दिलाये जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के पाइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने सौगातें दीं और साथ ही एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से तो काफी सौगातें दी हैं लेकिन भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय है और सम्भागीय मुख्यालय होने के नाते अभी भी भरतपुर विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है। उच्च शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान वहां पर होने चाहिए और मैं यह बताना चाहूंगा, सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि एन.सी.आर. के क्षेत्र में भरतपुर होने की वजह से, टी.टी.जेड. होने की वजह से इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं आ पाती हैं। जो इंडस्ट्रीज थीं, वह भी बंद हो गयी तो इसलिए भरतपुर सम्भाग को सबसे बड़ी आवश्यकता तकनीकी संस्थानों की है, आई.टी. हब की है और स्पेशल ऐसे हब, इलेक्ट्रॉनिक्स के हब वहां पर घोषित किये जाये जिससे कि भरतपुर के युवा लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं इस मामले में एक बात और कहना चाहूंगा भरतपुर के सन्दर्भ में ही, सबसे बड़ी पुरानी जो समस्या है भरतपुर की यमुना जल समझौता है। 1994 में पांच राज्यों के बीच में, उनके मध्य में यह समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि भरतपुर और डीग जिला, अब जो डीग हो गया है इसको 1281 क्यूसेक पानी मिलना था लेकिन दुर्भाग्य से केवल 800 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है, करीबन 400-450 क्यूसेक पानी मिलना अभी भी बाकी है। यमुना जल समझौते के तहत यह तय हुआ था पांच राज्यों के बीच कि इसकी कोई सहमति हरियाणा से आनी थी, वह हरियाणा से अभी तक भी सहमति नहीं मिली है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने झुन्झुनूं, चूरू और सीकर के लिए जो ताजेवाला हेड से पानी लाने की बात कही है, उसी तरह से ओखला हेड से भरतपुर और डीग को पानी मिले जो कि ड्यू है तो मैं यह समझता हूं कि भरतपुर

जिला उनका बड़ा आभारी रहेगा।

इसी के साथ-साथ मैं बात करना चाहूंगा मेडिकल सैक्टर की। पूर्व की बजट घोषणाओं में लगातार दस सुपर स्पेशलिटीज की घोषणा की गयी थीं, उनको शुरू करने की मांग कर रहा हूं और साथ ही ऊंदरा, गामरी, बरसो और घुस्यारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग कर रहा हूं और साथ ही जाटोली रथवान में, दो जी.एस.एस. दिये हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी। एक जी.एस.एस. की सख्त जरूरत है जाटोली रथवान में उसकी भी आप घोषणा करें। साथ ही सी.एफ.सी.डी. कार्य में जो रुकावट आयी है, उसमें गति लाकर उस काम को भी पूरा करें।

इसी के साथ-साथ मेरे गांव पीपला में अस्थाई पुलिस चौकी बनी हुई है, जिसको पूर्व बजट घोषणा में उसको स्थाई चौकी में कन्वर्ट किया गया था तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि उसको स्थाई भवन के लिए भी बजट आवंटन करें।

इसके साथ, जे.जे.एम. के तहत मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय जल मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं कि जे.जे.एम. की स्कीम को पी.एच.ई.डी. को देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत परेशान है, पंचायतें काम नहीं कर पाती हैं तो माननीय जल मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस जे.जे.एम. को एक निर्णय लेकर, हाई लेवल पर डिसीजन करवाकर पूरे जे.जे.एम. के संचालन का काम पंचायत को सौंपा जाये।

साथ ही, अब मैं थोड़ा सा विश्वविद्यालयों की स्थिति के लिए कहना चाहूंगा कि पेंशन की बड़ी समस्या है। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, वहां के विश्वविद्यालय शिक्षकों को, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, आज भी लोग वहां पर धरना दे रहे हैं तो उनकी मांगों पर भी ध्यान रखा जाये।

इसी के साथ-साथ, एक शब्द जो अभी आपने, अभी हमारा बिल विचाराधीन है। 'कुलपति' और 'कुलगुरु' की व्याख्या की गयी है और कुलपतियों का नाम बदल कर कुलगुरु किया गया है। एक लेख अभी राजदूत में छपा है, मैं उसका जिक्र तो नहीं करूंगा लेकिन सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कुलपति का मतलब क्या होता है, कुलगुरु का मतलब क्या होता है? कुलगुरु स्थाई होता है, कुलपति अस्थाई होता है, उसका भी आप ध्यान रखें।

इसी के साथ-साथ, मैं स्टेट की स्थिति के बारे में भी कहना चाहूंगा कि राज्यों की जो स्थिति है, एक वैश्विक एजेंडा हुआ था 2030 का, जिसमें यह दिया गया था कि कोई पीछे नहीं छोड़ना अर्थात, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, विकास में सबको साथ लेना है लेकिन प्रदेशों में स्थिति क्या हो रही है? माननीय सभापति महोदय, स्टेट की फाइनेंसेज पोजीशन बहुत खतम होती चली जा रही है और जब से जी.एस.टी. लागू हुआ है, सबने लागू किया, उससे राज्यों का स्कोप कम होता चला जा रहा है और जो 14वें वित्त कमीशन ने जो रिकमंडेशन की थी कि डिवोल्यूशन फंड में 42 परसेंट राज्यों को मिलना चाहिए वह 41 परसेंट ही मिल रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात को वित्त मंत्री को उठाना चाहिए कि राज्यों को वह हिस्सा 41 परसेंट की जगह 42 परसेंट मिले।

इसके साथ-साथ, एक बात और कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... असमानता जो हो रही है। रूरल इकोनॉमी पर कितना खर्च कर रहे हैं हम, इसका सर्वे करवाया जाना चाहिए, इसकी एक स्टडी होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर 75 परसेंट पापुलेशन रहती है, वहां पर राजस्थान की सरकार का, प्रदेशों की सरकारों का बजट पर कितना खर्च ग्रामीण क्षेत्र को होता है, शहरी क्षेत्र में कितना खर्च होता है तो मैं एक मॉडल कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 11 हजार से अधिक कुछ पंचायतें हैं, माननीय सभापति महोदय, उन 11 हजार पंचायातों में अगर पांच वर्षीय एजेंडा, सरकार का एजेंडा यह है कि 2047 तक विकसित राजस्थान, जिसमें भारत सरकार का भी एजेंडा है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपके पास करीब-करीब 25 वर्ष हैं, 22 वर्ष है तो 22 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 500 पंचायतों के लिए दस-दस करोड़ रुपये लेकर इंटिग्रेटेड डवलपमेंट प्लान लाया जाये जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नालियां और जल की व्यवस्था कर दी जाये तो प्रत्येक वर्ष केवल 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करना है और मैं यह समझता हूं कि 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद 20 वर्षों में सारे गांवों में मेडिकल की सुविधाएं, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर, जल की सुविधाएं, नालियों का निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था, स्वच्छता का अभियान और मेडिकल के केन्द्र खुल सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा इस सम्बन्ध में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं नगर निकायों की स्थिति पर चर्चा करना चाहूंगा। यह प्राब्लम पूरे देश की भी है कि नगर निकायों को जो बजट मिल रहा है, वह अब 20 परसेंट कम मिल रहा है और सारा दोष सरकार के ऊपर आ रहा है। जो अनुदान मिलना चाहिए था वह अनुदान केन्द्र से 20 परसेंट कम मिल रहा है, 80 परसेंट ही मिल रहा है, यह इकोनॉमिक सर्वे में, राजस्थान सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा है तो मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि निकायों की स्थिति को सुधारा जाये। ग्रांट्स की जो स्थिति है 20 परसेंट, उसको भी लिया जाये और निकायों को मजबूत किया जाये अन्यथा यह नगरपालिका, नगर-निगम तो हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन बजट नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट में, हमारे ऊपर जो ऋण का भार है, अभी पांच लाख करोड़ है, अब वह सात लाख करोड़ हो जायेगा। मैं यह बता रहा हूं कि अगले दो-तीन सालों में दस लाख करोड़ हो जायेगा और इसमें 6 लाख करोड़ तो डिस्कॉम का अलग है। जो डिस्कॉम, कॉर्पोरेशंस उधार लेते हैं, उसको तो हम इसमें बजट का हिस्सा ही नहीं मानते तो उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से यह जो मेजर इश्यूज हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं स्टेट के सम्बन्ध में, उनका अध्ययन करेगी और प्रदेश में जो असमानता की स्थिति, जो गैप बढ़ रहे हैं, रूरल और अरबन इकोनॉमी में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल और अरबन इकोनॉमी में उनको दूर करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. विश्वनाथ मेघवाल।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारीजी द्वारा राज्य का दूसरा शानदार और बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी का। बजट भावी राजस्थान के लिए प्रगतिशील और विकासशील होगा।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो बजट घोषणाएं हुईं, करीबन 4500 घोषणाएं उन्होंने कीं, उसमें से 2000 घोषणाएं बिलकुल भी धरातल पर नहीं उतरीं और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार अब बौखला चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस अभी आपके सामने नहीं बैठी हुई है तो यह इस वजह से है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पिछला बजट दिया है, वह भी एक ऐतिहासिक बजट दिया और वर्तमान जो बजट है, वह भी एक ऐतिहासिक बजट है। यह सिर्फ किसी तरीके से कोई बाहना लेकर विधान सभा को नहीं चलाना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी इन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को बोलने से डिस्टर्ब किया और बिना मतलब की बात करके, फोन टैपिंग की बात करके जबकि फोन टैपिंग का काम तो इनके समय में हुआ करता था। अभी 'दादी' शब्द पर जो इन्होंने जिस तरीके से उस पर बवाल मचाया। हमारे मुख्य मंत्री भी ऐसे रहे हैं जिनको 'मामा' शब्द से पुकारते थे।

**ssy/rtm/**27.02.2025/1**4.4**0/**2g**

हमारे प्रधान मंत्री भी देश में ऐसे रहे हैं जिनको चाचा शब्द से पुकारते थे। दादी एक सम्मान जनक शब्द है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देश के, राजस्थान के विकास के लिए यह कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा होता कि बजट में या राज्यपाल अभिभाषण पर प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष हमारे सामने बोलता तो माननीय मुख्य मंत्री जी अगर किसी प्रकार की बजट में और जरूरत होती तो वह पूरा करते। राजस्थान के विकास में यह भी सहयोग होता।

सभापति महोदय, यह बहुत ही अच्छा बजट है। पिछला बजट जो दिया था वह जुलाई में दिया था। हर विधान सभा को ध्यान में रखकर दिया। यह पहली बार हमने देखा। पुराना जो हमारा बजट है उसका 80 परसेंट क्रियान्वयन भी हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर जिले पर प्रभारी मंत्री और प्रभारी सेक्रेटरी के माध्यम से बजट का इंप्लीमेंटेशन करवाया है। मेरे क्षेत्र में भी खाजूवाला में एसबीएच कॉलेज, ए ईएन ऑफिस पूगल, इलेक्ट्रिकल और नहरों के लिए 100 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये सड़कों के लिए पेयजल के लिए खाजूवाला और पूगल में, 30 करोड़ रुपये 132 केवी जीएसएस दंतोर, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की। केवल

घोषणाएं ही नहीं, उनको धरातल पर उतारने का काम भी राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने किया है। मैं, इसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह बजट सर्वजन हिताय और सर्वांगीण विकास का बजट है। इसमें युवाओं का, बेरोजगार को रोजगार देना, किसानों के हित की बात करना महिला सशक्तिकरण और उद्योग के लिए बजट दिया गया है। माननीय नरेन्द्र जी मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट दिया। 12 लाख की आय तक आयकर में छूट देने का काम उन्होंने किया। केसीसी में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जो घोषणा की है, वह हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत ही अच्छा बजट प्रधान मंत्री जी ने भी दिया था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने युवाओं का जो ख्याल रखा, बहुत ही अच्छा किया है। 60 हजार से अधिक नौकरियां दे दी गई हैं और करीब 15 हजार अभी पाइप लाइन में हैं। 1 लाख 15 हजार पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा है। भर्ती की जा रही है। पेपर लीक की घटनाओं को रोका। इससे युवाओं का सरकार पर भरोसा जगा है। राजस्थान रोजगार नीति, 2025 लाने की भी जो घोषणा बजट में की है, बहुत ही अच्छी बात है। निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों का आयोजन कर 1 लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है।

मैं बात करूं, पीएम किसान सम्मान निधि में भी जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो हमारा संकल्प-पत्र था, उसमें घोषणा थी कि 6 हजार रुपये, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किसान सम्मान निधि की जायेगी। जिसके तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में 2 हजार रुपये बढ़ाये। इस बजट में भी हजार रुपये बढ़ाये हैं। मैं समझता हूं कि किसानों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में इसको 12 हजार रुपये भी किया जायेगा। यह राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत वर्ष में ऐसा एक उदाहरण पेश किया है कि किसान सम्मान निधि को इन्होंने डबल करने की बात की है।

गेहूं की एमएसपी और प्रति क्विंटल बोनस की बात हम करें तो 150 रुपये बढ़ाने की इन्होंने बजट में बात की है। गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण 150 करोड़ रुपये दिया जायेगा। गौशालाओं और नन्दी शालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को आगामी वर्ष 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति दिन किये जाने की घोषणा की गई है। यह बहुत ही अच्छी बात है।

मैं सिंचाई की बात करूं तो राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसीएल ईआरसीपी की जो सौगात दी है, यह बहुत बड़ी सौगात है। इससे 17 जिले लाभान्वित होंगे। सिंचित पानी भी मिलेगा। पेयजल भी मिलेगा। 9416 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। 12064 करोड़ के कार्य की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। 12807 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जा

चुकी हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से यहां आकर सौगात दी है राजस्थान के लिए यह बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की बात होगी।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में धोधा वितरिका, दंतौर वितरिका शाखा, नहर प्रणाली क्षेत्र में 65113 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण कार्य किये जायेंगे। इस हेतु 230 करोड़ रुपये का बजट में मेरी विधान सभा के लिए इन्होंने जो प्रावधान किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक मांग और भी करना चाहूंगा कि सिंचाई पानी का प्रबंधन, वर्तमान में मैं मानता हूं कि पौंग डैम में पानी की कमी है। इस वजह से कुछ दिक्कत है। लेकिन फिर भी बाद में जो फसलें बिजाई की गई हैं, उनको बचाने के लिए प्रबंधन थोड़ा ठीक होगा तो मैं समझता हूं कि किसानों को सिंचाई का पानी मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करुंगा जल जीवन मिशन की जिस तरीके से पिछली सरकार को समय मिला और देश के माननीय प्रधान मंत्री ने हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की बात की। उसको पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उन्होंने जो 3 साल का समय दिया, ऐसे ही व्यर्थ गंवाया। 40 परसेंट से अधिक काम नहीं हुआ। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस योजना को 2028 तक बढ़ाकर, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान को उसका फायदा मिलेगा। 20 लाख घरों को पेयजल के लिए कनेक्शन दिये जायेंगे।

मैं इस मौके पर मेरे क्षेत्र में भी वर्तमान में माधौली के लिए पाइप लाइन और उच्च जलाशय का निर्माण का जो बजट दिया गया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद। अमृत योजना के तहत खाजूवाला में 25 करोड़ रुपये दिये गये और 1 हजार ट्युब वैल और 1500 हैंडपंप दिये जायेंगे। यह भी हमारे क्षेत्र के लिए, सभी विधान सभाओं के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी।

खाजूवाला विधान सभा में भी पीएचईडी ऑफिस खोला गया और पूगल में इलेक्ट्रिकल ऑफिस खोला गया। इसके लिए भी मैं, मेरी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

ऊर्जा के क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान एक आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनने जा रहा है। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में जिस तरीके से कांग्रेस ने निगम की हालत खराब की, उसमें 64 हजार करोड़ रुपये का ऋण चुकाया और अभी 1 लाख करोड़ का जो कांग्रेस ने कर्जा निगम पर किया है, मैं समझता हूं कि बिजली की व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ी है। 6400 मेगावाट के उत्पादन की बात इस बजट में कही गई है। 150 यूनिट फ्री बिजली की बात भी कही गई है। 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के काम हाथ में

लिये जायेंगे।

सोलर पार्क, मेरे क्षेत्र में भी 4 हजार मेगावाट का सोलर पार्क पूगल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है। मैं समझता हूं कि सोलर के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम होगा। 33 केवी जीएसएस पर सोलर प्लांट लगाया जायेगा। जिससे किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली दी जायेगी। यह किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी। आगामी वर्ष में 50 हजार नये कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। यह भी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। खाजूवाला में भी 33 केवी के 2 सब स्टेशनों इस बजट में स्वीकृत किये गये हैं, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आगजनी जैसी घटनाएं हर विधान सभा में होती हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एमएलए लैड से ऐसी राशि स्वीकृत की जाये जिस तरीके से विधायक सेवा केन्द्र खोलने की बात कही गई है, 10 लाख की बात कही है तो वह 25 लाख भी किया जा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं समझता हूं कि एमएलए लैड से यदि आगजनी की घटना रोकने के लिए भी कुछ पैसा दिया जाये तो आने वाले समय में यह भी बहुत अच्छी बात होगी। मेरे क्षेत्र में एक अग्नि शमन वाहन भी उपलब्ध कराया जाये।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट। एक फायर स्टेशन स्वीकृत किया जाये। यह भी मेरी डिमांड रहेगी।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि कुछ डिमांड क्षेत्र की हैं, जिस तरीके से मेरी तहसील छतरगढ़ है, उसमें एक पंचायत समिति की अति आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार यह भी सौगात पूरी करे। 33 केवी जीएसएस जैसे हनुमान नगर, रानेल और जीरो आरडी में, कुछ सड़क के कार्य जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने छोड़े थे वह नहीं हो पाये। उसको दुबारा करवाया जाये।

पेयजल में नाल, भानीपुरा ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री कालूराम जी।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): नहरों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाये। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी विधान सभा डग की जनता की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इन्होंने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को जो बजट में सौगात दी है, इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं पिछली सरकार के बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में इस प्रदेश की जो दुर्दशा की है, वह इस प्रकार है कि आम जन पिछले 5 साल में बिजली से त्रस्त रहा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरूआत की। उसमें राजस्थान को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये दिये। बाकी जल जीवन मिशन को तहस-नहस कर दिया और पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन में हाहाकार मच गया पानी के लिए। आज भी जनता को पानी नहीं मिल रहा। एक साल में माननीय मंत्री महोदय ने काफी कुछ सुधारने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में जो काम हुआ है उसमें आपको एक कमेटी बनाकर के जांच कराने की जरूरत है।

**spp/rtm/27.02.2025/14.50/2h**

कई जगह पर पाइप लाइनें नहीं बिछी हैं तो कई जगहों पर पाइप लाइन फूटी हुई पड़ी हैं, कई जगह पर नल नहीं लगे हुए हैं। आज भी सबसे ज्यादा विधायकों के पास फोन आते हैं तो पानी के विषय में फोन आते हैं। गर्मी का सीजन आ रहा है तो पिछली सरकार ने जो इस जल जीवन मिशन में घोटाले किये हैं, इसको आप पुनः सुधारें और जल जीवन मिशन में आप इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार में एक मिनी फूड पार्क खुला था। उसकी लागत करीब 100 करोड़ थी, परंतु आज दिन तक वह कागजों में चल रहा है। मिनि फूड पार्क अभी तक नहीं बना है। पिछली सरकार ने घोषणाएं की थीं कि हम प्रत्येक पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। मगर आज दिन तक कोई विकास पथ नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ सभी विधान सभा क्षेत्रों में इन्होंने एक एक विकास पथ बनाया, वह भी अधूरा पडा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार का मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं और हमारी सरकार उन कामों को पूरा करने में पूरा सहयोग कर रही है। पिछला बजट, जो 2024-25 का मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मुझे मांगने से भी ज्यादा बजट दिया है। वह इस प्रकार है- डग में सी.एच.सी. से उप जिला चिकित्सालय का खोला गया जिसको वर्तमान में मूर्त रूप दिया जा चुका है और उप जिला चिकित्सालय में सभी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और इसमें चिकित्सा सुविधा भी शुरू हो चुकी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति का छात्रावास डग में खोला गया, जिसकी भूमि का आंवटन हो चुका है। भवानीमंडी में राजगढ़ पेयजल परियोजना से भवानीमंडी को 14 गांवों से जोड़ा गया जिसमें करीब 24 करोड़ 50 लाख की लागत का टेण्डर लग चुका है। डग में महाविद्यालय की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और महाविद्यालय में बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। डग एवं चौमहला में करीब 9 करोड़ रुपये

की लागत से पिछले बजट में जो हमारी टूटी हुई सड़कें थीं, उनका नोन-पेचेबल का काम चल रहा है। करीब 49 किलोमीटर की सड़कों का काम अभी चल रहा है। हमारी सरकार ने एक अटल पथ दिया था। डग में अटल पथ का टेंडर हो चुका है और साढ़े चार करोड़ रुपये का काम अभी चालू हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारी सरकार में पिछली सरकार का जो रूका हुआ काम पडा था चौमेला बाई पास का, जिसका 12 करोड़ 49 लाख का टेंडर हो चुका है और वह काम प्रक्रियाधीन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली माननीय वसुंधरा जी की सरकार में एक पुलिया का, ब्रिज का निर्माण होना था, जो पांच साल से इस सरकार ने रोककर रखा था। अभी वर्तमान सरकार ने कुछ दिन पहले इसका टेंडर जारी करके 18 करोड़ 54 लाख का टेंडर लग चुका है और बहुत जल्दी वह पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी ताकि इससे ग्रामवासियों को इसका फायदा मिलेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये का मिसिंग लिंक और नोन-पेचेबल सड़कों का भी काम चल रहा है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आपने पांच-पांच आंगनबाड़ी खोलने का काम किया, वह भी खुल चुकी है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 हैण्डपम्प और 20 ट्यूबवैल देने का काम किया, वह काम भी पूरा हो चुका है। पिछले बजट में कालीसिंध व चाचूणी नदी पर बांध स्वीकृत किया है, जिस पर 55 लाख की डी.पी.आर. पूर्ण हो चुकी है और उस बांध को बनाने में करीब 01 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बांध का वह काम भी प्रक्रिया में है।

माननीय सभापति महोदय, इस बार बजट में जो मुझे मिला है, बहुत ही अच्छा बजट मिला है। भवानी मण्डी में सी एच सी से उप जिला अस्पताल बनाया गया। सुनेल गोविन्दपुरा से करावल वाया बड़ी एम.पी. सीमा तक एम.डी.आर. 377 करीब 10.35 किलोमीटर का निर्माण कार्य व पुल का कार्य करवाया जाएगा जिसकी लागत 40 करोड़ रुपये है। किशननगर व बैसनगर में माही सिंचाई परियोजना में बांध का निर्माण कराया जाएगा जिससे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। गागरीन बांध से लिफ्ट कृत्रिम जलाशय बनाकर निर्माण व डी पी आर बनाकर किसानों को ड्रिप द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह बहुत ही सराहनीय काम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं और जो बजट में घोषणा हुई है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी और भी मैं कुछ डिमांड आपके सामने रखूंगा, उसको भी इस रिप्लाई में आप पूरी करें।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला यह बजट है। किसानों और युवाओं को और आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट है। इसमें 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों को अटल प्रगति पथ से जोड़ा जाएगा। इसमें हमारे झालावाड़, डूंगरपुर, जैसलमेर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाये जाएंगे और लाखों की सौगातें युवाओं को मिली हैं। सरकारी विभागों और राजकीय उपक्रमों में 01 लाख

25 हजार पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी। निजी क्षेत्र में 50 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिये प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरूआत की जाएगी।

ग्रामीण विकास के तहत मनरेगा के अन्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा और करीब 2 लाख परिवारों को मय पट्टे दिये जाएंगी। समय तो काफी कम है माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ डिमांड रखूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत पीपलिया में चौकी को पुलिस थाना बनाया जाए क्योंकि यहां भवानीमंडी बहुत बड़ा थाना है और इसमें अगर थाना बन जाता है तो यहां पर माइनिंग एरिया भी है। यहां पर करीब 4 हजार लेबर काम करती है, इससे यहां की जनता को फायदा मिलेगा। ग्राम पंचायत आवर में नई पुलिस चौका खोली जाए क्योंकि यह संवेदनशील एरिया है, इसमें बहुत जरूरी है। यहां पुलिस चौकी खोली जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

डग में वन मंडल विकसित किया जा सकता है। यहां करीब 2500 हैक्टेयर भूमि हमारे पास पड़ी है। एक और सबसे बड़ी मांग है पूरे राजस्थान में पशु चिकित्सालय के मात्र 3 कॉलेज हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डग में पशु अनुसंधान केन्द्र है, जिसमें 280 बीघा भूमि पड़ी हुई है और पशु अनुसंधान केन्द्र में वेटेरिनरी कॉलेज चल रहा है। अगर आप उसमें पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना करते हैं तो यह हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय रहेगा। हाड़ौती में एक भी महाविद्यालय नहीं है। इसकी मांग है माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको इसी बजट में जोड़कर रिप्लाई करवायें।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री कालूराम (डग): विधान सभा क्षेत्र डग में 220 के.वी.का जी.एस.एस. खुलवाया जाये। चम्बल नदी और कालीसिंध नदी में संगम पर इंटेक बनाया जाये और कोटा फोर लेन से वाया सुकेत भवानी मंडी तक चौड़ीकरण कर यहां पर टोल रोड है और इस पर आये दिन टोल लग रहे हैं। 10 साल से इस सड़क पर कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है। इस सड़क को या तो फोर लेन या थ्री लेन में किया जाये। डग में घनी आबादी होने के कारण यहां बाई पास दिया जाये। हमारे भवानी मंडी में खेल स्टेडियम बनाया जाये।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): ग्राम पंचायत डग को नगरपालिका बनाया जाये। ग्राम पंचायत चौमहला को नगरपालिका बनाया जाये। यहां की आबादी 15 हजार से ऊपर है। इसमें सभापति महोदय, मैं कुछ पेयजल के लिये एक मिनट देना मुझे।

श्री सभापतिः बिराजिये। श्री संजीव कुमार जी।

श्री कालूराम (डग): मेरे विधान सभा क्षेत्र में माइक्रो डेम या छोटे-छोटे एनीकट जैसे कोलवा गुर्जर और कुरेड़ा जोगा, सेमली, बारापीपली ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। ..(व्यवधान).. हां आप बोलिये।

## सूचना

## पोकरण में बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्मिक की मृत्यु व मुआवजे की प्रदायगी

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पोकरण में बिजली विभाग के एफ.आर.टी. ठेकेदारों की लापरवाही के कारण स्थानीय कार्मिक स्व.श्री मनीष सेन जी की असामयिक मृत्यु हुई है। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से, कि परिवार को उचित मुआवजा मिले और परिवार को न्याय मिले। बड़ी संख्या में लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे तरीके से उनको न्याय मिलना चाहिए।

श्री सभापति: हां, संजीव कुमार जी।

## आय-व्ययक

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, सदन में वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे भी आज वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिनांक 19 फरवरी, 2025 को हमारे प्रदेश की माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी इस पवित्र सदन में जिस बजट को रखा, आज पूरे प्रदेश में जनता उस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का पूरा-पूरा प्रयास किया है।

**jyg/rtm/27.02.25/15.00/2j**

इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे जन प्रतिनिधियों का मामला हो, हर वर्ग के हितों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। मैं इस मौके पर शानदार और ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का व माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे प्रदेश के विकास का सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 से 2018 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार थी तो उस समय सरकार की हमारी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने गांव का गौरव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ का निर्माण किया था, उसी गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी वर्तमान सरकार ने भी 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ प्रत्येक

विधान सभा क्षेत्र में दस-दस करोड़ रुपये की राशि से नोन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराने का निर्णय लेकर निश्चित रूप से सड़कों के मामले में भी एक शानदार काम सरकार ने हाथ में लिया है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान करके निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या का समाधान करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। 1000 ट्यूबवैल और 1500 हैण्डपम्प राजस्थान प्रदेश में लगाने का भी ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में लिया गया है। इसके साथ-साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने जल जीवन मिशन का आगाज किया था, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इस पूरे देश को पेश की थी, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते जल जीवन मिशन के जो आशातीत परिणाम इस प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था उसमें अनावश्यक विलम्ब करके उस काम को चालू करने में भी पिछली सरकार ने देरी की, उसमें अनियमितताएं हुईं, और बहुत से लोगों को पूरे प्रदेश में मैं मेरे जिले के लिए और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगा कि उनकी नीतियों की वजह से बहुत से घरों को, ढाणियों को जल की सुविधा से वंचित कर दिया गया। मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी का कि उन्होंने 2028 तक इस योजना की अवधि को बढ़ाने का काम किया है और इस जल जीवन मिशन योजना में हमारी राजस्थान की सरकार ने भी सम्मिलित होते हुए बचे हुए कामों को पूरा करने का निर्णय लिया है, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, पीएचईडी के मामले में हम कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभांवितों के घरों पर नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाकर 150 यूनिट बिजली प्रति माह नि:शुल्क देना, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक ऐतिहासिक काम है, बिजली के क्षेत्र में इस बजट के अन्दर हुआ है। माननीय सभापति महोदय, तीर्थयात्रा के मामले में हमारे पिछले बजट में भी प्रावधान किया गया, इस बजट में भी 6 हजार वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाने का और 50 हजार तीर्थ यात्रियों के लिए एसी ट्रेन से उनको तीर्थयात्रा कराने का प्रावधान निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम इस बजट में हमारी सरकार ने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, जहां तक, क्योंकि यह हमारा कृषि प्रधान इलाका है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं किसानों के लिए निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि की राशि 8000 से बढ़ाकर 9000 रुपये करके निश्चित रूप से किसान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ-साथ गेहूं के समर्थन मूल्य पर जो बोनस दिया, पिछले बजट में भी प्रावधान किया, बोनस को बढ़ाकर 150 रुपये करने का प्रावधान करके किसान के हितों की रक्षा करने का काम हमारी वर्तमान सरकार ने इस बजट के माध्यम से हाथ में लिया है। जहां तक जन प्रतिनिधियों के मान और सम्मान बढ़ाने का सवाल हो, इस बजट में पंचायती राज और स्थानीय निकाय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उनके मानदेय में भी 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला हमारे

माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से लिया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी अनेक घोषणाएं हुईं, निश्चित रूप से गोगाजी का ऐतिहासिक मन्दिर, गोगाजी का मन्दिर गोगामेड़ी में जो हमारा उत्तरी भारत का बहुत बड़ा श्रद्धा का केन्द्र है, उसमें प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए बेरिकेडिंग और शेड निर्माण करने की घोषणा इस बजट के अन्दर की गयी है। इसके साथ-साथ हमारे भादरा के बहुत ही प्राचीन अन्न-धनजी मन्दिर भादरा की जीर्णोद्धार और उसके विकास के लिए भी इस बजट में अतिरिक्त प्रावधान रखे जाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। हमारे भादरा विधान सभा क्षेत्र के रसराना के उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने का फैसला इस बजट में लिया गया है। इसके साथ-साथ हमारे भादरा विधान सभा क्षेत्र में जो लम्बे समय में हमारे वहां के उपभोक्ताओं की मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए भादरा के विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने के काम की इस सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। मैं भादरा विधान सभा क्षेत्र का विशेष ध्यान देने के लिए भी माननीय वित्त मंत्रीजी का, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से भादरा विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की जो दो-तीन छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनकी तरफ मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे कृषि प्रधान इलाके में सिंचाई का जहां तक सवाल है, अमरसिंह सब-ब्रांच और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का पानी हमारे क्षेत्र में किसान इस्तेमाल करता है, सिंचाई दोनों नहरों से हमारी होती है, उनमें खाळा निर्माण, खाळों की हालत जीर्णशीर्ण है, तो खाळों के नवीनीकरण और उन खाळों को नया बनाने की मांग भी लम्बे समय से है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि खाळा निर्माण के लिए इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं में बजट देने की कृपा करें। इसके साथ-साथ भादरा में एक बाईपास की घोषणा पिछले बजट में की गयी, उसमें कुछ शेष कार्य जो बकाया था, जो भादरा-राजगढ़ से भादरा-साहवा बाईपास, उस बाईपास की घोषणा पिछले बजट में की गयी, अब मैं मांग करता हूं कि भादरा-साहवा से भादरा-नोहर रोड तक इस बाईपास को आप बढ़ाने की कृपा करें। इसके साथ में क्योंकि वहां पर रेलवे की लाइन है, इसलिए वहां पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। शहर भादरा में भी बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रैनेज की स्वीकृति देने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अनिल कुमार कटारा।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय,

**बजट में सिर्फ सपने मिले, हक की रोटी गायब है,**

**सरकार के वादों में बस आदिवासियों की उम्मीद गायब है,**

**मजदूर रो रहा है, किसान खो रहा है,**

**युवा बेरोजगार है, बजट सो रहा है।**

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की इस बजट घोषणा में एक बार फिर से दक्षिणी राजस्थान के किसान, युवा, मजूदर, युवा, आम नागरिक के साथ सौतेला व्यवहार जैसा महसूस हो रहा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा आदिवासी क्षेत्र को मन्दिर का घण्टा समझकर बजाने का ही काम किया है किन्तु आदिवासियों के विशेषाधिकारों को कभी भी संरक्षण प्रदान नहीं किया। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों के प्रति संवेदशील बने, जल, जमीन, जंगल, आदिवासियों की धरोहर है, उनको सुरक्षा प्रदान करे, न कि उनका दोहन करे।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्हें आदिवासियों के वोट तो चाहिए, लेकिन आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई विशेष पॉलिसी लेकर नहीं आयी। आयी भी है तो गांव के अंतिम पायदान तक बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची है।

**MLS/RTM/27.02.2025/15:10/2k**

उसी क्रम में वर्तमान सरकार ने पिछली बजट घोषणा में टीएडी का 1500 करोड़ रुपये का खर्च अभी तक नहीं बताया और इसी बजट में फिर से आदिवासियों को 1750 करोड़ का झुन्झुना पकड़ा दिया। हमारा सरकार से निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्कूल के भवनों के जो हालात हैं, उनकी जो गम्भीर अवस्था है और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में जो हालात हैं, गम्भीर अवस्था है, उन पर सरकार गम्भीर होकर काम करेगी। साथ ही, सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने मेरे चौरासी विधान सभा क्षेत्र में सीमलवाड़ा में कृषि मण्डी प्रदान की, माण्डलई में उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया, करावड़ा में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण किया, जुलाई में जनजाति छात्रावास की घोषणा की और बोर का बाडड़ा चौरासी में तालाब निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए आपने जो बजट दिया है, उस कार्य को जल्दी से जल्दी कराएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही सरकार से हमारी मांग है कि संशोधन बजट में हमारी मांगों को सम्मिलित किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुमाद, चाडोली, सुराता को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करें व चिकली, सीमलवाड़ा को सीएचसी से जिला अस्पताल में क्रमोन्न्त करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकली, सीमलवाड़ा, जोतरी में हाइटेक लाइब्रेरी व कोचिंग की सुविधा प्रदान करें। वहां पर अभी भी छात्रावासों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चिकली, सीमलवाड़ा, जोतरी में नये छात्रावास खोलें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नवीन सहायक निदेशक कार्यालय भी खोला जाये। स्थानान्तरण पॉलिसी में स्थानीय विधायकों में प्राथमिकता होनी चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा महिलाओं का बड़ा ही सम्मान किया जाता है और पुरुषों से पहले स्थान दिया जाता

है। पूरे राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिलाओं का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चौरासी में एक बालिका खेल अकादमी खोली जाये, ताकि हमारे वहां की प्रतिभाएं आगे आएं।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में आदिवासी बच्चों को पोषित करने वाली मां बाड़ी केन्द्रों में 55 हजार बच्चों के मुख से निवाला छीना गया। आटा, पोहा व अन्य सामग्री छीनकर उनकी जो कालाबाजारी हो रही है, इस खेल को बन्द करने में आप सहयोग करें। मैं माननीय सभापति के माध्यम से सरकार और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके दोषियों को सज़ा दें। सभापति महोदय, गर्मियों में पानी की किल्लत आने वाली है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक राजस्व गांव में कुआं निर्माण की स्कीम लाएं।

सभापति महोदय, हमारे उस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, उस पर भी सरकार विशेष ध्यान रखे। अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कहना था, वह कह दिया, अब जनता के दिल में बात जायेगी। सत्ता के गलियारों में गूंज होगी, अब हक की आवाज उठायी जायेगी, अब हक की आवाज उठायी जायेगी। जय जोहार, जय भील प्रदेश।

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, बजट 2025-26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल जी और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने एक शानदार बजट दिया है, इसलिए मैं भजन लाल जी और उप मुख्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा।

आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता बधाई दे रही है कि यह किसानों, गरीबों, महिलाओं, सबका बजट है। इस बजट में सबका ध्यान रखते हुए विपक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिये विपक्ष कोई बात देख रहा था, बिना बात के आज विपक्ष बाहर बैठा है, यह दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह काला अध्याय है। यह इस राजस्थान की विधान सभा को तार-तार करने वाला अध्याय है। प्रदेश की एक पार्टी के मुखिया, जिस तरह इस विधान सभा में एक ओछी बात कहकर उन्होंने आसन का अपमान किया है, मैं इस भाषा के इस्तेमाल की भर्त्सना करता हूं, निन्दा करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रधान भी रहा हूं, मैं प्रमुख भी रहा हूं। मैंने सोचा, मेरे चूरू की जनता ने विधान सभा में 200 में से एक मुझे चुनकर भेजा है तो यहां कुछ सीखने को मिलेगा, पर यहां आकर मैंने देखा है, वहां जब प्रधान था तो मेरी सीट का इतना सम्मान होता था, मैं जिला प्रमुख था, इतना सम्मान होता था, मगर डोटासरा जी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक महोदय कह रहे थे कि मुझे चौथी बार जनता ने भेजा है। विधायक महोदय, यह जनता है। अहंकार रावण का भी नहीं चला और आने वाले समय में आपका भी नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय किसी पार्टी के नहीं हैं, वे इस पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद जिस तरह की भाषा का उपयोग किया

गया...।

हमारे अध्यक्ष जी एक अच्छे शिक्षक रहे, एक अच्छे शिक्षा मंत्री रहे और एक अच्छे विधान सभा अध्यक्ष हैं। उनके बारे में कुछ बोला है तो यह संविधान का अपमान है। मैं कहूंगा, इस संविधान का अपमान, जो इनके राहुल बाबा लेकर घूम रहे हैं न, उसका अपमान है। सभापति महोदय, एक दादी का सम्मान। हमारे यहां विधान सभा में कहा गया, दादी से घर चलता था, बचपन में देखते थे, घर में अगर खाना भी खिलाती दादी तो सबसे पहले बच्चों को खिलाकर सबको खिलाती थी। दादी का इतना सम्मान था। उस पर बवाल करके बाहर गये हैं। मेरी समझ के परे की बात है।

सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का दृष्टिकोण रखते हुए 120 पन्नों का राजस्थान का यह बजट प्रस्तुत किया। विकसित, शिक्षित और खुशहाल राजस्थान बनाने का सपना देखा। बजट में लिखी गयी हर बात को पूरा करने का सरकार का कार्य है, कर्तव्य है। हमारी सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह थोथी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती है। यह देखा भी जा सकता है। हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र में 58 प्रतिशत घोषणाएं केवल सवा साल में पूर्ण की हैं। साथ ही, 73 परसेंट घोषणाएं धरती पर उतारने का काम किया है। कांग्रेस की तरह हम घोषणा वीर नहीं हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 70 साल की आजादी के बाद मेरे चूरू जिले को भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए मरुस्थलीय जिला बनाया है। मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद दूंगा, 70 साल में इस कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था कि चूरू जिला एक मरुस्थलीय जिला बन सकता है। किसान वर्ग से आता हूं। कृषि बजट, पैरा नं. 164 में किसान को किसानी के लिये 110 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा घोषणा की गयी। पिछले कृषि बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा बढ़ोतरी कर किसान की खुशहाली के लिये काम किया है। एक शानदार काम। बात करते हैं, किसान का चोला पहनने वाले कांग्रेसी लोगों को कहना चाहूंगा कि कभी किसान की बात नहीं सोची थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड लाकर किसानों की हालत खुशहाल बनायी थी और उसके बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 6 हजार रुपये किसान सम्मान निधि देकर किसान का सम्मान किया था।

2014 में दे दिया था प्रधान मंत्री जी ने। इनकी तो 2019 से लेकर 2023 तक सरकार रही थी। कभी किसान की बात करते, 100 रुपये देते। हमारे भजन लाल जी की सरकार ने आते ही 2 हजार बढ़ाकर 8 हजार किये। इस बजट में 9 हजार तक किये हैं और आगे आने वाले समय में 12 हजार रुपये करेंगे। यह भजन लाल सरकार गरीब और किसान की सरकार है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिये अनेक काम किये। इस बजट में चूरू जिले में खेल स्कूल खोलने का जो सरकार का निर्णय है, उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, शहर की सड़कों को बनाना तो एक आम बात थी।

**MKD/RTM/27.02.2025/15:20/2I**

गांवों में सड़कों को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने अटल पथ बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा।

पिछली बार हमारी सरकार ने चूरू में रिंग रोड की घोषणा की थी। उसमें पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए मैं और बजट मांगूगा। जयपुर को चूरू से जोड़ने वाला ओवरब्रिज था, वह स्थगित हो गया है। उसके लिए 75 करोड़ रुपये की मांग करूंगा। 5 करोड़ सिकसला के अंडरब्रिज के लिए मांग करूंगा। मिनी सचिवालय के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये की मांग करूंगा।

मेरा पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा के नाम पर कोई नाम नहीं जोड़ा। हमारी सरकार 10 लाख लोगों का नाम जोड़ने का काम कर रही है। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी को और खाद्य मंत्री जी को।

चूरू जिले में फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों की झुकाई हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, यह गम्भीर समस्या है। हमारी सरकार द्वारा यह प्रयास किये गये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने 33 साल पुराना यमुना जल समझौता वापस जिन्दा किया। शेखावाटी अंचल के लिए यमुना का पानी पीने और सिंचाई के लिए ठोस बुनियाद रखी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यमुना के पानी का सबसे बड़ा जलाशय चूरू में बनेगा, जिसके लिए भूमि की तलाश प्रारम्भ कर चुके हैं। वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा के ताजेवाला हैड से पानी चलकर चूरू की धरती पर आयेगा।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 50 वर्ष से अधिक राज किया, परन्तु पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रयास नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्री जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाकर चूरूवासियों को घर-घर पानी देने के सपने को साकार किया है। राजस्थान के 17 जिलों के लिए बनी रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरती पर लाने हेतु 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान करने के लिए सरकार को धन्यवाद।

साथ ही, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जलदाय मंत्री जी को, जिन्होंने आगामी वर्ष में बीस लाख घरों में पानी पहुंचाने के लिए बजटीय घोषणा में 41 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की निविदाएं की हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, चूरू को सीवरेज ड्रैनेज के लिए 3 हजार 450 करोड़ रुपये की योजना में शामिल किया गया तथा बाढ़ के लिए आवश्यक धनराशि की घोषणा की, मैं स्वागत करता हूं।

**(समय : बजे)**

**(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदय, अन्त में, मैं यही कहूंगा कि यह बजट राजस्थान के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसान, गरीब, बेरोजागार, महिलाओं के लिए आने वाले समय

में यह बजट हथियार बनेगा। मैं शुभकामनाओं सहित मुख्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश खींची।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार के आय-व्ययक वर्ष 2025-26 के सामान्य वाद-विवाद पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा में आज मुझे भी आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

यह बजट अपने आप में अनूठा बजट है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला बजट है, जिसको ग्रीन बजट के नाम से अपने आप में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारी उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने 19 तारीख को प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह बजट युवाओं को रोजगार का, युवाओं की ताकत का, किसानों की उन्नति का, महिलाओं के कल्याण का और दलितों के भले का और मजदूरों के लिए बहुत ही हितकारी बजट है।

मैं समझता हूं माटी-माटी पर जाने वाले मरू प्रदेश में माटी का मोल चुकाने के खातिर पहली बार ग्रीन बजट प्रस्तुत होने पर मैं प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री का और वित्त मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। राजस्थान के लाल यानी हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म और मानववाद के संदेश को आगे बढ़ाया और प्रगति और संरक्षण हेतु दीर्घकालीन सतत विकास की नींव रखी।

मैं समझता हूं कि यह ग्रीन बजट योजनाओं पर किया जाने वाले कुल व्यय 11.39 प्रतिशत, प्रदेश को हरित राजस्थान के मार्ग पर ले जाने के लिए ग्रीन बजट पर खर्च किया जायेगा।

महोदय, जलवायु परिवर्तन आज मानव जाति और धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विकास और पर्यावरण के लिए संतुलन रखा जाना, हमसे बेहतर कौन जानता है। हम सब मां अमृता देवी के वंशज हैं, 'जो सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान', इस दर्शन पर विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूं यह बजट 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन के साथ प्रस्तुत किया हुआ बजट है। परन्तु इस विकास की कीमत प्रकृति को नहीं चुकानी पड़े, इसका प्रबन्ध इस बजट में किया गया है। इस बजट में हमारे पूर्वजों का महान दर्शन दिखाई देता है।

इस विजनरी बजट को, मैं समझता हूं माननीय विपक्षी सदस्य सदन में नहीं है। उनके कई सदस्यों ने जीरो बताया, बजट को सिरे से नकारा। मैं समझता हूं प्रदेश के पुरखों की सीख और भावी पीढ़ी को इन्होंने अपने आप में नकारा है, यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने इस ग्रीन बजट को शून्य बताया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, मैं आंकड़ों की गणित में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं शून्य की गणित की थोड़ी समझ जरूर

रखता हूं। आरम्भ का आधार शून्य है, गणित का आभार शून्य है, आत्मा का विस्तार शून्य है, शून्य ही है परम ब्रह्म, जीवन-मृत्यु का सार है। शून्य, हां शून्य है, पर मुझे उन्नत तक जाना है, हर शून्य से बहुमूल्य होने का सफर हम तय करना जानते हैं।

यदि आप सदन में ऐसे नकारात्मक बैठे रहे और दिल्ली में तो आपको जीरो मिल गई, आपने उप चुनाव में भी अपना रिजल्ट देखा होगा, किस तरह से हमारे राजस्थान में जब उप चुनाव हुए, आपको उसमें रिजल्ट मिला। आप बार-बार यह जीरो की बात कहकर अपने आप में, मैं समझता हूं, बहुत गलत बात है।

आपको बजट में सभी आंकड़े शून्य ही नजर आयेंगे। माननीय सदस्य, आपने कभी अपने बजट को नहीं देखा। आपके बजट की क्या स्थिति रही? कांग्रेस ने 5 वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया।

माननीय सभापति महोदय, आप तो पिछली बार थे। मैं समझता हूं कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, 41 से 96 घोषणाएं पांच वर्षों में कीं। उनकी पालना और क्रियान्विति हुई 19 से 12 कार्यों की। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आप में पालना की है। आपने देखा होगा गत वर्ष में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। कोई क्या देगा अपने शासन को जीरो, आपके बजट में कई बार अंग्रेजी माध्यम के 1 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही और उसमें जीरो। आपने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसमें क्या रहा, जीरो। आप हर बार अपनी-अपनी बात करते हो, लेकिन काम में अपने-आप में रहते हो जीरो।

आपने जन घोषणा में भ्रष्टाचार और टॉलरेंस की बात की थी और आपके मुख्य मंत्री जी जब शिक्षक समारोह में स्थानांतरण की बात कर रहे थे, मान्यवर सभापति महोदय, जब इन्होंने शिक्षकों से पूछा कि भाई क्या होता है तो उन्होंने खुलेआम कहा कि भ्रष्टाचार होता है तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षकों के मामले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने अपने आप में किया। मैं समझता हूं इस तरह की शिक्षा और इस तरह की सरकार इन्होंने चलाई, जिसे प्रदेश की जनता अपने आप जानती है।

मैं समझता हूं कि इस तरह की सरकार का अपने आप में नाश हो चुका है, अपने आप विपक्ष में बैठने लग चुकी है। लेकिन आने वाले समय में इनको इससे बड़ा ह्रास होगा। इसमें कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से इनका आचरण, जिस तरह से इनका काम है, वह अपने आप में कोई छिपा नहीं है।

मैं समझता हूं कि जिस तरह से पांच दिन से सदन को छोटी सी बात के ऊपर, जिस तरह से वातावारण को दूषित किया है, वह मैं समझता हूं प्रदेश की जनता अपने-आप में जान गई है। इस बजट पर कुछ बोलने का कोई अवसर नहीं था, बोलने के लिए इनके पास कोई मसाला नहीं था, इसलिए अपने आप में इन सब चीजों को ये जानने लग गये कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए अब कोई न कोई बहाना ढूंढिये और एक छोटे से इश्यु पर, जो इश्यु नहीं है। मैं समझता हूं दादी कहना एक सामान्य सी बात है, कोई इस तरह से असंसदीय भाषा नहीं है। दादी शब्द कहना बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह की

बात करते हैं, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से इनकी नकारात्मक सोच की बात है। प्रदेश की जनता इनको अपने-आप में जान गई है।

माननीय, हरित विकास के लिए आज ढाई सौ करोड़ की जो व्यवस्था की है, परियोजनाओं की घोषणा की है। वह अपने आप में बहुत ही योग्य है। नव भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई एक पेड़, एक नाम के अभियान को आगे ले जाने के लिए 10 करोड़ पौधारोपण की घोषणा, भावी जनरेशन के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करायेगा।

**Bhs/Rtm/27.02.25/15.30/2m**

सूक्ष्म ऊर्जा विकल्प के प्रति जन चेतना जाग्रत करने के लिए पच्चीस हजार सोलर देने की घोषणा किया जाना इस बजट की दूरदर्शिता को बताता है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस वादे को नेक इरादे के साथ दिल से निभाया, बहुत ही अल्पावधि में सरकार ने जन घोषणा में 58 प्रतिशत एवं बजट घोषणा में 73 प्रतिशत वादे निभाये और वित्त बजट की 96 प्रतिशत घोषणाओं को भूमि आवंटन कर मैं समझता हूं कि ठोस इच्छा शक्ति का परिचय माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने आप में और इस सरकार ने दिया।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रदेश की जनता को विकास की गारंटी दी है। इस समय प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ बन कर उभरे मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से राम जल सेतु लिंक परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना में सम्मिलित होने से प्रदेश की नयी उम्मीद जगी है। इससे मैं समझता हूं कि पूर्वी राजस्थान की अपने आप में जो बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या के समाधान हेतु इस माध्यम से हमें पानी मिलेगा।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रमेश खींची (कठूमर): इसमें से 17 जिलों की तीन करोड़ जनता को पेयजल मिलेगा। गत सरकार के कार्यकाल में उत्पन्न जनता की हताशा अब आशा में बदली है। बजट में इस परियोजना में 9,300 करोड़ के कार्य करवाये जाने की बात है जो कि राजस्थान की तस्वीर बदल कर रख देगी। विधान सभा क्षेत्र कठूमर में इस परियोजना का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। विगत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुई खुली लूट ...।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो अभी टाइम नहीं हुआ।

श्री सभापतिः आठ मिनट।

श्री रमेश खींची (कठूमर): विगत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुई खुली लूट से आम जन अब तक घर में नल-जल की प्रतीक्षा कर रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इस मिशन को 2028 तक बढ़ाये जाने पर मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं अपने आप में धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब जन प्रतिनिधियों को भी

निश्चित रूप से इस योजना के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार-प्रसार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको अन्त में यह कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट अपने आप में एक जानदार, शानदार बजट है, लेकिन कठूमर एक बहुत बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील और विनती करना चाहूंगा कि हमारी बहुत प्राचीन नगरपालिका खेड़ली और कठूमर है उनमें निश्चित रूप से ड्रैनेज सिस्टम में पानी के निकास का काम हो और हमारे खेड़ली एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्राचीन कस्बा है उसमें तहसील बने। यही मैं आपसे विनती करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल डेचा। आठ मिनट में अपनी बात कहें।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं धन्यवाद देता हूं मेरी सागवाड़ा की जनता को जिन्होंने मुझे सागवाड़ा एवं बागड़ की बात रखने इस मन्दिर में भेजा है। मैं बजट पर बात करने से पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी के लिए इन पंक्तियों से कहना चाहता हूं,

'हमारा लक्ष्य एक कदम विकास की ओर, अन्धेरे ठहराव से प्रकाश की ओर।
हमें बुजुर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, आओ मिल कर चलें विकास की ओर।
मंजिलों की तलाश में नाउम्मीद न हों, नाउम्मीद से बेहतर चलो विश्वास की ओर।
बेबसी की जिन्दगी जीने से बेहतर है, आओ मिल कर चलें साहस की ओर।
अन्धेरे ठहराव से प्रकाश की ओर, आओ मिल कर चलें विकास की ओर।'

माननीय सभापति महोदय, आज जो हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें मोदी जी का जो मंत्र है, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति के सशक्तीकरण को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूं। साथ ही, हमारे इस दूसरे बजट में किसानों के लिए जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादों को अमलीजामा पहनाते हुए भजन लाल जी की सरकार निरन्तर जनकल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, किसानों की सम्मान निधि, जो हमारा वादा था, हमने निरन्तर बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने 6 हजार से 9 हजार कर दिया जिससे किसानों को फायदा हुआ है। साथ ही, बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार का अनुदान मिलेगा जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, जंगली पशुओं से फसल खराबा होने वाले को तारबन्दी की सीमा भी बढ़ाई है। बेरोजगारों को नौकरी देने के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक लाख पच्चीस हजार नवीन भर्तियां इस बजट में देने के लिए मैं युवाओं की ओर से आपको साधुवाद देता हूं। साथ ही, निजी क्षेत्र में भी एक लाख पचास हजार युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया है जिससे युवाओं में बेरोजगारी दूर होगी।

सभापति महोदय, साथ ही, हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेन्शन 1,150 से बढ़ा कर 1,250 की है, जिससे राजस्थान के बूढे मां-बाप के लिए एक श्रवण कुमार के रूप में पुत्र के अवतार के रूप में आपने आकर सम्बल प्रदान किया है, जिसके लिए हजारों मां-बाप का अशीर्वाद आपके साथ है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा,

'बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती,

सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती।

जो झुक जाये मां-बाप के चरणों में,

ऐसा कोई बेटा भजन लाल ही होगा,

ऐसा कोई बेटा भजन लाल ही होगा।'

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट में बागड़ के मेरे सागवाड़ा के लिए जो सौगात दी है इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। आपने सागवाड़ा में विद्युत की समस्या के समाधान के लिए दो नये जी.एस.एस., दीवड़ाछोटा एवं सागवाड़ा के लिए, सागवाड़ा की जनता बहुत ही खुश है। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में विस्तार के लिए सागवाड़ा में डेचा एवं कराड़ा गांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिये हैं, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की जनता को चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी एवं गांवों की जनता में भारी उत्साह है।

सभापति महोदय, साथ ही, सिंचाई के लिए तो आपने पिटारा ही खोल दिया है। जिसमें सागवाड़ा भीखा भाई कैनाल के पुनरुत्थान के लिए पचास लाख की नवीन डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की है जो नहर कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जीता-जागता नमूना है। जिसने बागड़ की जनता के साथ पिछले पच्चीस वर्षों से छलावा किया और किसानों की इस उम्मीद पर पानी फेरा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आशीर्वाद से पहली बार हमारी सरकार ने इस नहर में पानी लाने के प्रयास किये हैं, परन्तु पहली बार ही नहर जगह-जगह टूट गई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कलई खुल गई, जिन्होंने इस नहर को पैसा खाने का जरिया समझा और घटिया काम कर भारी भ्रष्टाचार किया, उसे पुनर्जीवित करने का काम आपने अपने हाथों में लिया है।

सभापति महोदय, सोम, कमला, अम्बा के अधिशेष पानी को लोढ़ेश्वर डैम तक लाने के काम हेतु नवीन डी.पी.आर. बनाने हेतु पचास लाख की इस बजट में घोषणा की है। साथ ही, खड़गदा रिवर फ्रंट, गोवरेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव के सौन्दर्यीकरण हेतु नवीन डी.पी.आर. बनाने हेतु पचास लाख की घोषणा की है, जिससे सभी धर्मप्रेमी जनता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। विधान सभा क्षेत्र के काटल क्षेत्र में जो सदियों से कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां पर हमेशा शत-प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाली जनता को पिछले सत्तर साल से कांग्रेस ने ठगा और विकास नहीं किया, उस क्षेत्र में जनता के लिए 150 करोड़ की लागत से भुवासा एवं भगेरी माही बेसिन पर बने एनिकट से सोलर जनित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से बीस गाँवों की पन्द्रह सौ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने हेतु जारी किये हैं, जिससे इस

क्षेत्र की जनता एवं किसानों को फायदा होगा। हमारी सरकार ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है एवं जिस जनता को कांग्रेस ने वर्षों तक ठगा उसके लिए आपने पिटारा खोल दिया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल सड़कों के लिए दस करोड़ का प्रावधान किया है जिससे सागवाड़ा की जनता को भी फायदा होगा।

सभापति महोदय, आदिवासी समाज की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने हेतु बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीतामाता अभयारण्य को पर्यटन कॉरीडोर विकसित करने हेतु सौ करोड़ की घोषणा इस बजट में की है, जिससे समस्त आदिवासी समाज आपका आभारी रहेगा। जिस योजना को कांग्रेस सरकार ने पूर्व में बंद कर दिया था उस योजना को आपने अटल गौरव पथ के नाम से शुरू कर ग्राम विकास को प्राथमिकता दी है।

**Kas/rtm/27.02.2025/15.40/2n**

सड़क के विकास एवं समुचित विकास को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया है, जिससे कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के लोगों के पेट में मरोड़ उत्पन्न हो गई है। वो इस बजट को देखकर असमंजस में हैं कि इसकी तारीफ करें या आलोचना करें, क्योंकि जिनका हम पर्ची की सरकार कह कर उपहास करते थे, वो सिकंदर निकला। उसने राजस्थान को 350 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा दिया है। कांग्रेस के कुप्रबंध से आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जो अपनी सरकार बचाने के लिये कई दिनों तक होटलों के बंद कमरों में विधायकों की खरीद-फरोख्त में रहे, उन्हें यह विकास हजम कैसे होगा?

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्षों में से 50 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा। वागड़ में हमेशा से कांग्रेस के विधायक रहे, परन्तु कांग्रेस ने हमेशा वागड़ एवं टीएसपी क्षेत्र की उपेक्षा की एवं हमेशा वागड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। वागड़ में यहां के आदिवासी एवं सामान्य वर्ग को हमेशा प्रतिनिधित्व से वंचित रखा एवं विकास को प्रभावित किया। परंतु जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब-तब वागड़ में विकास को गति मिली है। यहां पूर्व उप राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी एवं वसुंधरा राजे सिंधिया ने विकास के नये आयाम स्थापित किये और वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार ने उसे और गति दी है, जिससे वागड़ के लोगों में आशा की एक किरण जगी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वागड़ को काकरी डूंगरी जैसे जख्म दिये, जिससे आज दिन तक वागड़ का आदिवासी युवा पीड़ित है। उन्हें बरगलाया गया और गलत तरीके से आंदोलन करवाया, जिससे आज वागड़ का आदिवासी युवा कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): उन्हें सही ज्ञान दिया होता तो वो कभी आंदोलन नहीं करते और वागड़ की आम शांति को नजर नहीं लगती। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की कुछ प्रमुख मांगें हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे भेमई

और खुटवाड़ा में 33 केवी जीएसएस की स्थापना हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडवा एवं चितरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना अति आवश्यक है। कई विद्यालय हैं, जिनमें छात्र अनुपात में बच्चों के बैठने के लिये कक्षा कक्षों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां नवीन कक्षा-कक्षो के निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस करता हूं, ताकि विद्यालय प्रभावित न हो, बच्चे प्रभावित न हो।

श्री सभापति: विराजें।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): साथ ही कई विद्यालयों में नये संकाय खोलने के लिये शिक्षा मंत्री महोदय को मैंने लिखित में दिया है, इसकी स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। श्री राजेन्द्र भाम्बू।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): एक मिनट, साहब।

श्री सभापति: विराजिए, समय पूरा हो गया, आपको ज्यादा बुलवा दिया, बैठें। श्री राजेन्द्र भाम्बू।

श्री राजेन्द्र भाम्बू (झुन्झुनू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के वर्ष 2025-26 के बजट के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने के लिये प्रतिबद्ध हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने के लिये हरित राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के संकल्प की तस्वीर 2025-26 के बजट में प्रस्तुत की है। यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण, समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प है। यह समावेशी बजट जन कल्याणकारी एवं सर्व जनहिताय वाला बजट है, जो कि राजस्थान के चहुंमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट राज्य की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

सभापति महोदय, राज्य में विगत कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के आधार पर कार्य कर रही थी। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होटल की सरकार थी, जो होटलों में रह कर कुर्सी बचाने के लिये पेपर लीक के घोटालों में व्यस्त थी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की होटल की सरकार को निकाल कर सत्ता से बाहर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को चुना है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिये जब विगत बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था, तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह कागजी बजट है, जिसे जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। हां, विपक्ष में होने के नाते उनका यह कहना सही भी है,

क्योंकि उनके लिये एक परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। इन्होंने परिवार के विकास को ही राष्ट्र का विकास मान लिया, किन्तु राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भाजपा के घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करने के लिये विगत और इस वर्ष बजट में जनता के कल्याण के लिये अनेक सौगातें दी हैं।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मुख्य मंत्री महोदय व उप मुख्य मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। झुंझुनूं, जो कि जयपुर और दिल्ली का प्रवेश द्वार है, एलसी 265 पर वर्षों से एक आरओबी ब्रिज का कार्य अधूरा पडा था, इस बजट में हमें यह सौगात दी है, जो झुंझुनूं के लिये एक नई सौगात है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य बजट में दिया है। शेखावाटी, जो वीरों की भूमि है और झुंझुनूं पूरे देश में मातृ भूमि के लिये बलिदान देने में सिरमौर है, उनका सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों की नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है। सैनिक पुत्र होने के नाते मैं राज्य सरकार को इस कदम के लिये साधुवाद देता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही बुज़ुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन में वृद्धि करना और उनके स्वास्थ्य का खयाल रखने के लिये 70 वर्ष से अधिक आयु के बुज़ुर्गों के लिये घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करके मुख्य मंत्री महोदय ने उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त किया है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं की भावनाओं को समझते हुए आगामी एक वर्ष में 1 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में व 1 लाख 50 हजार नौकरियां निजी क्षेत्र में दिये जाने का प्रावधान करना, निश्चित रूप से उनके सपनों को पंख लगाने के समान है। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिये राजस्थान रोजगार नीति, 2025 की घोषणा करके शिक्षित एवं विकसित राजस्थान की नींव रखने का कार्य किया है।

सभापति महोदय, राजस्थान में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी शर्मा किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझते हुए, किसानों के कल्याण के लिये किसान सम्मान निधि को बढ़ा कर 9 हजार रुपये किये हैं। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। राज्य सरकार का यह कदम किसानों के आत्म सम्मान एवं समृद्धि को बढ़ावा देगा। साथ ही कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन देने, घरेलू कनेक्शन में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान करके किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। मैं किसान पुत्र होने के नाते किसानों के मसीहा माननीय भजन लाल जी शर्मा का आभार प्रकट करता हूं। राज्य सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए हरित बजट प्रस्तुत करके सतत विकास के लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिये अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जिला प्रभारी मंत्री व जिला अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय लिया, जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि यशस्वी

मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिये अति संवेदनशील हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय और राज्य सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान के विकास की गाथा बजट 2024-25 एवं 2025-26 को लिखते समय विगत बजट में यमुना जल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। विगत वर्ष के बजट की भांति इस बजट में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की जनता का ध्यान रखते हुए उन्होंने उन्हें राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनाते हुए महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। आपने मेरे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बैड क्षमताओं में वृद्धि की है।

**msk/rtm/27.02.25/1550/2o**

इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार करते हुए ग्रास ग्राउंड बनाने की घोषणा की है। शेखावाटी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार करते हुए फ़्लाइंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन की स्थापना का निर्णय मेरी विधान सभा की जनता के लिए विकास का द्वार खोलेगा। झुंझुनूं शहर को मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी योजना में शामिल कर शहर के लोगों को पेयजल की समस्या से छुटकारा दिलाया है। इसके साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शहर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, घर-घर कचरा संग्रहण हेतु व्हिकल ट्रेकिंग सिस्टम का संचालन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय का प्रावधान करके जवाबदेह प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठाया है। मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में न केवल आम जन को राहत पहुंचाने का काम किया है, अपितु अपराधियों में सुधार, पुनर्वास तथा जेल सुधार के लिए जिला जेल में बंदी शिविर पेट्रोल पंप का संचालन कर मानव समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

अंत में, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता आपसे कुछ और आस लगाये बैठी है। उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आशा और अपेक्षा करता हूं और सदन में मेरी मांग रख रहा हूं। आपने विगत बजट में युमना का जल शेखावाटी की धरा तक जल पहुंचाने के लिए डीपीआर निर्माण हेतु बजट प्रदान किया था, उसको धरातल पर लाने की दिशा में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना उचित होगा। साथ ही, मैं मांग करता हूँ कि यमुना जल समझौते में शेखावाटी क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान भी किया जाये। झुंझुनूं नगर परिषद् में सालों साल से निर्माणाधीन ऑडिटोरियम अधूरा है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस भवन को स्वीकृत करके जनता को लाभ पहुंचायें।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है, जो काग़ज़ों में चलकर कागज़ों में ही बंद हो गया है, जिसका नाम है, राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं। इसके लिए 50.58 हेक्टेयर जमीन अर्थात 500 बीघा जमीन विगत काफ़ी समय से दोरासर गांव

आवंटित है। सरकार ने इस खेल विश्वविद्यालय के साथ खेल करते हुए इसका नाम बदलकर राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान कर जोधपुर में स्थापित कर दिया। अतः जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए झुझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की आशा करता हूं। झुंझुनूं चूंकि सेना, सैनिक और शहादत की धरती है। इसलिए मैं बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की भी मांग करता हूं।

इसके अतिरिक्त अधूरे पड़े शौर्य उद्यान का कार्य पूर्ण करने हेतु बजट स्वीकृत करना, कणाना में उप तहसील कार्यालय खोले जाने तथा बग्गड़ में ट्रोमा हॉस्पिटल व बग्गड़ बाइपास के निर्माण की मांग करता हूं। झुंझुनूं में नगर परिषद् क्षेत्र में आधुनिक तरीक़े से ड्रोन से सर्वे कराकर पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक मज़बूत ड्रैनेज सिस्टम विकसित करने के लिए मैं बजट में मांग करता हूं। अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में अर्थात झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और बग्गड़ में महाविद्यालय की कमी है। ये दोनों बातें भी हमारी मानी जाएं। बजट 2025-26 समाज के प्रत्येक वर्ग, युवा, बेरोजगार, जवान, किसान, महिलाओं बुजुर्गों, दलितों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण का वाहक बनेगा। जय जवान, जय किसान। निरालो राजस्थान, निरोगो राजस्थान, हरियालो राजस्थान। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अशोक कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 पर समय प्रदान करने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। प्रदेश की सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ, जो ग्रीन बजट के नाम से जाना जायेगा। जो प्रदेश के आर्थिक एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखेगा, यह एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अगर पर्यावरण और धरा सुरक्षित है, तभी हम भी सुरक्षित हैं। सरकार का यह प्रथम बजट भी बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कई उपलब्धियां रहीं। उसमें राम जल सेतु लिंक परियोजना तो पूरे प्रदेश को समृद्ध बनायेगी और साथ ही, राजस्थान राइजिंग प्रदेश के विकास का नया इतिहास लिखेगा। पिछले बजट की घोषणाओं का 73 प्रतिशत और संकल्पपत्र के 58 प्रतिशत कार्यों की क्रियान्विति इस बात को चरितार्थ करती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं, वह करते भी हैं।

माननीय सभापति जी, वर्तमान बजट एवं इसके क्रियान्वयन हेतु सदन के सामने यह बात बताना चाहेंगे कि 19 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, जिसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा को भी एक 132 केवी जीएसएस मिला था और दिनांक 24 फरवरी को हमारी विधान सभा में जीएसएस लगाने हेतु जमीन भी अलॉट की चुकी है और कार्य हेतु आगे भी पत्र लिखा जा चुका है। यह सरकार की कथनी और करनी को दर्शाता है। बजट घोषणा के मात्र पांच दिन में सब कार्यवाही को करना, सरकार द्वारा वर्तमान बजट की 107 घोषणाओं में प्रदेश के सभी वर्गों को बहुत कुछ दिया गया है और इसकी जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। नवीन बजट में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डवलपमेंट के लिए बड़ा बजट दिया

गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नयी गति मिलेगी। सरकार द्वारा 2 लाख 75 हजार नौकरियों की घोषणा, जिनमें 1 लाख 25 हजार सरकारी क्षेत्र में और 1 लाख 50 हजार प्राइवेट क्षेत्र में, बहुत ही प्रशंसनीय बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप द्वारा किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि में 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करना, आपके किसान पुत्र होने की बात को सार्थक करता है। बजट में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी परियोजना शुरू करने की घोषणा करना, शहर की जन समस्याओं को दूर करेगा और आपके राजस्थान के भागीरथ के नाम को चरितार्थ करेगा। आप द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र 10 करोड़ रुपये और मरुस्थलीय क्षेत्रों हेतु 15 करोड़ रुपये की घोषणा, सम्पूर्ण राजस्थान के आधारभूत विकास हेतु एक अच्छा कदम है। आप द्वारा इस बजट में निकायों की मुख्य समस्या, स्वच्छता, साफ-सफाई और कचरा निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड, प्रोसेसिंग प्लांट, बॉयलर प्लांट, ठोस कचरा संग्रहण आदि की घोषणा करना स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाने के समान है, जो आपके हरित बजट की परिकल्पना को साकार करता है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाने की घोषणा के साथ नंदी से कृषि करने पर तीस हजार रुपये की प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देना, नंदी को रोड पर छोड़ने की समस्या का भी समाधान करवायेगा। आप द्वारा गोशालाओं और नंदीशाला हेतु प्रति गाय अनुदान राशि को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जाना, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस हेतु सभी गोशाला संचालकों की ओर से आपका ह्रदय से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

आप द्वारा अरावली पर्वतमाला हेतु ढाई सौ करोड़ की राशि, हरित अरावली विकास परियोजना हेतु घोषणा और 16 नवीन शहरों को केन्द्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर क्लीन ग्रीन ईकोसिटी के रूप में घोषित करना क्लीन-ग्रीन ईको राजस्थान की तरफ बढ़ते कदम हैं। एक पेड़ मां के नाम, दस करोड़ पौधों का लक्ष्य हरित राजस्थान बनाने में मदद करेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप द्वारा इस बजट में भीलवाड़ा को केन्द्र सरकार की तर्ज पर स्मार्ट सिटी, जो क्लीन एंड ग्रीन ईकोसिटी के नाम से जानी जायेगी, जिससे भीलवाड़ा शहर स्वच्छ, सुंदर व व्यवस्थित हो पायेगा। आपकी इस घोषणा से आपने भीलवाड़ा की जनता का दिल जीता, इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का भी ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं।

भीलवाड़ा वह भूमि है, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान का अवतरण हुआ है। यह शहर 31 हजार करोड़ के टर्नओवर के साथ वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। भीलवाड़ा राजस्थान की जीडीपी में तीसरे स्थान पर आता है, पर भीलवाड़ा के विकास के लिए अभी तक कोई बड़े कार्य नहीं हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि भीलवाड़ा के विकास के लिए बड़ा बजट प्रदान किया जाये। भीलवाड़ा की मुख्य समस्या ट्रैफिक है, इस हेतु भीलवाड़ा को एलिवेटेड रोड प्रदान किया जाये। इसी के साथ भीलवाड़ा में बहुउद्देश्यीय योजना के नाम से एक योजना पहले से ही स्वीकृत है। इस योजना का नामांकन करते हुए

लैण्ड पूलिंग के माध्यम से नवीन हाइटेक सिटी निर्माण की घोषणा की जाये। भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाली कोठारी नदी के रिवरफ्रंट को विकसित कर इसका सौंदर्यकरण इन्दोर की तर्ज पर, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-758 पर 9 किलोमीटर का एक सुपथ कॉरिडोर प्रदान किया जाए, जो कि भीलवाड़ा शहर के सुनियोजित विकास में मदद करेगा। भीलवाड़ा शहर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा की जाये व आप द्वारा हम्मीरगढ़ हवाई पट्टी में सुधार हेतु बजट दिया है। इसी के साथ एयरकार्गो की सुविधा भी दी जाये। भीलवाड़ा में मेडिसिटी परियोजना में 4 लाख 50 स्क्वायर फीट भूमि राजकीय चिकित्सालय हेतु आरक्षित है। उक्त भूमि पर हमारा यह निवेदन है कि भीलवाड़ा की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए टर्शरी कैंसर मय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की घोषणा की जाये, भीलवाड़ा के भामाशाहों या पीपीपी के माध्यम से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करा दिया जायेगा। भीलवाड़ा में 6 लाख 20 स्क्वायर फीट भूमि स्पोर्ट हेतु आरक्षित है, जिस पर सरकार द्वारा एक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिया जाये।

भीलवाड़ा के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु भीलवाड़ा को यूनिवर्सिटी प्रदान की जाये। साथ ही, राजस्थान का एकमात्र टैक्सटाइल कॉलेज एमएलवी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सम्मिलित किया जाए, ताकि कॉलेज का विकास हो सके। भीलवाड़ा में जर्जर पशु चिकित्सालय की अवस्था को देखते हुए एक आधुनिक पशु चिकित्सालय की घोषणा की जाये, जिससे भीलवाड़ा के पशु प्रेमियों को बहुत राहत की सांस होगी। भीलवाड़ा में संभागीय स्तर पर कर भवन आज जर्जर अवस्था में आ गया है और स्टाफ हेतु बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होने से भवन का पुनः नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। माननीय मुख्य मंत्री जी, भीलवाड़ा एक सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण किसानों का पलायन, उद्योगों का पलायन आदि की मार झेल रहा है। भीलवाड़ा, कोटा, टोंक और अजमेर के निकट होने के कारण ईआरसीपी परियोजना का केन्द्र बिन्दु बन सकता है। इस हेतु सम्पूर्ण भीलवाड़ा को ईआरसीपी परियोजना में शामिल किया जाए। इसी के साथ आप द्वारा वर्तमान बजट में चरागाह विकास के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जाने की बात की है, पर जो कार्य नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत नहीं हैं, जैसे बाउंड्री निर्माण आदि को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर या उनके लिए अलग से स्थायी प्रावधान किये जाने की घोषणा एवं बजट आवंटन कराया जाए, ताकि ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर बजट घोषणा की पालना में चरागाह विकास के कार्य करवाये जा सकें। सरकार के इस निर्णय से चरागाह विकास से ग्रीन बजट की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

**mdp/rtm/27.02.2025/16:00/2p**

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि पक्ष के सदस्य अपनी बात मोदी चालीसा से शुरू करते हैं। हम माननीय सदस्यों से कहना चाहेंगे, आपने जो कहा वह सत्य होगा, आपकी यह बात जल्दी ही पूरी होगी। आगे आने

वाले समय में पूरा देश मोदी चालीसा पढ़ेगा। आज पूरा विश्व हमारे प्रधान मंत्री जी को सम्मान देता है। उनमें श्रेष्ठ नेता के सभी गुण हैं। वह देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हम सभी को हमारे प्रधान मंत्री जी पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कई ऐतिहासक निर्णय लिये और असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। वह एक सारथी हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्मयोगी हैं, युग पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। अंत में आपसे कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है-

'कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहां निष्फल होगा,

हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।'

आपने जो समय प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विक्रम बंशीवाल।

श्री विक्रम बंशीवाल (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। यह बजट केवल आंकडो का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य की आर्थिक दिशा और जनता की आशाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में सरकार ने विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रदेश की जनता को अधिक लाभ मिलेगा।

महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व की सरकार की तरह हमारी सरकार लोक-लुभावन वादे नहीं करती, बल्कि जो कहते हैं वह करते हैं। इसी में विश्वास करती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा राजस्थान की शान आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार नित्य नये आयाम स्थापित कर रही है। जो विश्वास हमारी सरकार पर जताया गया है, उसको सही दिशा में ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महोदय, चाहे वह राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट हो, हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसे बखूबी संभाला है और आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बजट का प्रभाव जमीनी स्तर पर पहुंचे। बजट का सही क्रियान्वयन ही असली सफलता है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पिछले बजट की अधिकांश योजनाओं को एक वर्ष के अन्दर ही प्रारम्भ करवाने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बजट में कई जन-कल्याणकारी घोषणाएं की गयी हैं। जैसे राज्य में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारु करने के लिए 5 हजार करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी है। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाना, 20 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, एक साल में 2 लाख 75 हजार सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालना, ट्रेफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनवाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1000 नई बस खरीदना, मां कोष गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों की आंखों की जांच के

बाद फ्री चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन-प्लेन से फ्री धार्मिक यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, जीरो एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर दवा उपलब्ध करवाना, एक साल में 1500 हैंडपम्प और 1000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जन-सुनवाई केन्द्र खुलवाना। ऐसी कई जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश में गत कुछ वर्षों से वर्षा से करीब 21 हजार किलोमीटर की सड़कें नॉन-पेचेबल स्थिति में हैं, जिनको इस सरकार में सुधारने हेतु बजट में 6 हजार करोड़ रुपये का चरणबद्ध रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा में 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा एवं माननीया उप मुख्य मंत्री श्रीमती दिया कुमारी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य में 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ बनाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत मेरी विधान सभा में 8 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है, जो कि अलूदा, पापड़दा, ख्वारावजी, कालाखोह, मानपुर, टोड़ा, उदयपुरा, भरावंडा में स्वीकृत किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा और माननीय उप मुख्य मंत्री श्री दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष की गयी है। साथ ही, हमारे किसानों के लिए गेहूं के एम.एस.पी. प्रति क्विंटल बोनस राशि को 150 रुपये की दर से उपलब्ध कराने हेतु भी प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा कालोखोह बांध और माधोसागर बांध को ई.आर.सी.पी. राम जल सेतु योजना में जोड़ना डी.पी.आर. में प्रस्तावित है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, परंतु साथ में उम्मीद करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सभी नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा तथा डोलीका भंडारी बांध को भी ई.आर.सी.पी. में जोड़ा जावे, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

पिछले बजट में आपके द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 220 के.वी. का एक जी.एस.एस. और 32 के.वी. के दो जी.एस.एस. दिये गये। अब आपके द्वारा 33 के.वी. के दो जी.एस.एस. स्वीकृत किये गये हैं, जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भांडारेज में 33 के.वी. का जी.एस.एस. दिया गया था, जबकि भांडारेज में एक मेडिकल कॉलेज, नगर पालिका और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों की बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 के.वी. की जगह पर 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति प्रदान की जावे। साथ ही, नांगलछापा और गांगदवाड़ी में भी 33 के.वी. का जी.एस.एस. स्वीकृत कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और उप मुख्य मंत्री आदरणीया दिया कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने सिकराय विधान सभा क्षेत्र के आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्यों को बजट में शामिल किया है। विकास के कार्य हमारी सरकार की समग्र एवं समावेशी विकास की नीति की स्पष्ट अवधारणा को दिखाता है।

श्री सभापति: आपस में बातें न करें।

श्री विक्रम बंशीवाल (सिकराय): बजट में सम्मिलित विकास कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लम्बे समय से विकास के कुछ कार्यों की मांग की जा रही है। जैसे सिकन्दरा से अलूदा..

श्री सभापति: कृपया वार्तालाप न करें। सभी माननीय सदस्य, यहां वार्तालाप मत कीजिए।

श्री विक्रम बंशीवाल (सिकराय): सिकन्दरा से अलूदा वाया सराय सड़क का चौड़ाईकरण, जिला अस्पताल दौसा से सयालावास वाया रलावता सड़क का चौड़ाईकरण और नवीनीकरण, नवीन राजकीय महाविद्यालय अलूदा, सिकराय में स्वीकृत करवाना, नवीन बालिका विद्यालय, हींगवा में स्वीकृत करवाना, सिकराय विधान सभा क्षेत्र में कई नवीन सड़कों का कार्य करवाना। सिकन्दरा से एन.एच. 21 वाया बामनपाड़ा मरियाड़ा संवास सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण का कार्य, सिकराय से चांदेरा, सिकराय से उदयपुरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण का कार्य, नांदरी से गरोठा सड़क का नवीनीकरण कार्य, स्टेट हाईवे 25 से मानपुर वाया नामनेड़ डूंगर सिकराय सड़क का चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण का कार्य, बरावंडा से गुमानपुरा शेखपुरा तक सड़क का नवीनीकरण का कार्य, सिकन्दरा को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत करवाना, सिकराय, सिकन्दरा, बरावंड़ा, सराय, ख्वाराव जी, मानपुर में नये खेल स्टेडियम बनवाना, 33 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण नांगलछापड़ और घनरावा और 33 के.वी. के स्थान पर 132 के.वी. जी.एस.एस. भांडारेज में स्वीकृत करवाना, सिकन्दरा में पी.एच.ई.डी. ए.ईएन. कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करना, नवीन स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी में स्वीकृत करवाना, बरावंडा और अलूदा में एस.डी.एम. आफिस खुलवाना आदि ऐसी कई मांगें हैं, जिन पर आप गौर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उप मुख्य मंत्री इनको पूरा करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, सभापति महोदय। सबसे पहले मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा कि मैं उनकी आवाज बनकर इस पवित्र सदन के अन्दर पहुंचा हूं। मैं जब घर से निकला था तो क्षेत्र के लिए बड़ी उम्मीर लेकर यहां निकला था, लेकिन जो उम्मीद और सपने थे, जब बजट को पढ़ा और सुना तो सपने टूटे, उम्मीदें टूटी।

वादों की चादर तान कर सोई ये सरकार,

हकीकत में जनता रोई है बेकरार।

अपना गहरा असंतोष व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर आर्थिक रूप से जूझ रहा है मेरा समाज और वहां का नौजवान। मैं आर्थिक रूप से जूझ रहे उस नौजवान की पीड़ा को आपके सामने रखता हूं। मेरे इलाके के अन्दर शिक्षा व्यवस्था बेहरत तरीके से नहीं है। कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु मैं आपसे सीधे-सीधे शब्दों में सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारे इलाके के अन्दर धरियावाद में कन्या महाविद्यालय और जो महाविद्यालय अभी है, उसको पी.जी. में किया जाए, उसकी सीटें बढ़ाई जाए ताकि हमारे नौजवान जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनको इधर से उधर, महंगी फीस और समय पर छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण, उनको अहमदाबाद, बम्बई में मजदूरी करनी पड़ती है, फीस जुटाने के लिए। प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

साथ-साथ में मैं जलावा के अन्दर महाविद्यालय की भी मांग करता हूं। धरियावद में कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज की भी मांग करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जब परिवर्तित बजट आएगा, इसमें सरकार जरूर इस बात को पूरा करेगी। इस सरकार ने बजट के अन्दर, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, माननीय सभापति, मुझे समय भी ज्यादा देंगे क्योंकि आज विपक्ष है नहीं और राजस्थान के इस सदन के अन्दर तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी है तो शायद समय भी हमको ज्यादा मिलेगा, विपक्ष की भूमिका में।

**Ans/rtm 16.10 2q 27.02.2025**

सभापति महोदय, 1.50 लाख भर्तियों का वादा हुआ था, मैं पूछना चाहूंगा कि वह भर्तियां किस-किस रूप में, कब-कब, कहां होगी? आपने चतुर्थ श्रेणी भर्तियों की बात कर ली, पिछली जो भर्तियां थी उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं थी, इस बार भी बेरोजगार व नौजवाद उम्मीद लेकर रहेगा या ठगा महसूस करेगा? मैं चाहूंगा कि इस बार भर्तियों का स्पष्टीकरण हो।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गरीबों की थाली से निवाला चला गया, बजट आया और फिर सपना खिला-खिला रह गया। यह बजट किसानों के साथ धोखा करता हुआ आया। हमारी कई ऐसी मांगें थीं जो इस सरकार के सामने रखी थी लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई।

माननीय सदस्य बैठे हैं, सब कह रहे थे कि छह घंटे बिजली आती है। मेरे इलाक़े में किसान की यह दुर्दशा है कि खेत में जाकर मोटर चालू करेगा या वापस आएगा जाकर, बार-बार बिजली जाती है, किसान उस मोटर को पकड़कर रोता है। ...(व्यवधान)... यह हालात बने हुए हैं। बिजली की व्यवस्था में आप कठोरतम बात कर सकते हो, इस व्यवस्था को पुरज़ोर तरीके से पूरा किया जाए। यह सच्चाई है जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं।

मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि मेरे इलाक़े में जेईएन ऑफिस मानाडाब के अन्दर खोली जाए, एईएन ऑफिस बुआना के अन्दर स्थापित की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। चरी व खूंटा में घाटा गांव में 38/11 केवी जीएसएस की स्थापना कर ग्रामीणों को

बिजली आपूर्ति कर सहयोग किया जाए। मुंगेरा में विद्युत सब डिविजन की घोषणा की जाए ताकि क्षेत्र में सुचारु विद्युत आपूर्ति हो सके। हमने बुझते चिराग़ों से हवा दी थी, इस मिट्टी को खून-पसीने से सींचा था पर अफसोस इस सरकार ने हमें सूखे सपनों का बीज दिया था।

सभापति महोदय, मेरे इलाक़े में किसानों को जाखम का पानी मिलता है, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होती है। जाखम का डैम बनने के बाद, जो नहरें बनी हुई हैं आज भी वह नहरें वैसी की वैसी हैं, अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। इस बार नहरों का दोर चला था, 2-3 जगह मुंगेरा के अन्दर, नाहर के अन्दर, केसियालात के अन्दर, सादलोक के अन्दर नहरें टूट गई थीं जिससे किसानों को पीड़ा हुई थी। मैं नहरों के लिए उम्मीद लेकर बैठा था कि बजट में कुछ मिलेगा। मैं फिर से उम्मीद लेकर बैठा हूं कि परिवर्तित बजट में नहरों को कुछ ना कुछ मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वहां थोड़े दिनों पहले एक बेटी सुशीला क्रिकेट के नाम पर वायरल हुई थी, सबने साथ में फोटो खिंचवाई। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने धरियावद को खेल स्टेडियम दिया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक अकेली सुशीला पारीक ही हमारे यहां टेलेंट नहीं रखती है, ट्राइबल क्षेत्र में आपको कई तीरंदाज मिलेगे, कई तेज दौड़ने वाले मिलेंगे, कई तैराक मिलेंगे, कई ऐसे टेलेंट मिलेंगे जिनको निखारने की जरूरत है। धरियावद के साथ-साथ मुंगेरा में भी खेल स्टेडियम होना चाहिए, जलारा के अन्दर भी खेल स्टेडियम होना चाहिए, लसाडिया के अन्दर भी खेल स्टेडियम होना चाहिए ताकि प्रतिभाएं आगे आये और देश-दुनिया में आदिवासी अपना नाम कमा सके।

सभापति महोदय, आपने बजट घोषणा में 65 करोड़ की सड़कें हमारे धरियावद विधान सभा क्षेत्र में दी है, मैं आपकी सरकार को पुन: एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि धरियावाद से बांसवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क को स्टेट हाईवे में लिया जाए। धरियावद से बांसवाड़ा की ओर जाते हैं तो नरवाली के अन्दर माही नदी पर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है जो नीचे की ओर है और बहुत पुराना है, बारिश के समय जब पानी ऊपर से आता है तो यहां यातायात बाधित होता है, 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है उस इलाक़े को पार करने के लिए, मैं परिवर्तित बजट के अन्दर उम्मीद करता हूं कि आप हमें पुल निर्माण के लिए अलग से बजट दें। कई ऐसी सड़कें हैं जो रह गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वह सड़कें हमें मिले।

लसाडिया ब्लॉक में कन्या महाविद्यालय खोला जाए। साथ ही बिलडिया जरना से वननाका लसाडिया वाया पीपाला, पीपालापानी गांव है, बहुत पुरानी सड़क की मांग है, उसको पूरा किया जाए। जलारा में धोलपुरा से बैंसा तक डामर सड़क और मालपुर से पूकडा पडवा बुडेर से केलाकुआ सड़क, मोहिया से सर्वणी सड़क, उम्मीद करता हूं कि इस परिवर्तित बजट में इन सड़कों को जोड़ा जाए, जिससे आम जीवन सुरक्षित महसूस कर सके।

आज हम सब चाहते हैं कि आदिवासी पढ़े-लिखे और आगे बढें, लेकिन पूरे ट्राइबल क्षेत्र में 80 परसेंट व्याख्याताओं के पद खाली हैं। मैंने स्कूलों की हालत देखी थी, हर विद्यालय के भवन जर्जर हो रहे हैं, तो उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है। इस बार स्पष्ट करें कि आप

विद्यालय के लिए, शिक्षा के लिए कितना बजट उस इलाक़े को देना चाहेंगे? जब 80 परसेंट व्याख्याताओं के पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली है, हर विद्यालय में भवन की आवश्यकता है, तो कैसे शिक्षा में आदिवासी आगे आएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बजट देगी, व्याख्याताओं की पूर्ति करेगी।

शिक्षकों की जो पीड़ा है वह सदन में आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। थर्ड ग्रेड शिक्षक के ट्रांसफर की पीड़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई ठोस नीति लाकर थर्ड ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर करेगी, ताकि उनको राहत मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, जिनके हौसले बुलंद हैं वह चांद तक जा पहुंचे है, पर जिनके गांव में टॉवर नहीं है वह अभी भी पत्थर के युग में जी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाक़े में पहाड़ा, बीरावल, सती और उसके अलावा बिल्ड़िया, पड़वा ऐसे कई इलाक़े हैं जहां आज भी टॉवर नहीं हैं। हम लोग योजना बनाते हैं जियो टैगिंग के नाम पर, वह योजना उन तक कैसे पहुंचेगी? सभापति महोदय, शायद मैं अंतिम वक्ता हूं तो मुझे थोड़ा समय दिया जाए। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, हमारा आदिवासियों का मानगढ़ धाम है जो शहीद और खून से सिंचित आदिवासियों के पराक्रम को दर्शाता है। हमारे आदिवासियों की वर्षो से मांग थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, ताकि वहां के शहीदों को सम्मान मिल सके। मानगढ़ धाम पर जलियावाला बाग़ से भी भंयकर घटना घटी थी। यदि इसको राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाता है तो आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम होगा।

सभापति महोदय, मैं छोटा-सा एक और निवेदन करना चाहूंगा। गांव के अन्दर सबसे निचले, पिछड़े स्तर के जो लोग हैं, विद्यालय में, आंगनबाड़ी में माताएं-बहनें खाना बनाती है, हमें जितना यहां फोन के लिए पेमेंट मिलता है उतना बजट उनको इस महंगाई के जमाने में मिलता है, तेल, नमक, मिर्च कैसे खरीदे, उनका बजट बढ़ाया जाए। नरेगा के अन्दर 200 दिन किया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके। उनकी तनख्वाह नरेगा में 500 रुपये की जाए, ताकि उनको सम्बल प्रदान हो सके। नरेगा मेट को परमानेंट तनख्वाह दी जाए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनकी आंखों की स्क्रीनिंग भी होती है। जब कोई मेट जेठ जी है तो बहु आंखों को कैसे आगे दिखा सकती है। मजदूर की आंखों की स्क्रीनिंग, हमारे भी आंखों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हमारे साथ हर विभाग की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, नरेगा के मजदूर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे, उन राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से बहाल करके..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजे।

श्री थावर चन्द (धरियावद): लास्ट मांग है। मेरी विधान सभा में सीता माता वन अभयारण्य है, हमारे इलाक़े में बहुत बड़ा जंगल है, गर्मी के दिनों में कहीं ना कहीं आग लग जाती है, कई ग़रीबों के आशियानें उजड़ जाते हैं, ऐसे में हम लोग यह मांग करते हैं कि

अग्निशमन की घोषणा की जाए। धरियावद विधान सभा में फायर ब्रिगेड दिया जाए।

श्री सभापतिः आप विराजें। श्री कुलदीप।

श्री थावर चन्द (धरियावद): एक शायरी बोल देता हूं।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): हम चले तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी, सागरों की बात क्या,

श्री सभापतिः विराजिये। श्री कुलदीप।

श्री थावर चन्द (धरियावद): चल पड़ेगे, हम अगर सब साथ, तो दीप क्या सूरज ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब की बार शानदार व जानदार बजट के लिए राजस्थान के यशस्वी नेता लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा, वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता का, हर कौम का आपने ख्याल रखने का प्रयास किया है। विपक्ष गायब है, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं-

अच्छे कर्म किए होते तो हॉफ नहीं होते,<br>
दिल्ली में पूरी तरह से यूं साफ नहीं होते,<br>
परिवार की गुलामी में राज्य को भूल गए,<br>
ऐसे गुनाहगारों के गुनाह कभी माफ नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, 2018 से 2023 के बीच गत कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत जी की सरकार में जितने बजट की घोषणाएं हुईं मैं उनका अध्ययन कर रहा था।

**VPS-RTM-27.02.2025-16.20-3a**

मैं कुछ ऐसे विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2020-21 में इनकी सरकार में 364 योजनाओं को स्वीकृत किया गया था पर मात्र 261 योजनाओं का ही काम हुआ, बाकी उस काम को पूरा नहीं कर पाये। 2021-22 में 951 योजनाएं इन्होंने स्वीकृत की थीं जिसमें से मात्र 601 योजनाओं पर ही पूरा काम ये कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में तो 1028 योजनाओं में से मात्र 481 योजनाओं पर ये काम पूरा कर पाये और 2023-24 में जो कि चुनावी वर्ष था, बड़ी ताल ठोक कर इन्होंने घोषणा की, 1426 योजनाएं इन्होंने स्वीकृत कीं, जिसमें से मात्र 284 योजनाओं पर ही ये काम कर पाये, तो यह बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। ये पांच साल तक केवल एक विषय को लेकर घूमते रहे। राजस्थान की ई.आर.सी.पी. को, हमारी भारत सरकार को, हमारी

पार्टी को पानी पी-पीकर ये गाली निकालते रहे, तंज़ कसते रहे, कोसते रहे, पांच साल में एक रुपये का भी काम नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने इनके कुछ परसेंटेज के आधार पर आंकड़े निकाले हैं, उसमें टोटल इनकी योजना जो स्वीकृत हुई थी 4148, उसमें ये काम कितना कर पाये? 1935 और मात्र इन्होंने 47 परसेंट काम किया। यह राजस्थान के लिए जो हमेशा करते हैं, ये बारबार हमारी पार्टी को कोसते रहते हैं। यह दादा-दादी का विषय नहीं है, यह विषय आंख में आंख मिलाकर आमना सामना करने का विषय है। जब इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई विजन नहीं है तो मैं इतना ही कह सकता हूं इस सदन को वे इसलिए छोड़कर चले गये कि उनके पास राजस्थान को लेकर और राजस्थान की जनता ने जो इनको मैनडेट देने का काम किया था, उसका अपमान करने का काम किसी ने किया है तो विपक्षी दल ने किया है।

तो इसलिए, महोदय, अगला मैं जो विषय रखना चाहता हूं, जो प्रगतिशील कार्य थे, जो इन्होंने प्रयास किया था, उसमें भी मात्र 35 परसेंट काम ही ये कर पाये यानी, किसी बच्चे को एग्जाम में पास होने के लिए 36 परसेंट मार्क्स चाहिए लेकिन एक परसेंट मार्क्स उनके इसमें भी कम रहे, ऐसी हालत कांग्रेस की सरकार की रही।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारे मेरे पास इनके डाक्यूमेंट भी हैं, आंकड़े भी हैं। बहुत सारे विषय, राजस्थान में इनकी सरकार के समय जो बिजली का मुद्दा हमेशा छाया रहता था, अंधकार में राजस्थान डूबा। किसान को, कंज्यूमर को, आम आदमी को बिजली चाहिए लेकिन मैं बिजली के सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने छबड़ा में 1320 मेगावाट का वहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए इन्होंने अपने बजट में कहा था। कालीसिंध में 800 मेगावाट, बाड़मेर में 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन की बात इन्होंने कही थी। कुल मिलाकर 3220 मेगावाट बिजली उत्पादन की बात कही थी अपने बजट में लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक पर भी ये उत्पादन का कार्य नहीं करवा पाये, इस कारण से राजस्थान की यह जनता पांच साल तक अंधेरे में डूबती रही।

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उद्योग विभाग के मैंने कुछ आकड़े उठाये हैं। इन्होंने जितने उद्योग विभाग में, विकास कैसे सम्भव हो सकता है जब तक राजस्थान का विकास नहीं होगा, जब तक खेत और खलियान का विकास नहीं होगा, जब तक गांवों में उद्योग नहीं लगेगा तो राजस्थान का विकास भी कैसे संभव है? लेकिन मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट अपने बजट में घोषित किये। 2021-22 में 31 ऐसी परियोजनाएं इन्होंने उठाईं और साथ में 2023-24 में 31 औद्योगिक क्षेत्रों की इन्होंने घोषणा की थी, तो कुल मिलाकर 71 इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जिसका एक का काम भी ये प्रारंभ नहीं कर पाये। यह इनके कार्यकाल के मैं नमूने बताना चाहता हूं।

महोदय, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं पानी को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थान पानी के संकट से बहुत त्रस्त है। मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर से आता हूं जहां पर

वास्तव में पीने का पानी नहीं है। हम जब एक हजार फीट तक भी बोर करवाते हैं तो वहां पर पानी नहीं निकलता है और जे.जे.एम. योजना जब चली, भारत सरकार के, हमारे देश और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदीजी ने जे.जे.एम. के अंतर्गत हर घर तक पानी पहुंचाने का एक फैसला, संकल्प लिया था और उस फैसले को आगे तक पहुंचाने का प्रयास भी किया लेकिन पांच साल तक कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोतजी की सरकार में इसमें जितना करप्शन हुआ, अगर इसकी जांच प्रोपर तरीके से हो जाये तो इनका एक नेता और एक अधिकारी बचे नहीं, इस प्रकार का जे.जे.एम. में आपके घोटाले हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जे.जे.एम. के कामों की हालत तो जैसी रही, उनकी जांच भी चल रही है, कुछ विषय, ऐसे सेंसेटिव बिंदु भी है जहां पर बड़े-बड़े इन्होंने काम घोषित कर दिये। उधर मैं झुन्झुनूं जिले की बात करना चाहता हूं। 4765 करोड़ की एक योजना थी। उदयपुर संभाग में इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं इन्होंने स्वीकृत कर दीं 4674 करोड़ रुपये की, इसके अलावा बहुत सारी परियोजना, इसमें एक योजना पर भी इन्होंने काम नहीं किया। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, इस कांग्रेस ने जो किया उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने 2023 के चुनाव में दिया।

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, हमारे मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान अंधेरे में डूबा था, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, आखिर में यह दोनों सरकारें इनकी थीं फिर भी ये बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाये। वहां से कोल लाने में भी इनको समस्या हो रही थी लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय भजन लालजी शर्मा के बनने के बाद हमने यह व्यवस्था की और राजस्थान में कोल की व्यवस्था की तो उसके कारण से राजस्थान में आज बिजली उत्पादन का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने लगातार पांच साल तक इतने पाप कमाये हैं, अगर मैं उन पापों का जिक्र करूंगा तो मेरी बात समाप्त नहीं होगी लेकिन मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं-

कभी तो हिंदू होने का फर्ज निभा लेते,
राष्ट्र प्रेम में डूब कर काई नारा लगा देते।
दरगाह पर जाना ठीक है वोट बैंक के लिए,
पर हिंदू बनकर एक बार कुंभ तो नहा लिये होते।

मैं उनको यह सलाह भी देना चाहता हूं कि जो पांच साल में उन लोगों ने पाप कमाये हैं, उस पर उनको कुछ पुण्य करने की आवश्यकता भी थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार में हमने राजस्थान में बिजली का उत्पादन अच्छा हो, हमारी सरकार ने, प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने एक संकल्प लिया है। हमारे प्रदेश के किसान को और हमारा जो देशवासी, यह प्रदेशवासी

है, उसको दिन में बिजली कैसे मिल सकती है? 2027 तक हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम दिन में बिजली किसान को और कंज्यूमर को देंगे। इतनी बड़ी योजना बनाकर हमारी सरकार ने आवश्यकतानुसार लगभग 3325 मेगावाट कोयला आधारित एवं 28,500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से उत्पादन करने के लिए और साथ ही साथ मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 35,138 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए, अब कितना बड़ा बजट, 1 लाख 58 हजार 800 करोड़ रुपये और साथ ही प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के साथ पावर ग्रिड के माध्यम दस हजार करोड़ का एम.ओ.यू. हमारी सरकार ने किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज तक राजस्थान के इतिहास में बिजली विभाग का सबसे बड़ा एम.ओ.यू. यह है। मैं भजन लालजी शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए, ये कांग्रेस के लोग हमेशा किसान के नाम पर राजनीति करते आये हैं, हमेशा किसान को गुमराह करके वोट मांगते आये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गये और 75 साल तक ये कहते रहे और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान का किसान बहुत ही भोला-भाला है। यह किसान इस धरती माता का सीना चीर कर अनाज पैदा करने का काम कोई करता है तो हिंदुस्तान का यह किसान करता है और हमारे हिंदुस्तान की जनता का पेट पालने का काम भी हिंदुस्तान का किसान करता है। उसके नाम पर ये राजनीति करते रहे। किसान को कभी दिया नहीं, किसान का कभी सम्मान किया नहीं। इनकी सरकार में सैकड़ों किसान भाइयों ने आत्महत्याएं की थीं, किसान के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्रीजी को और राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लालजी शर्मा को जिन्होंने किसान का सम्मान करने का काम किया। मैं एक बात कह सकता हूं कि नौ हजार रुपये से उसका घर तो नहीं चल सकता लेकिन, माननीय सभापति महोदय, नौ हजार उससे भी ज्यादा है जिससे एक किसान का सम्मान करके उसको उसके विकास को आगे बढ़ाने में किसान के लिए सार्थक होगा, ऐसा सम्मान हमारी सरकार ने करने का प्रयास किया है।

महोदय, हमेशा यह कहते थे कि हमारे किसानों की फसलों का बीमा करेंगे, उस पर भी कांग्रेस हमेशा राजनीति करती रही लेकिन उन्होंने कभी किसान का सम्मान किया नहीं। हमारी सरकार ने किसानों की फसलों का बीमा भी किया और पी.एम. किसान सम्मान निधि के साथ-साथ यह फसल बीमा भी चलता रहा और साथ-साथ स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आप भी किसान के बेटे हो, आपने भी देखा है। आप कोटा क्षेत्र से आते हो। जब जमाबंदी की नकल लेने के लिए जाते थे तो इनके शासन में तब भी किसान को ठगा जाता था, लूटा

जाता था लेकिन हमारी सरकार ने, भजन लालजी शर्मा की सरकार ने ये सारी चीजें ऑनलाइन कर दीं। इसमें हमारे किसान को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना हूं कि आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करने का हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं किसान होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते भजन लालजी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया। किसान को क्या चाहिए? एक पीड़ित व्यक्ति को क्या चाहिए? मैं आपको छोटे-छोटे नमूने बताना चाहता हूं। किसान को चाहिए अपने फार्म पोंड बना ले, अपने डिग्गियों का निर्माण कर ले, अपने पम्पसेट लगा ले, अपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा ले।

**ssy/rtm/**27.02.2025**/**1**6.3**0**/3b**

उसमें हमें कुछ अनुदान मिल जाये, कुछ पाइप लाइन मिल जाये। हमारा किसान यही चाहता है। वह किसान तो पहले ही मरा पड़ा है। पानी सूख गया, जो धरती हरी-भरी हुआ करती थी, आज वह मिट्‌टी सूखी पड़ी है। वह धरती माता प्यासी पड़ी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है, राज आते हैं और राज जाते हैं, लेकिन इस समय को हमेशा याद किया जायेगा। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सानिध्य में राजस्थान में आपने एक इतिहास कायम किया है।

प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने भागीरथ बनकर जो पुरानी ईआरसीपी हुआ करती थी, उसको राम जल सेतु लिंक परियोजना बनाकर राजस्थान में एक इतिहास रचने का काम किया है। मैं इतना कह सकता हूं, अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि किसान को पानी नहीं मिल पाता। मेरे पड़ोसी साथी हैं, जमवारामगढ़ से विधायक बनकर आये हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रामगढ़ बांध को जोड़ा गया है। मैं इनसे कह ही रहा था कि एक साल बाद आप भी जुड़ जायेंगे और 3 साल के अन्दर-अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मेरे विराटनगर के 3 बड़े बांधों को भी जोड़ने का काम किया है, मैं भी जुड़ जाऊंगा।

सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि जब इन बांधों में पानी आयेगा तो राजस्थान का किसान हरा-भरा हो जायेगा। जब राजस्थान का किसान हरा-भरा होगा तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के विकास में हमारा साझा होगा। हिन्दुस्तान की तकदीर बनाने में राजस्थान का किसान बड़ा उपयोगी रहेगा। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, इन्होंने ऐसा काम भी किया, आज आपको हालात का पता है। राजस्थान में कांग्रेस के समय में कृषि कनेक्शन जारी होते थे, बजट में हम सुनते थे, लेकिन जमीन पर उनकी कोई क्रियान्वित होती नहीं थी। मैं 24 घंटे गांव में और ढाणी में रहता हूं। मैं देखता हूं, काश्तकार मेरे पास आते थे कि, भाई साहब, कुछ हमारी मदद करिये। 5 साल में जो इन्होंने बजट में कृषि कनेक्शनों की घोषणा की, उनको जमीन पर उतार नहीं पाये। हमारी

सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने 1 लाख 10 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन देने का जो काम किया है, वह राजस्थान का इतिहास रचने का आपने काम किया है।

साथ ही, ऐसे छोटे-छोटे बिन्दु, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमेशा सनातनी बनकर आपने संगठन में काम किया है, इस व्यक्ति को सब चीजों का ध्यान है, ऐसे छोटे-छोटे विषयों को आपने जोड़ने का काम किया है। जैसे मुख्य मंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत आपने निशुल्क सोलर प्लांट लगाकर 145 यूनिट्स बिजली प्रति माह निशुल्क देने का फैसला आपने किया। ऐसे बहुत सारे हैं।

मैं 2 बातों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। विकास के पथ पर अवरोध जायज नहीं, करना यूं बात-बात पर क्रोध जायज नहीं। विचारों को विचारों से मात दीजिये, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना जायज नहीं। विपक्ष खाली पडा है।

महोदय, अभी मैं राम जल सेतु की बात कर रहा था। 9416 करोड़ रुपये की स्वीकृति निकल चुकी है। 12,064 करोड़ की निविदाएं जारी हैं। 12,807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी होगी। मेरे ऐसे पुराने साथी, बराबर के पड़ोसी इलाके से आते हैं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि आपका इस सेकण्ड फेज में काम होने वाला है। मैं आपके बाद जो अगला फेज आयेगा उसमें जुड़ जाऊंगा।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जेजेएम की मैंने बात रखी, जेजेएम का जिक्र तो मैंने पहले कर भी दिया, लेकिन जेजेएम के लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जेजेएम की लगभग 120 योजनाएं अभी निर्माणाधीन पड़ी थीं, लेकिन उस पर एक कोर्ट स्टे आ गया किसी कांट्रेक्टर के माध्यम से। सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि लगभग 60 परसेंट काम उनमें हुआ है, आगे काम हो नहीं रहा है। ढाई-ढाई साल से जो कांग्रेस में करप्शन हुआ था, उसके समय से पैंडिंग पड़ी हैं। आधी टंकियों का निर्माण हो गया। मैं मुख्य मंत्री महोदय से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जलदाय मंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसका जिस प्रकार बैठकर समाधान हो सकता है, वह करिये। वह जो टंकियां खड़ी हैं, वह अगर गिर जायेंगी, वह पाप कांग्रेस ने कमाया है, करप्शन उनके राज में हुआ है और कहीं न कहीं उसके छींटे हम पर भी इसलिए आयेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने टंकियां आधी खड़ी कर दी वह कभी गिर गई तो वहां कैजुअलटी हो सकती हैं, इसलिए जेजेएम पर आपको विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 6091 करोड़ रुपये व्यय कर 11 लाख 17 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। बहुत सारे विषय रखना चाहता हूं। मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक उदाहरण के रूप में मेरे विराटनगर में ड्राई जोन है, पीने का पानी नहीं है। कोई विधायक 5 ट्यूबवैल मांगता है, कोई 10 मांगता है। मेरे तो 1 हजार फीट तक पानी नहीं है। मेरा तो हमेशा सरकार के पास में 5 साल यही काम रहेगा, सड़कें चाहे मुझे मत दीजिये, मेरे गांवों में

पीने के पानी की कांग्रेस ने 5 साल में कोई योजना नहीं बनाई, इसलिए मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे ट्यूबवैल लगाकर के विराटनगर में पीने का पानी उपलब्ध हो पायेगा तो अच्छा होगा।

साथ ही साथ मेरा पावटा है, जिसमें अमृत योजना के अंतर्गत कुछ काम होगा तो पीने का पानी मिलेगा। मेरे यहां एक-एक गांव में पर डे के 5-5 सौ रुपये के टैंकर किराये से मंगाकर हमारे काश्तकार भाई पीने का पानी लेने का काम करते हैं। इतने बड़े संकट में मैं हूं।

सभापति महोदय, आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने और साथ-साथ हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री महोदया ने विराटनगर में इतने सारे तोहफे दिये हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने विराटनगर नगरपालिका में सीवरेज देने का काम किया। विराटनगर एक पौराणिक नगरी है। सम्राट अशोक ने वहां 300 दिन रहकर के आध्यात्मिकता से जुड़ने का काम किया था। जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, वह विराटनगर है। ऐसी पौराणिक नगरी में आपने सीवरेज का काम दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

विराटनगर में आपने एक अच्छा काम दिया है, आधुनिक बस स्टैंड बनाने का काम होगा, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। विराटनगर में जो उपखंड कार्यालय है, पंचायत समिति है, नगरपालिका है, वहां उप जिला अस्पताल की घोषणा भी इस बजट में की है। मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, पावटा किसानों का क्षेत्र है, पावटा में कोई मंडी नहीं होती थी। सरकार ने, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने और दिया कुमारी जी, दोनों ने मिलकर मेरे पावटा में विकसित कृषि उपज मंडी की घोषणा की है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं धरातल है, कहीं नदी, नाले हैं, उस क्षेत्र का आपने इतना ख्याल रखा है। यह हमारा विराटनगर पहले बैराठ हुआ करता था। बड़े-बड़े लोगों ने यहां चुनाव लड़ा है। हमारे ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से मिल सकें, इसके लिए 2-2 पीएचसी आपने मुझे दी हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विराटनगर में संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल है, जयपुर संभाग में सबसे बड़ा कोई विद्यालय चलता है तो मेरे विराटनगर में संस्कृत विद्यालय चलता है। हमारी संस्कृत भाषा पूरे देश और दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा को आगे बढ़ावा देने के लिए और इसकी आवश्यकता भी है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे वरिष्ठ उपाध्याय को महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। मेरी इस मांग को मंजूर करें।

साथ ही मेरे विराटनगर का पार्ट है, एक पार्ट मेरा हाईवे के ऊपर है, एक पार्ट मेरा पहाड़ों के बीच में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 70 किलोमीटर मेरा विधान सभा क्षेत्र लगता है। पावटा में अभी नगरपालिका है। उसका एक पार्ट राजनौता लगता है। पिछले दिनों

हमारी डिप्टी सीएम साहिबा वहां पधारी भी, मेरे को खबर है, कोई कार्यक्रम था। मैंने तब भी आपसे आग्रह किया था कि वहां पर एक उप तहसील का निर्माण हो जाये तो हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। साथ ही, विराटनगर क्षेत्र में कूरला क्षेत्र है, जिसको मेड क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र में सब तहसील बन जाये तो मैं समझता हूं कि लगभग 125 गांवों का उससे जुड़ाव होगा। इससे हमारे काश्तकारों को फायदा होगा। लगभग 40 किलोमीटर का फायदा हमारे काश्तकार भाइयों को होगा। इस प्रकार की मांग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैंने कहा ना कि मेरा विराटनगर जिसमें इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दिये हैं, पिछली बार भी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और हमारी डिप्टी सीएम साहिबा ने वहां जैन सर्किट है, उसमें 87 करोड़ रुपये की घोषणा, आपने जितना मुझे ध्यान है, उतनी की थी। मैं उस पर भी आग्रह करना चाहता हूं कि इतना अच्छा बजट है।

साथ में एक बड़ी मांग मैं करना चाहता हूं और सदन को बताना भी चाहता हूं, इस सदन के सभी सदस्य साहिबानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश और दुनिया में लगभग 52 शक्ति पीठ हैं, उसमें से 49वीं शक्ति पीठ कहीं है तो मेरे विराटनगर में मंशा माता का मन्दिर है, जो 49वीं शक्ति पीठ है। उसको देश के पटल पर लाया जाये। मैं, प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, वह आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप इस मांग को पूरा करें। आप हमेशा देव दर्शन करते रहते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है।

**spp/rtm/27.02.2025/16.40/3c**

और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, जो सदन में अपनी बात कहते हैं या किसी मंच पर अपनी बात कहते हैं तो ताल ठोककर कहते हैं और जो कहते हैं हम उस बात को पूरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, अंत में दो लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा-

विकास का मजबूत आधार चाहिए,
आपस में भाईचारा और प्यार चाहिए,
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास की किरण,
इसलिए भाजपा का नेतृत्व हर बार चाहिए।।'

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री बहादुर सिंह कोली।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, 2025-26 के बजट पर बोलने के लिये अवसर देने पर बहुत-बहुत धन्यवाद। आज राजस्थान का जो बजट पास हुआ, बहुत ही सराहनीय है और सारे राजस्थान के अन्दर खुशी का माहौल है। जो पिछली सरकार थी, वह कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी मैं वैर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, दो बार सांसद रहा हूं और तीसरी बार विधायक बना हूं। मेरे यहां पर जो मंत्री थे भजनलाल जाटव, अब वह एम.पी. बन चुके हैं। धौलपुर और करौली संसदीय क्षेत्र से

एम.पी. हैं। यानी भ्रष्टाचार उन्होंने वैर में किया, भरतपुर में किया, पूरे राजस्थान में किया और हमारे भरतपुर से सुभाष गर्ग भी मंत्री थे, यह भी कोई कम नहीं पड़े थे। वह PWD मंत्री थे तो जिस प्रकार से वहां पर रोड बनायी गयी और दो महीने बाद वह रोड उखड़ गयी, उसमें डामर का नाम तक नहीं और काला तेल, जो ट्रेक्टर और ट्रकों में से निकलता है, वह मिलाकर लीपापोती कर दी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): उन सारे कार्यों की जांच करवा लो।

श्री बहादुर सिंह (वैर): जांच हो रही है। भजनलाल जी के जीजा ने ठेके लिये थे भगवान सिंह ने, उसकी जांच हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने किये थे, चाहे तो एस.डी.एम. के पास चले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास चले जाओ, चाहे थानेदार के पास चले जाओ, चाहे एस.पी. के पास चले जाओ, बिना पैसे दिये कोई काम नहीं होता था। आज पूरा प्रशासन और शासन जिस प्रकार से सख्ती में आया है, इससे मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का जो काम बिना पैसे के पूरे राजस्थान के अन्दर, हमारे भरतपुर जिले के अन्दर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, भजन लाल जी शर्मा जब मुख्य मंत्री बने, यह मात्र एक कार्यकर्ता थे और भरतपुर के लाल हैं। यानी जमीनी स्तर पर देखा हुआ है एक कार्यकर्ता ने कि गरीब का दु:ख क्या होता है, किसान का दु:ख क्या होता है, उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में, मैं अलग से एक बात कहना चाहता हूं, जो सब सदस्य बोले हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहां जो कोई भी पेपर होता था, वह पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता था। आज रीट की परीक्षा हुई है, उससे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं। पूरे राजस्थान में और भरतपुर में ढोल-नगाड़े और बाजे वाले भूखे मरने लग गये थे क्योंकि लड़के इस आस में बैठे थे कि हमें नौकरी मिलेगी और हमारी शादी होगी। मगर ओवर एज हो गये और अब वह कुंवारे ही रह गये, +++ ही रह गये। उनकी ओवर एज होने के कारण शादी नहीं हुई। यह कांग्रेस वाले अभी हैं नहीं यहां पर, अब उनकी शादी हो रही है। यानी इस सीजन में जब से हमारी सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार बनी है, हम गांवों में शादियों में जाते हैं एक लड़की के लिये कन्यादान देने के लिये और वहां दस जगह ढोल-नगाड़े और बाजे बजते हुए मिलते हैं। इस तरीके से शादियां हो रही हैं। वह युवा आज भजन लाल जी की सरकार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि, साहब, दोबारा से ढोल-नगाड़े बजने लग गये। जो मैरिज हॉल थे वहां पर भी सन्नाटा छा गया था। वह भी भूखे मरने लग गये थे क्योंकि शादियां नहीं होंगी तो मैरिज हॉल में कौन जाएगा? नौकरी उनको मिली नहीं और शादी उनकी हुई नहीं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने, हमारे यहां तो पहले ही +++ बहुत रहते हैं, जाटों का इलाका है और उससे भी ज्यादा +++ पांच साल में रह गये हमारे यहां भरतपुर में। जब से भजन लाल सरकार आयी है तो शादियां होने लग गयी हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान

और भरतपुर जिले में लोगों में उत्साह है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज हमारी सरकार काम कर रही है और बिलकुल ईमानदारी से अधिकारी काम कर रहे हैं। उस टाइम तो कहीं भी मजिस्ट्रेट या जज के पास जाते थे तो वहां पर आंखों पर पट्टी बंधी रहती है तो वहां पर सभी मंत्रियों के और सभी अधिकारियों के पट्टी बंधी हुई होती थी। आज कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है, वह पट्टी खुली हुई है। आज कोई भी गरीब आदमी कोई भी काम कराने के लिये कहीं जाएगा तो उसका सीधा काम होगा। जिस प्रकार से आज राजस्थान सरकार काम कर रही है, वो काम सराहनीय हैं।

दो बार बजट पास हुआ, पहले बजट को पेश हुए छह महीने हो गये हैं। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट की घोषणा की तो सभी सदस्यों ने अच्छा बताया। किसी ने यह नहीं कहा होगा कि हमको कुछ नहीं दिया। सबको कुछ न कुछ मिला है। कांग्रेसियों को भी दिया है और जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं दिया और बोलते रहे, चिल्लाते रहे। गांव में कहावत है, सभापतिजी, कोई भिखारी जब गांव में भीख मांगने के लिये जाता है तो घर पर जाकर बोलता है सीताराम। उसका रोजाना का काम है, भिक्षाम् देहि बोलता है। एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, वहां पर कभी उसको आटा नहीं मिलेगा या गेहूं नहीं मिलेगा तो दोबारा उस घर पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया है। चाहे यह भीख मांगे, चाहे सीताराम बोलें, तो इनको कभी भी जनता कबूल नहीं करेगी। इनको जनता ने नकार दिया है और कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज सामने देखो बिलकुल खाली पडा हुआ है। विपक्ष को आज यहां पर आना चाहिए था और हमारी बात को सुनना चाहिए था। हमने पांच साल में क्या किया और उन्होंने कुछ किया नहीं तो उनको सुनने की क्षमता ही नहीं थी। वह मुंह छिपाकर चले गये।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेसी यह कहते हैं कि हमने इतने साल राज किया। आज हमारी डबल इंजन की सरकार है। माननीय नरेन्द्र मोदीजी प्रधान मंत्री हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिये जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। जल जीवन मिशन के अन्दर, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी, गौरव पथ बनाये थे और इन्होंने ठेके दे दिये और ठेकेदार आधा-अधूरा काम करके भाग गये। वह टंकी भरी जा रही हैं, कोई टपटपा रही है। सारे रोड खोदकर पटक दिये और रोड खोदने के बाद जो ठेका होता है, उसकी बनाने की गारंटी होती है और ठेकेदारों का काम पूरा हो गया, उनको पेमेंट भी दे चुके। अब जब हम गांव में जाते हैं तो हमारी खुद की गाड़ी उस पर नहीं चलती और वहां कहते हैं, क्योंकि गांवों में जब शादी होती है।

**jyg/rtm/27.02.25/16.50/3d**

पैसे वालों को तो कार और चार पहिये की गाड़ी मिल जाती है, बचे हुओं को मोटरसाइकिल ही मिलती है। जो अपनी घरवाली को, बहू को गली में या रोड पर लेकर जाता

है, आये दिन गिरती है, किसी का हाथ टूटता है और किसी का कूल्हा टूटता है, वो स्थिति गांवों में हो रही है। तो इनके राज में जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि जो गांव की स्थिति खराब है, जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, उन ठेकेदारों ने जो भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया था। इसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार में डूब गये थे, आज उनकी जांच करायी जाये, उनकी जांच करायी जाये, यानी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो चिनाई का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी करते थे और आज उसके पास कितनी प्रोपर्टी है, कितनी सम्पत्ति है, जो चिनाई करने वाला, एक ठेकेदार, जगह-जगह होटल खोल लिये, दुनियाभर की प्रोपर्टी बना ली। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेसियों ने जो भी भ्रष्टाचार किया था, उनकी जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, होटल सीज होने चाहिए। जिस प्रकार से जो आज हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, काम में जो कमी रह गयी है उसकी भी पूर्ति करें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी विधायक दल की जो मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, मैंने आपको वो प्रोफार्मा दिया है, बहुत कम लोगों ने भरकर दिया है, वो भरकर दो। यानी जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, वो यह कह रहे हैं कि मुझसे लो, मुझसे मांगो, ऐसा कोई मुख्य मंत्री मिलेगा आपको, ऐसा मुख्य मंत्री मिलेगा? नहीं तो कांग्रेस के अन्दर हमारे सदस्य या कांग्रेस के सदस्य पीछे डोलते थे, पीछे डोलते थे, मुख्य मंत्री और मंत्रियों के और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी कह, कहकर जो आपको दे रहे हैं, तो मेरी यह डिमाण्ड है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हां पक्ष लॉबी में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, बाबा मनोहर दास जी हैं, उनकी प्रशंसा की थी, वो मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र के पास ही हैं। उनको मन से कोई दर्शन करने के लिए जाता था तो दर्शन हो जाते थे, बुरे मन से, जैसा कांग्रेसी बुरे मन से ही रहते हैं, तो बुरे मन से दर्शन करने जाता था तो पैर कहीं मिलता था और धड़ कहीं मिलता था, वो डर के मारे भग आते, कहते किसी ने मार दिया, काट दिया, मार दिया। यानी उसको मन से कभी गोवर्धन, कभी वृंदावन, तो वहां दर्शन नहीं होते थे। मेरा यह निवेदन है कि उसके मन्दिर के लिए बजट दिलवाया जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में लिखा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा करी थी, वो बजट में नहीं है। हमारे बाबा देव बाबा, झाझ के अन्दर और लखावतजी जिनके पास व्यवहार है, बाबा देव, झाझ तो वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और जब भी हम जाते हैं, हमारे बेढ़म साहब भी मंत्रीजी भी जाते हैं, वहां पर कई प्रदेशों के लोग आते हैं, लक्खी मेला लगता है, अभी भी एक महीने बाद मेला लगने वाला है, तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वहां पर बजट घोषित करके काम चालू कराया जाये क्योंकि वहां पर लोगों को, यात्रियों को सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यानी आपके हमारे भरतपुर जिले के अन्दर जाटों

के चार गांव हैं। एक गांव मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र में भी आता है, पथैना। यानी इतना पुराना गांव है, जब राजा-महाराजाओं का राज हुआ करता था, एक पथैने ने राजा-महाराजाओं को लगान नहीं दी थी, उन्होंने अपने खुद के हथियार लाकर, उनकी फौज से लड़े थे, फौज से लड़े थे, जो गांव लगान नहीं दे सकता है राजा-महाराजाओं को, उनकी मांग है उप तहसील उस पथैना को बनाया जाये। नहीं तो आगे हमको भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि सिनसिनवारों का है, तो वो हमको भी वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने राजा-महाराजाओं तक को लगान नहीं दिया तो हमको भी नहीं बख्शेंगे। हमको भी नहीं बख्शेंगे, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पथैना गांव की और मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है तो वहां इसकी सुनवाई करें, यह मेरा बजट पर निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामावतार बैरवा।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने व विधान सभा क्षेत्र चाकसू के आमजन की आवाज को सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको आभार और धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं प्रदेश के चहुंमुखी विकास को समर्पित बजट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी तथा वित्त मंत्रीजी सुश्री दिया कुमारी जी को चाकसू विधान सभा क्षेत्र वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने 19 फरवरी को जो बजट पेश किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसमें प्रदेश के चहुंमुखी विकास का ध्यान रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से पेयजल, ऊर्जा, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा आदि की बात हो या प्रदेश के किसानों की, महिलाओं को, युवाओं को, वृद्ध जनों की बात या सभी का समावेश करते हुए सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से राज्य में पहली बार 100 वेटरिनरी डॉक्टरों और 1000 वेटरिनरी इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी जो कि पशुपालन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि की बात कहूं, कृषि की बातकी जाये तो 1350 करोड़ रुपये के काम नयी कृषि तकनीकों पर होंगे और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिवर्ष किये जाने से किसान भाइयों को काफी राहत मिलेगी। गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस, 75 हजार किसानों को, उनको खेती में बहुत बड़ी समस्या आती है जैसे बाड़ करने के लिए, जाली, तार बंदी करने में, तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा, वो भी हमारे किसान पुत्र हैं तो किसानों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपये का जो अनुदान और 2000 किसानों को आधुनिक खेती के लिए पॉली हाउस, शेड नेट हाउस के लिए 225 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

**MLS/RTM/27.02.2025/17:00/3e**

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, इस बजट को पिछली सरकार की तरह पक्ष-विपक्ष का भेदभाव न करते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया है। यह एक ऐसा बजट है, जिसमें विकास के साथ-साथ प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रकृति के संरक्षण के लिये पहली बार हरित बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत 27 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये गये अभियान ''एक पेड़ मां के नाम'' से प्रेरणा लेकर प्रदेश में इसी वर्ष 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरित राजस्थान की संकल्पना के साथ आगामी वर्ष हेतु इस बजट में ''मिशन हरियालो राजस्थान'' तथा 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान चलाया गया, जो पेड़ हम लगाते हैं, वह मां के नाम रखा गया, क्योंकि मां को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मां जीवन में एक बार मिलती है, जो हमें जन्म देती है।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए बढ़ायी जाये।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये बढ़ायी जाती है।

**(स्वीकृत)**

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए बढ़ायी गयी।

**आय-व्ययक**

**आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद**

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु सतत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में आगामी वर्ष 25 हजार महिलाओं को सौर उपकरणों एवं अक्षय ऊर्जा के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा, जो हरित ऊर्जा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान बजट 2025-26 में चाकसू विधान सभा क्षेत्र को भी कई सौगातें दी हैं। रोड के लिये कम से कम 70 करोड़ रुपये का बजट और चाकसू विधान सभा क्षेत्र के कोटखावदा में कन्या महाविद्यालय खेड़ापति बालाजी व भोमिया जी मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये बजट घोषणा, चाकसू में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना, चंदलाई बांध के लिये दोनों तरफ कंकरीट वॉल निर्माण के लिये बजट घोषणा। उक्त विकास योजनाओं के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री

महोदया का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।

**चुनावी वादे उनके पूरे नहीं होते,**
**जिनके नेक इरादे नहीं होते,**
**अपना नेक इरादा है,**
**सर्वांगीण विकास का वादा है।**

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट भाषण में विकास को प्राथमिकता देते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू के आमजन की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री महोदया से निम्न मांगों के लिये निवेदन करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू के उप खण्ड माधोराजपुरा में शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। एक महाविद्यालय माधोराजपुरा में खोलने हेतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

दूसरी मांग मेरी यह है, सीतापुरा से चाकसू तक निरन्तर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण लोगों की नियमित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अम्बाबाड़ी से सीतापुरा मेट्रो के द्वितीय फेज को विस्तार देते हुए मेट्रो को चाकसू तक संचालित किये जाने की कार्य योजना बनाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि सीतापुरा और चाकसू में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। चाकसू और जयपुर में कोई दूरी नहीं है, इसलिये मेट्रो को चाकसू तक पहुंचाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोटखावदा में उप खण्ड कार्यालय खोले जाने के लिये आवश्यक बजट स्वीकृति हेतु मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का और विधान सभा क्षेत्र चाकसू की जनता की ओर से अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री शत्रुघन गौतम।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को और राजस्थान की वित्त मंत्री जी को हृदय के अंतः स्थल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव-गरीब की सोच और गांव-गरीब की पीड़ा क्या होती है, किसान की पीड़ा क्या होती है, नौजवानों की पीड़ा क्या होती है, महिलाओं की पीड़ा क्या होती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुख्य मंत्री जी ने 2025-26 का बजट राजस्थान की जनता के हित में रखा। इस बजट से उन्होंने सभी वर्गों को साधने का काम किया है।

मैं मुख्य मंत्री जी की टीम को, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को और राजस्थान की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो-तीन दिन से हमें जो विधान सभा में गतिरोध देखने को मिल रहा है, यह एक पवित्र सदन है, इस पवित्र सदन में जनता हमें जिताकर भेजती है, जनता के मन में यह सपना होता है कि हमारा विधायक

जाकर हमारी बात सरकार और सदन में रखेगा, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषा काम में लेकर इस राजस्थान की जनता के सामने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गयी हैं, यह शोचनीय है, विचारणीय है।

सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1998 में कांग्रेस की एक सरकार बनी। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 156 सीटें दीं और एक नया व्यक्ति, जिसे नहीं जानते थे, कम से कम 8-10 बड़े नेताओं को सुपरसीड करके राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने उस समय जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उसे हटाकर 5 कम्पनियां बनाईं, 5 कम्पनियां जीरो से शुरू कीं। जब 2003 में वसुन्धरा जी की सरकार आयी तो बिजली पर 80 हजार करोड़ का कर्जा था और भारत उदय में राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने वह कर्जा वहन किया और 2008 में बिलकुल न्यूनतम परिस्थितियों में लाये।

2008 से 2013 में जब वापस से कांग्रेस की सरकार थी तो वह कर्जा 80 हजार करोड़ रुपये हो गया और आज देख रहे हैं कि बिजली में क्या हुआ। निश्चित रूप से 1998 के बाद कांग्रेस इस राजस्थान प्रदेश में 100 सीटें नहीं क्रॉस कर पायी। पिछली सरकार, चाहे 2018 से 2023 की सरकार की चर्चा करें, यह सरकार कैसी थी, इससे राजस्थान का आमजन त्रस्त था, कोरोना में कांग्रेस के शासन में कितनी लूट मची और कोविड में राजस्थान के अधिकारियों ने और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने जो हाहाकार मचाया...। 2018 से 2023 का जनता से कुछ छिपा हुआ नहीं है। जनता सब जानती है। चाहे वे नौजवान हों, महिलाओं को भट्टी में जिन्दा जलाकर मार दिया गया। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ? जब 2023 आया, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सोचा कि अब जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे, क्या करेंगे, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने अपने विधायकों को बुलाकर कहा कि क्या किया जाये।

18 जिले राजस्थान में एक साथ बनाने का काम किया। बड़ी वाह-वाही लूटने की बात करने लगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उसके मात्र 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के बाद देवली टोंक जिले में है, उसकी 8 पंचायतें जो डूब क्षेत्र है, उसको भी केकड़ी जिले में शामिल नहीं किया गया। शाहपुरा के एक नेता को खुश करना है, शाहपुरा को जिला बनाओ। केकड़ी को जिला बना दो, ये केकड़ी के जो बड़े नेता हैं, जो किस तरह से जीतकर आये, मालपुरा में भी राजनीति में एक नेता को जिन्दा करना था तो मालपुरा भी घोषित कर दिया गया, दूदू भी घोषित कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें लगता है कि 18 कम पड़ रहे हैं, हम सरकार में कैसे आएंगे तो 200 जिले बना सकते थे और 200 जिले बनाते तो भी शायद सरकार उनकी नहीं बनती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कांग्रेस के लोग आज मर्यादा की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, मालपुरा से जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया, वह आज 5 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे

है। 700 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी में बन्द है। उसे टिकट किसने दिया, ये डोटासरा साहब बताएं, वे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। क्या परिस्थितियां थीं, वह नेता भी नहीं था, यह आत्म चिन्तन कांग्रेस को करना चाहिये। यह कांग्रेस कहां खड़ी है? 1998 के बाद 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, आज सड़कों के माध्यम से हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया, जो पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर हैं, किस तरह के काम, चाहे हमने 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज पिछले बजट में लिये हों, मेरे केकड़ी, देवली, नसीराबाद, रोजाना घटनाएं घटती हैं और जिले, मात्र जिले बनाने के लिये 2 लाख रुपये नहीं दिये और कलक्टर-एसपी बैठा दिया। राजस्थान की जनता से अशोक गहलोत जी को और उनकी पूरी टीम को माफी मांगनी चाहिये।

**MKD/RTM/27.02.2025/17:10/3f**

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने 2023-24 के आखरी बजट में सात हजार करोड़ की स्वीकृति थी और उसके अगेंस्ट 17 हजार करोड़ की स्वीकृति निकाल दी गई। जब चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता चल रही थी तब भी अधिकारी स्वीकृतियां निकालकर और नेताओं को जिताने में लगे थे।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आज मैं निवेदन करूंगा कि ये बार-बार बोलते हैं, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। मैं कहता हूं कि यह पर्ची सरकार का मुख्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी ने चूं तक नहीं बोला कि यह पर्ची सरकार का मुख्य मंत्री है। यह गरीब का बेटा है, यह किसान का बेटा है, ये सबके हित को साधते हैं। रात को दो बजे मुख्य मंत्री जी हर विधायक से, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसके काम लिए संवदेनशील हैं। इनको बोलते हुए ये नहीं दिखता कि आठ दिन तक जयपुर-दिल्ली, जयपुर-दिल्ली एक नेता आ रहा है, एक नेता जा रहा है, फिर वोट पड़ रहे हैं, वोट पडेंगे और फिर कहते हैं अपने उप मुख्य मंत्री को +++ नालायक और किस तरह की भाषा काम में ली गई, अमर्यादित भाषाएं, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सब चीज जानती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जयपुर विकास प्राधिकरण 2018 से 2023 तक लूट का अड्डा बना हुआ था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चाकसू में बीस लाख रुपये की जमीन समर्पण करके यहां जयपुर में रिंग रोड पर 35 हजार रुपये गज की जमीनें दी गईं। आप जांच करा लीजिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लीजिये। 10 हजार करोड़ का घोटाला, यह पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में था। क्या जरूरत थी, चाकसू में जमीन समर्पण करवाने की। क्या ऐसी आवश्यकता थी तो निश्चित रूप आप आत्म चिन्तन करिये। आज विपक्ष के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आत्म चिन्तन करिये, क्यों हमारी ऐसी स्थिति हुई। राज देखा है,

विपक्ष देखा नहीं। अभी आप कह रहे थे दिल्ली में 2014 से लेकर टिल टुडे तीन चुनाव हो गये। 2013 का विधान सभा चुनाव हुआ, राजस्थान के साथ। 2014 का लोक सभा हुआ। 2019-20 का विधान सभा, 2019 का लोक सभा, आप जीरो हो। इस बात पर आकलन करना चाहिए। आप भारत के अन्दर 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाये, दस साल से।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी, जो सरकार में बजट दिया, जो सोच है काम करने की, किसान हो, आमजन हो, नौजवान हो, सबके लिए काम करते हैं। जेजेएम की बात करें तो हमारे मंत्री कन्हैया लाल जी पूरे राजस्थान में घूम-घूमकर हर विधान सभा क्षेत्र में आकलन करके कि किस तरह से हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आने वाले समय में 20 साल की सोच लेकर, चाहे अमृत योजना में हो, चाहे जेजेएम में हो, किस तरह से पैसा आये, दस-पांच साल तक पानी का बिल नहीं भेजा, पानी के बारे में कुछ नहीं किया। जेजेएम में जो घोटाले हुए, मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को कि जेजेएम के सारे घोटोलों की जांच करके, किस अधिकारी ने ये टेंडर स्वीकृति किये, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

ईआरसीपी, ईआरसीपी में रामसेतु का जो काम किया है, इस राजस्थान में हर तरह की परिस्थिति है। यह राजस्थान आगे जा सकता है। इस सोच के साथ हम आये, इस पवित्र सदन में हम आये, नहीं आये, लेकिन हमें जो जनता ने दी है, जनता ने हमें जिताकर भेजा है तो हमारी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। राजस्थान की जनता में, आज मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री बनते ही, सरकार बनते ही, दिल्ली में प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी से बात करके जो परिस्थितियां बन सकती थी, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से बात करके और एक टेबल पर बैठकर और 14 जिलों की लाखों हैक्टेयर भूमि को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। यह सामान्य बात नहीं है। ये भागीरथ बनकर आये हैं। यह सामान्य बात नहीं है। 4 साल तक आप कहते रहे कि दिल्ली जा रहे हैं, गजेन्द्र सिंह जी शेखावत जोधपुर के मंत्री हैं,यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी सोच पवित्र नहीं थी। आपकी सोच सकारात्मक नहीं थी। आपकी सोच में राजस्थान के किसान का भला नहीं था। इसलिए माननीय भजन लाल जी शर्मा को मैं सदन की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान के लिए ये भागीरथ बनकर आये हैं। आज के बाद नहीं, वर्षों तक नहीं, सदियों तक राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी को और देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जनता जय-जयकार कहेगी कि वास्तव में आपने किसान के भले के लिए। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, यह सोच आपकी गलत है। उसका अध्ययन करिये।

मैं तो यह कहता हूं कि निश्चित रूप से रोडवेज आवगमन का साधन है। रोडवेज में, इतनी सरकारें आईं। जयपुर की बात करें, जेसीटीएल में अभी जयपुर में 1 हजार नई बसें लाकर जयपुर के आम व्यक्ति के लिए सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, यह भजन लाल जी की

सरकार ने सोचा है। मैं कहना चाहता हूं, पहले की सरकार थी, पहले की सरकारों ने काम किया, 90 करोड़ रुपये महीने का घाटा राजस्थान की रोडवेज में है। माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में वह घाटा पूरा होकर राजस्थान रोडवेज आज प्रोफिट में है। यह सरकार की सकारात्मक सोच है। तीन हजार बसें नई मिलने वाली हैं। यह सोच है, सोच से काम होते हैं, मेहनत से काम होते हैं, पारदर्शिता से काम होते हैं।

मैं तो मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की ब्यूरोक्रसी पर, राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक सोच, एक विजन बनाना चाहिए। जितने भी कैडर हैं, उस कैडर के एक परसेंट लोगों को हर साल शिकायत के आधार पर सेवानिवृत्त करके घर भेजा जाये। यह राजस्थान की पारदर्शी सरकार है। यह नये नियम और कानून बनाकर कुछ करना चाहती है।

माननीय मंत्री महोदय, पिछली सरकार की बात, इनको लगा सरकार कैसे आयेगी। मोबाइल बांट दो। कितने हजार करोड़ के मोबाइल बांटे गये और मोबाइल गांव के गरीब को, मोबाइल का भला कुछ हुआ कि नहीं? मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आप सब भी इस बात पर आत्म चिन्तन करना कि मोबाइल से, किसी बुजुर्ग महिला को मोबाइल मिला तो महिला ने अपनी बेटी या पोती को दे दिया और आज वे महिलाएं उस स्थिति में, क्या परिस्थितियों हो रही हैं, सब जान रहे हैं। वह कहती है कि मेरे माता-पिता से, सख्त कानून बनना चाहिए। वह लड़की कहती है, उसके प्रेमी के साथ जाकर कहती है, मुझे मेरे मां-बाप से सख्त नफरत है। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन वारंट लेकर आती है। आप इतनी वाहियात पर आ गये कि आखिर में जाते-जाते आपने मोबाइल। आपने गरीब का मजाक बनाया। आपने गरीब को क्या दिया? खाद्य सुरक्षा किट। नमक और मिर्च तो गहलोत साहब गरीब खरीद सकता है। यही कारण था कि आप सरकार में नहीं आ पाये। आपने गरीब की तौहीन की। गरीब का मजाक बनाया। खाद्य सुरक्षा किट कभी नमक, मिर्च, आटा। नमक मिर्च भी कभी किसी को दिया, सरकार की सहायता में, क्यों नहीं दिया आपने पांच साल तक, क्यों नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह के गलत काम करके और राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम किया, राजस्थान की जनता का मजाक बनाने का काम किया, चाहे जिले में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हों।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो काम किये हैं, हर क्षेत्र के अन्दर, आज महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं की योजनाओं को लेकर, आज किसान सम्मान निधि है, भारत की सरकार ने 6 हजार रुपये दिये और माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच थी कि राजस्थान के किसान को 6 हजार रुपये कम पड़ते हैं, वह 6 हजार में काम क्या करेगा, पहले बजट में 2 हजार रुपये जोड़े और अभी 1 हजार रुपये और बढ़ाकर 9 हजार रुपये किये हैं और आने वाले समय में 12 हजार रुपये करेंगे तो यह मुख्य मंत्री जी की सोच है। यह मुख्य मंत्री जी का विजन है कि राजस्थान का किसान किस तरह से आगे आये।

माननीय सभापति महोदय, हर चीज का, क्योंकि सरपंच से चलकर ये मुख्य मंत्री बने हैं। आप लोगों ने जब कहा था, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वन नेशन-वन स्टेट-वन इलेक्शन, राजस्थान की विपक्ष के नेता ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने मजाक बनाई थी कि एक भरतपुर का चुनाव तो करा नहीं पा रहे और वन स्टेट-वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा जो कहते हैं, वह करके बताते हैं और साढ़े 6 हजार सरपंचों का कार्यकाल आगे प्रशासक के रूप में बढ़ाते हुए राजस्थान की जनता को यह मैसेज दिया कि नहीं, वन स्टेट-वन इलेक्शन होगा और यह होगा। भजन लाल शर्मा जी जो कहते हैं, वह करते हैं। इतना बड़ा काम, क्योंकि छोटे, कहीं कैसे चुनाव। आप पंचायत परिसीमन की बात करते हो, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सबके लिए नियम बनाये, सबके लिए कानून बनाये, आपने तो चालीस वोटो में।

माननीय सभापति महोदय, चालीस वोटों में सावर के अन्दर आपने एक नगरपालिका का वार्ड बनाया, यह स्थिति है आपकी। आप इस पर आत्म चिन्तन तो करते नहीं कि हमसे कहां गलतियां हुईं और बाहर निकलकर कहते हो कि पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। पर्ची सरकार, ऐसी सरकार सर्वमान्य सरकार है। 2028 में भी भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अब आपको भजन ही करने पड़ेंगे, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा। आपको भजन ही करने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अन्दर, चाहे किसी में भी बात करें, सड़कों का जाल बिछा है। आज सड़कों के बारे में या गांवों की रिंग रोड के बारे में, अभी आपने 18 कस्बों की रिंग रोड ली है। पिछले बजट में 23-25 कस्बों के रिंग रोड लिये थे। ये सामान्य बात नहीं है। एक सकारात्मक सोच से राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कि राजस्थान में क्या हो सकता है, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे।

माननीय सभापति महोदय,  मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम जिस विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, मुख्य मंत्री जी जिस विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी चाहिए। हम सबको मिलकर विकल्प सोचना चाहिए, हम सबको मिलकर विकल्प सोचना चाहिए। आज जयपुर-अजमेर हाइवे, जयपुर भीलवाड़ा हाइवे, इस पर कितना ट्रैफिक है। पहले यह फोरलेन था, फिर आठ लेन बना, अब दस लेन की बात कर रहे हैं, फिर 16 लेन की बात करेंगे।

**Bhs/Rtm/27.02.25/17.20/3g**

मैं कहता हूं कि इसका विकल्प होना चाहिये। इसका सब्स्टीट्यूट होना चाहिये कि किधर से जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी सांगानेर से विधायक हैं और यह सड़क सांगानेर से शुरू होकर उसके आगे चाकसू से हमारे रामावतार जी विधायक हैं, उसके पहले

कैलाश जी बगरू से विधायक हैं, उसके आगे प्रेम चन्द जी उप मुख्य मंत्री हैं सरकार में फागी से, उसके आगे कन्हैया लाल जी हैं मालपुरा से विधायक, उसके आगे केकड़ी से मैं विधायक हूं, उसके आगे शाहपुरा से लालाराम जी विधायक हैं, उसके आगे माण्डल से उदयलाल जी भडाना विधायक है। यह सड़क चल रही है लेकिन रोजाना चार से पांच आदमी दुर्घटनाओं में खत्म होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्जस्टिंग रोड है यह रोड फोर लेन होना चाहिये। यह फोर लेन होगा तो इसमें दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। इस रोड पर ट्रैफिक कम होगा क्योंकि इस तरफ से भीलवाड़ा चालीस किलोमीटर कम पड़ता है। यह सकारात्मक सोच होनी चाहिये। आपने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से दो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ब्यावर से भरतपुर और जयपुर से भीलवाड़ा है 191 किलोमीटर, लेकिन यह एग्जस्टिंग रोड और टोल रोड है। आर.एस.आर.डी.सी. बना सकती है, आर.एस.आर.डी.सी. इस रोड को कर सकती है। 40-40, 50-50 किलोमीटर की करे तो यह सोच हमारी होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आज आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह भ्रष्टाचार की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि 2008 से 2013 में सरकार थी। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में एक अजगरा गांव है, अजगरा गांव में चार सौ बीघा जमीन बिना सोचे-समझे चरागाह की जमीन को दे दी गयी। यह बीसलपुर विस्थापितों के लिए आवंटित की गई। बीसलपुर विस्थापितों को आवंटित नहीं की गई। उनसे खरीद ली गई डेढ़ लाख रुपये बीघा में और उस समय तत्कालीन कलेक्टर ने बिना सेटअपार्ट किये, बिना चरागाह की क्षतिपूर्ति करे उस जमीन को आवंटन कर दिया। आज चार सौ करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उसकी जांच करायी जाये और उस आवंटन को निरस्त किया जाये। पिछली सरकार वसुन्धरा जी की सरकार में जब मैं विधायक था तो हमने वसुन्धरा जी से कह कर और 200 बीघा वापस चरागाह के नाम चढ़वाई और अभी पिछली सरकार जो थी आपकी, आपने उसको उन शिकायतों को सारहीन करते हुए वापस जमीन सम्भालने की बात की। ऐसा भी क्या है, क्या मजबूरी है? निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हर चीज का जवाब मांगती है जनता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हम लोगों को ऐसे काम करने चाहिये, सकारात्मक काम करने चाहिये। गांव में चरागाह बचे नहीं। गांव के चरागाह की स्थिति क्या है? सिवायचक की स्थिति क्या है? कहां से लायेंगे? क्या करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं। आप लोग आप विपक्ष में बैठे हो। आपने गाय की चिन्ता नहीं की। मैं सरकार को और सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के बारे में इस तरह की पॉलिसी बने कि गोशालाओं को ज्यादा से ज्यादा अनुदान, अभी आने वाला है जुलाई-अगस्त का महीना और जुलाई-अगस्त के महीने में दुर्घटनाओं में

लोग मरते हैं, कारण कि गाय माता सड़क पर बैठी रहती है। एक्सीडेंट होते हैं और गांव का व्यक्ति भी जिम्मेदार है इसके लिए टैग करना जरूरी है। जिस तरह से हम भैंस के ऊपर कान पर टैग करते हैं वैसे हर किसान को ऐसा कानून बना कर या पशुपालन विभाग इस तरह का काम करे कि निश्चित रूप से कोई भी पशु को दूध निकाल कर बाहर नहीं छोड़े।

माननीय सभापति महोदय, आज गाय की स्थिति चिन्तनीय है और गाय को हमें बचाना है तो हर तीन-चार पंचायतों की बना कर एक गोशाला बनायें और हम चरागाह पर और सिवायचक जमीन पर माननीय राजस्व मंत्री भी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिवायचक जमीन पर एक अभियान के रूप में, चरागाह जमीनें एक अभियान के रूप में क्योंकि गांव में चार से पांच लोग जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो ही चरागाह और सिवायचक पर कब्जा करते हैं इसमें सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिये कि लोग उसके लिए डरे, उनके मन में एक भय हो कि नहीं, यह गलत है यह चरागाह भूमि पर हम हाथ नहीं लगा सकते।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान के बारे में किसान कहां जाये, हर गांव में सौ-सौ, दो सौ-दो सौ बीघा पर जिनको हम कहते हैं कि गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं वो उस पर कब्जा करके बैठे हैं तो इस पर एक योजना बननी चाहिये। आज राजस्व विभाग को, मैं सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक व्यक्ति जमाबन्दी की नकल लेने के लिए पटवारी के पास जाता है, पटवारी उससे कितने चक्कर लगवाता है, लेकिन आपने अच्छा काम किया, सब चीजें ऑनलाइन कर दी। रजिस्ट्री के बाद नामान्तरण अपने आप ऑनलाइन हो गया। यह सरकार की सकारात्मक सोच का पहलू है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार काम कर रही है और राजस्थान की जनता काम चाहती है। अभी हमारे वैर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे। कितने पेपर लीक हुए और किस तरह से काम किया, हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने तत्कालीन सरकार में जाते-जाते दीपक उप्रेती जी को आर.पी.एस.सी. का चैयरमेन बनाया था और उन्होंने जिस तरह से नियम-कानून बनाये थे, जिस तरह से उनके काम की शैली थी और उसके बाद कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन ने उसकी धज्जियां उड़ा कर नियम-कानून को तार-तार करके और आर.पी.एस.सी. जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था राजस्थान में जिसका नाम यू.पी.एस.सी. की तरह लिया जाता था ईमानदारी के लिए, जिसके लिए सब लोग कहते थे आर.पी.एस.सी. में ईमानदारी से काम होता है लेकिन क्या हुआ? पांच साल में आपने तार-तार कर दिया। कितनी बार पेपर आउट हुए और यह ईमानदारी का गुणगान करते थे वो अधिकारी चाहे चैयरमेन हो, चाहे मैम्बर हो, क्या परिस्थितियां बनी, आपसे किसी से छिपी हुई नहीं है और आज किसी आदमी के व्यक्तित्व में सोच होनी चाहिये, किसी का जज्बा होना चाहिये। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि डेढ़ सौ से ज्यादा लोग जेल की सलाखों

के पीछे हैं और कितने ही पेपर हो गये। आज भी रीट कापेपर है लेकिन क्या मजाल जो पेपर आउट हो जाये। यह सोच होनी चाहिये सरकार की और सरकार के व्यक्तियों की।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी कहा गया था, मैं कोई तैयारी से नहीं आया लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को जिस सोच के साथ हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की बात करें तो राजस्थान में साढ़े चार हजार ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल थे मात्र जब वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थी। 2015 के बजट में वसुन्धरा जी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटियां पढ़ने के लिए 11वीं-12वीं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाती हैं और उनसे उनके माता-पिता उनके पेरेन्ट्स पढ़ाई छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तू बड़ी हो गई दूसरे गांव तुझे पढ़ने नहीं भेजेंगे और राजस्थान की यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत पर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिये और एक साथ साढ़े पांच हजार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल वसुन्धरा जी ने खोलने का काम किया। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय थे। हम सब अध्यक्ष महोदय के पास जाते थे लेकिन एक थर्ड ग्रेड का मास्टर जो सरकार बदलने की बात करता था गांव के नुक्कड़ पर बैठ कर कहता था अबके इसको हरा देंगे, अबके इसको जिता देंगे लेकिन पता चलता कि यह थर्ड ग्रेड का मास्टर बी.ए. भी है एम.ए. भी है, बी.एड. भी कर रखा है। आपने सबका शाला दर्पण ऑनलाइन करते हुए और हर स्कूल का हर बच्चे का ऑनलाइन करते हुए शाला दर्पण एप में डाला और पता चला कि यह थर्ड के मास्टर साहब ये तो फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रमोशन हुआ, सेकंड ग्रेड में आ गये, सेकंड ग्रेड के बाद भी पता चला कि ये तो फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में आ गये व्याख्याता बन गये। हम पूछते मास्टर साहब आजकल नजर नहीं आते तो बताते कि मेरा सरकार ने प्रमोशन कर दिया, मैं अब व्याख्याता बन गया, मुझे तीन घंटे घर पर पढ़ना पड़ता है तब मैं बारहवीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। ये ऐसे काम लोकप्रिय काम इस तरह के बड़े काम, बड़े फैसले करने का काम राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने किया और शिक्षा का मजाक आपने बनाया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे गांव में मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में एक काचरिया गांव हैं जिसमें स्कूल में दो कमरे हैं और तीन मास्टर हैं और जाते-जाते तत्कालीन सरकार ने 12वीं कर दी। जब मैं चुनाव में गया तो कहते हैं कि हमारे स्कूल में कमरे बनाने हैं। दो मास्टर से 12वें के बच्चे कैसे पढ़ायेंगे? आप इस तरह के काम तो नहीं करें। इस तरह के निर्णय तो नहीं करें कि जिस निर्णय से जनता को दर्द हो, जनता को दुख हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. को मत देखो, इर्रिगेशन को मत देखो लेकिन शिक्षा को देखने की जरूरत है। यह आने वाला भविष्य है, यह आने वाला कल है इस पर चिन्तन करना चाहिये। हम सबको मिल कर एक प्रभावी कानून बनाना चाहिये इन्हीं बच्चों के लिए कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित रहे। हमारे आने वाले बच्चे अच्छे हों तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा पर जो सरकार ने बढ़ावा दिया। बेटियों के लिए निश्चित रूप से आज भी मैं कह सकता हूं कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में केकड़ी कस्बे में ऐसा

सीनियर सेकेण्डरी स्कूल है जिसमें 2400 बच्चियां एक साथ पढ़ती हैं और जब छुट्टी होती हैं तो मुझे थाने का जाब्ता लगाना पड़ता है। सामने बॉयज स्कूल है, उसमें भी ढाई हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच होनी चाहिये। ऐसा नहीं कि हम सरकार में आ गये, हम पांच साल के लिए आ गये। हम तीन साल काम नहीं करें, हम चार साल जनता की सुध नहीं लें, गांव-गरीब की सुध नहीं लें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मजाक बना दिया कोरोना के अन्दर आपकी स्थिति क्या थी। कोविड में क्या किया? आप देखते रहे पूरे राजस्थान में और आज भी मैं कह सकता हूं दावे से माननीय मुख्य मंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से कि कोरोना में जो ऑक्सीजन प्लांट आनन-फानन में डाले गये थे, आज वो कितने चालू हैं, कितने चालू नहीं है, यह जांच का विषय है कि क्या हो रहा है। सारे बन्द पड़े हैं तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, सरकार की सोच सकारात्मक होनी चाहिये। कोई भी चीज हो, आप जाते-जाते यह कर दो, वह कर दो। आपके निर्णय की समीक्षा होनी चाहिये कि आपने क्या किया। यही कारण था कि आज आपकी स्थिति क्या हो गई। आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की, चाहे वित्त विभाग की, चाहे किसी भी विभाग की सकारात्मक टीम जो काम कर रही है वो निश्चित रूप से जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। यह सारे 115 विधायक और जो हमारे साथी विधायक हैं यह सब जानते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं, किसान का बेटा है, सरपंच रहे हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी है सरपंच।

**Kas/rtm/27.02.2025/17.30/3h**

सरपंच से चलकर राजनीति में आये, तभी सरपंचों की पीड़ा समझ कर सभी सरपंचों को प्रशासक लगा कर जब तक वो चुनावों में जाएं तो निश्चित रूप से वापस जीत कर आएं। यही कारण है कि राजस्थान में आज भजन लाल जी का इकबाल बुलंद है। आज गांव का व्यक्ति कहता है कि यह पहला मुख्य मंत्री है जिसने गांव, गरीब सरपंच की सुन कर, अंतिम छोर के व्यक्ति की सुन कर यह निर्णय किया है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में एक साथ चुनाव होंगे। स्वायत्त शासन विभाग में कभी 15 निकायों के चुनाव होंगे, कभी 20 निकायों के चुनाव होंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने सोच लिया कि हर नगरपालिका का, हर नगर निगम का, हर नगर परिषद का एरिया बढ़ना चाहिये। हम सबको कहा है कि एरिया बढ़ाओ। ऐरिया बढ़ाने से और कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन एक बड़ा फायदा होगा, जो सरकारी जमीनें हैं, जो सिवायचक जमीनें हैं, वो नगर परिषद के खाते में आयेंगी, नगर परिषद की आय बढ़ेगी। अभी मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 175 बीघा जमीन थी, जिसमें कब्जा था। हमने नगर परिषद से खाली करा कर रीको को दी है और वहां पर इंडस्ट्री के 3000 करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं और 48 करोड़ रुपये केकड़ी नगर पालिका को हमारा रीको डिपार्टमेंट देगा, तो यह हमारे लिये गर्व की बात है, यह हमारे लिये खुशी की बात है।

सभापति महोदय, आपने देखा कि जयपुर में हम जीत नहीं सकते, जोधपुर में हम जीत नहीं सकते, कोटा में हम जीत नहीं सकते, आपने कहा कि नहीं, एक नगर निगम की जगह दो कर दो। चार कर दो, आप मुख्य मंत्री हो, चार कर दो, क्या हो जायेगा? माननीय सभापति महोदय, आप कोटा से आते हैं, वहां प्रताप सिंह जी बैठे हैं, कोटा में सरकार ने बड़े-बड़े काम किये, चम्बल रिवर फ्रंट बनाया। कोटा के लिये सबसे ज्यादा बजट दिया। पूरी सरकार कोटा चली गई, मुख्य मंत्री चले गये। मुख्य मंत्री को एक प्रेस कांफ्रेस के बाद हवाई अड्डे के लिये रवाना होना था, आप रवाना नहीं हुए। आपके किसी के भी उस उद्घाटन पट्टिका के हाथ नहीं लगे। सारी सरकार लौट गई और वह रिवर फ्रंट ऐसा का ऐसा रह गया। फिर तीन दिन बाद तत्कालीन मंत्री जी की इज्जत बचाने के लिये मुख्य मंत्री जी गये और सीबी गार्डन में शायद एक ट्रेन का उद्घाटन करके आये हैं। ऐसा क्या हो गया? यह जांच का विषय है कि चंबल रिवर फ्रंट, जो घडियाल सेंचुरी है, उसकी एनओसी नहीं ली गई, एनजीटी से उसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया ही नहीं और आपने हजारों करोड़ के काम कर दिये। माननीय सभापति महोदय, कोटा में जब दूसरा ब्रिज बनना था, घडियाल सेंचुरी की एनजीटी से एनओसी नहीं आई थी, तो बाई पास की पुलिया बनाने के लिये वर्षों इंतजार करना पडा। 600 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मरे होंगे, क्या यह सामान्य बात है? आपने क्या नहीं किया, आप किस स्थिति में ले जाना चाहते हो? आप पट्टों की बात करते हो कि हम प्रशासन शहरों के संग में कैम्प लगायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं निवेदन करूंगा, मैं इतना सा कहता हूं कि जयपुर पुलिस हैड क्वार्टर के सामने दो बीघा जमीन का आबादी में पट्टा बन गया। यह कितना बड़ा जांच का विषय है और कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह राजस्थान की जनता जानती है, यह दुर्भाग्य पूर्ण है। नियम कायदे बनाएं, एक क्राइटेरिया तय करें, लेकिन आपने सब कुछ कर दिया। जो नहीं करना था, वो भी कर दिया और फिर कहते हैं कि यह पर्ची सरकार है। आप आत्मचिंतन कीजिए, यह राजस्थान के इतिहास की बात है, यह राजस्थान की विधान सभा है, माननीय सभापति महोदय, आज भी इस कुर्सी का सम्मान है। पहली बार हुआ होगा राजस्थान के लोकतंत्र के पवित्र इतिहास में कि लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण ना दें, ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको राजस्थान की जनता ने चुनकर सीएलपी लीडर बनाया है। मैं आपके माध्यम से सीएलपी लीडर से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बड़े हैं, पद की गरिमा है। विपक्ष में कितने रहे, कितनों को देखा है, हम ज्यादा नहीं रहे, दूसरी बार आये हैं, लेकिन हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, चाहे आदरणीय गुलाब जी कटारिया हो, या कोई भी व्यक्ति हो, राजेन्द्र जी राठौड़ थे, सीट पर बैठे रहते थे, नारे लगाते थे, लेकिन सीट छोड़ कर वैल में नहीं आते थे। क्या हो गया? आपको जनता ने जिता कर भेजा है, आप सरकार में नहीं आये तो आप अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को सदन में रखने के लिये नियम-कानून का पालन नहीं कर सकते? नियम कानून का पालन करके जो अच्छे मुद्दे हैं,

जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, उन मुद्दों को लाना चाहिये। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान के पवित्र सदन में कभी नहीं हुआ होगा कि आसन की कुर्सी से आँख में आंसू आ जाये। आप हमारे गार्जिन के बराबर हैं, हमारे पिता तुल्य हो, आसन की सबको इज्जत करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नियम कानून बनाये कि जो आसन का अपमान करें, वह व्यक्ति स्वत: ही 6 महीने के लिये या पूरे साल के लिये निलम्बित माना जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको और सरकार को पुन: धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने और पूरी टीम ने जो 2025-26 का बजट दिया है, यह राजस्थान के हित में होगा। यह गरीब, किसान, नौजवान, छात्र-छात्राओं, महिलाओं के हित में होगा। यह जो दूसरा बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने दिया है, यह निश्चित रूप से गांव-गरीब के हित में जो अच्छे निर्णय सरकार ने किये हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिये बहुत काम आयेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबा बालकनाथ।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे इस बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। अच्छा होता कि विपक्ष के लोग भी आज यहां बैठे होते और विपक्ष को भी पता लगता कि उन्होंने पूर्व में राजस्थान में स्वतंत्र भारत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने देश को कैसे-कैसे लूटने का काम किया है। आज हमारे सभी माननीय विधायकों ने अपनी चर्चा में हरेक विषय को बहुत ही अच्छे स्वरूप से और तथ्यों के साथ हम सबके बीच में रखा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को और हमारे राजस्थान प्रदेश की उप मुख्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने न केवल राजस्थान के मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में, अपितु राजस्थान की 200-200 विधान सभा क्षेत्र में, यह विपक्ष को भी सोचना चाहिये कि राजस्थान की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले हमारे राजस्थान के नागरिकों का ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, सभी को योजनाओं का और राजस्थान प्रदेश के पैसों का लाभ देने का काम किया, उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सुन रहा था जब हमारे गुरमीत सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने गंगानगर के साथ सभी विधान सभा क्षेत्रों की चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जहां जिस विकास की आवश्यकता है, उस विकास को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी सरकार की भावना है, हमारे प्रधान मंत्री जी की जो भावना है, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने इस बजट को राजस्थान की जनता के लिये समर्पित किया और हर वर्ग को और हरेक क्षेत्र को इस बजट के हिस्से में क्षेत्र की योजना के माध्यम से, उसके विकास के माध्यम से जो कार्य आवश्यक हैं, उन कार्यों को इस बजट में स्थान देकर आने वाले भविष्य में करवाने का काम किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे तिजारा के लिये भी अनेक योजनाएं, चाहे महिला कॉलेज की बात हो, महिला हॉस्टल की बात हो या क्षेत्र में पूर्व के बजट में और वर्तमान बजट में, 20-20, 25-25 सालों से क्षेत्र की जनता की मांगें थीं ...

**msk/rtm/27.02.25/1740/3j**

उन मांगों पर संज्ञान लेकर इस बजट के अन्दर उनको और आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोगों को भी विकास के पथ, हर क्षेत्र के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बजट के अन्दर जो राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ, जो मेरे संज्ञान में है कि दस-दस करोड़ रुपये हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए जो पैसा दिया, उसमें नॉन-पेचेबल का जो पैसा मिला है, मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसमें मिसिंग लिंक को भी जोड़ा जाये, जिसके माध्यम से जहां कोई सड़क बनानी आवश्यक है, माननीय विधायक उसका संज्ञान लेंगे और आपके माध्यम से अनुशंसा करेंगे ताकि मिसिंग लिंक भी, हमारे क्षेत्र का और भला, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से होना सुनिश्चित होगा।

**(समय: बजे)**

**(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)**

मैं इस बजट के अन्दर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो तिजारा क्षेत्र है, जिसमें खैरथल-तिजारा जिला है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले समय में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि खैरथल-तिजारा को यथावत रखकर हमारे जिले को आगे बढ़ाने का, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और खैरथल-तिजारा में आने वाले में समय पर जो विकास बढ़ेगा, उसमें हमारे तिजारा के अन्दर आने वाले समय में सेशन न्यायालय खुलना चाहिए। तिजारा की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार भी तिजारा में सेशन न्यायालय खुलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसकी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तिजारा के एक तरफ मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र के इर्द-गिर्द कुछ ऐसी संस्थाएं काम करती हैं, जो सदैव हमारे देश को और हमारे देश के आपस के भाइचारे को तोड़ने का काम करती हैं। चाहे धर्म परिवर्तन की घटनाएं हों, चाहे उसके साथ-साथ गो-कसी की घटनाएं हो, चोरी-चपाटी की घटनाएं हैं, ओएलएक्स है, टटलूबाजी हैं, अनेकों ऐसी चीजें वहां से संचालित की जाती हैं और मुझे लगता है कि अगर वहां सेशन न्यायालय खुलेगा तो उसके माध्यम से वहां पर ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि वहां पर जब न्यायाधीश बैठेंगे, न्यायाधीश जहां पर बैठते हैं तो वहां पर प्रशासन और पुलिस विभाग भी एक्टिव होता है और कोई भी ऐसी घटना होगी, जिसका संज्ञान न्यायाधीश को तुरंत मिलेगा, जिसके माध्यम से आने वाले समय में अपराधों में भी कमी आयेगी और उस क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी के साथ-साथ में हमारे तिजारा के अन्दर अन्य जो प्रशासनिक कार्यालय बराबर रूप से खुलने चाहिए। हमारे जितने भी विभाग हैं, जिनके मुख्य कार्यालय जिला स्तर पर होते हैं, वहां पर जमीन की उपलब्धता भी है और अपार संभावनाएं भी हैं और पूरे खैरथल-तिजारा क्षेत्र के जिले का केन्द्र भी है। उस भावना के साथ भी हमारे खैरथल-तिजारा के अन्दर ये सभी कार्यालय भी वहां पर खुलें, जिससे आने वाले समय के अन्दर, जो बड़ी औद्योगिक नगरी है, तिजारा विधान सभा भिवाड़ी क्षेत्र, उसको भी आने वाले समय में एक अच्छी गति मिलेगी।

मैं इस विधान सभा के परिसर में इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हम सब को, हमारे सभी माननीय विधायकों, जो हमारा और पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव कहेंगे, मेला कहेंगे, कुंभ मेला, जो अभी कल सम्पन्न हुआ है। उसमें सभी माननीय सदस्यों को कुंभ नगरी में ले जाकर, प्रयाग क्षेत्र में ले जाकर सभी को स्नान कराने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद, अभिनन्दन करता हूं। मैं विचार कर रहा था कि विपक्ष के कुछ नेता तो गये हैं, लेकिन ज्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की ऐसी है, जो कुंभ क्षेत्र में स्नान करने गये ही नहीं। जब भी विपक्ष के लोग आएं तो मेरा यह प्रश्न रहेगा कि पूरे भारत वर्ष से क्या, पूरी दुनिया लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने तीर्थ नगरी प्रयाजराज में जाकर पवित्र स्नान किया है, पुण्य के भागी बने हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गये? यह मेरा प्रश्न है। मैं ऐसा प्रश्न भी लगा सकता हूं, अगर मुझे ऐसी व्यवस्था दी जाये तो मैं कांग्रेस से पूछना भी चाहूंगा कि वे लोग कुंभ के स्नान में क्यों नहीं गये? उनके कुछ नेता गये हैं, जिन्हें अपनी धर्म संस्कृति में आस्था है, लेकिन उनकी बड़ी संख्या ऐसी है, जो नहीं गये। क्या कारण है? यह कारण दर्शाता है, कांग्रेस की विचाराधारा को, कांग्रेस की नीति को और जो आज पूरा देश भी जान चुका है कि कांग्रेस कभी भी देश के हित में, सनातन धर्म के हित में, कांग्रेस की विचारधारा काम नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल देश के लोगों को आपस में विभाजित करना, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर हो। कांग्रेस केवल और केवल यही चाहती है कि देश के लोगों को आपस में बांटकर अपनी दुकानदारी संजाना, अपना काम संजाना और पैसा कमाना, यही कांग्रेस का कार्य रहा है।

अभी मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने सदन से वाक्आउट किया हुआ है। ऐसा क्या विषय है? जो बात सत्य है, वही तो हमारी तरफ से कही गयी। हमारे एक नेता ने कही, उसमें गलती क्या है? आपका पारिवारिक रिश्ता है, नाता है, उसी को तो उजागर किया गया है। उसमें गलत क्या कहा गया? लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने उसको मुद्दा बनाकर इस प्रकार से सदन को बाधित करने का काम किया, राजस्थान की जनता का जो पैसा, राजस्थान की जनता की आवाज को उठाने के लिए हम सब लोग यहां पर आये हैं, उस पर चर्चा न करके अनावश्यक किसी विषय के ऊपर इस प्रकार से राजस्थान की जनता के विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है, उसको राजस्थान की जनता भलीभांति जानती

है और यह समझती है कि आने वाले समय में राजस्थान में एक नये युग की शुरूआत 2023 के चुनाव के बाद में हो चुकी है और निरन्तर आने वाले चुनावों में भाजपा का ही परचम लहरायेगा और पुनः भाजपा की ही सरकार 2028 में बनेगी, यह बात मैं आज आप सबके बीच में कहता हूं। यह बात आपको 2028 में प्रमाणित होती हुई दिखेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात मैंने पीछे के समय पर.. ...(व्यवधान)...

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन में प्रवेश)**

मेरे को पहले ही बुलवा लेते तो टीकाराम जूली जी पहले ही आ जाते। चलो, ऐसा है। ...(व्यवधान)... माननीय सभी विपक्ष के नेताओं मैं कहना चाहता हूं। विपक्ष के सभी कांग्रेस के भाई बंधु आये हैं, इनको कहना चाहता हूं कि सदन के बाद, देखिये, प्रयाग की भूमि है। प्रयाग की भूमि पर विश्व का सबसे बड़े आयोजन कुंभ का कल महाशिवरात्रि को समापन हुआ है। जो-जो कांग्रेस के नेता कुंभ नहीं जा पाये, उनको मेरी तरफ से न्यौता है। आपको ले जाने की व्यवस्था मैं करता हूं, आपको वहां पर स्नान कराने की व्यवस्था मैं करता हूं। देखिये, उसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो भी पाप आपने पिछले 5 वर्षों में, 60 सालों में, 70 सालों में किये, वे सारे आपके धुलेंगे और यह मेरा दावा है। ...(व्यवधान)... क्योंकि ऐसा है कि वहां पर जो इतने संतों ने ...(व्यवधान)... आप शांति का दान दें।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य। आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखें।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): देखिये, आप बुरा मत मानिये। पाप क्या होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैंने यह कहा कि आप सबको ले जाने का कार्य मैं करता हूं। मेरे को आप सेवा का अवसर दें, मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा। मेरे से भी कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई आप हुआ होगा तो मुझे भी उनको धोने का अवसर मिलेगा। साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं। देखिये, आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। हजारों-हजार वर्ष, हजारों-लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन उस पवित्र भूमि पर होता है और वह पवित्र भूमि इतनी पवित्र है ...(व्यवधान)... मेरी बात को सुनिये। देखिये, आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है? आप मेरी बात को सुनिये। आप अपने कुल देवता, ब्राह्मण हैं, उनसे पूछ लीजियेगा। आपके जो गुरु हैं, वे भी बतायेंगे कि जो मैंने कहा है, सत्य कहा है। इतना बड़ा आयोजन और लाखों वर्षों से वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। वहां पर पवित्र त्रिवेणी का संगम है। आप अनुमान लगाइये कि लाखों वर्षों से अरबों-खरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में साधु संतों ने उस पवित्र भूमि पर स्नान किया है। वहां की गंगा की जो मिट्टी है, जो रज है, वह रज भी इतनी पवित्र है कि लाखों वर्षों से अनेकों लाखों करोड़ों/अरबों श्रद्धालुओं ने वहां पर उनके कदमों से उस पवित्र भूमि का स्पर्श हुआ है। साधु-संतों से उस पवित्र भूमि का स्पर्श हुआ है।

**mdp/rtm/27.02.2025/17:50/3k**

आज जो भारतवर्ष के अन्दर 2025 का प्रयागक्षेत्र का कुम्भ है, उस कुम्भ के अन्दर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, साधु-संतों नेकिया, उन सबके स्नान का फल जो वे सब करके निकल गये और उस पवित्र स्नान पर जब आप उनके जाने के बाद स्नान करेंगे तो आपको उनका भी पुण्य प्राप्त होगा और पिछले कर्मो, पिछले जन्मों के अन्दर, वर्तमान जन्म के अन्दर जो कुछ भी आपसे पाप हुआ है, जो किसी से भी कुछ पाप हुआ है, उसका भी आपका पिंडदान होगा और मैं मानता हूं कि आने वाले समय पर आप भी जो आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ में मिलकर आप भी राजस्थान के विकास की चिंता करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश बदल चुका है, देश के लोगों की विचारधारा बदल चुकी है, लेकिन कांग्रेस यथावत वहीं पर ही है, जो आज से पहले थी, जो उनसे पूर्वजों में थी, उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं है।

देखिए, किस प्रकार से राजस्थान में इन्होंने जिले बनाये। माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीगण भी यहां बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, जितने भी इन्होंने 19 जिले बनाए, मेरा आपसे यह कहना है कि उसकी जांच हों। 19 जिलों की घोषणा करने से पहले जो भी कांग्रेस के दलाल थे, उनको पता था कि कहां-कहां जिला गठित होने जा रहा है, वहां-वहां की आस-पड़ोस की सारी जमीनें, मुख्य-मुख्य जमीनें थी, कांग्रेस चट्टे-बट्टों ने वह जमीनें खरीद ली। जमीनें खरीदने के बाद में जैसे ही जिला घोषित हुआ और जिला घोषित होने के 6 महीने के अन्दर-अन्दर वह जमीनें बेचकर वहां से निकल गये। ये तो जिला बनाने की इनकी कार्ययोजना है। राजस्थान के विकास की चिंता के लिए जिला नहीं बनाना था, केवल जिला इस बात के लिए बनाना था, इस बात के लिए यहां इस सदन में घोषणा होती थी, इस बात के लिए, इस सदन के अन्दर कांग्रेस ने अपनी घोषणा या बजट का उपयोग किया ताकि कांग्रेस के जो चेले-चपाटे हैं, वह प्रोपर्टी के मामले में, प्रोपर्टी के धंधे में अपना पैसा कमाएं और मौज करें, क्योंकि ये तो जनता का लूट रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है, ....(व्यवधान)... उनको इस प्रकार का अवसर देकर उनको जमीनों की लूट मचाने का काम करें। मैं दावे से कहता हूं कि जितने जिले बने हैं, उन जिलों के आस-पड़ौस में जितनी जमीनें, उस समय पर जिला बनने से पहले कितनी जमीनें बिकी और जिला बनने के बाद में वह जमीनें बेचकर निकल गये, आज उन लोगों को बरबादी के कगार पर लाकर इन लोगों ने छोड़ दिया। यही कार्ययोजना इन सरकारों की रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि इनके एक-एक कार्य की जांच हो, तभी इनकी बोलती बंद होगी, क्योंकि जब तक इनकी जांच होकर, इनके सामने इनका आइना नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये चुप बैठने वाले नहीं है। इनका आइना, इनको सामने दिखाना पड़ेगा। जो इन्होंने किया है, उस किये हुए को, इनको पारदर्शित रूप से जनता के सामने रखकर, इनके सामने रखकर, इनकी कथनी व करनी में फर्क हमें आने वाले समय में दिखाना होगा। मैं माननीय सभापति जी, का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः कांग्रेस

के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप तैयारी कीजिए, आप सबको कुम्भ स्नान करवा कर आपका भी कल्याण करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रविन्द सिंह जी भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, सभापति महोदय। माफी चाहूं, म्है जानयो कि साहब म्हारा विपक्ष हाला भाई आय रह्या। हमें बोलन रो मौको देव, कोनी देवे।

श्री सभापतिः आप बोलिए। अपनी बात रखिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सबसे पहले तो मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा एक बार जब हम साथ में बैठे हैं, विपक्ष के भाई भी आए हैं, कर्टसी के नाते एक बार टेबल बजाकर इनका स्वागत करना चाहिए। मैं तो निर्दलीय हूं। पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठा हूं। दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि विपक्ष के बिना इस सदन का आनन्द भी नहीं आ रहा था। चर्चा होनी चाहिए। कई सारी कमियां रही हैं। बड़े लोग बैठकर उस चीज को निपटाएंगे, परंतु आपका स्वागत करते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इनकी कमी आप अच्छे से पूरे कर रहे थे, पता है हमको।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं तो आपका अपना हूं। आप मानो या नहीं मानो, वह अलग बात है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अपनी बात रखिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सीमांत के उस क्षेत्र से आता हूं जिन्होंने 1965 व 1971 के कई सारे युद्ध झेले। कई सारे काल और अकाल देखे। सीमांत के लोग बहुत मजबूत है। 1965 व 1971 के उस युद्ध के दौर में जब भी इस देश को जरूरत रही, अपने प्राणों की बाजी उन लोगों ने लगायी।

**(समयः बजे)**

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में बाघा बार्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी करवाने के लिए हम केन्द्र को लिखे। साथ ही साथ, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप एक वॉर म्यूजियम वहां पर डवलप करें ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारा शौर्य दिख सके। मेरा निवेदन रहेगा कि बार्डर को मजबूत करने के लिए वहां पर तमाम जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसके लिए हम सभी को मिलकर एक सामूहिक प्रयास भी करना होगा। मैं डीएनपी क्षेत्र की बात पहले भी कई बार कर चुका हूं। आज भी मेरा पुनः निवेदन रहेगा। डीएनपी के वह गांव जो आज भी बिजली से वंचित हैं, पानी से वंचित हैं, सड़क से वंचित हैं, तमाम उन चीजों से वंचित हैं, उन्हों जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा। एक तरफ जब हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): दूसरी तरफ हमारे वहां उस डीएनपी क्षेत्र में आज भी मोबाइल नेटवर्क की बड़ी कमी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वन मंत्री जी को उन्होंने आज आश्वासन दिया कि आने वाले समय में कई सारे मोबाइल नेटवर्क वहां पर डवलप किये जाएंगे। साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एजुकेशन के मामले में जो क्षेत्र दिन-ब-दिन पिछड़ता जा रहा है, वहां पर हम शिक्षकों की पूर्ति करके जो कमी वहां पर है, उसको भरकर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः अध्यक्ष महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: बजट पर चर्चा समाप्त हुई। अब मैं विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, कुछ कहना चाह रहे हैं, माननीय टीकाराज जी जूली।

**अनुरोध एवं मांग**

**दिनांक 21 फरवरी 2025 से उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने हेतु अनुरोध**

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से सदन के अन्दर गतिरोध रहा और उसकी वजह से हम लोग यहां भी धरने पर रहे, बाहर भी धरने पर रहे। हमारी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गयी थी, वहां से वह विवाद बढ़ता-बढ़ता यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को, जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से कि ये वार्ता आप चाहते तो आज से चार दिन पहले हो जाती। हमें न तो यहां सोना पड़ता, न बाहर सड़कों पर रहना पड़ता, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं, माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक है ही यहां के, हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं हैं। हम सब लोगों से मिलकर ही ये सदन बनता है। यही इसकी खूबसूरती है। मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ता पक्ष के, जिन्होंने हमारी कमी को महसूस किया कि बिना विपक्ष के तो मजा नहीं आ रहा, इसके लिए मैं सत्ता पक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बिना एक दूसरे के वे सब चीजें अधूरी हैं। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि-

**आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, एक होने की,**
**यूं बिखरे-बिखरे न तुम अच्छे लगते हो, न हम।**

ये इस सदन की खूबसूरती रही है और कभी-भी गतिरोध पहले भी रहे हैं। इससे बड़े-बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अन्दर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया है।

**Ans/rtm 18.00 3l 27.02.2025**

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविन्द सिंह डोटासरा जी का

जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ, या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई वह आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इससे मुझे कोई संकोच नहीं है।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये परम्पराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं, अच्छी परम्पराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं। जब भी कोई गतिरोध शुरू हो, मैं अध्यक्ष जी से यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, आप मालिक हैं, आसन सर्वोपरि है। हमेशा हम सब लोगों ने चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आसन का सम्मान किया है, आसन को सर्वोपरि रखा है। यहां जिस प्रकार का गतिरोध हुआ, यह गतिरोध नहीं होना चाहिए था। आपने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसी दिन आपसे आग्रह किया था कि हम कभी गतिरोध भी पैदा करें तो आप अपने चेम्बर में बुलाकर हमें दो मिनट में कहेंगे हम मान जाएंगे, क्योंकि हम सदन चलाना चाहते हैं। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहले है, दूसरी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है, सहयोग एक दूसरे का दोनों को चाहिए।

इसलिए मैं, अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदन के नेता ने जो शुरूआत की है उस पर आप व्यवस्था देवे। इंदिरा जी के प्रति जो टिप्पणी की है, उस पर आप व्यवस्था देवें। मैं चाहूंगा कि आगे यह गतिरोध नहीं बने, इस चीज का हमारी तरफ से भी हम ध्यान रखे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी। देखिये, अब तक जो गतिरोध आए हैं, उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं, बीच में इस प्रकार की उत्तेजना बढ़ जाती है कि सदन बाधित होता है, वे नहीं आने चाहिए। समय रहते, विशेष रूप से जिम्मेदारी, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा आपकी है, आप सदन के नेता है, आपके लिए हम और सत्ता पक्ष दोनों ही बराबर है। आपने आज आगे बढ़कर जो पहल की इस प्रकार से जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, मुझे खुशी होगी, आप हमें बुलाएंगे और आप जो भी निर्देश देंगे, दोनों के जो हित में है, प्रदेश के हित में है, राजस्थान के हित में है, वह निर्णय हम ले, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो घटना हुई, यह सही नहीं थी, हमारी परम्पराओं के अनुरूप नहीं थी, इसके लिए हमें खेद है।

श्री अध्यक्षः इसमें मुझे जो बताया गया कि माननीय डोटासरा जी के द्वारा जो अमर्यादित आचरण हुआ, उसके लिये क्षमा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष)ः वही बोला है, साहब। आप खूब स्पष्ट सुन लें, गोविन्द सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वे आसन तक आये या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री)ः माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को, उनके मुख्य सचेतक जी को कि लगातार उन्होंने पहल की, सम्पर्क किया। जो गतिरोध सदन के अन्दर था, यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा हर विषय पर

वाद-विवाद होता है, तो कई बातें ऐसी होती हैं हम नहीं कहना चाहतेख फिर भी वे निकल जाती हैं, लेकिन उसके लिए हम इस बात को इतना खींचे कि सदन बाधित हो, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम वे लोग हैं जो राजस्थान की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं।

मित्रों मैं कहना चाहता हूं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको राजस्थान की जनता ने, चाहे वे पक्ष में हों प्रतिपक्ष में हों, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी आशा है। आप अगर उनके मन में भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति उनका जो भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरे की बात खतम हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं। हम अपने ईगो के लिए भी नहीं हैं। हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए सदन में आए हैं। हम इसलिए भी नहीं है कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वह जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वह खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमारे कोई भी माननीय सदस्य, उनके मुंह से अगर कोई भी गलत बात निकलेगी उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। इसलिए होता है कि हमने सदन में जो बात कही है वह उसके अनुरूप नहीं है। हम कुछ भी बोले, हम अपनी बात रखें, हमें उसको सोच विचार कर रखना चाहिए। छोटी सी बात कोई भी हो सकती है, लेकिन वह बढ़ते-बढ़ते कितनी हो जाती है, आखिरकार उसको खतम तो करना ही पड़ता है। आखिरकार काम तो वही होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अध्यक्ष के आसन पर अब से पहले बहुत बड़े माननीय हमारे अध्यक्ष रहे हैं। चाहे नरोत्तम लाल जी जोशी हों, रामनिवास जी मिर्धा हों, रामकिशोर जी व्यास हों, लक्ष्मण सिंह जी हों, पूनम चंद जी विश्नोई हों, हीरालाल देवपुरा हों, हरिशंकर भाभड़ा जी हों, शांति लाल जी चपलोत हों, परसराम मदेरणा जी हों, कैलाश जी मेघवाल हों, सी.पी.जोशी जी हों, गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी जी हों, दीपेन्द्र सिंह जी, समर्थलाल जी, बहुत हैं। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह सभी हमारे सम्माननीय होते हैं। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष इस सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। कुछ बातें ये भी हैं क्योंकि जब मैं देखता हूं, सदन चलता है हमारे कई साथी हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा यह है कि हम उसकी पालना करें। हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं, जोर से हल्ला मचाते हुए, एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है। इसका पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक-एक मिनट कैसे उपयोगी हो सकता है, हम राजस्थान की जनता के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता

है।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं दो-तीन दिन से सदन में बड़ा व्यवधान, कई लोगों ने कहा कि सदन की कार्यवाही आगे के लिए कर दी जाए, मैंने कहा नहीं, सदन इसके लिए नहीं होता है, सदन राजस्थान की जनता का है। एक उस तरह का आसरा है जहां राजस्थान की जनता सोचती है कि हमारे बारे में विचार होता है, हमारे बारे में राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वे हमारे लिए सोचते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम भावावेश में आकर कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं।

**VPS-RTM-27.02.2025-18.10-3m**

मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। कभी-कभी कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं, पर मैं तो यह कहता हूं कि आदमी जब बड़ा होता है तो उसको बड़े के आधार पर व्यवहार भी बदलना होता है, आचरण भी बदलना होता है, उसको यह देखना भी पड़ता है कि मैं आखिर किस पद पर हूं, कैसे मुझे यह करना है, कैसे नहीं करना है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं, वह ही झुकता है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से और मैं आगे के लिए भी इतना कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, यह ठीक नहीं है।

मैं इसलिए यह ही निवेदन करूंगा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी है और कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, यह दोनों की जिम्मेदारी है और मैं यह कहता हूं कि हमारे दो सौ सदस्यों की यह जिम्मेदारी है। हर सदस्य चुनकर आया है। उनको अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए हमारे सदन की मर्यादा कैसे रहे, मैं अपनी बात कैसे कह पाऊं, कभी-कभी होता था, इस सदन में देखा है और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उनको भी हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं। आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने यह अच्छी बात कही। यह हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा। अच्छे को अच्छा कहना, हमें उसको उत्साहित करना होगा और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। यह हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और हमारे अध्यक्षजी से मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्षजी ने भी उस दिन यह कहा कि हमने उस शब्द को जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले, उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप, विलोपित करने का निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि यह हम सबका दायित्व है। यह जनता पूरा देखती है। सब कुछ देखती है। वह आपके बारे में टिप्पणी हो या इधर के बारे में टिप्पणी हो, वह टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को,

जिस भाव और भावना से इस सदन में हमको राजस्थान की जनता ने भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है। यह आपका दायित्व है।

हमेशा हम यह कहते हैं कि विपक्ष हमारी ताकत है। विपक्ष हमारे उन कामों को भी बताता है और विपक्ष जब कहता है तो हम उस बात पर संज्ञान भी लेते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि आपने कौनसी बात ठीक प्रकार से कही है, जिसका हमारी सरकार से, हमारे राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिले। यह हमेशा हमने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत होता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को गरिमापूर्ण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आपके दिल को तो ठेस लगी है, निश्चित रूप से हम भी आपसे यह कहना चाहते हैं कि ये सदन के सभी सदस्य आपके उस धैर्य को, आपने जिस तरह से किया, लेकिन इतना ही है, उस दिन जो मैं देख रहा था, मैं सी.एम.ओ. में बैठा था, इतना समय नहीं मिला, सदस्य ने बात उठाई और वह तीन मिनट के, ढाई मिनट के अन्दर यह वाकया पूरा हुआ। थोड़ा हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर वह ही काम होना है तो थोड़ा उसमें समय लेते हुए हमें आगे हमारे काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है।

अध्यक्षजी, पुनः आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद, जो सत्ता पक्ष के हमारे सभी माननीय सदस्य हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक प्रकार से अपना काम किया है और आगे भी सभी आप लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए हैं। जनता की हर बात का ध्यान रखते हुए, राजस्थान हमारा किस तरह से विकसित हो, राजस्थान हमारा उत्कृष्ट हो, सभी विषयों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी, विपक्ष के नेता जूली जी, जो दोनों ने अपनी-अपनी बात सदन में रखी है, वास्तव में ये बातें राजस्थान विधान सभा में जो घटित हुईं, यह बहुत ही गम्भीर और चिंतनीय है। मैं भी लगभग जब से समझ आयी है तब से संसद की कार्यवाही, विभिन्न विधान सभाओं की कार्यवाही मैंने देखी है, समझी है। गतिरोध आते हैं, समाधान भी निकलता है, लेकिन इस प्रकार की घटना तो मुझे यह लगता है कि देश की किसी विधान सभा में, किसी भी सदस्य ने, वह भी एक विपक्षी दल का बड़ा नेता हो, उसने कभी भी नहीं किया।

बारबार यह कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा और छोटों को उत्पात, यह कहा जाता है, लेकिन उसमें छोटों के उत्पात की भी एक सीमा होती है। जब सीमाएं अपनी लांघ देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। गतिरोध के बारे में भी मैं लगातार सम्पर्क में था, विपक्ष के नेताओं से भी था और माननीय मुख्य मंत्रीजी और बाकी सदस्यों के भी सम्पर्क में था और जब यह कहा गया तो मैंने यह कहा कि दोनों पक्ष सर्व-सम्मति बनाकर मेरे पास आएं और मुझे उसमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यह चाहूंगा कि समाधान

निकले, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन यह घटना हुई, जो मंत्रीजी ने कुछ कहा, आज भी वह रिकार्ड में है, मैंने यह कहा कि इसको देखकर मैं उसका समाधान निकाल दूंगा, समाधान करूंगा तो उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। हार्डली दो मिनट ही हुए थे, वे तुरंत डायस पर आ गये तो मेरे लिए निर्णय लेने का भी समय मुझे नहीं मिला।

इसलिए चाहे इधर से हो या चाहे इधर से हो, हमेशा अध्यक्ष पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यहां पर अध्यक्ष, केवल मेरा नाम, मेरे से सम्मान की बात नहीं है, यह आसन का सम्मान है और आसन को सर्वोपरि कहते हैं, लेकिन कहने से ही सर्वोपरि नहीं बनता। अपने व्यवहार और आचरण में वह सर्वोपरि दिखना भी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए।

अब विपक्ष के नेता ने जिन सदस्य के बारे में क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है, मैं यह आशा करता हूं कि विपक्ष के नेता उनको अपने आचरण में यह परिवर्तन लाने के लिए सुनिश्चित करेंगे और अनुशासन का पालन करने के लिए आग्रह करेंगे। मैं यह कई बार प्रयत्न करता हूं, कोई सदस्य आउट ऑफ कंट्रोल इधर भी कुछ हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं यानी, सदन के नेता के कंट्रोल में सब इधर के लोग रहें और जब सदन के नेता नहीं हैं तो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं, वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इधर विपक्ष के नेता हैं, ये किसी को कहें कि बैठो तो बैठना चाहिए। ये किसी को कहे कि आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना चाहिए। जब तक यह नियंत्रण दोनों पक्षों के नेता अपने-अपने दलों में नहीं रखेंगे, तब तक सदन को चलना, चलाना बहुत ही कठिन होगा।

हम सब समझदार हैं, आखिर जन-प्रतिनिधि चुनकर आये हैं। लगभग हर जगह दो लाख, तीन लाख मतदाताओं से चुनकर आये हैं, उनकी अपेक्षाएं भी हैं और अपेक्षा के मुद्दे पर आप यहां पर खरे उतरें लेकिन मुझे पिछले साल-डेढ़ साल से यह लग रहा है और स्पेशली उस दिन से लग रहा है जिस दिन मुख्य मंत्रीजी का भाषण था। उस समय भी दो बार मैंने रोककर बुलाया। दुर्योग कहें या संयोग कहें, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाया और आज भी जब स्थिति बनी, आखिर हमारी बातचीत लगातार हो रही थी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और विपक्ष के नेता को धन्यवाद दूंगा कि वे इस समय निकले हैं लेकिन इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि आज सदस्य क्षमा, मेरी यह इच्छा थी कि क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणियां थीं, वे टिप्पणियां शायद इतिहास में लिखी जाएंगी, वह कलंक के बराबर होंगी लेकिन क्षमा के बाद सब चीजें रुक जाती हैं, लेकिन वह क्षमा, आखिरी दिन दुबारा उस तरह का आचरण होता है तो फिर उस क्षमा का कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप माननीय सदस्य को, यहां चूंकि, वे निलंबित हैं इसलिए वे कुछ नहीं, यहां पर सदन में नहीं आ सकते इसलिए वे अभी यहां पर नहीं हैं इसलिए उनके नाम पर विपक्ष के नेता ने जो क्षमा-याचना की है, खेद प्रकट किया है, मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार करते हुए आगे से उनके आचरण को और अनुशासन को सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। भविष्य में कंट्रोल भी रखेंगे, ताकि ये टिप्पणियां, वास्तव में जब मेरे से यह चर्चा हुई, क्षमा योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आपने एक नेता के रूप में क्षमा

मांगी है तो मैं आप पर विश्वास करते हुए यह बात कहता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं कहे ताकि सदन सुचारु रूप से चले और सदन चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। यह कहे कि साहब, केवल पक्ष का है तो भी नहीं है और केवल विपक्ष का है तो भी नहीं है। दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक आसन तो फिर इस प्रकार का होगा।

कल ही मैंने वैसे व्यवस्था दी थी कि अब कोई भी इस डायस पर आयेगा तो उसके निलंबन का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, वह पार्लियामेंट के अनुसार ऑटोमैटिक यहां से निलंबित माना जायेगा। इस प्रकार से करते हैं। अब अनुशासन में हम लोग रहें। कोई बात कहनी है तो मेरे चैम्बर में आकर कहें, मैं सबसे मिलता हूं। आज शायद मैं यह समझता हूं कि मैंने सर्वदलीय बैठक में भी यह कहा और अभी भी शायद पहले कितना समय बैठते हो, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूं। कोई विपक्ष का सदस्य आये, पक्ष का आये, सबके साथ मिलता हूं, उसकी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करता हूं अपनी क्षमता के अनुसार और उसमें हर व्यक्ति कोई भी भगवान नहीं होता, इसको स्वीकार करें।

**ssy/rtm/**27.02.2025**/**1**8.2**0**/3n**

लेकिन कही हुई बात का बार-बार यदि उसका उल्लंघन होता है तो फिर कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह कठोरता बरतने का दुबारा अवसर ना मिले, हम इसका पालन करते हुए एक अनुशासित और राजस्थान की जनता के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें। मैंने भी विपक्ष के नेता और कई लोगों से बैठक में कहा है कि मैं चाहता हूं कि सदन अधिक दिन चले, सदन में अधिक क्वेश्चन आयें, सदन में अधिक बहस हो। आपकी जितनी समस्याएं हैं वे आप मुद्दे रखो, सरकार उसको सुने और जितना संभव हो, नियमानुसार वह भी समाधान हो, ताकि एक आदर्श विधान सभा के रूप में विकसित हो।

मैं साल, सवा साल से इसी में लग रहा हूं। उसमें आपका सहयोग भी मिला है। लेकिन बीच-बीच में इस प्रकार की जो बातें आती हैं, वह बड़ी पीड़ा दायक और कष्ट दायक होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों के आने से, बाकी लोगों ने भी सुन लिया होगा, वे भी आचरण करें। यह केवल अकेले विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता की बात नहीं है। यह जो 200 लोग बैठे हैं, यह सबके लिए है। सब लोग इसको अपने व्यवहार और आचरण में लायें, ताकि यह विधान सभा देश में अपना नाम रोशन कर सके। नाम विधान सभा का होगा। इसमें अध्यक्ष की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष तो एक निमित्त है जो आप लोगों ने सर्वसम्मति से चुना।

मुझे वह शब्द याद आते हैं जिस दिन आपने निर्विरोध मेरे को निर्वाचित किया। उस दिन आपने जो भावनाएं रखीं और मैंने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यह व्यक्तिगत बातचीत में होता है। लेकिन कई बार कहते हैं कि व्यक्तिगत बातचीत में तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सार्वजनिक में नहीं। भैया, सार्वजनिक

रूप से तो आप आलोचना करो और अन्दर आकर के कोई हाथ जोड़ ले, पाँव पड़ ले, यह नहीं। जो आचरण अन्दर है वही आचरण बाहर है। सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान और अन्दर माफी, यह नहीं, इसलिए आज मेरा आग्रह था जो आपने किया। मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा मन करके इस प्रकार का किया। अब मैं सोचता हूं कि सचेतक महोदय को मैं कहूंगा कि वे उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव लाएं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बहाली के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बहाली के लिए।

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बहाली के लिए, बहाली।

श्री अध्यक्ष: हां, बहाली के लिए। निलंबन वापस लेना है, बहाली, एक ही बात है। निलंबन के लिए नहीं कह रहा हूं।

## सदस्य का निलम्बन

### सर्व श्री (1) गोविन्द सिंह डोटासरा, (2) रामकेश, (3) अमीन कागजी, (4) जाकिर हुसैन गैसावत, (5) हाकम अली खां एवं (6) संजय कुमार, सदस्यगण के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष और सदन के नेता महोदय और आपने जो उद्गार प्रकट किये हैं, उस सबसे लब्बोलुआब यही है कि पक्ष, विपक्ष जब आमने-सामने होंगे तो टकराव भी होगा, आरोप-प्रत्यारोप भी होंगे। उत्तेजना के क्षण भी आयेंगे। पर हम सबका दायित्व है कि उत्तेजना के क्षणों में भी हम मर्यादा की सीमा नहीं लांघें। कुछ ऐसा नहीं कर जायें जिसके लिए हमारी निंदा हो। कुछ ऐसा नहीं कर जायें जिसके कारण हमको लज्जित होना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहकर फिर प्रस्ताव लाना चाहूंगा,

**'दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रखो,**
**जब कभी फिर सामना हो शर्मिंदा ना होना पड़े।'**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रक्रिया के नियम 292 (2) के परन्तुक के अंतर्गत निम्नांकित प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 21 फरवरी, 2025 को सदन द्वारा निम्नांकित माननीय सदस्यों का जो निलंबन किया गया था, उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाये:-

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा

(2)श्री रामकेश मीणा

(3)श्री अमीन कागजी

(4)श्री जाकिर हुसैन गैसावत

(5)श्री हाकम अली खां

(6)श्री संजय कुमार

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी

सहमति प्रकट करता है?

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

अब बीच में नहीं, अब कुछ नहीं, नो, नो। माननीय विपक्ष के नेता। माननीय आप बैठें, नो ...(व्यवधान)... अब जो हो गया। माननीय विपक्ष के नेता, बजट पर अपनी बात रखें। अब कुछ नहीं। अब इनका बोलना शुरू हो गया, अब आप बैठो। बाकी बातें कल। बाकी बातें कल, आज कुछ नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कुछ नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

**आय-व्ययक**

**आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद**

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। दो लाइनों के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। गुरु जी आप तो चुप रहो।

**'उसूलों पर जहां आंच आये टकराना जरूरी है,**
**जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है,**
**आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे ना देख,**
**घर अँधेरा देख, तू आकाश के तारे ना देख।'**

**'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,**
**सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए,**
**सियासत इस क़दर आवाम पर अहसान करती है,**
**पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है।'**

माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी 3-4 दिन का गतिरोध रहा। गतिरोध जब था तब मैं सोच रहा था कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कारण था बजट। बजट में ऐसा कुछ था नहीं कि जो जनता के बीच में उसको लेकर जाया जाए और यह मुख्य मंत्री जी भी जान रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से बजट का 'ब' भी जनता के बीच में नहीं है। जनता सारा समझ गई कि बजट के अन्दर कुछ है नहीं।

मैंने भी कहा कि मुख्य मंत्री जी यह गतिरोध अब तक तोड़ देते। मुख्य मंत्री जी तो भले आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। मेरी भी बात हुई। फिर मेरे को पता चला कि मुख्य मंत्री पर तो दबाव मंत्रियों का है, साहब, ऐसे ही चलने दो, नहीं तो यह क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। यह स्थिति थी। तो यह हकीकत थी।

बीच में एक बात और आई कि दलित को दबाया जा रहा है। दलित को दबाया जा रहा है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): पिछली बार भी नहीं बोलने दिया था आपको।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया, पिछली बार की बात सुनो, यह बेढ़म साहब हमारे पड़ोसी हैं। यह बेढ़म साहब एकदम मेरे पड़ोसी हैं। इनकी रिश्तेदारी भी अलवर में है। पिछली बार जब हमने कहा कि किरोड़ी जी का फोन टेप हो रहा है, हम यहां पर हंगामा कर रहे थे, तो इनको पता था कि आज नेता, प्रतिपक्ष का भाषण होगा। इन्होंने, यहां हम कह रहे हैं कि सरकार से जवाब दिलाओ, तो जोगाराम जी और ये दोनों बतला लिये कि यहां तो जवाब अपने को देना ही नहीं है। बाहर जाकर जवाब देकर आये मीडिया में। वही जवाब यहां दे देते तो क्यों तो हम 7 घंटे यहां नारे लगाते और क्यों हमारा स्पीच नहीं होता। मुख्य कारण यह है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस दिन बेढ़म साहब वक्तव्य सदन में दें। वही बात आपने अगले दिन कह दी। अगले दिन भी तो कही यहीं पर। उसी दिन कह देते तो मेरा भी भाषण हो जाता। बात यह है।

दलित की बात कर रहे हो आप? पहली बार 75 साल में दलित नेता, प्रतिपक्ष बना है। पहली बार। वह भी हमारी कांग्रेस ने ही बनाया है। आपने तो 75 साल में एक बार भी नहीं बनाया। और सुनिये, हमारी सरकार ने तो दलित मुख्य मंत्री भी बनाया है। आप लोगों ने आज तक नहीं बनाया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बीच में हटा भी दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज भी आपकी 21 राज्यों के अन्दर सरकार है, केन्द्र शासित प्रदेश सारे मिलाकर। लेकिन आप बता दीजिये, एक भी दलित को बनाया क्या? एक दलित हमारे डिप्टी सीएम बैरवा जी को बनाया, उनको बनाया जैसा ना बनाया। दूदू और खत्म कर दिया। जो बनी थी वह और बिगाड़ दी आपने। जितना डिप्टी सीएम से लाभ नहीं हुआ, मैं दूदू गया था बीच में, जिस दिन धरना था तो मैं दूदू गया साथ में। मेरे को बड़ा दु:ख हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम साहब को डिप्टी सीएम बनने का जो फायदा मिला ना, उससे कहीं ज्यादा दूदू को खत्म करके उनका आपने वहां नुकसान कर दिया क्षेत्र के अन्दर।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): दूदू में दूदू के लोग थे ही नहीं। वहां पर केवल बाहर के लोग गये हुए थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी पिछली सरकार थी ना तो मुख्य मंत्री जी, 4-4 दलित कैबिनेट मंत्री थे और 5-5 आदिवासी मंत्री थे। लेकिन आपने तो, मैं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब, आपकी भी कह रहा हूं। यादव तो एक भी नहीं बनाया आपने। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हमारे महाराज जी को, डॉक्टर साहब को ...।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह ठीक कही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सही कही है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह बेढ़म साहब मेरे से यह भी कह रहे थे कि यह भी कह देना आज यह बोलो तो कि एक गुर्जर कैबिनेट तो बना दो। मेरे को भी गृह राज्य ही बना रखो है, स्टेट ही बना रखो है, स्टेट भी ऐसा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। ऐसा तो मत करो मुख्य मंत्री जी। भरतपुर का होकर भरतपुर वालों का ही ध्यान नहीं रख रहे। मैं समझता हूं कि पड़ोसी को तो सबसे ज्यादा

नुकसान है। या तो गुरु जी अलवर में नुकसान है या भरतपुर में नुकसान है। मैं समझता हूं कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे।

अभी एक वाकया आया लोक सभा के अन्दर। आपके गृह मंत्री ने कहा कि अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, एक फैशन बन गया है। यह नहीं बनना चाहिए।

**spp/rtm/27.02.2025/18.30/3o**

आपको तो वह बात अच्छी लगी होगी, लेकिन हमारा एक ही दलित है. In Union Government you don't even a Dalit Minister in your top Ministries. Mr. Arjun Ram Meghwal from Rajasthan is a Dalit, but he is not even a Cabinet Minister. This is your liking about Dalits. यह बताती है कि आप लोगों की भारत सरकार में टॉप मिनिस्टरी में कोई दलित नहीं है। You have BJP ruling governments in 21 States and in UTs, but you don't have a single Dalit Chief Minister. About Dalits, यह बात आपको सोचनी पड़ेगी कि यह ऐसा सब क्यों हो रहा है? हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है। खड़गे जी हमारी पार्टी के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं तो आपके बीजेपी में भी मुझे पता चला कि चुनाव चल रहे हैं। जोगारामजी, आप बात कर रहे हैं, देखो साहब। ...(व्यवधान) .. संसदीय मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। बीजेपी ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक महान महिला को बिठाया, उसके सम्बन्ध में आपके नेताओं ने क्या वैचारिक टिप्पणी की? उड़ीसा में कौन मुख्य मंत्री हैं, कृपया वह भी याद कर लें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो इनके रिलेटिव बतायें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): देखिए, आपको 12-13 मिनट हो गये। आप तैयारी करके आये बजट की, लेकिन बजट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चिंता मत करो आप। आप तो यह सोचो कि मैं बजट पर कम से कम बोलूं। जितना कम इस बजट पर बोलूंगा न, ..(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कांग्रेस वालों ने मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवायी हुई कि खड़गे जी नहीं रहे, भगवान करे 200 साल जीएं वे। परंतु इन्होंने उनका क्या हाल किया है? एफ आई आर में ...(व्यवधान).. वे धरती पर नहीं हैं, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। मेरे खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मैं आप सभी से अपील करूंगा। ..(व्यवधान).. एक सैकण्ड। मैं सभी से अपील करूंगा।..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि जब नेता और नेता,प्रतिपक्ष बोलें तो बीच में इंटरवीन नहीं हो। यह क्या मजाक बना रखा है आप सब लोगों ने? मेहरबानी करके आप नेता, प्रतिपक्ष को सुनें, उसके बाद हम सदन के

नेता को सुनेंगे। यह सदन की परम्परा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आप निवेदन फरमाएं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा या निर्देश दूंगा, उसे कुछ भी मानें कि वह सदन के विपक्ष के नेता को शांतिपूर्वक सुनें और इनसे भी अपील करूंगा कि अपना भाषण केवल बजट तक सीमित रखें। बाकी भाषण होते रहेंगे, आगे बहुत समय आयेगा। आज तो समय भी कम है, इसलिए आप जल्दी ही बजट पर अपनी बात रखें ताकि बजट पर उत्तर भी आ जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का मेरे से प्यार है। यह इन लोगों का प्यार है। मैं टोटल बातें बजट पर ही कहूंगा और आप मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, बजट के अलावा रखी हो तो सबको डिलीट कर दोगे आप तो बीजेपी का खाना खाली हो जाएगा। जैसे विपक्ष की तरफ से कोई नहीं बोला न, ऐसे ही इधर का आयेगा। मैं देख रहा था पीछे से क्या-क्या ये लोग बोल रहे थे, उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहां नहीं थे तब पीछे से जो-जो टिप्पणियां की गयी हैं, जिनकी भाषा सम्मानजनक नहीं हैं, उनको भी आप हटाने का काम करें।

अब मैंने एक आप लोगों के ऊपर एक कविता बनायी है। उसको मैं यहां पर सुनाना चाहूगा। आप कहते हो न डबल इंजन, डबल इंजन।

'कि डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी
योजनाओं का नाम बदलकर
भाजपा कहती यह है हमारी
भ्रष्टाचार की सीमाएं
लांघ चुकी है सारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
खत्म किये संभाग-जिले
विकास को लगी नजर तुम्हारी
डींगें हांकी ई.आर.सी.पी. पर
नहीं दी एम.ओ.यू.की जानकारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
शिक्षा पर है चुप्पी साधी
बंद किये स्कूल सरकारी
विधवा, बुड्ढे, दिव्यांग आदि
पेन्शन नहीं की जारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
टूटी सड़कें, उफनते नाले
बहुत हुई बेगारी

जल की एक-एक बूंद को तरसे
देखो जनता हमारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
पेपर लीक, अटकी नियुक्तियां
बढ़ती बेरोजगारी, युवा हुए मजबूर
प्रतिभा भी जीवन हारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
रेप, लूट, हत्या, हिंसा से
डरते प्रदेश के नर-नारी
सक्रिय है खनन माफिया
किसकी है जिम्मेदारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
मुंबई सूं आया पावणां
ठगली बातां सारी
(समझ गये होगे सोनू निगम ने क्या कहा)
कि मुंबई से आया पावणां
ठगली बातां सारी
पैंतीस लाख करोड़ रो सौदो
पोत दी स्याही काली
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।
हाल-बेहाल है प्रदेश का
पर रूकती नहीं दिल्ली की सवारी
(मुख्य मंत्रीजी कितना दिल्ली जाओगे)
कि हाल-बेहाल है प्रदेश का
पर रूकती नहीं दिल्ली की सवारी
नहीं देखी जाती है
अब जनता की यह लाचारी
डबल इंजन की सरकार आयी थी इस बारी।।

अच्छी लगी होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी?

उड़ीसा से जो मुख्य मंत्री हैं, वे आदिवासी हैं, दलित नहीं हैं।

अब मैं बजट पर आ जाता हूं। अब बजट में जो मुख्य मंत्रीजी के और उप मुख्य मंत्रीजी के आंकड़ों में अंतर है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्य मंत्रीजी, आपने 27 जुलाई को सदन में घोषणा की कि हमारे घोषणा पत्र को सरकार एक-एक शब्द को पूरा करेगी और वही बात आपने अभिभाषण में भी कही। लेकिन जो वादों की सच्चाई है न, वह जनता के सामने

आनी चाहिए। आप जब बोल रहे थे, जिस प्रकार से जो अभिभाषण था, तो दो लाइनें मुझे याद आ गयीं-

'कि वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से

मैं एतबार न करता तो क्या करता?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता, क्योंकि अन्दर और बाहर जो आंकड़े हैं, उनमें काफी अंतर आया है। आपने 07 फरवरी को अभिभाषण में गिनाया कि पिछले बजट में हमने 1272 घोषणाएं की थीं। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है। और आपने 297 तो पूरी कर लीं और 488 की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकल गयी और काम प्रगति पर है। यानी हम दोनों को जोड़ें तो 785 घोषणाएं यानी 61 प्रतिशत हुईं। आप कह रहे थे 61 प्रतिशत, 7 तारीख को और 19 फरवरी को डिप्टी सी.एम. साहिबा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि 73 प्रतिशत घोषणाएं प्रगतिरत हैं, तो यह 12 दिन में ही 12 प्रतिशत का अंतर कैसे आ गया, यह बता देना जब आप बोलें तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काम करने की गति ज्यादा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): डिप्टी सी.एम. साहब ने पिछले भाषण में और सी.एम. साहब ने अपने भाषण में जो अंतर बताया, आपने यह कहा कि 2028 तक प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। यह सी.एम. साहब ने कहा 07 फरवरी को और फिर 19 फरवरी को आपने बजट में कहा कि हम 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। यह डबल इंजन की सरकार है तो घंटा, दो घंटा लेट हो जाये या दो-दो साल लेट हो। दो-दो साल का अंतर, आप चैक कर लेना। एक भी वर्ड, एक भी तथ्य, सबके स्रोत आपके बजट हैं, उनके आधार पर ही मैं बोल रहा हूं। इसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए यह टार्गेट बढ़ता ही जा रहा है। अगले बजट में और हो सकता है कि आप इसको 2032 कर देंगे या 2042 कर देंगे, यह तो समय बताएगा। पिछली बार आपने जो प्रेस कांफ्रेंस की तो, मुख्य मंत्रीजी, आपने डिप्टी सी.एम. साहब को साथ में ही नहीं बिठाया। बजट इन्होंने पास किया और बजट पर प्रेस कांफ्रेंस आपने की। अब की बार साथ तो बिठाया, पर अबकी बार भी प्रेस को ब्रीफ आपने ही किया। वित्त मंत्रीजी को भी थोड़ा मौका दो। जब बजट इन्होंने पढ़ा है तो थोड़ा सा बाहर बतायें तो सही।

**jyg/rtm/27.02.25/18.40/3p**

अब इसमें जो गैप आया है दो साल का 350 बिलियन डॉलर की जीडीपी अपनी आगे गयी उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आपने पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17 लाख 81 हजार करोड़ रुपये हो जायेगी। परंतु अब आप बता रहे हो कि स्टेट जीडीपी 17 लाख 04 हजार करोड़ रुपये तक ही पहुंचेगी, यानी 77 हजार करोड़ रुपये आप अपने लक्ष्य से कम रहे। 4 परसेंट आपकी स्टेट की जो जीडीपी है, वो कम रही। इसलिए 2028 से 2030 हुआ है और अगले बजट में ये जीडीपी और घटी तो यह 2030 से

2032 भी और फिर 2035 भी आपका हो जायेगा, आपके सारे अधिकारी इस चीज को समझ रहे हैं। हमारी सरकार के समय में जब हम काम कर रहे थे, विकास की हम बात कर रहे थे, 2022-23 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट जीडीपी 13 लाख 34 हजार करोड़ रुपये होगी लेकिन हमारी जो नीतियां थीं उनकी वजह से यह बढ़ी और 14 लाख 13 हजार करोड़ रुपये तक पहुंची। 2023-24 के लिए हमने जो अनुमान रखा कि 15 लाख 76 हजार करोड़ रुपये स्टेट जीडीपी का साइज होगा तो बीच में आपकी सरकार आ गयी, थोड़ा-सा कम रह गया 15 लाख 21 हजार करोड़ रुपये, नहीं तो यह पूरा ही जाता हमारा जो टार्गेट था, लेकिन बीच में आप लोग आ गये। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल आपकी सरकार रही है। 77 हजार करोड़ रुपये आप लक्ष्य से पीछे रह गये। आप दावा कर रहे हैं कि अगली साल 19 लाख 79 हजार करोड़ रुपये स्टेट जीडीपी का साइज होगा। देख लेंगे वो तो, वो कहते हैं कि मेरे बाल कितने हैं, बोला यजमान आया अभी आगे। तो यह भी पता चल जायेगा कि आपका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा। आपने पिछले बजट में राजस्व घाटे का जो अनुमान लगाया था वो 25 हजार 758 करोड़ रुपये लगाया था। अभी आपने कहा है कि इस घाटे को पहुंचने का जो अनुमान है वह है 31 हजार 939 करोड़ रुपये। यानी राजस्व घाटा भी आपने जो अनुमान लगाया था, मुख्य मंत्रीजी, उससे 24 परसेंट अधिक हो रहा है आपको, राजस्थान को। आपका राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी के 3.9 से बढ़कर 4.1 परसेंट हो गया है। इसका खामियाजा तो राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है जो अबकी बार 70 हजार करोड़ रुपये हो गया है और आपने इस बजट में इसको बढ़ाकर 84 हजार 643 करोड़ रुपये अंदाजा इसका बताया है। ये भी जो आपका राजकोषीय घाटा है वो स्टेट जीडीपी के 1.4 से बढ़कर 1.9 परसेंट हो गया है।

अब आय-व्यय की बात करते हैं। 2024-25 में कहा कि लोन पेमेंट के अलावा नेट एक्सपेंडिचर 3 लाख 34 हजार 796 करोड़ रुपये होगा, परंतु आपका नेट एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ और करीब 1 हजार करोड़ रुपये कम खर्च करके 3 लाख 33 हजार 259 करोड़ रुपये का आपका ...।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है।

## आय-व्ययक

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आमदनी की बात करें तो आपने 2024-25 में नेट रिसीट्स जो 2 लाख 64 हजार 787 करोड़ रुपये होगी पर आपकी रिसीट्स करीब 16 सौ करोड़ रुपये कम रहकर 2 लाख 63 हजार 168 करोड़ रुपये ही रही। आप बार-बार कहते हो कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहे हैं, कैपिटल आउटले बढ़ा रहे हैं, आपने 2024-25 पर कैपिटल आउटले का बजट रखा 44 हजार 216 करोड़ रुपये, पर आप 13 परसेंट कम खर्च कर पाये और आपका खर्चा हुआ केवल 38 हजार 288 करोड़ रुपये। आपने खेल, कला, साहित्य के अन्दर 65 हजार करोड़ रुपये लिये थे बीई में लेकिन आरई में क्या आया? 63 हजार 516, आप खर्च ही नहीं कर पाये। ऊर्जा में 30 हजार 729 आपने बीई में लिया था, लेकिन खर्च आपने ज्यादा कर दिये, 33 हजार 51, लेकिन यह पैसा जा कहा रहा है? बिजली तो आ ही नहीं रही है। आपने कहा कि नेट बैंकिंग भी नहीं करेंगे, महंगी भी नहीं खरीदेंगे तो बिजली भी नहीं आयी और खर्चा भी बढ़ गया, इसका भी जरा बता देना। समाज कल्याण में 24 हजार करोड़ रुपये आपको खर्च करने थे, आपने 22 हजार 797 करोड़ रुपये ही खर्च किये क्योंकि समाज कल्याण तो वैसे भी आपका फेवरेट विषय नहीं है, दसवें नम्बर पर है। शहरी विकास में भी 16 हजार 918 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े, उसकी जगह आपने 14 हजार 641 ही किये और एग्रीकल्चर, किसान के लिए, उसके भी आपको 14 हजार 544 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान था बीई में, लेकिन आरई में आपका 14 हजार 36 करोड़ रुपये ही आया। यानी कि शिक्षा, समाज कल्याण, अरबन डवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सबके अन्दर जो बजट में प्रावधान था उससे कम आप लोगों ने खर्च किया, यह आम जनता का पैसा था, आप लोग खर्च नहीं कर पाये, इस पर भी जवाब दे देना। आपने जो टैक्स था, टैक्स में 4 परसेंट की कमी आयी है, आप टैक्स ही वसूल नहीं कर पाये। चाहे वो सेंटर के जो कर हैं उनके अन्दर हमारा हिस्सा हो या स्टेट जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, एक्साइज हो, या अन्य कोई टैक्स हो, आप सब में पीछे रह गये, क्यों नहीं कर पाये? यानी न आप पूरा टैक्स वसूल कर पा रहे हो, न पूरा खर्चा कर पा रहे हो, दोनों ही चीजों में आप फेल्योर हैं, दोनों ही चीजें आप पूरी नहीं कर पाये, जो आपने बजट में अनुमान लगाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपने ईआरसीपी के लिए कहा कि हम ईआरसीपी लेकर आयेंगे। ईआरसीपी को आपने पीकेसी किया, फिर आपने श्री राम जल सेतु किया, नाम बदलते रहे। आज एक बात पूछना चाहूंगा, एमओयू मांगा हमने, आपने नहीं दिया, यहीं मांगा था, आपने यहीं पर मना किया। हमारे माननीय सदस्य, कोटा से आते हैं माननीय धारीवालजी, उन्होंने क्वेश्चन लगाया, तो जवाब आया कि इसके पेज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम नहीं दे पायेंगे। किसी अन्य आम पब्लिक ने आरटीआई लगायी तो उसके अन्दर कहा कि यह जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इसकी जानकारी नहीं दे पायेंगे।

अब पता चला कि आपने पोर्टल पर डाल दिया। यानी कि आप विधान सभा में नहीं दे सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बता रहे हो और पोर्टल पर आपके एमओयू डला है। मैं चाहूंगा कि आगे एक दिन आप पूरी चर्चा ईआरसीपी पर भी करा दो क्योंकि ईआरसीपी आप कह रहे हो कि ईआरसीपी की जो फण्डिंग है वो 90 परसेंट भारत सरकार करेगी, 5 परसेंट हम करेंगे, 5 परसेंट मध्य प्रदेश करेगा तो हमारा 5 परसेंट वो बनेगा 2250 करोड़ रुपये, 45 हजार की आपकी योजना है तो 2250 करोड़ रुपये है, 12-13 हजार करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिये, आपने इस बजट में 2 जगह आपने ईआरसीपी के लिए प्रावधान कर दिया तो फिर भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं बना रही? नदी जोड़ो अभियान के तहत क्यों नहीं ले रही है, तो यह चक्कर क्या है इसके बारे में आप लोग बतायें। आपने बजट में यह कह दिया कि हम असेट मोनिटाइजेशन करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है? सरकार अपनी सम्पत्ति बेचेगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके होते हुए राज्य सरकार की सम्पत्तियों को बेचकर पैसा इकट्ठा किया जायेगा, यह हालत हो गयी आपकी वित्तीय व्यवस्थाओं की, यह स्थिति हो गयी है, आप खुद कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए आप बहुत बात करते हैं। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हमने राजस्थान के अन्दर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया कि मासिक पेन्शन हर साल 15 परसेंट बढ़ेगी। पिछली बार 1150 होगी, अबकी बार 1300 होनी चाहिए थी, आपके वादे के मुताबिक 1500 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान के अन्दर जो कानून बना, जिसके आप नियम नहीं बना रहे हैं, उसके तहत ये पेन्शन 1300 रुपये होनी चाहिए थी। आप क्योंकि गरीब का, विधवा का, दिव्यांग का इसमें भला होता है, आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जब आपकी बजट रिप्लाई आये, वित्त मंत्री महोदया, इन गरीबों के बारे में ध्यान रखते हुए और आपकी बजट, आपके चुनाव घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए इसको 1500 रुपये करें।

**MLS/RTM/27.02.2025/18:50/3q**

1500 नहीं करते तो हमने जो एक्ट बनाया है, उसके तहत इसको 1300 जरूर करें। एक बात और कहना चाहूंगा, पेन्शन से मुझे ध्यान में आ गया। यहीं पर समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हम हर महीने पेन्शन के पैसे दे रहे हैं। आपने भी कहा कि हमने दिसम्बर तक की पेन्शन सबको दे दी। मुझे बड़ा दु:ख है, यह जो पेपर है, यह भरतपुर का है, ''भरतपुर के 23 हजार दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन को 4 महीनों से पेन्शन नहीं मिली।'', भरतपुर में। पूरे राजस्थान के लाखों लोग ऐसे हैं, जो पेन्शन मांगने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं और आपके मंत्री के सामने झुंझुनूं में एक बुजुर्ग पेन्शन मांगने चला गया, उसे 2 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। यह है पेन्शन की स्थिति।

''पेन्शन की मांग पर कलक्टरेट में चूडियां-पायल रखकर रोयी महिला'', भरतपुर का समाचार है मुख्य मंत्री जी। जब आप बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे खुशी होती

है कि आज उस सीट पर किसान का बेटा बैठा है तो गरीब के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए ऐसे निर्णय किये जाएंगे कि उसे दिक्कत नहीं आये। हमने निर्णय किये समाज कल्याण विभाग में, जब पेन्शन के लिए व्यक्ति को सरपंच, सैक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एसडीएम, पता नहीं कहां-कहां चक्कर लगाने पड़ते थे, हमने उसे जनाधार से जोड़ा और रास्ते की सारी दीवारों को खत्म किया। जिस दिन उसने पेन्शन केलिए अप्लाई कर दिया, उसी दिन से उसकी पेन्शन बनती थी। ऑफलाइन सिस्टम छोड़ा ही नहीं, ताकि गरीबों का भला हो सके।

मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, वित्त मंत्री महोदया से भी विनम्र आग्रह है कि यह पेन्शन का मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पेन्शन ने बुजुर्गों को, जो दो वक्त की रोटी है, वह बहुत मान-सम्मान से दिलायी है। पहले जो साथ नहीं रखते थे, कई घरों में तो झगड़े हो गये कि बूढा-बूढी किसके साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर अगर ज्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको 1500-1500 रुपये, 3 हजार रुपये घर में आते हैं, उन बुजुर्गों का गुजारा हो जाता है। यह निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा।

मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मुख्य मंत्री जी, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है, आप बुरा मान गये। आपको बुरा नहीं मानना चाहिये था। पिछली बार भी आप सरपंचों के प्रोग्राम में गये थे और अबकी बार भी आप एक महीने पहले सरपंचों के प्रोग्राम में फिर चले गये। पता नहीं सरपंचों के प्रोग्राम में जाकर आपको क्या हो जाता है? आप भूल जाते हैं सब-कुछ कि आप मुख्य मंत्री हैं कि सरपंच हैं। पूरी जो बीच की दीवार है, वह खत्म कर देते हैं। सबसे पहली बात तो सरपंच यह कह रहे थे कि हमारे सरपंचों में से कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री बना है, हमें इस चीज की तो बड़ी खुशी है, पर यह हमारे सरपंचों के चुनाव ही नहीं करा रहा। हमारे चुनाव तो समय पर करा दे।

यही नहीं, आपने वहां पर एक बात और कही। अब आपका कहना होता है और मेरा टीवी देखना होता है, मैं देख ही नहीं पाता, इतना बिजी रहता हूं। आपने कहा, ''पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है। सरपंचों के अन्दर ताकत होनी चाहिये कि अपने क्षेत्र में वे अधिक से अधिक काम कराएं।'' मैं बताता हूं, पैसा कितना उड़ रहा है। 15वें वित्त आयोग का मिलना था 3775 करोड़, और मिला है 3087 करोड़। जो उड़ रहा है, वह। 3500 करोड़ तो नरेगा के बाकी हैं, जिसमें आप कह रहे थे कि नरेगा में आपने काम कराये थे। 3500 करोड़ स्टेट के अन्दर बाकी हैं नरेगा के और संख्या भी नरेगा के अन्दर 50 परसेंट रह गयी लोगों के काम करने की।

मुख्य मंत्री जी, ऐसा तो मत करो। सरपंचों का भला करो। किश्तें 6-6 महीने लेट जा रही हैं। एक बात भी रिकॉर्ड के बिना नहीं बोल रहा हूं मैं। इन्तजार कर रहे हैं। ये सारे एमएलए साहेबान बैठे, ये एमएलए तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पहली बार एमएलए लेड का बजट भी 6-6 महीने में आ रहा है, जो कि सबसे पहले आ जाता था। एएस, एफएस जारी हो गयी। उसके बावजूद एमएलए लेड का बजट देने के पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं

पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं। अब वो कहां उड़ रहे हैं?

और ये जो पीछे से बोलते हैं न, आपकी सरकार, आपकी सरकार, वह पहले 2 बजट तक तो ठीक था। अब सवा साल से ज्यादा हो गया, अब तो आपकी सरकार हो गयी। कब तक ये तीसरा हिसाब का 33 परसेंट तो पूरा हो गया थोड़े दिन में, 2 हिस्से पूरे और राज आया। और आप पिछली बार गुस्सा हो गये यहां पर भाषण देते-देते। आपने कहा, मैं सूद समेत चुकाऊंगा, सूद समेत चुकाऊंगा, किसी का रखूंगा नहीं। मुख्य मंत्री जी, यह तो ऐसा लग रहा है, यह सूद-सूद इतना हो जायेगा राजस्थान पर, 1 लाख तो हर आदमी पर अभी पहुंच गया और आप 4 साल में तो इसे ऐसे पहुंचा जाएंगे, हमारा राज आयेगा तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल होगा, हमें नयी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 2024-25 की एसएफसी की पूरी किश्त ही बाकी है अभी तो। एसएफसी की पूरी किश्त बाकी है। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

युवा सम्बल योजना। आप भत्ते नहीं दे रहे हैं बेरोजगारों के। 867 करोड़ रुपये उनके खर्च करने थे। आपने 448 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं। सिंचाई का बजट 5804 करोड़ रुपये का था और आपने 2816 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जिसके लिए हमारे बच्चे विदेश के अन्दर जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उनको भीख मांगनी पड़ी, आपके बजट में सवा 200 करोड़ थे, लेकिन आपने मात्र 81 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वे पैसे उन्हें मिल जाते तो हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे राजस्थान के लोगों को विदेश में भीख नहीं मांगनी पड़ती हमारे उन युवा साथियों को। आपको नाम से तकलीफ थी, आपने नाम बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बदलने के बाद में बजट तो जारी करो। यह बजट कौन देगा उनको? उन्होंने एडमिशन ले लिये। एडमिशन लेट हो रहे हैं। बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

फिर दूसरा, आपकी मेरे से तो नाराजगी हो सकती है, वैसे आप भले आदमी रखते नहीं, पर आपने मेरा जो स्टाफ है, दिव्यांगजन, इनकी स्कूटी नहीं दी अबकी बार। दिव्यांगजन की स्कूटी नहीं दी। वह दिव्यांगजन, जो स्कूटी मिलने के बाद में यह कहता है कि मुख्य मंत्री जी ने मुझे स्कूटी नहीं, भगवान ने तो मुझे पैर नहीं दिये, आप लोगों ने पैर दे दिये। आपने उनकी स्कूटी इस बजट के अन्दर...। क्या इतना पैसा नहीं कि आप उनको स्कूटी दे सको। हमने 2 बार 5-5 हजार और उससे पहले 3 हजार स्कूटी दीं तीनों बजट के अन्दर लगातार और आपने पिछले बजट में 5 हजार से शायद 3 हजार कर दिया उनको और अबकी बार जीरो कर दिया। स्कूटी तो देनी चाहिये। यह मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे सभी दिव्यांग साथियों की तरफ से स्पेशल अपील भी है आप लोगों से कि दिव्यांगजन की स्कूटी आप मत काटो। उनको स्कूटी दीजिये।

अभी तो 45 साल की उम्र तक के लोगों को भी नहीं दे पाये हैं हम। अभी जरूरत है उससे आगे बढ़ने की। हम ज्यादा देंगे तो 45 से बढ़ाकर फिर 35 साल, 45 साल, 60 साल तक हमें लोगों को स्कूटी देनी है। इन दिव्यांगजन की स्कूटी जरूर दीजिये। यह गरीब के हक का पैसा मत काटो। बड़े-बड़ों का काट दो अमीर लोगों का, लेकिन गरीबों का, पेन्शन का,

स्कूटी का, नरेगा का, सरपंचों के बजट का, यह पैसा कम कर रहे हो, किसानों का, यह तो नहीं करो। इसका तो मेरा आपसे निवेदन है।

8वें वेतन आयोग के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं न, वे बाट देख रहे हैं कि आपने अभी तक कमेटी नहीं बनायी। दिल्ली में तो कमेटी बना दी आपने, क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कमेटी बन गयी, राजस्थान के कर्मचारी बाट देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ कमेटी ही बनानी है। पैसा तो जब आप देंगे, तब दे देना। कमेटी तो आप बना दीजिये। कम से कम कर्मचारियों का इतना तो आप ध्यान रखें। यह निवेदन मैं करना चाहूंगा।

दो लाइनें कह देता हूं-

**विरासत में मिली है वफादारी,**
**तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है,**
**खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारा,**
**क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है,**
**हमें जलने की बीमारी नहीं है।**

मुख्य मंत्री जी, आपने कहा कि राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। आपने टास्क फोर्स बना दी, अक्टूबर 2024 में ही बना दी थी, आज तक आपको इतना समय नहीं मिला कि उसकी आप एक मीटिंग तो कर लें, क्योंकि मैं समझता हूं, आपको दिल्ली जाने से ही फुरसत नहीं है, इनकी मीटिंग तो आप कब करेंगे? वित्त मंत्री जी ने कहा था, पिछली सरकार में जो कमियां रह गयी थीं, वे हम सही करेंगे। मेरे को तो लगता नहीं कि, आपने हमारे प्रबन्धन की तो इतनी यहां पर कमियां गिनाईं और आपका वित्तीय प्रबन्धन तो एकदम फेल हो गया।

**MKD/RTM/27.02.2025/19:00/4a**

ऐसा लग रहा है जैसे कर्ज लेकर घी पी रहे हो आप लोग। कर्ज लेकर घी पीने वाली बात जो है, मुझे खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि मेरे जो-जो क्वश्चन है, उन्हीं पर जवाब दिया जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जैसी हमारी वित्त मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर आज इस चीज का फायदा हमें मिलेगा।

अब आप कर्जे के अन्दर आ जाइये। 2019-20 के अन्दर हमने कर्जा लिया, जब हमारी सरकार आई, 41 हजार 328 करोड़ रुपये। 2020-21 में जब कोरोना था, कोरोना के समय सारी छूट दे दी गई, सब वित्तीय प्रबन्धन फेल हो गये, उस समय हमने कर्जा लिया 57 हजार 798 करोड़ रुपये। उसके बाद अगले साल हमने उसको घटाना शुरू किया। 2021-22 में हमने लिया 52 हजार 346 करोड़ और 2022-23 के अन्दर हमने उसको और कम किया। हमने कर्जा लिया 42 हजार 728 करोड़। अब आपकी सरकार आ गई 2024-25 में, तो आपने ले लिया 70 हजार करोड़ और 2025-26 में आपने अनुमान दे दिया 84 हजार 645

करोड़। ये स्थिति कर्जे की है। हमारी लगभग आठ करोड़ की आबादी है तो हर एक राजस्थानी के सिर पर आपने एक लाख रुपये का कर्जा मांड दिया है।

अब आप कह रहे हो, हमारी प्लानिंग, आपका वित्तीय प्रबन्धन। 2024-25 के लिए आपने अनुमान लगाया है कि स्टेट जीडीपी जो है, 35.97 परसेंट ही कर्ज होगा, पर रिवाइज आरई के अन्दर आपका यह बढ़कर 37.65 परसेंट निकलकर आ गया, यानी अब जो एफआरबीएम की आखिरी लिमिट है 38.20, उस पर भी आप पहुंच गये हैं। अब लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। स्थिति क्या होगी, मुख्य मंत्री जी, आप इस बात को जरूर समझें। एक शेर पढ़ना चाहूंगा:-

यह कर्ज तो मेरा है, चुकायेगा कोई और,
दु:ख मुझको है और नीर बहायेगा कोई और,
या फिर यूंही दी जायेगी, उजरत में गवाही,
क्या तेरी सज़ा अबके भी पायेगा कोई और,
कि पायेगा कोई और।

यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी-बड़ी बात की, 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गये हैं। राजस्थान की जो आज की जीडीपी है, उससे दुगने से भी ज्यादा के हैं ये एमओयू। मैं तो चाहूंगा वे धरातल पर आये, पर एक विपक्ष के नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, यह बात मैं आपकी जानकारी में भी लेकर आऊं और प्रदेश की जनता की जानकारी में भी लेकर आऊं, ये बात आप समझें। यह स्थिति वही होगी, जो लॉकडाउन में मोदी जी ने एक बार एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का, कई प्रेस कॉफ्रेस हुई थी पूरे देश के अन्दर, किसी को भी वह एक रुपया भी नहीं मिला, कहां आया, कहां गया। ऐसी स्थिति चलेगी।

अब मैं, बार-बार पता नहीं क्यों, आपके भरतपुर में ही चला जाता हूं। उदाहरण देने के लिए ठीक रहता है, इसलिए आप बुरा मत मानना, अगली बार आप कहेंगे तो मैं जिला चेंज कर दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब, आज मामला जम नहीं रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि, राइजिंग राजस्थान के अन्दर ऐसे-ऐसे एमओयू हुए हैं कि एक पक्ष का तो एमओयू है, दूसरे के साइन ही नहीं हैं। ऐसे-ऐसे एमओयू हुए हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 करोड़ की है और एमओयू एक लाख करोड़ के कर रहे हैं, इनकी भी जरा छटनी करवा लेना।

सबसे अहम बात कि जिस होटल के अन्दर भरतपुर में यह समिट हुई थी, द ग्रांड बार्सों होटल है भरतपुर के अन्दर, जहां पर आपने यह समिट आयोजित की थी, उसका भी आपने एमओयू 30 करोड़ रुपये का कर दिया। यानी, होटल तो बन गया और आप मीटिंग कर रहे हो और उसी का एमओयू कर दिया तीस करोड़ रुपये का। जिन्दल हॉस्पिटल, भरतपुर, उसका 80 करोड़ रुपये का एमओयू कर दिया, उसका भी 6 महीने से काम चल रहा है, गुरूजी। सैनी

होटल और रिसोर्ट, भरतपुर 20 करोड़ का एमओयू किया गया है, होटल का काम 50 परसेंट पूरा हो चुका है। भरतपुर में जो सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट हुआ है, 300 करोड़ रुपये का, जसवन्त सिंह भदौरिया यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही पूरी बन चुकी है, कम्प्लीट बिल्डिंग बन चुकी है, फाइनल काम चल रहा है, एमओयू दिखा दिया। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए था।

आपने फिल्म सिटी की घोषणा की। के. सी. बोकाडिया को जमीन भी आपने दिखा दी। राइजिंग राजस्थान में आपने उसका काफी बखान भी किया, लेकिन कुछ दिन पहले उनका दैनिक भास्कर के अन्दर इंटरव्यू आया है तो उन्होंने कहा है कि 6-7 महीने होने के बाद भी कोई काम नहीं बढ़ा है, फिल्म सिटी बस प्रचार तक समिति रह गई है, यह हकीकत है।

20 जनवरी को मीडिया वालों ने हमारे संसदीय मंत्री जी से पूछा कि कितने एमओयू जमीन पर आ गये, तो उन्होंने बोला 25 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गये हैं। अगले ही दिन, दो दिन बाद, के.के. विश्नोई जी, मेरे तो मित्र हैं, उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो पहले तो बोले नहीं, इधर-उधर घुमाते रहे, लेकिन मीडिया वाले भी क्या है कि छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, 2 लाख 23 हजार करोड़ के एमओयू जमीन पर आ चुके हैं। एक ही दिन में 23 लाख करोड़ के एमओयू गायब, यह स्थिति है।

बजट के बाद मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डेढ़ लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गये हैं। अब कुछ तो बताओ सही कौन कह रहा है? तीन लोगों के बयान, तीनों ही अलग-अलग और यह तो रिकॉर्ड की चीजें हैं, मुख्य मंत्री जी। जो एक आदमी बोलेगा, वही बोलना चाहिए। आगे से अब इनको जो प्रेस नोट आप दें, वह इस हिसाब से दें कि ये अलग-अलग नहीं बोल सकें।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप भले आदमी हैं, मन भी आपका अच्छा है। हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप एक व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं कर देते हैं, इस एमओयू पर। श्वेत पत्र जारी कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, सबको पता चल जायेगा कि कितने एमओयू हैं और कहां हैं।

ये एमओयू सफल होने चाहिए, यह भी मैं चाहता हूं, लेकिन इस चीज का फायदा जो है ना कुछ लोगों को ही हो रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरे प्रदेश के हित की बात है, कहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करें।

एक बात और कहना चाहूंगा कि आप भरतपुर से आते हैं, आपका टारगेट भरतपुर नहीं है, बात को समझो। पूरे राजस्थान के अन्दर जाट समाज को आरक्षण मिल गया, लेकिन भरतपुर और धौलपुर रह गया है, इन जगहों पर भी, दोनों ही जगहों पर जाट समाज को आरक्षण दिया जाये। आपके मुख्य मंत्री होते हुए नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। हमारी जब सरकार थी...

श्री जगत सिंह (नदबई): (..व्यवधान..) ये आप गलत कह रहे हो (..व्यवधान..)।

श्री अध्यक्ष: माननीय, विराजो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार ने इसको लागू भी कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको रोक दिया। अपने यहां की बात नहीं है, जगत जी। वही तो कह रहा हूं, अब भारत सरकार से तो आप ही बात करोगे, यह डबल इंजन कब काम आयेगा, बात करने के लिए ही है क्या?

आपके कैबिनेट मंत्री, जो जलदाय मंत्री हैं, वे मिले थे और इन्होंने उनसे वादा भी किया था कि भजन लाल जी इस बात को लेकर गम्भीर हैं, जल्दी ही इसको कानूनी रूप से सकारात्मक लागू करेंगे।

**Bhs/Rtm/27.02.25/19.10/4b**

यह कोई बहस का विषय नहीं है पर लागू होना चाहिये मेरा तो यह निवेदन है। हमारे माननीय सदस्य जगत सिंह जी कह रहे थे। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

एक बात और यह जो छात्र संघ चुनावों का मुद्दा है यहां पर आप आसन पर विराज रहे हैं, आप स्वयं छात्र संघ चुनाव से निकल कर आये हैं। अशोक गहलोत जी, हरीश चौधरी जी, मनीष यादव जी, मुकेश भाकर जी, विकास चौधरी जी, रामनिवास गावड़िया जी, कालीचरण सराफ जी, श्रीचन्द कृपलानी जी, राजेन्द्र राठौड़ जी, रघु शर्मा जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल जी, महेन्द्र चौधरी जी, अशोक लाहोटी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, ये सारे लोग जो हैं ...(व्यवधान)... बाबू सिंह राठौड़ जी और भी काफी लोग हैं जो छात्र संघ चुनावों से निकल कर आये हैं तो आप उन बच्चों पर लाठियां बरसाना, उन पर मुकदमे लगाना बन्द कीजिये और उन बच्चों को छात्र संघ चुनाव करा कर राजनीतिक जीवन में उनको आने का भी मौका दीजिये। यह बात मैं कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

दूसरा, अब जल जीवन मिशन पर आते हैं अपन। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी। मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: नो। नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पण्डित जी, अपन अलवर में लड़ लेंगे न, यहां क्या जरूरत है?...(व्यवधान)... कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता आती-जाती माया है सदा नहीं रहनी है इसलिये सत्ता के अन्दर भी आदमी सहनशील रहे तो अच्छा है। अब यह यहां बोलने की अनुमति नहीं है बीच में। ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठे-बैठे नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जल जीवन मिशन जब भारत सरकार ने शुरू किया कि 2022 तक सब जगह घर-घर नल लगेंगे, इससे पहले भारत सरकार की जो योजनाएं थी वो 90/10 के रेशो में थे। 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार से आता था और 10 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार देती थी लेकिन भारत सरकार के निर्देश थे कि 45 प्रतिशत पैसा भारत

सरकार देगी, 45 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार देगी और दस प्रतिशत पैसा पब्लिक देगी। यह नियम बना कर इन्होंने इसको लागू किया क्योंकि और राज्यों में यह औसत जो आता है 300-400 रुपये आता है लेकिन हमारे यहां मरुस्थल के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति है एक-एक कनेक्शन में बीस से पच्चीस हजार रुपये तक भी इसकी लागत आ रही थी। हमने 90/10 की डिमाण्ड की, आप लोगों ने नहीं माना। यहां बहुत अभियान चलाया आप लोगों के द्वारा कि जे.जे.एम. के अन्दर भ्रष्टाचार हो गया और काम नहीं हुआ और पता नहीं क्या-क्या जो नहीं कहना था वह आप लोगों ने कहा कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो भारत सरकार ने जारी किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जो जल जीवन मिशन है इसका बजट 70 हजार 163 करोड़ रुपये रखा था और देश के अन्दर जो हमारा जलशक्ति मंत्रालय है इसका तीसरा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाया, पूरी साल के अन्दर 22 हजार 694 करोड़ रुपये ही खर्च किये। इसका मतलब पूरे देश के अन्दर ही जे.जे.एम. की जो स्पीड है वह स्लो चल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, आपने अभी बात की कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से बात करके इसको 2028 तक बढ़वा दिया है जे.जे.एम. को, अच्छी बात है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको पर यह जे.जे.एम. सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बढ़ा है यह पूरे देश के लिए ही बढ़ा है तो जो ठीकरा आप हमारे सर फोड़ रहे हो न, यहां काम नहीं हुआ, यह देश के अन्दर ही काम नहीं हुआ इसलिये जल जीवन मिशन अभियान पूरे देश के अन्दर 2028 तक बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान)...

घोटालों की भी बात कर लो। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि सवा साल हो गये तो वो घोटाले खुलेंगे कब? हमारे समय में जे.जे.एम. का जो काम हुआ, हमारे जो इसके ए.सी.एस. थे आज वो सी.एस. हैं, राजस्थान के हैं, इनको तो सारा ही पता होगा डिपार्टमेंट में कहां-कहां घोटाले हुए हैं, तो इससे बैटर कौन बता सकता है। जब हम लोग खुले मन से ...(व्यवधान)... चौधरी, डट जा। खुले मन से जब हम कह रहे हैं कि आपको ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब, एक मिनट। किसी अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए को नाम से सम्बोधित नहीं किया जा सकता और उनको कोट नहीं किया जा सकता। कृपया इसको डिलीट करवायें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे मैंने नाम लिया नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, आपने नाम लिया है सी.एस. और ए.सी.एस., यह डिलीट करना पड़ेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नाम लिया नहीं है। ...(व्यवधान)... तो आप यह घोटालों की अगर जांच कराना चाहें ...(व्यवधान)... किनके?

श्री अध्यक्ष: किसी भी राष्ट्रीय नेता का नाम न लें। जैसे आपको किसी नाम पर आपत्ति थी, इनको भी है। किसी राष्ट्रीय नेता का नाम न लें। वो यही तो पाइंट आउट कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब जब हमारे समय में अगर घोटाले हुए हैं तो जांच

कराने में आप सक्षम हैं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... पडित जी, डट जा। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी, यह चीज गलत है। देखो, मैंने पहले भी कहा था इस प्रकार से जब और सदस्य भी हंसी-मजाक जितनी मैं सहन कर सकता हूं न कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिये बड़ा मन रखो, आप मंत्री हो, मेरे अलवर के हो इसलिये मैं ज्यादा विशेष प्रेम रखता हूं आपसे। इस चीज की ...(व्यवधान)... हां।

श्री अध्यक्षः अब कन्क्लूड करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन आपने सरकार आते ही कहा कि हम पच्चीस लाख घरों में कनेक्शन देंगे, तो दे देते, किसने रोका? हमने रोका क्या? पच्चीस लाख कनेक्शन देने का आपने बजट में वादा किया और अभिभाषण में आप लोगों ने राज्यपाल महोदय से पढ़वाया कि 14 महीनों में 11 लाख घरों में ही आप पानी पहुंचा पाये, और यही नहीं भारत सरकार की वेबसाइट तो कह रही है कि आपने साढ़े आठ लाख घरों में ही पानी पहुंचाया है, तो बजट में पच्चीस लाख, अभिभाषण में 1 लाख और भारत सरकार की वेबसाइट कह रही है साढ़े आठ लाख तो पानी भी नहीं पहुंचा सकते आप लोग। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कुल मिला कर पच्चीस हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बात है, ऐसा टोटल करने वालों की जरूरत है इस सरकार में। इसलिये जो पच्चीस लाख का वादा था, वो काम ढीला चल रहा है, तो इसमें आप कोई घोटाला हुआ है तो जांच कराने की कोई बात रखते। यह मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इस एक साल के अन्दर जे.जे.एम. के काम की स्पीड है वह बहुत स्लो रही है।

अध्यक्ष जी, अभी तो दो मिनट बच रही है मेरी उधर नजर ही नहीं गयी, आप पहले ही मेरे को इशारा कर रहे हो। इतने में मैं एकाध और बोल जाऊंगा।

श्री अध्यक्षः नहीं-नहीं, अब थोड़ा वाइंडअप करिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कुछ जो बजट की घोषणाएं हैं आपकी, एक तो मैं आपके डिपार्टमेंट की ही कहना चाहूंगा। आपने सी.आर.एफ. का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, जो भारत सरकार के बजट में है वो सैंक्शन हो गया उसकी ए.एस., एफ.एस. दोनों जारी हो गई और आप उसको बजट में ले रहे हो, तो वह कहां से आ गया?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपने भी लिया था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने लिया होगा पर हमारे और आप में कोई अन्तर तो होना चाहिये न, फिर आपकी और हमारी सरकार में अन्तर क्या हुआ? जो काम हम कर रहे थे वो ही आप कर रहे हो तो फिर अन्तर क्या हुआ? यह बात नहीं होनी चाहिये। कुछ तो अलग लेकर आओ। आपकी सरकार आई, आपके घोषणा पत्र में है कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम किसान को बारह हजार सम्मान निधि देंगे। अभी नौ हजार तक ही आप पहुंचे हो, बारह हजार कब दोगे? घोषणा पत्र में तो उसी दिन का था। आपने कहा कि हम बाजरे की एम.एस.पी. पर खरीद करेंगे और बाजरे की खरीद के लिए तो ...(व्यवधान)... सुनो भई

सुनो, अब बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज आयी है कि बाजरे की खरीद के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जब संगठन मंत्री थे तब आपने कई बार ट्वीट किये। आपने 13 अक्टूबर, 2022 से लेकर 15 अक्टूबर, 2022 के बीच में कई ट्वीट किये आपने सीकर में, लक्ष्मणगढ़ में, खेतड़ी में, सिंघाना में, चूरू में, बाजरे की एम.एस.पी. खरीद के लिए, तो आप वो जैसे दिल्ली में सी.एम. बनते ही पुराने ट्वीट हटा रहे हैं न, ये पुराने हटवा दो आप। ये आपके किये हुए आप ही नहीं कर पा रहे हो। आपके घोषणा पत्र में है और आपके ट्वीट हैं, आप बाजरे की खरीद नहीं करवा पा रहे हो। आपने कहा कि हरियाणा के बराबर राजस्थान के डीजल, पेट्रोल के रेट करेंगे।

**Kas/rtm/27.02.2025/19.20/4c**

आप नहीं कर पा रहे हो, आज भी दोनों जगहों में 10 रुपये का अंतर है। आपने भरतपुर में बांध बारेंडा में, गृह राज्य मंत्री जी भी यही विराज रहे हैं, आपने वहां घोषणा की कि हम थाना खोलेंगे। अब तक भरतपुर में ही थाना नहीं खुला, तो और कहीं कैसे पूरी होंगी घोषणाएं, यह मैं पूछना चाहूंगा। आपको भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना था, लेकिन सिर्फ इनका नाम बदला, कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से आपने गेहूं को 2700 रुपये में खरीद का कहा, आज तक 2700 में नहीं खरीदा। बीकानेर संभाग में नहर का पानी बंद होने से किसान धरने पर हैं। 450 में सिलेंडर की घोषणा की, लोग सब्सिडी के लिये घूम रहे हैं। एस.टी. कोष में आपने 1750 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी, लेकिन पिछली बार के 1500 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार आरसीडीएफ को दूध बेचने पर 5 लीटर की सब्सिडी है, 4-4 महीने हो गये पशुपालकों को पैसा नहीं मिल रहा है। जयपुर में आपने 2173 करोड़ रुपये के 4 फ्लाईओवर, 3 एलिवेटेड, 3 आरओबी, 1 अंडरपास की घोषणा की, सिर्फ 160 करोड़ रुपये जारी हुए हैं और 2 प्रोजेक्ट के ही टेंडर हुए हैं, सब पेंडिंग हैं। खाटू श्याम बाबा के 100 करोड़ की घोषणा थी, कुछ नहीं हुआ। पीएम मातृ योजना वित्तीय सहायता 5 हजार से 8 हजार की जायेगी, किन्तु सिर्फ 6500 ही किया है। प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की घोषणा की, उसको तो छोड़िए, अभी तक आरयूएचएस में यह इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाया है। आप लोग वीसी तक की नियुक्ति नहीं कर पाये हैं।

आपने महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की, कोई पता नहीं। आपने वादा किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 7500, सहायिकाओं को 6500, आशा कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये मानदेय दिया जायेगा, वह अब तक पूरा नहीं हुआ। आप कहते थे जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, उनको मुआवजा देंगे, एक रुपया किसी को दे दिया हो तो आप बता दीजिए। आपने कहा था कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लेकर आयेंगे, वो आपने अभी तक जारी नहीं किया, उसको जारी कीजिए, यह मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा।

लास्ट में एक मिनट में अपनी बात खतम करना चाहूंगा, मेरा समय थोड़ा ऊपर हो गया। आपने मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट राजस्थान में लागू नहीं किया। गिग वर्कर कानून, जिसके लिये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी राजस्थान की बड़ाई हुई है, उसके नियम लागू नहीं किये। भारत सरकार ने भी उसके लिये कहा है, आपने भी बजट में 250 करोड़ रुपये किये हैं, लेकिन वह कानून अभी लागू नहीं हुआ। राइट टू हैल्थ, जो कानून हमने बनाया, वह लागू नहीं हुआ। किसान ऋण सहायता राहत आयोग हमने बनाया, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बजट एक प्रकार से नीरस, पूरे प्रदेश को भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल, धरातल पर कुछ नहीं है और हर राजस्थानी को एक-एक लाख के कर्जे में डुबोने वाला बजट है। इस बजट की मैं निंदा करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सार्थक विचार रखने के लिये आभार व्यक्त करती हूं। माननीय सदस्यों के साथ-साथ आम जनता एवं सभी स्टेक हॉल्डर्स ने भी बजट का खुले दिल से स्वागत किया है तथा समस्त प्रदेश में नवीन आशा और विश्वास का संचार हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिये गये प्रेरणा मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास', के अनुसरण में हम प्रदेश की विकास यात्रा में सभी को साथ लेकर सतत रूप से आगे बढेंगे।

मैं विपक्ष के उन साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बजट की सकारात्मक आलोचना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। वैसे तो विपक्ष के बहुत सारे साथियों को इस बजट में भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारी बातें रखीं, मैं उन पर भी बताना चाहूंगी, लेकिन मैं पहले अपनी बात की शुरुआत करती हूं।

हमारी सरकार सभी प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लेगी। हम सदा से ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम का स्वागत करते हैं, किन्तु प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के शेख चिल्ली, थोथी एवं मिथ्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे भी स्पष्ट है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में कोई भी सार्थक कमी निकालना संभव ही नहीं था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़ें बताएं, जिनका भी मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से आंकड़ों पर भी ध्यान नहीं दिया। अभी जो आपने बहुत सारे आंकड़ें रखे, वो सही नहीं हैं, उन पर अभी मैं कुछ समय बाद आपको बताना चाहूंगी। लेकिन एक बार आप फिर से चैक करवा लें, बहुत ही गलत हैं। और यह बार-बार आप क्या कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबोया है। डुबोने का काम तो आपने किया है,

कर्जा हम उतारेंगे। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कर्जा उतारने का काम हम करेंगे। साथ ही यह भी एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई माननीय सदस्य इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ही नहीं ले पाये तथा उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षेत्रीय बिन्दुओं से अवगत कराने की जो महती जिम्मेदारी दी थी, उसे भी वो नहीं निभा पाये।

हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी की जो कविता थी, मुझे लगता है कि जो उनकी सरकार के पांच वर्ष थे, वह वो ही कहानी थी, हमारे बारे में कुछ नहीं था। वैसे दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि जो आपका पूरा भाषण था, बहुत जोर-जोर से चिल्ला कर आपने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है और प्रदेश की जनता देख रही है कि काम कौन कर रहा है और असत्य बातें, असत्य घोषणाएं किस सरकार ने की हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः बैठिए।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): एक जो आपने बात रखी, सरपंचों, नगरीय निकायों का फाइनेंस कमीशन का गत सरकार के समय का फंड भी हमें देना पडा, हमारी सरकार को देना पडा। आप आंकड़ें दोबारा देख लें, दुबारा जांच कर लें।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान तीन-चार महीनों तक बकाया रहता था, जबकि हमारी सरकार ने जनवरी, 2025 तक का भुगतान कर दिया है। फिर से आप अपने आंकड़ें चैक करवा लें। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने बजट में एसेट मोनेटाइजेशन के कंपोनेंट्स लैंड एग्रीगेशन, लैंड पूलिंग और इनविट्स लगता है पढ़ा ही नहीं। एसेट बेचने की बात नहीं होती है, एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम बेचेंगे। मुझे लगता है कि आपने ना तो ठीक से बजट सुना, ना बाद में जाकर उसको पढ़ा है। अब अगर निंदा ही करनी है तो थोड़ा सोच-समझकर, पढ़कर करें। ....(व्यवधान).... मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा कि शायद बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि पिछली बार हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो अवसर मिला ही नहीं हमारे नेता, प्रतिपक्ष जी को, बहुत दुख की बात है। अभी तो मुख्य मंत्री जी के प्रयासों की वजह से अवसर मिला। मैं बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, कि उन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो, ठीक से चर्चा हो और एक डेमोक्रेसी की पालना होनी चाहिये, सदन में चर्चा होनी चाहिये। सकारात्मक क्रिटिसिजम भी होना चाहिये, हम लोग सुनेंगे बिलकुल, लेकिन गलत आंकड़ें तो बिलकुल नहीं सुनेंगे।

**msk/rtm/27.02.25/1930/4d**

माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गयी कि बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य

भी, जो कि अभी हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किये गये हैं जिनकी प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति एवं एनआईटी जारी हो गयी है व राशि केन्द्र सरकार देती है। साथ ही, सदन के बाहर माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अन्दर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूंगी-

**ज्यादा कहते हैं, थोड़ा समझते हैं वो,**

**हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो।**

अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म्स स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिये जाने वाले कार्यों का रोडमैप प्रस्तुत किया जाता है।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नो, बैठिये। नो डिस्टर्बनेंस। मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): यह प्रक्रिया विगत कई वर्षों में प्रदेश में अपनायी जाती है। हमारे द्वारा बजट में सड़कों से सम्बन्धित की गयी घोषणा में भारत सरकार के Ministry of Road Transport and Highways द्वारा सीआरआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत कार्य भी सम्मिलित किये गये हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा इन कार्यों की केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति की दिनांक का मुद्दा बनाया जाना निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। यह गत सरकार के समय उत्पन्न ऐसी ही स्थिति को कितनी आसानी से भूल गये। उस समय बोल देते, उस समय आपने कुछ नहीं बोला। आपकी सरकार करे, वह सही है। हमने तो सिर्फ उसके बारे में विवरण दिया है, वह गलत है। क्या करें? इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र के द्वारा माह दिसम्बर, 2024 में 27 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिनकी राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जनवरी, 2025 में जारी करने के उपरान्त बजट में इनकी घोषणा की गयी है। इन सभी कार्यों पर कार्यादेश उपरान्त व्यय आगामी वर्ष ही होगा। यह प्रक्रिया योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उपयुक्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दोहरे मापदण्ड आचरण को मैं सभी के समक्ष उजागर करने के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में गत सरकार के समय की याद दिलाना चाहूंगी। दिनांक 17.03.2023 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में की गयी घोषणाओं में पृष्ठ 25 व 26 पर सीआरएफ के अन्तर्गत अंकित ROBs भी केन्द्र सरकार सरकार द्वारा उक्त घोषणा से पूर्व 21 फरवरी को स्वीकृत किये जा चुके थे। तब इन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया में राइजिंग राजस्थान और अब तो उन्होंने सदन में भी बात रखी है, भरतपुर के एक एमओयू के सन्दर्भ में टिप्पणी की, अभी आपने सदन में जो बात रखी, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से नये होटल की स्थापना भी हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं सुहा रही है। वे सभी जिलों में हो रहे विकास तथा उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसरों से प्रसन्न होने के स्थान पर विचलित होते नजर आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा। आपको इसमें भी समस्या हो रही है। कुछ रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, राजस्थान, विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, आपको समस्या हो रही है। एमओयूज धरातल पर

उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि एमओयूज धरातल पर नहीं उतर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उतर रहे हैं, उनमें आपको समस्या हो रही है। तो आप सोच लीजिये, आपको बोलना क्या है? सोच समझ कर बोलिये। मुझे, सबको आज लगा कि आपने जल्दबाजी में तैयारी की थी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तैयारी टाइम से ही की है। बस इतना ही निवेदन है कि एमओयू पहले होता है या होटल पहले बनता है, यह बता दें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों (Long term goals) तथा विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आम जन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किये गये थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1 लाख 20 हजार से अधिक सुझाव हमको प्रेषित किये गये। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है, सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के साथियों का इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक हॉल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मण्डलों, कर्मचारियों, युवाओं, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री-बजट कंसलटेशन मीटिंग्स आयोजित की गयीं और राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में त्वरित गति से लिये गये निर्णयों तथा संपादित किये गये कार्यों को देखते हुए आज आम जन में हमारी सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। मैं माननीय सदन को कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष तथा हमारे एक वर्ष में किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगी। टैबलेट वितरण- गत सरकार का अंतिम वर्ष-जीरो, हमारी सरकार का एक वर्ष 88 हजार 800,

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई प्रतिक्रिया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टेण्डर कब हुए, यह तो देख लो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): सौलर पंप की स्थापना-गत सरकार के अंतिम वर्ष में सिर्फ 1 हजार 200 और हमारी सरकार का एक वर्ष- 88 हजार 884, अब स्कूटी वितरण की भी बात कर लेते हैं, जिसकी आपने अभी बात रखी है। स्कूटी वितरण- गत सरकार का अंतिम वर्ष 4 हजार 232, हमारी सरकार का एक वर्ष- 24 हजार 517..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे समय वाली घड़ी है, वही बांट रहे हैं और अभी

बंटी भी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने क्यों नहीं बांटी?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वित्त मंत्री जी, आपके पड़ोस में डिप्टी सीएम साहब हैं। अभी पांच दिन पहले इन्होंने जवाब दिया कि स्कूटी हम इसलिए नहीं बांट पाये कि विधान सभा की आचार संहिता आ गयी, फिर लोक सभा की आचार संहिता आ गयी। इस वजह से नहीं बांट पाये। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैंने आपको संख्या बतायी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): चलिये, अभी और भी हैं। गेहूं की खरीद, मैट्रिक टन- गत सरकार का अंतिम वर्ष 4 लाख 38 हजार, हमारी सरकार का एक वर्ष 12 लाख 5 हजार, लगभग तीन गुना ज्यादा। ...(व्यवधान)... अब क्या प्रतिपक्ष के हमारे साथी यह गणित स्वयं ही नहीं देख पा रहे हैं कि इनके अंतिम चुनावी साल और हमारा पहला साल। आपका अंतिम चुनाव साल था, जिसमें ये आंकड़े थे। सोचिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सितम्बर में तो आचार संहिता लग गयी, छह महीने..

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अब बहाने बहुत हैं, करते रहें।

**ये है, हमारे काम करने की गति,**

**ये है, हमारे लक्ष्य प्राप्त करने का जनून,**

अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार को केन्द्र सरकार से प्रदेश की जनता के हित में तथा उनकी खुशहाली के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में 17 हजार 653 करोड़ रुपये अधिक अर्थात 85 हजार 716 करोड़ रुपये होंगे।

**mdp/rtm/27.02.2025/19:40/4e**

डबल इंजन का कमाल है ये। डबल इंजन की सरकार अभी आपने बोला तो डबल इंजन की बात बता रही हूं। इनके अलावा केन्द्र सरकार की SASCI (स्पेशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फोर केपिटल इंवेस्टमेंट) पचास वर्षीय इंटरेस्ट फ्री लोन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 8 हजार 500 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। हमारे द्वारा केपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करने एवं परफार्मेंस के कारण ये राशि इस योजनान्तर्गत अब तक प्राप्त राशियों में सर्वाधिक है। भविष्य में इस राशि में भी वृद्धि होना संभावित है।

**वित्तीय संसाधन जुटाना** - विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये चिंता व्यक्त की गयी कि राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार से की जायेगी। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य तथा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन चकित रह गयी कि जनता से हमारे द्वारा किये गये वादों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का जो हमारा कार्य है, उसकी भी

चिंता विपक्ष कर रहा है। उस समय आपने कर ली होती जब आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। लगता है अभी तक इनका सत्ता का मोह भंग नहीं हुआ। आपका बस यही..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रात को सपने देखते हैं ये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): वैसे तो अगर जनहित में अपने सच्चे मन से चिंता करते हुए इन्होंने हमारा साथ देने का निश्चय किया है तो मुझे और हमारे सभी साथियों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। किंतु इन लोगों का जो ट्रेक रिकॉर्ड है, वह कुछ और ही कहता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुन: अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स एवं नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में एफिसिएंशी बढ़ाने के साथ ही टैक्स पेयर की सुविधा एवं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आई.टी. इनेबल प्रोसिजरल रि-इंजीनियरिंग तथा सिस्टेमेटिक रि-स्ट्रक्चरिंग के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही राज्य के रेवेन्यू में अधिकाधिक वृद्धि होना निश्चित है। यद्यपि मैं बजट प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बता चुकी हूं, किंतु विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिंदुओं से ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो ध्यान से सुना ही नहीं या इन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया। इसलिए मैं पुन: सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि आगामी वर्ष रिफाइनरी प्रारम्भ होन के फलस्वरूप लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वैट प्राप्त होगा।

अभी मैं असेट मोनिटाइजेशन की आपको दोबारा बात समझाती हूं। असेट मोनिटाइजेशन यथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इनविट्स के माध्यम से 4 हजार 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि असेट मोनिटाइजेशन का ये ही मतलब नहीं होता है कि कोई सरकार की जमीनें बेच रहा है। इसका मोनिटाइजेशन असेट को सही तरह से उसका उपयोग करने की बात मैंने की।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बता दीजिए क्या किया?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपको मैंने बता दिया। बिलकुल आपको समय पर ये भी बता देंगे कि हम क्या करते हैं? कैसे करते हैं? कुछ छिपाने की बात नहीं है। हम प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन जुटाकर सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेब्ट के सम्बन्ध में होलिस्टिक एवं प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है। हमारी सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सब्सक्राइब किया गया एवं इसके साथ ही हमने आर.बी.आई. द्वारा संचालित गारंटी रिडम्पशन फंड की भी ऑन वर्डिंग की है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। साथ ही, इन कदमों को उठाने के फलस्वरूप राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्व में बढ़ोत्तरी भी नहीं होती। हमारी सरकार विशेष आहरण सुविधा (स्पेशल ड्राइंग फेसिलिटी) तथा मार्गोपयाय

अग्रिम (वेज एंड मींस एडवांस) के माध्यम से भी कम ब्याज दर पर लगातार संसाधन जुटा रही है। साथ ही, हमने अब इस कड़ी में ग्रीन फंडिंग को भी लेवरेश करने का लक्ष्य रखा है।

**पूंजीगत व्यय (केपिटल एक्सपेंडिचर) -** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने गत सरकार के कार्यकाल के समय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के अनुमान को हमारे द्वारा सरकार बनाने पर कम कर 26 हजार 646 करोड़ रुपये करने की बात कही। मुझे यह समझाने अथवा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके द्वारा उठाया गया ये बिंदु तो स्वयं इस बात को स्वीकारने के समान है कि इनकी सरकार के कार्यकाल में काम समय से होते ही नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष ये तथ्य रखना चाहूंगी कि पूंजीगत व्यय (केपिटल एक्सपेंडिचर) जहां वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक पांच वर्षों में केवल 35 प्रतिशत ही बढ़ा, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में ये केपिटल एक्सपेंडिचर 44 प्रतिशत बढ़ाकर 38 हजार 288 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों में 53 हजार 686 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। क्या मुझे यहां फिर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को गणित याद दिलानी पड़ेगी। यह तो सब देख ही सकते हैं कि यहां भी इनके पांच वर्ष पर हमारा एक वर्ष भारी पड़ गया है। हमारी सरकार का ध्येय है सर्वजन हिताय, समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयासरत है। मैं यह कहना चाहूंगी कि-

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर,<br>
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर वे भी बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख के बाद मंत्रिमंडल में कुछ हो रहा है क्या?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमने आय-व्ययक अनुमान 2025-26 में प्रावधित किये गये खर्चों के लिए सभी संसाधनों का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए भी उचित संसाधन उपलब्ध है। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्जा 7 लाख 26 हजार 385 करोड़ हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि राज्य के सर्वांगीण विकास तथा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु ऋण का लिया जाना उचित है। ऋण एवं अन्य दायित्वों का आकलन कुल राशि से न किया जाकर, डेब्ट जी.एस.डी.पी. रेशियो से किया जाता है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में डेब्ट जी.एस.डी.पी. रेशियो 40.33 प्रतिशत से 37.57 प्रतिशत के मध्य रहा था। इसके विपरीत वर्ष 2025-26 में डेब्ट जी.एस.डी.पी. रेशियो केवल 36.50 प्रतिशत अनुमानित है। हमारी सरकार में लिये गये ऋण का प्री-डोमिनेंट उपयोग आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में हो रहा है, जिससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास होता है। हम कांग्रेस सरकार की तरह चुनावी वर्ष में मात्र जनता को गुमराह करने वाली असत्य

अल्पकालीन योजनाओं के लिए ऋण नहीं लेते हैं। आधारभूत संरचना पर अधिक पूंजीगत व्यय किये जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट से सभी क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार होगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में लिये गये ऋण का औसतन 59 प्रतिशत उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिए करना प्रस्तावित किया है, जबकि पिछली सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक लिये गये ऋण का उपयोग अनप्रोडक्टिव राजस्व व्यय में किया था और पूंजीगत कार्यों में केवल 38.97 प्रतिशत ही उपयोग किया था।

**Ans/rtm 19.50 4f 27.02.2025**

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ऋण एवं दायित्वों को एफआरबीएम द्वारा अनुमत सीमा में ही रखेगी। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने वर्ष 2025-26 के जीएसडीपी के आंकड़ों पर आपत्ति उठाई, साथ ही अधिक राजस्व घाटा होने का भी उल्लेख किया है। जीएसडीपी और पर-केपीटा इनकम।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी की गणना 15वें वित्त आयोग द्वारा दिये गये फ़ार्मुला के आधार पर ही की गई है। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा हमारे समय हुई जीएसडीपी की वृद्धि को मात्र इन्फ्लेशन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यहां यह अवगत कराना चाहूंगी कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों, कांस्टेंट प्राइस के अनुसार वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 65 हजार 695 करोड़ की वृद्धि हुई है अर्थात यह वृद्धि इन्फ्लेशन के प्रभाव हटाने के उपरांत की गई है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 6 हजार 224 रूपये की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 2024-25 के प्रचलित मूल्यों, करंट प्राइस के अनुसार वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 18 हजार 406 रुपये की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ें गिना रही हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंकड़ें हमको भी गिनाये, उनके जो आंकडें थे पता नहीं कहां से लेकर आए थे, एक बार फिर से चेक करा लें। मैंने भी बहुत सारे आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं क्योंकि आंकड़ों के अलावा तो आपके पास कुछ बोलने को था ही नहीं, आप तो पता नहीं कौनसे चार्ट पर चले गये, इसलिए मैं अभी आँकड़ों की ही बात कर रही हूं। सब लोग थोड़े चुप है, बोर हो रहे होंगे क्योंकि आंकडें सुनने व समझने में समय लगता है। मैं तो पूरा लिखकर लाई हूं, आपको पता नहीं किसने आंकडें दिए लेकिन आज आंकड़ें बताना जरूरी था।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी सदस्यों ने बजट में राजकोषीय घाटे पर भी चिंता व्यक्त की है। लगता है विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के दृढ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व से प्रस्तुत किये गये हमारे बजट से इतने विचलित हो गए कि जब उन्हें कोई कमी दिखाई ही नहीं दी तो मात्र आंकड़ों के सम्बन्ध में मायाजाल बुनकर, उनका जो यह पूरा असफल प्रयास रहा, इसलिए बहुत जरूरी था कि आपके मैं थोड़े आंकडें सही कर दूं, इसलिए बहुत सारे आंकड़ें मैंने अभी गिनाये हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि

भाजपा सरकार सदैव ही वित्तीय अनुशासन का पालन करती है। हमने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम एक्ट की अनुमत सीमा में ही रखा है।

**शिक्षा एवं स्वास्थ्य।**

अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंसेज 20-24 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों के औसत जहां मात्र 6.13 प्रतिशत है वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु 8.26 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 के लिए 8.40 प्रतिशत का प्रावधान रखा है। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करेगी। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 68 हजार 369 करोड़ का व्यय करेगी जो कि वर्ष 2023-24 से 33.42 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार 2025-26 में शिक्षा पर 38 हजार 369 करोड़ रुपये और इनका 2023-24 में 33.42 प्रतिशत ही था, हमारा उनसे अधिक है, तो देखिये कितना फर्क है। हम लोग शिक्षा के लिये, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना फंड भी एलोकेट किया है। आपने पता नहीं क्या किया, आपके आंकड़ें कुछ और ही कह रहे हैं।

**नियुक्तियां, भर्ती।**

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने अभी तक एक भी नौकरी नहीं दी। लगता है कि इन सदस्यों ने ना तो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना और ना ही उसकी बहस पर दिये गये माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब को सुना। यह तो हल्ला ही करने पर है, हल्ला करो, तमाशा करो, बाहर जाओ, सुनना भी नहीं पड़े और बोलना भी नहीं पड़े।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके बजट की स्पीच इतनी बढ़िया हो रही है कि रफीक साहब बाहर चले गये, धीरे-धीरे सब बैंचें खाली हो गई। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपके मंत्री जी ने कहा कि बोर हो रहे हैं ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपको आंकड़ें सुनना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगा। फिर सब कुछ आईना दिखाने के हिसाब से हो गया, आईना हमने दिखा दिया आपको। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने इन वक्तव्यों को सुना होता तो इन्हें दी गई नियुक्तियों तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों दोनों की ही संख्या पता चल गई होती। मैं इनके ज्ञानवर्धन के लिए एक बार फिर बता दूं कि हमारी सरकार अपने अल्प कार्यकाल में ही 69 हजार से अधिक नियुक्तियां दे चुकी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बता दो कि 69 हजार में आपकी विज्ञप्ति कितनी है, आपने कितने पेपर कराए, आपने कितने भर्ती किए?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमारी ही है, आपका तो जीरो है जीरो ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 01 लाख 73 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सभी को यह बार-बार स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्या तथ्य कौन प्रस्तुत कर रहा है। यहां भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ गलत करना ही गलत नहीं, गलत का साथ देना भी गलत है, चुपचाप रहना गलत नहीं, गलत पर चुप रहना गलत है, किसी की गलती बताना गलत नहीं, अपनी गलती छुपाना गलत है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो लाइनें बोल दूं।

मुख्य मंत्री जी, जुबां तो खोलो, नजर तो मिलाओ जवाब तो दो,

बेरोज़गारों को कितनी बार लूटा है, हिसाब तो दो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): यह तो आपके लिए है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आपके लिए है ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री महोदय, नाराज मत होना, यह अपने खुद के लिए कहा है ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अब प्रतिपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य स्वयं आकलन कर ले कि उन्हें आईना दिखा या नहीं। ...(व्यवधान)... हमारी सरकार तो युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों तथा किसान साथियों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती है।

**ऊर्जा।**

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सिंगल फेज में बिजली बहुत कम आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल में इंस्टाल कैपेसिटी ऑफ पॉवर औसत प्रतिवर्ष लगभग 700 मेगावाट बढ़ी। हमने राज्य के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केवल वर्ष 2024-25 में ही 01 हजार 500 मेगावाट की वृद्धि करते हुए कुल इंस्टाल कैपेसिटी को 26 हजार 325 मेगावाट तक पहुंचा दिया है एवं आगामी वर्षों में भी हम इसे और भी तेजी से बढ़ाएंगे। इसके विपरीत यह तो सभी जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के स्थान पर बिजली खरीद पर ही सारा ध्यान किस सरकार का था। ऊर्जा उत्पादन की तो बात छोड़ दीजिए, बिजली की खरीद पर जब इनकी सरकार थी उस समय पूरा ध्यान तो उसी पर था।

**VPS-RTM-27.02.2025-20.00-4g**

तो कहां से बिजली आप लोग सब लोगों को देते? पूरा आप यह तो देखिये। हमारी सरकार राज्य के सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित करने हेतु ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्प है। इसी कड़ी में मैंने अपने बजट भाषण में भी घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट प्रति माह नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश में जहां एक और ग्रीन एनर्जी में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 50 यूनिट नि:शुल्क बिजली मिलेगी, वही दूसरी ओर लॉन्ग टर्म में बिजली हेतु दी जा रही सब्सिडी का भार भी घटेगा।

आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा जनजाति उप योजना क्षेत्र के

विकास से सम्बन्धित मुद्दे उठाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एस.सी एवं एस.टी. कल्याण के लिए जनसंख्या के अनुपात में 17.83 प्रतिशत एवं 13.48 प्रतिशत से भी अधिक प्रावधान किये हैं, वही साथ ही एस.सी.एस.पी एवं टी.एस.पी. फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाकर 1 हजार 750 करोड़ रुपये प्रावधित किये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुखता देते हुए क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाकर लगभग 10800 करोड़ रुपये का प्रावधान तो किया ही गया है, इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लेबर कम्पोनेंट पर लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए कृषि बजट में भी 14.67 प्रतिशत की वृद्धि भी की गयी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की अधिकांश जनता की जीविका कृषि पर आधारित है। हमारी सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु तत्पर है। हमने किसानों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दी है तथा गेहूं की एम.एस.पी. खरीद पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले बोनस की राशि भी बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि राजकोषीय घाटा 84 हजार करोड़ रुपये कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सर्व-विदित है कि राजकोषीय घाटे की गणना जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 4.11 प्रतिशत तथा 4.25 प्रतिशत अनुमानित किया है जो कि एफ.आर.बी.एम. की अनुमत सीमा में ही है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य घोषणाओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाते हैं कि थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही कागजी घोषणाएं की जाती थीं। मुझे तो विपक्ष के माननीय सदस्यों की सोच पर भी यह सोच कर आश्चर्य होता है कि-

औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी,

और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह दबदबा, यह हुकूमत, यह नशा ए दौलत, किरायेदार है सब, घर बदलते रहते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह हुकूमत और यह नशा बदलते नहीं हैं, आपके लिए परमानेंट सीटें उधर ही रिजर्व की गयी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपके मंत्रीजी सक्षम हैं। वे बोल देंगी। आप

बैठो। आप भी विराजें। ऐसा चलता है। माननीय सचेतक महोदय, नो। और कोई नहीं। विपक्ष के नेता ने कह दिया, आप जवाब देंगी, आप सक्षम हैं। हर बार जवाब देना आवश्यक थोड़े ही है? ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूं। छबड़ा में 1,320 मेगावाट, कालीसिंध में 800 मेगावाट व बाड़मेर में 1,100 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा। अभी और भी है। 71 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना नहीं हुई जो इन्होंने घोषणा की थी। बाड़मेर तथा झुन्झुनूं जिले के लिए 4,765 करोड़ रुपये, उदयपुर सम्भाग के जिलों हेतु 4,674 करोड़ रुपये, परवन पेयजल परियोजना के लिए 3,523 करोड़ रुपये, आदि सिंचाई परियोजनाओं की हवाई घोषणाएं। 8 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नहीं खोला गया। 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान नहीं दिया। विशेष योग्यजन महाविद्यालय नहीं बनाया। ऐसी अनेकों घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी करना तो दूर, काम भी शुरू नहीं किया।

मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगी कि इनके पांच वर्षों में कुल 4,148 घोषणाओं में से लगभग आधी 1,921 घोषणाएं अपूर्ण रही हैं जबकि हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है। जैसे किसान सम्मान निधि पहली बार में ही 8 हजार रुपये एवं दूसरी बार में 9 हजार रुपये कर दी गयी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया तथा वर्ष 2025-26 में पुनः बढ़ाकर 1,250 रुपये किया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत थाली का वजन 250 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एल.पी.जी. सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की गयी है। 73 लाख परिवारों को। 73 लाख परिवारों को। पेंशनर्स को देय आउट डोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दी गयी। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया। ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने हेतु सी.एन.जी., पी.एन.जी. पर वैट को 14.50 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया। 13 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के उन्नयन के कार्य पूर्ण। जहां गत सरकार राजनीति पर समय बरबाद करती थी, वही दूसरी ओर हमने सरकार बनाते ही ई.आर.सी.पी.-पी.के.सी. परियोजना के कार्य को हाथ में लेकर गति देने का काम किया। आज यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि राम जल सेतु परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बजट प्रस्तुत करते समय भी अवगत कराया था, हमने जनता से किये अपने वादों को 58 प्रतिशत तो पांच वर्षों के स्थान पर एक वर्ष में ही पूरा करने का काम किया है।

मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष हमारी सरकार की कार्य प्रणाली में गत सरकार के साक्षेप अंतर के साथ ही आकड़ों की वास्तविकता भी स्पष्ट की है किंतु सबसे बड़ी कसौटी तो आमजन का विश्वास होता है।

**ssy/rtm/**27.02.2025**/20.10/4h**

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर रही माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर जनता द्वारा दी गई सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं घोषणाओं पर आऊंगी। अब तो ताली बजा दो।

**घोषणाएं:**

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट के पश्चात् जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब मैं, नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं-

**पेयजल:**

2. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 330 करोड़ (तीन सौ तीस करोड़) रुपये से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं-

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)**

**ऊर्जा:**

3. विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जायेंगे। इन GSS की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)**

**सड़क:**

4. प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक हजार 870 करोड़ (एक हजार आठ सौ सत्तर करोड़) रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)**

...(व्यवधान)... अभी बहुत सारे पन्ने हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आराम से, आराम से।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): **सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं:**

5. प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान तत्काल सहायता, बचाव कार्य के साथ-साथ आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए-

I. जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग एवं State Disaster Reserve Force (SDRF) के लिए 55 (पचपन) Quick Response Vehicles (QRV) उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग 120 करोड़ (एक सौ बीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।

II. प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित District Emergency Operation Centres के सुदृढीकरण हेतु 41 करोड़ (इकतालीस करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।

6. प्रदेश के बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर एवं बांसवाड़ा में अग्निशमन Aerol Hydraulic Ladder Platform उपलब्ध करवाने के साथ ही, शेष रही निकायों एवं नवीन निकायों में 3 से 4 हजार 500 लीटर क्षमता के Fire Water Tenders उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

7. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)**

8. जोजरी नदी-जोधपुर के जीर्णोद्धार व प्रदूषण सुधार कार्य के अन्तर्गत नादंडी एवं झालामंडल क्षेत्र में STPs का निर्माण एवं सीवर मुख्य ट्रंक लाइनों के पुनर्वास का कार्य तथा गंदे पानी हेतु Sewerage Pumping Station के कार्य 176 करोड़ (एक सौ छिहत्तर करोड़) रुपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

**औद्योगिक विकास:**

9. शाहपुरा-भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क व लालसोट-दौसा में Wood Park की स्थापना की जायेगी।

**पर्यटन, कला एवं संस्कृति:**

10. जनजाति कलाकार वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केन्द्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थल, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ व प्रस्थर कला, नृत्य एवं गायन के प्रलेखन कार्य हेतु सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूं।

11. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सदृश्य स्थानों की दीवारों पर स्थानीय चित्रकारों द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का चित्रण करती हुई Paintings चरणबद्ध रूप से करवायी जानी प्रस्तावित हैं। इस हेतु आगामी वर्ष 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।

12. प्रदेश में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)**

**युवा विकास एवं कल्याण:**

13. युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर Viksit Bharat Young Leaders Dialogue आयोजित किये जाने के साथ ही, आगामी वर्ष Youth Festival का आयोजन करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

14. युवाओं को Startup तथा Digital Ecosystem से अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष TIE Global से जुड़ते हुए Rajasthan Digi Fest का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 15 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

15. छत्तीसगढ़ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश से भाग लेने वाले लगभग 2 हजार 500 प्रतिभागियों की तैयारी हेतु जिला/Block स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना व क्रमोन्नयन, नवीन संकाय/विषय खोले जाने व निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)**

17. जैतारण-ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना, अजमेर में multipurpose स्टेडियम का निर्माण, माचड़ा (विद्याधर नगर)-जयपुर में Play Ground व माउंट आबू-सिरोही में पोलो ग्राउण्ड के उन्नयन कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही ओसियां-जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन-पाली, प्रतापनगर-जयपुर एवं डीडवाना में खेल स्टेडियम के निर्माण करवाये जायेंगे।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :**

18. MAA योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीक से किये जाने वाले नये procedures शामिल किये जाने प्रस्तावित हैं।

ये procedures हैं-

1. Robotic Surgery.
2. Neuro Surgery Procedures.
3. Plastic Surgery and Skin Transplant,
4. Cardiothoracic and Vascular Surgery.

19. प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए Oncology, Midwifery, Forensic सहित 14 नवीन Advanced Courses शुरू किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं। साथ ही, संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 प्रकार के नवीन Para Medical Courses भी शुरू किये जायेंगे।

20. मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए Hospital Manager का Cadre बनाया जाना प्रस्तावित है।

21. मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में hospital support services-laundry, canteen, house keeping, security, parking, garden आदि का सुदृढ़ीकरण Out Sourced/PPP Mode पर किया जायेगा।

22. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, upgradation, भवन निर्माण, repair व maintenance सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)**

23. Rajasthan Digital Health Mission के अगले चरण में मरीज के One Time Registration हेतु IPD मरीजों के लिए Single Window Registration System लागू किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, hassle free service delivery हेतु MAA योजना तथा RGHS Portal को IHMS (Integrated Health Management System) के अन्तर्गत integrate भी किया जायेगा।

**spp/rtm/27.02.2025/20.20/4j**

**सामाजिक सुरक्षा :**

**24.** विशेष आवश्यकता वाले (Specially abled) विद्यार्थियों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से Building को accessible बनाये जाने व Portable Ramps, Disable Friendly Toilets एवं Signages का निर्माण करवाया जायेगा। इन पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

**25.** आगामी वर्ष 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की 50 करोड़ रुपये व्यय कर मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है।

**कृषि एवं पशुपालन :**

**26.** जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित 300 हेक्टेयर तक के 3 हजार 236 (तीन हजार दो सौ छत्तीस) छोटे बांधों को पुनः जल संरचनाओं के समुचित प्रबंधन हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

**27.** प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 240 करोड़ (दो सौ चालीस करोड़) रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूंः-

**(सूची के लिये परिशिष्ट 8 देखें।)**

**28.** पशु रोग नियंत्रण हेतु पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए cold chain युक्त वाहन एवं Ice Linear Refrigerators उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

**29.** कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बाड़ी धौलपुर को Polyclinic में क्रमोन्नत किया जायेगा।

**30.** प्रदेश में रियाबड़ी (मेड़ता) - नागौर में कृषि उपज मण्डी, माखूपुरा-अजमेर, बर (जैतारण) - ब्यावर में फल सब्जी मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, कृषि फल मण्डी

अजमेर में जीर्णोद्धार व प्लेटफार्म सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

**Green Growth (हरित विकास) :**

31. अधिक घनत्व एवं जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में Rare, Threatened, Endangered Species के संरक्षण व संवर्धन हेतु आगामी 2 वर्षों में 40 Plant Micro Reserves 16 करोड़ (सोलह करोड़) रुपये की लागत से बनाये जायेंगे।

32. गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ (Forest Rights Cell) का 18 (अठारह) जिलों में गठन किया जायेगा।

33. राज्य में समन्वित कीट प्रबंधन के लिए 10 प्रयोगशालाएं Tricoderma एवं NPV जैसे Bio-Agents तैयार कर रही हैं। आगामी वर्ष Bio-Agents की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए 100 मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है।

34. प्रदेश के विभिन्न Agro-Climatic Zones के अनुरूप उचित Species एवं उनमें सुधार (Agri-Biologicals) से सम्बन्धित Bio-informatics Data Base स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

35. Plastic की Recycling एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु Plastic Waste Collection Campaign के तहत मोबाइल वैन तथा Plastic Waste Exchange Booths के माध्यम से Plastic Waste Collection करने तथा Plastic Waste के बदले में कपड़े के थैले वितरित किये जायेंगे।

**सुशासन:**

36. State Data Centre (SDC) के अन्तर्गत AI/ML आधारित Research, Simulation, VFX, Gaming, Advance Analytics एवं Image Processing के लिए High Performance Computing (HPC) server infrastructure की स्थापना 65 करोड़ (पैंसठ करोड़) रुपये की लागत से किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, State Data Centre (SDC) के संचालन को automate किया जाना एवं Cyber Security को बढाते हुए Comprehensive Red Teaming Strategy लागू किया जाना भी प्रस्तावित है।

37. प्रदेश में संसाधनों के समुचित उपयोग एवं आधारभूत संरचना पर व्यय में बचत के उद्देश्य से remote sensing एवं GIS प्लेटफॉर्म को Artificial Intelligence से जोड़ते हुए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान कर 'राजधरा 2.0 स्थापित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, RajKaj, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग के IT Platforms एवं IT तंत्र का उन्नयन किया जाना भी प्रस्तावित है।

38. सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की efficiency में वृद्धि हेतु motivate करने के लिए उनसे सम्बन्धित सभी आवश्यक राजकीय प्रक्रियायें यथा-पदस्थापन, पदोन्नति एवं सेवा नियमों से सम्बन्धित कार्य Hassle free, online पद्धति से हो सके, इस दृष्टि से 15 करोड़

(पन्द्रह करोड़) रुपये की लागत से Integrated Human Resource Management System (IHRMS) बनाया जाना प्रस्तावित है।

39. क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा। इनका विवरण मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं:-

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)**

40. प्रदेश के विकास में आमजन की महती भूमिका एवं योगदान को देखते हुए, नवाचार कर समाज से जुड़ी समस्या का उत्कृष्ट व उल्लेखनीय समाधान करने का कार्य करने वाले आमजन को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी वर्ष से Atal Innovation Awards दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

41. अध्यक्ष महोदय, हम जनहित के लिए निरन्तर अथक प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का सामना करते हुए हम विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार कर चहुँमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर मैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरक पंक्तियों का स्मरण भी करना चाहूँगी-

**"हास्य-रूदन में, तूफानों में,**
**अमर असंख्यक बलिदानों में,**
**उद्यानों में, वीरानों में,**
**अपमानों में, सम्मानों में**

**उन्नत मस्तक, उभरा सीना,**
**पीड़ाओं में पलना होगा।**
**कदम मिलाकर चलना होगा।**
**कदम मिलाकर चलना होगा।।"**

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनंतर सदन की बैठक 20.27 बजे शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)**

-------

**परिशिष्ट 1**

**पैरा संख्या 2 में उल्लिखित सूची**

| क्र.सं. | पेयजल सम्बन्धी कार्य | लागत |
|---|---|---|
| 1. | तख्तगढ़ व सुमेरपुर-पाली के लिए पेयजल योजना | 45 करोड रुपये |
| 2. | बिजौलिया-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना का पुनर्गठन | 5 करोड़ रुपये |
| 3. | सहाड़ा, पोटला व गंगापुर शहरी पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन व राथलियास बांध पर नवीन पम्प हाउस-भीलवाडा | 6 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 4. | बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य-दौसा | 72 करोड़ 8 लाख रुपये |
| 5. | बसवा नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य-दौसा | 30 करोड़ 46 लाख रुपये |
| 6. | भोमादा बांध से काणुजा, कोटकिराणा, कलालिया बगड़ी ग्राम पंचायतों को पेयजल योजना से जोड़ने का कार्य जैतारण-ब्यावर | 50 करोड़ रुपये |
| 7. | क्षेत्रीय पेयजल ग्राम पंचायत भाँसु, दाबडदुम्बा, मुंडियाकलां, भंवता, लक्ष्मीपुरा धाकड़ान, राजमहल, बोटुण्डा, कवरांवास, नयागांव एवं बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में स्थित तहसील देवली के 20 ग्रामों की पेयजल योजना के संवर्धन के कार्य टोंक | 22 करोड़ रुपये |
| 8. | इंदिरा गांधी नहर से जसवंत सागर बांध में पानी का पुनर्भरण कर जोधपुर के बिलाड़ा को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना की Feasibility Report-जोधपुर | 50 लाख रुपये |
| 9. | जल जीवन मिशन के अंतर्गत 145 ग्रामों एवं ढाणियों को जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से पेयजल योजना (जमवारामगढ़)- जयपुर | 80 करोड़ 82 लाख रुपये |
| 10. | श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़ में विभिन्न ट्यूबवेल व पाइप लाइन के कार्य-सीकर | 20 करोड़ रुपये |

## परिशिष्ट 2

### पैरा संख्या 3 में उल्लिखित सूची

| क्र.सं. | जीएसएस |
|---|---|
| 1. | 33 केवी जीएसएस- खूंटेटा कलां (रामगढ़) - अलवर, सुवास, छीनोद, सन्दोकड़ा (किशनगंज)-बारां, नामखेड़ा, गांगरोली (नदबई), जाटोली रथभान (सेवर), मोतीझील, स्कीम नम्बर 13-भरतपुर, बांगरेड़ा (निम्बाहेड़ा), रघुनाथपुरा (बेगूं)- चित्तौड़गढ़, जैतारण-ब्यावर, भाण्डू कलां (लूणी)-जोधपुर, कंवला (आहोर) - जालोर, नारदपुरा (जमवारामगढ़), छांदेल कलां (चाकसू), इंजीनियर्स कॉलोनी (मानसरोवर)-जयपुर, पोछिणा-जैसलमेर, कालाकोट (छोटी सादड़ी)- प्रतापगढ़, खूण्डा (मासलपुर)-करौली |
| 2. | 132 केवी जीएसएस- बनेड़ा (शाहपुरा)-भीलवाड़ा, कल्याणपुर (पचपदरा) - बालोतरा, आरडी 837 (कोलायत)-बीकानेर, गुराडिया कलां (डग) - झालावाड़, थांवला-नागौर |
| 3. | 220 केवी जीएसएस-पलाना (कोलायत) - बीकानेर 132 केवी जीएसएस से 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर |

**परिशिष्ट 3**

**पैरा संख्या 4 में उल्लिखित सूची**

| क्र.सं | सड़क सम्बन्धी कार्य | लागत |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर के चारों ओर रिंग रोड निर्माण की DPR-अजमेर | 3 करोड़ रुपये |
| 2. | दत्तोब भादू का खेडा कुहाडा-कणोज-लसाडिया-एकलसिंहा - केकड़ी, एमडीआर सड़क (केकड़ी) अजमेर | 25 करोड़ रुपये |
| 3. | सिंघावल-गोपालपुरा-भिनाय-टांटोटी-डबरेला, MDR सड़क (36 किमी.) (केकड़ी)-अजमेर | 57 करोड़ रूपये |
| 4. | रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड ग्राम चिडवाई से बडौदामेव वाया जयसिंहपुरा, चौलाईबास सड़क का चौड़ाईकरण, नवीनीकरण (8 किमी.) (रामगढ़)-अलवर | 14 करोड़ रुपये |
| 5. | जालुकी चौराहे से सीकरी वाया गोविन्दगढ़ सड़क (स्टेट हाईवे 35) सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (14 किमी.) (रामगढ़) - अलवर | 21 करोड़ रुपये |
| 6. | राजपुर से सेमली फाटक (किशनगंज)-बारां | 6 करोड़ 90 लाख रुपये |
| 7. | आमली से बडोरा MDR 04 के पुनर्निर्माण (13 किमी.) (बारां-अटरू)-बारां | 12 करोड़ रुपये |
| 8. | बाराना से डडवाडा वाया कुंजेड सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण MDR-266 (16 किमी.) (बारां-अटरू)-बारां | 36 करोड़ रुपये |
| 9. | बोरेन से खरदा से पीपल्दा तक सड़क कार्य (6 किमी.) (किशनगंज)-बारां | 6 करोड़ रुपये |
| 10. | पाली जैतपुर-गेलावास-बरवा-मजल-करमावास किमी 49/0 से 68/0 डबल लेन सड़क (सिवाना)-बालोतरा | 22 करोड़ रुपये |
| 11. | भानावास-कोटडी मठ खरन्टीया सड़क पर पुलिया निर्माण (सिवाना)-बालोतरा | 2 करोड़ 40 लाख रुपये |
| 12. | बांझाकुडी, बलुन्दा, कानावास, काणेचा फाटा, बिकरलाई, रामावास, बिरोल तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (18 किमी.) (जैतारण) - ब्यावर | 18 करोड़ रुपये |
| 13. | बर मेघड़दा, भैंरू का नाका, काणुजा सड़क (जैतारण)-ब्यावर | 7 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 14. | गाफा सम्पर्क सड़क से गांव सरूपा तक सड़क (6.25 | 3 करोड़ 50 लाख |

| | | |
|---|---|---|
| | किमी.) ब्यावर | रुपये |
| 15. | चरकड़ा फांटा (NH 62) से सीएससी मूलवास (सीलवा) किमी 0/0 से 9/500 तक सड़क नवीनीकरण कार्य (8) किमी.) (नोखा) - बीकानेर | 1 करोड़ 85 लाख रुपये |
| 16. | बी.टी. सड़क निर्माण इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 1000 आरडी से चारणवाला ब्रांच की 50 आरडी तक वाया नारायणसर तक (16.50 किमी.) (कोलायत) - बीकानेर | 8 करोड़ 80 लाख रुपये |
| 17. | लूणकरणसर से बडेरन सड़क का निर्माण (15 किमी.) (लूणकरणसर) - बीकानेर | 19 करोड़ रुपये |
| 18. | बाड़मेर शहर में विभिन्न नवीन सड़कों का निर्माण व सड़कों का चौड़ाईकरण-बाड़मेर | 20 करोड़ रूपये |
| 19. | SH 40 का बाड़मेर खण्ड के अधीन चवा से बायतु भीमजी तक सड़क सुदृढीकरण (5 किमी.) (बाड़मेर)- बाड़मेर | 5 करोड़ रुपये |
| 20. | बाखासर से रड़वा तक सड़क डामरीकरण (9 किमी.) (चौहटन) -बाडमेर | 1 करोड़ 80 लाख रुपये |
| 21. | भदराई (डाबली) से पी.एच. 1 वाया चकगुढा से जीवाणीयों की ढाणी पी.एच.3 तक मैन कैनाल के पास धोरीमन्ना रोड़ तक सड़क (25 किमी.) - बाड़मेर | 30 करोड़ रुपये |
| 22. | धोरीमन्ना कृषि मंडी फांटा से मिठड़ा, खारी, भारते की बेरी तक सड़क (17 किमी.) - बाड़मेर | 20 करोड़ रुपये |
| 23. | रूपवास जटमासी सड़क निर्माण (8 किमी.)- भरतपुर | 15 करोड़ रुपये |
| 24. | ब्रह्मवाद-बारैठा सड़क का सुदृढ़ीकरण (5.5 किमी.)- भरतपुर | 8 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 25. | मथुरा बाईपास से मुरवारा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (2 किमी.)-भरतपुर | 10 करोड़ रुपये |
| 26. | प्लाट नम्बर ई-90, ब्रज औद्योगिक क्षेत्र से जघीना रोड (LC-24G) तक सड़क का उन्नयन कार्य-भरतपुर | 4 करोड़ 10 लाख रुपये |
| 27. | प्लाट नम्बर GI-128 से E-90, ब्रज औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य-भरतपुर | 2 करोड़ 95 लाख रुपये |
| 28. | रेडक्रॉस सर्किल से रेलवे स्टेशन सड़क का चौड़ाईकरण- भरतपुर | 7 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| 29. | समिधी से चावण्डपुरा होते हुए खातौली तक सड़क (7 किमी.) (केशोरायपाटन)-बूंदी | 5 करोड़ रुपये |
| 30. | मांगली नदी पर रपट पुलिया निर्माण कार्य लालपुरा गांव से मंडी को जोड़ने वाले रास्ते पर-बूंदी | 2 करोड़ रुपये |
| 31. | नाथडियास (रायपुर) से मोटरा का खेड़ा के बीच कोठारी नदी पर पुलिया का निर्माण (सहाड़ा) - भीलवाड़ा | 4 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 32. | पहुँना (चित्तौड़गढ़) से भरक माताजी (भीलवाड़ा) तक सड़क (25 किमी.) - चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा | 40 करोड़ रुपये |
| 33. | सुदरी चौराहा (चित्तौड़गढ़) से सोनियाणा (भीलवाड़ा) तक सड़क मय पुलिया (25 किमी.) चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा | 25 करोड़ रुपये |
| 34. | माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों को जोड़ने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पुल निर्माण (गढ़ी)-बांसवाड़ा | 60 करोड़ रुपये |
| 35. | तारानगर से बांय वाया चंगोई सड़क (22 किमी.)-चूरू | 30 करोड़ रुपये |
| 36. | क्षतिग्रस्त ऑवरब्रिज (चूरू-जयपुर रोड पर) की मरम्मत-चूरू | 20 करोड़ रुपये |
| 37. | चूरू शहर की सड़कों का उन्नयन-चूरू | 10 करोड़ रुपये |
| 38. | ग्राम सिरसला रेलवे लाईन पर अन्डरब्रिज निर्माण कार्य (चूरू)- चूरू | 6 करोड़ रुपये |
| 39. | मेहरासर उपाध्यान से लूकसा मंदिर व महाविद्यालय तक सड़क (5 किमी.)-चूरू | 1 करोड़ 75 लाख रुपये |
| 40. | ढाणा पट्टा राजपुरा से रतनपुरा NH 52 तक (4 किमी.)- चूरू | 1 करोड़ 40 लाख रुपये |
| 41. | बूचावास से गाजूवास तक सड़क (7 किमी.)-चूरू | 2 करोड़ 45 लाख रुपये |
| 42. | लालसोट में विभिन्न सड़क कार्य (लालसोट) दौसा | 20 करोड़ रूपये |
| 43. | सिकराय में विभिन्न नवीन सड़कों के निर्माण कार्य (सिकराय)- दौसा | 20 करोड़ रूपये |
| 44. | जिला अस्पताल से श्यालावास जेल वाया रलावता चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (12 किमी.)(सिकराय) दौसा | 16 करोड़ रूपये |
| 45. | NH 921 से दौसा कुण्डल बांदीकुई, मण्डावर, कठूमर | 3 करोड़ 50 लाख |

| | | |
|---|---|---|
| | सड़क (3.5 किमी.) (महवा) दौसा | रुपये |
| 46. | NH 21 करोडी मोड से लोटवाड़ा सड़क (4 किमी.) (महवा) दौसा | 2 करोड़ रुपये |
| 47. | कोट से बनावड, राजपुर, लाडनपुर एवं बनावड घाटी सृदृढ़ीकरण (8 किमी.) (महुवा)- दौसा | 6 करोड़ रुपये |
| 48. | डीडवाना-मारवाड़ बालिया-खुनखुना-रूवां-बडाबरा-खाटू खुर्द तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य (41 किमी.)- डीडवाना कुचामन | 60 करोड़ रुपये |
| 49. | ग्राम मौलासर में बाईपास निर्माण (4.6 किमी.)- डीडवाना-कुचामन | 14 करोड़ 20 लाख रुपये |
| 50. | गामडा चारणिया से बरसिंगपुर तक, करियाणा बस स्टेण्ड से उबापाणा साटिया से भचडिया तक सड़क निर्माण एवं कसारीया से मोरडी भैरवजी मंदिर के बीच पुलिया निर्माण (12 किमी.) (सागवाड़ा)-डूंगरपुर | 11 करोड़ रुपये |
| 51. | धौलपुर शहर की विभिन्न सड़कों की मरम्मत-धौलपुर | 10 करोड़ रुपये |
| 52. | माजरी भाण्डा रोड से सरूपसराय होते हुए पदमाडा कलां की ओर सड़क ब्लॉक मुण्डावर (3.5 किमी.)- खैरथल तिजारा | 1 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 53. | तिजारा टोल टैक्स से कृषि उपज मण्डी तिजारा तक वाया बस स्टैण्ड तिजारा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण (3 किमी.)- खैरथल तिजारा | 26 करोड़ रुपये |
| 54. | खेड़ी-खरखड़ी upto हरियाणा सीमा तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण (3.5 किमी.)- खैरथल तिजारा | 7 करोड़ रुपये |
| 55. | SH-52 से नीमूचाणा-कुण्डली-कराणा-चैनपुरा सड़क (13.5 किमी. ) (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़ | 20 करोड़ 25 लाख रुपये |
| 56. | एम.डी.आर प्रागपुरा से किरारोद, मालेरा जोहड़, सामोता की ढाणी, NH 48 तक, भाबरू (NH 48) से जवानपुरा होते हुए बागावास चौरासी तक, NH-48 रिलायंस पेट्रोल पंप से तुलसीपुरा वाया तलियारा सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (16.4 किमी.) (विराटनगर) - कोटपूतली बहरोड़ | 24 करोड़ रुपये |
| 57. | आतेंला (पिपली स्टेण्ड) से छितोली वाया किशनपुरा, सूरजपुरा तक सड़क (8.2 किमी.) (विराटनगर)- | 10 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | कोटपूतली बहरोड़ | |
| 58. | बालाजी मन्दिर, मूडिंया से माहला गांव बदलेटा वाया इन्द्रा कॉलोनी मूडिंया तक सड़क (5 किमी.) करौली | 2 करोड़ 10 लाख रुपये |
| 59. | स्टेट हाईवे-137 (किमी. 65/500 से 68/500) पर करणपुर घाटी सड़क का निर्माण कार्य (3 किमी.) (सपोटरा) - करौली | 50 करोड़ रुपये |
| 60. | ताजपुर-भरतून-मसावता-रानेटा-नारौली डांग-खेड़ला-विच्छदोना सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (45 किमी.) (सपोटरा)-करौली | 65 करोड़ रुपये |
| 61. | रायपुरा चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा | 75 करोड़ रुपये |
| 62. | नौनेरा से गैंता तक सड़क (4.2 किमी.) (पीपल्दा)-कोटा | 3 करोड़ रुपये |
| 63. | सनमानपुरा से भोपालगंज की सड़क तलाव माइनर के किनारे (4.5 किमी.) (पीपल्दा)-कोटा | 3 करोड़ 15 लाख रुपये |
| 64. | ओटवाला मामाजी से ओरण तक सायला बाईपास (10 किमी.) - जालोर | 15 करोड़ रुपये |
| 65. | ऊण से भैंसवाड़ा, आलावा सी से पावटा, भागली पुरोहितान से आहोर, गुड़ा बालोतान से थांवला, अगवरी से कुआड़ा, छीपरवाड़ा से आहोर, चांदना से सियाणा, हरजी से सिरोही सीमा तक सड़क मय पुल निर्माण (17 किमी.) (आहौर) - जालोर | 76 करोड़ 80 लाख रुपये |
| 66. | रूचियार से पाथेडी तक सड़क (5 किमी.) (भीनमाल)-जालोर | 2 करोड़ रुपये |
| 67. | थोबाऊ से निम्बाऊ तक सड़क (4 किमी.) (भीनमाल) - जालोर | 2 करोड़ रुपये |
| 68. | कावतरा से दासपा सड़क (10 किमी.) (भीनमाल)-जालोर | 4 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 69. | सारब का बेरा देलदरी से बिबलसर तक सड़क डामरीकरण (6 किमी.) (आहौर)-जालोर | 2 करोड़ 90 लाख रुपये |
| 70. | दहीवा से भाटा (बालोतरा सीमा) तक सड़क (4 किमी.) जालोर | 1 करोड़ 60 लाख रुपये |
| 71. | हीरा का बास से कुमावतों की ढाणी, बावड़ी गोपीनाथ से लालासर सीमा, गुवारडी से जयसिंहपुरा, रेनवाल रोड़ से | 5 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | विमलपुरा सड़क, सबलपुरा से रायथल, ढोढसर से श्रीराम सामोता के मकान तक, जाटावाली से लेकर मानपुरा माचेड़ी सड़क (13 किमी.)-जयपुर | |
| 72 | दम्बा का बास से हस्तेड़ा, लोहरवाड़ा से बेरावाली ढाणी, विमलपुरा से कुमावतों का बाढ़, कालाडेरा से रैगरों की ढाणी, सुल्तानपुरा से फतेहपुरा तक, दूतों की ढाणी से प्रागपुरा सड़क (13 किमी.)-जयपुर | 5 करोड़ रुपये |
| 73. | ग्राम साखून में बाईपास निर्माण कार्य (5 किमी.) (दूदू)-जयपुर | 14 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 74. | NH 48 जाजे कलाँ से SH 13 साईवाड़ मोड तक वाया रामपुरा, छापर की ढाणी, जलेबी चौक, बाड़ीजोड़ी साईवाड-जयपुर | 25 करोड़ रूपये |
| 75. | सीकर रोड पर रोड़ नं. 1 पर RUB (विद्याधर नगर)-जयपुर | 20 करोड़ रुपये |
| 76. | रामौला सड़क से वाया बृसिंहपुरा होते हुए बरना स्कूल तक सड़क (3.5 किमी.) (आमेर)-जयपुर | 1 करोड़ 90 लाख रुपये |
| 77. | डिडावता से मुकन्दपुरा तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (5 किमी.) (चाकसू)-जयपुर | 7 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 78. | डिडावता से भानपुरा संग्रामपुरा, डिडावता से नई तन की ढाणी, हनुतिया खुर्द से केरा वाली ढाणी तक सड़क (11 किमी.) (चाकसू)-जयपुर | 6 करोड़ 60 लाख रुपये |
| 79. | एसडीएम कोर्ट से वाया साऊ ध्यावणा होते हुए साऊ सीरा तक नवीनीकरण एवं आंतरिक सड़क निर्माण (15 किमी.) (जमवारामगढ़) - जयपुर | 8 करोड़ रुपये |
| 80. | जयपुर-भीलवाड़ा रोड (एसएच-12) पर मुहाना मोड़ जंक्शन पर फ्लाईओवर-जयपुर | 80 करोड़ रुपये |
| 81. | सांगानेर क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य-जयपुर | 50 करोड़ रुपये |
| 82. | फुलेरा शहर की विभिन्न सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-जयपुर | 10 करोड़ रुपये |
| 83. | सुधारवाला रोड से 3 JJM से 4/6 DDM तक सड़क (5 किमी.)-जैसलमेर | 1 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 84. | सोयला-औंसिया सड़क का सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण (51 किमी.) - जोधपुर | 65 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| 85. | रोहिचा फांटा से उत्तेसर तक सड़क का सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण (12 किमी.)-जोधपुर | 17 करोड़ रुपये |
| 86. | राष्ट्रीय राज मार्ग NH-25 झुरली से खेजड़ला तक 2 लेन सड़क (14) किमी.) (बिलाड़ा) - जोधपुर | 15 करोड़ रुपये |
| 87. | अकलेरा में बाईपास निर्माण (मनोहरथाना) - झालावाड़ | 7 करोड़ रुपये |
| 88. | नेहरावाद से कनवारी मय कॉजवे का निर्माण (4 किमी.) (डग)-झालावाड़ | 8 करोड़ 12 लाख रुपये |
| 89. | सिंघाणा से माकड़े तक सड़क का नवीनीकरण (सूरजगढ़) - झुंझुनूं | 1 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 90. | पीएचसी बुगाला से छऊ खेदडो की ढाणी, नवलड़ी में श्मशान से लेकर बदरीया वाली ढाणी, डूमरा पावर हाउस से लेकर जेजूसर डाबडी बलौदा, राणासर से लेकर डाबड़ी बलौदा, डूढिया की ढाणी से बेरी, परसरामपुरा में सिगनोर मुख्य सड़क से खेदड की सीमा तक, परसरामपुरा रामदेव मंदिर सड़क, जाखल गौशाला से डूडियो का बास, कोलसिया की सड़क (20 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं | 6 करोड़ रुपये |
| 91. | जयसिंहपुरा सिरसला, आईसीआईसीआई बैंक महराणा रोड वाया नीमली पहानिया चितोसा खांदवा इटावाजोहड़, भैसावता खुर्द-लामडीजोहडी, पचेरी इन्द्रसर, खांदवा मांडी, शहीद मूर्ति सागा, रसूलपुर शिव मंदिर, रायपुर सांतोर घरडाना खर्द- गोठ, किठाना भैसावता रोड-राजपुरा हीरवा जीवन निवास, बुहाना खडेश्वरी धाम तक सड़क कार्य (15 किमी.) (सूरजगढ़) - झुंझुनूं | 6 करोड़ रुपये |
| 92 | चिड़ावा (SH-8) से उद्यमपुरा- बास कल्याणा- काकोडा - जयसिंहवास - बेरला बलौदा (हरियाण सीमा) तक MDR 317 (31.5 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं | 38 करोड़ रुपये |
| 93. | बगड़ कस्बे के उत्तर दिशा में बाईपास सड़क की DPR का कार्य (झुंझुनूं)-झुंझुनूं | 20 लाख रुपये |
| 94. | खरनाल से धुन्धियाड़ी वाया पालड़ी व्यासा-मुन्दियाड़-मोड़ी-कालियास-भदौरा दोहरी तक डामर सड़क चौड़ाईकरण (40 किमी) (खींवसर)-नागौर | 32 करोड़ रुपये |
| 95. | सिली बॉर्डर ईसरनावडा-पांचलासिद्धा-सैनिक नगर-आचीणा-माडपुरा- दुजासर-एसएच 19 तक डामर सड़क | 24 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | चौड़ाईकरण (40 किमी) (खींवसर)-नागौर | |
| 96. | मेड़तासिटी (NH-58) खेड़ुली दतानी ईग्यासनी-खुडीकलां -बरना-बामणा-चुई-कंवाल-जाखेड़ा मुण्डाखेड़ी-राणीगांव (SH -2B) तक सड़क (25 किमी.) (मेड़तासिटी) - नागौर | 25 करोड़ रुपये |
| 97. | NH-458 से NH-58 तक बाईपास सड़क की DPR (मेड़तासिटी) - नागौर | 1 करोड़ रुपये |
| 98. | शंखवास में बाईपास निर्माण (3.8 किमी.) (खींवसर)-नागौर | 5 करोड़ 33 लाख रुपये |
| 99. | शंखवास से सैनणी मिसिंग लिंक सड़क (10 किमी.) (खींवसर)-नागौर | 3 करोड़ रुपये |
| 100. | खरनाल बस स्टेण्ड से बुंगरी माता मंदिर तक सीसी सड़क (2 किमी.) (खींवसर)-नागौर | 2 करोड़ रुपये |
| 101. | ढेलाणा गायनों की ढाणी रिंग रोड़ से भोमिया जी का थान, सुथारों की ढाणी, ढेलाणा तक सड़क (600 मी.)-फलौदी | 20 लाख रुपये |
| 102. | ग्रा.पं. नौसर, पूनियों की ढाणी चौतीणा बेरा से गुरू जम्भेश्वर मन्दिर तक सड़क (1.5 किमी.)-फलौदी | 50 लाख रुपये |
| 103. | करणीपुरा पडियाल कडेला की ढाणी से महाराज की दुकान तक सड़क (3 किमी.)-फलौदी | 1 करोड़ रुपये |
| 104. | ग्राम भोजासर से ग्राम पडियाल तक डबल रोड (12 किमी.) फलौदी | 14 करोड़ रुपये |
| 105. | जीवन्द कलां से बोरड़ी वाया पंचायत भवन, विद्यालय भवन सड़क (2 किमी.)-पाली | 96 लाख रुपये |
| 106. | जीवन्द कलां से खारडा डामर सड़क से जीवन्द ढाणी-पाली | 1 करोड़ 37 लाख रुपये |
| 107. | MDR 373 मारवाड जंक्शन से रानी (मारवाड़ जंक्शन) - पाली | 40 करोड़ रुपये |
| 108. | A/R दांता वाया केलामेला सड़क (4.5 किमी.)-प्रतापगढ़ | 6 करोड़ 60 लाख रुपये |
| 109. | करडका से भोपा की ढाणी तक सड़क (श्रीमाधोपुर)-सीकर | 2 करोड़ रुपये |
| 110. | मुण्डरू से फूटाला तक सड़क (2.83 किमी.) | 2 करोड़ 25 लाख |

| | | |
|---|---|---|
| | (श्रीमाधोपुर) - सीकर | रुपये |
| 111. | NH-552 से SH-122 (कावड) वाया नया गांव बालाजी डेकवा इटावा का बालाजी (12 किमी.) (खण्डार)- सवाई माधोपुर | 20 करोड़ रुपये |
| 112. | खण्डार में महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य-सवाई माधोपुर | 10 करोड़ रुपये |
| 113. | सवाई माधोपुर में विभिन्न सड़कों के कार्य-सवाई माधोपुर | 35 करोड़ रुपये |
| 114. | नांगल खानवास रोड से टोडरवास वाया देहलास बाबा का स्थान तक सड़क (1.5 किमी.)-सवाई माधोपुर | 1 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 115. | चांदनहोली सड़क से हल्कारा की ढाणी तक सड़क (3.7 किमी.) (बामनवास) - सवाई माधोपुर | 1 करोड़ 75 लाख रुपये |
| 116. | गंगापुर सिटी ताजपुर-डाबरा रोड वाया रेलवे स्टेशन, गंगापुर सिटी (7 किमी.) (गंगापुर सिटी)- सवाई माधोपुर | 12 करोड़ रुपये |
| 117. | स्वरूपगंज-कालन्दी सड़क चैनेज किमी 0/00 से 19/00 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (19 किमी.) (पिण्डवाडा आबू)-सिरोही | 25 करोड़ रुपये |
| 118. | सड़क चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण-सिवेरा मालनू चैनेज किमी 0/00 से 4/00 तक तथा चैनेज किमी 3/00 पर मय पुलिया निर्माण (4 किमी.) (पिण्डवाड़ा-आबू)-सिरोही | 6 करोड़ 20 लाख रुपये |
| 119. | अचपुरा कासिन्द्रा से एनएच 14 तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा चैनेज 3/00 पर मय पुलिया निर्माण कार्य (3.5 किमी.) (पिण्डवाड़ा-आबू) - सिरोही | 8 करोड़ रुपये |
| 120. | पिण्डवाडा से उदयपुर रोड वाया गडिया चैनेज किमी. 4/00 से 8/00 सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (पिण्डवाड़ा-आबू) - सिरोही | 5 करोड़ 30 लाख रुपये |
| 121. | रायसिंहनगर जियनगर एम.डी.आर. से 35 जी.बी. सड़क कार्य (3) किमी.) (रायसिंहनगर) - श्रीगंगानगर | 1 करोड़ रुपये |
| 122. | 7 एसजेएम लिंक रोड से 12 SJM सड़क कार्य (3.75 किमी.) (रायसिंहनगर) - श्रीगंगानगर | 1 करोड़ रुपये |
| 123. | 74 आर.बी. लिंक रोड से गांव 74 आर.बी. सड़क कार्य (1.5 किमी.) (रायसिंहनगर) - श्रीगंगानगर | 1 करोड़ 15 लाख रुपये |
| 124. | हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य नाथडी-पीपलू-रानोली- | 6 करोड़ रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | कठमाना रोड SH-121 (भोपता नाला नाथडी से पीपलू रोड) (निवाई) - टोंक | |
| 125. | झिलाय से बहड़ तक जिला सीमा वाया खिडगी बस्सी-खेड़ा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (16.5) (निवाई) - टोंक | 23 करोड रुपये |
| 126. | भाड़ोती-खिरनी-बौंली-लाखनपुर-मित्रपुरा-बोरदा दत्तवास तक NH 11A, एक्सटेन्शन किमी. 48/200 से 49/500 (MDR-233) तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (1.30 किमी.) (निवाई)-टोंक | 10 करोड़ 98 लाख रुपये |
| 127. | दोलतपुरा बशीर मुख्य सड़क से बाबा मोहनगिरी महाराज कुटिया तक सड़क (3 किमी.) (टिब्बी) - हनुमानगढ़ | 1 करोड़ 35 लाख रुपये |

## परिशिष्ट 4
## पैरा संख्या 7 में उल्लिखित सूची

| क्र.सं. | विकास कार्य |
|---|---|
| 1 | तारानगर-चूरू, नगर व सीकरी -डीग में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य |
| 2 | लोहागढ़ स्टेडियम एवं जसवंत प्रदर्शनी मैदान में ड्रेनेज कार्य-भरतपुर |
| 3 | बिलाड़ा-जोधपुर, जहाजपुर-भीलवाड़ा, निवाई टोंक में बस स्टेण्ड का जीर्णोद्वार एवं नवीनीकरण तथा केकड़ी-अजमेर में बस डिपो |
| 4 | रिम लसर कबीर वाटिका सिटी पार्क के विकास कार्य (लूणकरणसर)-बीकानेर |
| 5 | विद्याधर नगर-जयपुर में STP का निर्माण |
| 6 | लाल महल उद्यान एवं चौपाटी के विकास कार्य-भरतपुर |
| 7 | अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर से भांकरोटा पुलिया तक बरसाती पानी भराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु पक्के नाले का निर्माण-जयपुर |
| 8 | झालाना चौड़ में सीवरेज लाइन का कार्य-जयपुर |
| 9 | सांगानेर कस्बे में मालपुरा गेट पर वर्षा जल निकासी हेतु नाला निर्माण एवं पूर्व निर्मित नालों के मरम्मत कार्य-जयपुर |
| 10 | निवाई शहर में सीवरेज कार्य-टोंक |
| 11 | अंता में बरसाती नालों के निर्माण व विकास कार्य-बारां |
| 12 | रतन सागर तालाब के अधिशेष पानी हेतु नाला निर्माण कार्य (मसूदा)-अजमेर |
| 13 | भारत माता व द्वारिकादास पार्क सहित सांगानेर के विभिन्न पार्कों का विकास-जयपुर |
| 14 | कॉपरेन कस्बे में ड्रेनेज तंत्र व सौन्दर्यीकरण का कार्य-बूंदी |
| 15 | सामुदायिक केन्द्र का निर्माण- बारां, पाली, प्रतापनगर-जयपुर पोकरण-जैसलमेर में टाउन हॉल का निर्माण |

## परिशिष्ट 5

## पैरा संख्या 12 में उल्लिखित सूची

| क्र.सं. | पर्यटक/धार्मिक स्थलों के कार्य |
|---|---|
| 1 | दांतड़ा धाम मंदिर, घाटारानी माताजी मंदिर के जीर्णोद्धार व अन्य विकास कार्य (जहाजपुर)-भीलवाड़ा |
| 2 | मांडलगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते ऐतिहासिक (बावड़ी) सागर-सागरी का जीर्णोद्धार व राणा सांगा, महाराणा प्रताप स्मारक के निर्माण कार्य (माण्डलगढ़)-भीलवाड़ा |
| 3 | प्रसिद्ध शक्ति पीठ धनोप माता मंदिर व चलानिया भैंरुनाथ मंदिर के विकास कार्य (शाहपुरा)-भीलवाड़ा |
| 4 | श्री मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर का कार्य-कोटा |
| 5 | रामसागर झील का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (हिण्डोली)-बूंदी |
| 6 | शाकम्भरी माता मंदिर (सांभर लेक) के सौन्दर्यीकरण व आधारभूत विकास कार्य-जयपुर |
| 7 | श्री द्वारकाधीश जी मंदिर (झालरापाटन) व श्री पीपानन्द जी मंदिर का उन्नयन, मरम्मत व विकास कार्य-झालावाड़ |
| 8 | गौमती सागर तालाब (झालरापाटन) पर वॉकिंग ट्रेक व अन्य निर्माण कार्य-झालावाड़ |
| 9 | Rural Tourism को बढ़ावा देने हेतु रायसर-बीकानेर को विकसित किया जायेगा। |
| 10 | पदम हवेली का जीर्णोद्धार कार्य-भरतपुर |
| 11 | पुष्कर कॉरिडोर के अन्तर्गत ब्रह्मामंदिर एवं घाट विकास के कार्य-अजमेर |
| 12 | जगन्नाथ मंदिर, केमरी का जीर्णोद्धार व आधारभूत सुविधाओं के कार्य-करौली |
| 13 | खेमजी महाराज तालाब का सौन्दर्यीकरण (हिण्डोली)-बूंदी |
| 14 | चारभुजानाथ मंदिर के पास सेन्ट्रल पार्क विकास का कार्य (केकड़ी)-अजमेर |
| 15 | विमलकुण्ड के सौन्दर्यीकरण का कार्य (कामां)-डीग |
| 16 | पेनोरमा निर्माण-तेजाजी महाराज, सुरपुरा-अजमेर, हड़बूजी सांखला, भूण्डेल (खींवसर)-नागौर तथा श्रीगोगादेव जी राठौड़, सेखाला-जोधपुर |
| 17 | खोड़ियार माता मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (चौहटन)-बाड़मेर |
| 18 | मार्कुण्डेश्वर महादेव जी मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने सम्बन्धी कार्य (पिण्डवाड़ा)-सिरोही |
| 19 | खेतलाजी मंदिर धाम सारंगवास व कुबाजी महाराज तीर्थ-देसूरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व सुविधाओं का निर्माण कार्य (सुमेरपुर)-पाली |

## परिशिष्ट 6
## पैरा संख्या 16 में उल्लिखित सूची

| क्र सं. | महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक/ITI |
|---|---|
| 1. | नवीन महाविद्यालय-भोपालसागर, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़, सायरा-उदयपुर, माधोराजपुरा-जयपुर एवं श्रीविजयनगर- श्रीगंगानगर |
| 2. | नवीन कन्या महाविद्यालय-अलवर, आहोर-जालोर, मांढण-कोटपूतली बहरोड़ |
| 3. | नवीन कृषि महाविद्यालय-सिरोही<br>- उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा-जयपुर में बालिका छात्रावास एवं Sports Complex का निर्माण |
| 4. | महाविद्यालय भवन निर्माण-<br>- महाविद्यालय भवन मय ऑडिटोरियम-अजमेर<br>- कन्या महाविद्यालय-सादुलशहर-श्रीगंगानगर<br>- MSJ महाविद्यालय-भरतपुर में अध्ययन ब्लॉक, ऑडिटोरियम निर्माण व अन्य कार्य |
| 5. | नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय-रामगंज मण्डी, कनवास-कोटा |
| 6. | नवीन ITI-विद्याधरनगर-जयपुर |
| 7. | ITI भवन का निर्माण-कोटकासिम खैरथल तिजारा |

## परिशिष्ट 7
## पैरा संख्या 22 में उल्लिखित सूची

| क्र.सं. | चिकित्सा संस्थान/कार्य |
|---|---|
| 1. | उप जिला चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन-रामगंजमण्डी-कोटा |
| 2. | - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन-रामगढ़-अलवर, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, खण्डार-सवाई माधोपुर<br>- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-मुरलीपुरा, प्रतापनगर-जयपुर<br>- नवीन सैटेलाइट अस्पताल-पृथ्वीराज नगर-जयपुर |
| 3. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- मानोता कलां (नगर)- भरतपुर, किटनोद (पचपदरा) - बाड़मेर, सवाईपुर (जहाजपुर), कारोई (सहाड़ा), ब्राह्मणों की सरेरी (आसींद)-भीलवाड़ा, जसनगर एवं पादुकलां (मेड़ता), लूणवां (नावां) नागौर, चाड़ी (लोहावट)-फलौदी |
| 4. | नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- महनपुर (बानसूर) कोटपूतली बहरोड़, भेड़ाना (गुड़ामालानी)- बाड़मेर, पीरकामडिया (टिब्बी)-हनुमानगढ़ |
| 5. | नवीन UAAM- बुद्ध विहार-अलवर |
| 6. | उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- खोड़ीप (भदेसर)-चित्तौड़गढ़, माडियाई खुर्द (औंसिया), बडलिया (धवा)-जोधपुर, बहलोड (जमवारामगढ़), थूणी अहिरान (चाकसू), अजयराजपुरा (बगरू)- जयपुर, छायण (पोकरण)-जैसलमेर, भादसी (आसींद)-भीलवाड़ा, हडियाल, आसलखेड़ी-चूरू, खेतलावास (आहौर)- जालोर, निम्बो का तालाब, बुडकिया (लोहावट), जैसला (घंटियाली)- फलौदी, कनोडिया पुरोहितान (शेरगढ़)-जोधपुर, श्यामगढ़ (नावां)-नागौर, दाबड़दुम्बा (टोडारायसिंह)-टोंक |
| 7. | नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र-कुआरड़ा (आहोर) - जालोर, बांकासर, लालसर (लोहावट)-फलौदी, भेलाणी (फतेहगढ़) - जैसलमेर |
| 8. | ट्रोमा सेंटर - केरू-जोधपुर, भांकरोटा-जयपुर |
| 9. | भवन निर्माण-आयुष चिकित्सालय-रायपुर (सहाड़ा)-भीलवाड़ा बेड क्षमता वृद्धि-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहरगढ़ (किशनगंज)-बारां; इन्द्रगढ़-बूंदी; नारायणपुर (बानसूर)-खैरथल तिजारा, मुकुन्दगढ़-झुंझुनूं, गोविन्दगढ़ (रामगढ़)-अलवर; उप जिला चिकित्सालय जहाजपुर-भीलवाड़ा तथा जिला अस्पताल नवलगढ़-झुंझुनूं |
| 10. | आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य- धौलपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, डीग में अतिआधुनिक Mammography, MRI, CT-Scan Machines |

## परिशिष्ट 8

## पैरा संख्या 27 में उल्लिखित सूची

| क्र.सं. | सिंचाई कार्य | लागत |
|---|---|---|
| 1. | हरिश्चन्द्र सागर परियोजना में मुख्य नहर की शेष वितरिका व माइनर्स के जीर्णोद्धार कार्य-कोटा | 35 करोड़ रुपये |
| 2. | ग्राम नालवास ग्राम पंचायत झापदा के पास पक्का सब सरफेस बेरियर व गेवियन संरचना के कार्य (लालसोट)-दौसा | 8 करोड़ रुपये |
| 3. | भाण्डाहेड़ा में सुहाना तालाब की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार कार्य (सांगोद)-कोटा | 43 लाख रुपये |
| 4. | साहवा लिफ्ट नहर के अन्तर्गत तारानगर-चूरू क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किये जाने हेतु DPR-चूरू | 3 करोड़ रुपये |
| 5. | उम्मेदसागर बांध के वेस्टवियर से निकलने वाले जल प्रवाह के कारण बकनपुरा ग्राम के निकट सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य (किशनगंज)-बारां | 3 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 6. | नारायणखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना डिसिल्टिंग एवं विंगवाल मरम्मत का कार्य (किशनगंज)-बारां | 3 करोड़ रुपये |
| 7. | सादुलशहर एवं श्रीगंगानगर तहसील में गंगनहर प्रणाली के पक्के खालों का निर्माण-श्रीगंगानगर | 15 करोड़ रुपये |
| 8. | भाखड़ा नहर प्रणाली के अन्तर्गत सादुलशहर के पक्के खालों का निर्माण-श्रीगंगानगर | 30 करोड़ रुपये |
| 9. | बांध, एनिकट निर्माण / मरम्मत कार्य- फूलन (समदड़ी) बांध का जीर्णोद्धार; वरदा में साकेरडा फला (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, जीनपुर (सिवाना) बालोतरा, नाई, वडली वाला नाका जाबला, तेलिया मगरा वाडा फला खजुरी, हमाल फला खजुरी-उदयपुर में एनिकट निर्माण तथा बाघेश्वर महादेव व चौहानों का कंथारिया (सतपुडा)-चित्तौड़गढ़ में एनिकट कम कॉजवे का मरम्मत कार्य | 10 करोड़ रुपये |
| 10. | संशोधित पार्वती-कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना के अन्तर्गत आहू एवं पिपलाद नदी के इंटरलिंकिंग के कार्य तथा सिंचाई हेतु आहू नदी पर दो बैराज निर्माण कार्य की DPR-झालावाड़ | 1 करोड़ 20 लाख रुपये |
| 11. | बंध बारैठा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने हेतु DPR-भरतपुर | 2 करोड़ रुपये |
| 12. | Construction of Sub Surface Barrier भायल के बेरे से | 60 लाख रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | आम रास्ता तक पीपलुन (सिवाना)- बालोतरा | |
| 13. | अंता में गणेशगंज लिफ्ट के शेष रहे पम्पों का नवीनीकरण का कार्य-बारां | 2 करोड़ रुपये |
| 14. | चंवली बांध के अपस्ट्रीम में स्थित धरोनिया, सरोनिया एवं ओढ़ियाखेड़ी आदि गांवों की 4 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु DPR-झालावाड़ | 40 लाख रुपये |
| 15. | पार्वती नदी पर ईआरसीपी में प्रस्तावित महलपुर बैराज से बारां जिले में परवन परियोजना के द्वितीय चरण को जल उपलब्ध करवाकर परवन परियोजना के अधिशेष जल से झालावाड़ एवं बारां जिले की 18 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य-बारां | 1 करोड़ 50 लाख रुपये |
| 16. | सोम कागदर मध्यम सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आरडी 6470 पर स्थित क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट का पुनर्निर्माण - उदयपुर | 10 करोड़ रुपये |
| 17. | दिदावली व परमदरा माईनर तथा डीग सब माईनर का जीर्णोद्धार कार्य (नगर)-डीग | 10 करोड़ रुपये |
| 18. | देवी सागर फीडर को गहरी एवं पक्की करने का कार्य (मसूदा)-अजमेर | 3 करोड़ रुपये |
| 19. | लोरड़ी बाँध के अधिशेष जल को लोरड़ी-लोडियाना नाले में डायवर्जन हेतु चैनल निर्माण एवं डाउन स्ट्रीम ड्रेन का निर्माण कार्य (मसूदा)-अजमेर | 5 करोड़ रुपये |
| 20. | इन्द्रगढ़ के मुख्य नहर से सम्बन्धित कार्य-बूंदी | 75 करोड़ रुपये |
| 21. | भादरा क्षेत्र में अमरसिंह सब ब्रांच का नवीनीकरण एवं पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़ | 15 करोड़ रुपये |
| 22. | भादरा क्षेत्र में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजनाओं की नहरों का जीर्णोद्धार-हनुमानगढ़ | 15 करोड़ रुपये |

## परिशिष्ट 9

## पैरा संख्या 39 में उल्लिखित विवरण

| क्र.सं. | इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन |
|---|---|
| 1. | ऊर्जा विभाग-पांचू (नोखा)-बीकानेर, तारानगर-चूरू व बालोतरा में सहायक अभियंता (विद्युत) |
| 2. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- बढारणा (हरमाड़ा), बगरू-जयपुर, खोहरामुल्ला (महुवा)-दौसा व चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर में सहायक अभियंता जैतारण-ब्यावर में अधिशाषी अभियंता |
| 3. | परिवहन विभाग-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में उप जिला परिवहन कार्यालय |
| 4. | पुलिस चौकी से पुलिस थाने में क्रमोन्नयन-समरानिया व रामगढ़-बारां |
| 5. | नवीन तहसील-केरू-जोधपुर उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नयन-केलवाड़ा (किशनगंज)-बारां नवीन उप तहसील-पचेवर (मालपुरा)-टोंक, इटावा-कोटा |
| 6. | सैनिक कल्याण कार्यालय भवन निर्माण-फलौदी |
| 7. | अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय-केशोरायपाटन-बूंदी विशेष न्यायालय (एससी/एसटी)- केकड़ी-अजमेर |